द्वादश माला, खंड 9, अंक 19

गुरूवार, 15 अप्रैल, 1999
25 चैत्र, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 19, गुरूवार, 15 अप्रैल, 1999/25 चैत्र, 1921 (शक)

विषय	कालम
गढ़वाल क्षेत्र और उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में आए भूकंप के बारे में	1—2
प्रश्न काल का निलम्बन किए जाने के बारे में प्रस्ताव	2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	2—193
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360	2—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 से 3672	28—193
मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव	193—284
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	193
श्री शरद पवार	193—204
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	204—218
श्री लालू प्रसाद	218—228
श्री यशवन्त सिन्हा	228—244
श्री पूर्णो ए॰ संगमा	244—252
श्री आर॰ मुथैया	252—256
श्री वैको	256—265
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन	265—271
श्री मुख्तार नकवी	271—277
श्री एस॰सुधाकर रेड्डी	277—282
श्री प्रभुनाथ सिंह	282—284

लोक सभा

गुरूवार, 15 अप्रैल, 1999/25 चैत्र, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

गढ़वाल क्षेत्र और उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में आये भूकंप के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे हाल में ही घटी एक त्रासदी का उल्लेख करना है, जिसमें उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र, प्रभावित हुए हैं।

जैसा कि सभा को मालूम है, कि गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में 29 मार्च, 1999 को एक भीषण भूकम्प आया, जिसमें जान-माल की भारी क्षति हुई। महिलाओं और बच्चों सहित काफी संख्या में लोगों के मारे जाने, घायल होने तथा बेघर होने का समाचार है। चमोली, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और ऊखीमठ बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राहत कार्य चलाए जा रहे हैं।

सदस्यगण प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने में मेरा साथ देंगे; और अब वे खड़े होकर दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालंधर) : भूकम्प से प्रभावित हुए व्यक्तियों के बारे में आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उसमें शामिल हूं। मेरा सुझाव है कि यह सभा सर्वसम्मति से निर्णय करे कि हम अपना एक दिन का वेतन और भत्ता गढ़वाल क्षेत्र के लिए राहत कोष में दान करें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ०प्र०) : एक महीने का वेतन देना चाहिए, हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकरा) : मैं श्री गुजराल का समर्थन करता हूं।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्) : हमें कोई परेशानी नहीं है। एक दिन का वेतन और भत्ता ठीक है। हम अपनी ओर से एक महीने का वेतन देने के लिए सहमत हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यदि आप एक महीने का वेतन दान करने पर सहमत हैं तो मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नकाल का निलम्बन किए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि नियम 388 के अधीन प्रश्नकाल को निलंबित किया जाए ताकि यह सभा मंत्रिमंडल में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा कर सके, जिसकी सूचना माननीय प्रधान मंत्री ने पहले ही दी हुई है।

मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

> "कि यह सभा विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 32 को निलम्बित करती है जिसमें बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "यह सभा विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 32 को निलम्बित करती है। जिसमें बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बीड़ी उद्योग में कार्यरत लोग

***341. डा० उल्हास वासुदेव पाटील :**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी उद्योग में इस समय राज्यवार अनुमानतः कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) क्या इस उद्योग में अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं तथा महिलाएं भी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा बीड़ी की प्रतिस्पर्धा में छोटी सिगरेटें बनाने की अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या छोटी सिगरेटों के निर्माण के कारण बीड़ी निर्माताओं को हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो बीड़ी उद्योग और इसके कामगारों के हितों की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में लगभग 44 लाख बीड़ी कामगार हैं।

(ख) और (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में कराये गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, बीड़ी बनाने में लगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमश : 15.2, 3.3 और 43.3 है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार कारखाना कामगार श्रेणी और गृह कामगार श्रेणी में, बीड़ी बनाने में लगे कुल कामगारों में से, महिला कामगार क्रमश : 50 प्रतिशत और 68 प्रतिशत हैं।

(घ) से (च) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत सिगरेट के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। फिर भी इस प्रावधान के तहत इस तरह से जारी किये गये लाइसेंस में सिगरेट की लम्बाई विनिर्दिष्ट नहीं होती है। सिगरेट विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस सिगरेट संख्या के आधार पर दिया जाता है न कि उसकी लम्बाई के अनुसार। सिगरेट की लम्बाई के आधार पर किया जाने वाला अंतर उत्पाद शुल्क के प्रयोजन के लिए है।

सरकार को बीड़ी उत्पादकों एवं बीड़ी कर्मकारों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें यह सुझाव दिए गए हैं। कि 60 मि. मी. से अधिक लम्बाई की गैर-फिल्टर वाली सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दर में वृद्धि की जाए क्योंकि ऐसी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क का स्तर बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ऐसी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दर 1994-95 में 60 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 1996-97 में 75 रुपये प्रति हजार, 1997-98 में 90 रुपये प्रति हजार एवं 1998-99 में 100 रु. प्रति हजार कर दी गयी। वर्ष 1999-2000 के लिए बजट में ऐसी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दर 110 रुपये प्रति हजार स्टिक नियत की गई है।

रेल आरक्षण टर्मिनल निजी एजेंसियों को देना

*342. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल आरक्षण टर्मिनलों को निजी एजेंसियों को देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उससे क्या लाभ होगा?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) आम आदमी को रेल आरक्षण की सुविधा देने के उद्देश्य से यात्री आरक्षण प्रणाली (या॰आ॰प्र॰) को पार्टी की लागत तथा उपयुक्त पूर्वोपाय इत्यादि के आधार पर प्रयोग के तौर पर रेलों की रेल पर्यटक एजेंट्स योजना तथा रेल यात्री सेवा एजेंट्स योजना के अंतर्गत प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों को देने का प्रस्ताव है। इस सुविधा की व्यवस्था से और अधिक आरक्षण काउंटर उपलब्ध हो जाएंगे परिणामस्वरूप टिकट खरीदने इत्यादि के लिए प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

*343. श्री सी॰ कुप्पुसामी :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रीष्म ऋतु के दौरान अतिरिक्त यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके प्रारंभिक और गंतव्य स्थान जोनवार क्या हैं;

(ग) क्या लंबी दूरी की गाड़ियों में विशेषकर दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में सभी श्रेणियों के डिब्बे उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लंबी दूरी की सभी गाड़ियों में भोजन यान सहित खानपान की व्यवस्था किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लंबी दूरी के यात्रियों के लिए रेलगाड़ी के अन्दर ही खानपान के क्या वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) 10 अप्रैल से जून, 1999 के अंत तक 40 लोकप्रिय मार्गों पर लगभग 2270 ग्रीष्म स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी जिसमें स्थान की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी अर्थात सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी, वातानुकूल कुर्सी यान, एक्जीक्यूटिव कुर्सी यान और वातानुकूल 2 टियर। गर्मी के माह के दौरान कम से कम 68 लोकप्रिय गाड़ियों के सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि की जा

रही है। जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है, ग्रीष्म स्पेशल की अब तक की सबसे बड़ी संख्या चालू वर्ष के दौरान चलाई जाएंगी।

वर्ष	स्पेशल गाड़ियों की संख्या
1995	1155
1996	1214
1997	1347
1998	1959
1999	2270

योजनाबद्ध ग्रीष्म स्पेशल गाड़ियों की एक सूची जोन-वार तैयार की गई है जो विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) 8 ग्रीष्म स्पेशल गाडियों में रसोई यान सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलों को ग्रीष्म स्पेशल गाड़ियों के लिए गाड़ियों से भोजन संदेश दिए जाने का उपयुक्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करके स्थैतिक इकाइयों के लिए मौजूदा/खान-पान व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, आधार रसोई/अल्पाहार गृह से आदेशों के निष्पादन तथा यात्रियों के लिए शीघ्र आपूर्ति, स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में अच्छी गुणवत्ता के किफायती भोजन, जनता खाना, फास्ट फूड मदें आदि के विक्रय द्वारा खाना-पान सेवाओं की व्यवस्था की निगरानी करने के लिए अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

ग्रीष्म स्पेशल की जोन-वार सूची

क्र.सं.	जोन	मार्ग	फेरे	संरचना
1	2	3	4	5
1.	मध्य	मुम्बई-मडगांव	सप्ताह में तीन बार	कुर्सी यान सामान्य, वातानुकूल कुर्सीयान, रसोई यान, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
2.		कुर्ला-वाराणसी	दैनिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, कुर्सी यान सामान्य, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
3.		कुर्ला-वाराणासी	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, कुर्सी यान सामान्य, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
4.		पुणे-गोरखपुर	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, कुर्सी यान सामान्य, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
5.		कुर्ला-पटना-दरभंगा	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
6.		मुम्बई-एर्णाकुलम	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, वातानुकूल 2-टियर, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
7.	पश्चिम	अहमदाबाद-वाराणसी बरास्ता लखनऊ	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
8.		अहमदाबाद-वाराणासी बरास्ता इलाहाबाद	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
9.		मुम्बई-पोरबंदर	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
10.		मुम्बई-गांधीधाम	सप्ताह में तीन बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
11.		अजमेर-मुम्बई	सप्ताह में तीन बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
12.		अहमदाबाद-चेन्नई	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
13.		जयपुर-बेंगलूरू	साप्ताहिक	वातानुकूल 2 टियर, सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान

1	2	3	4	5
14.		गांधीधाम-दिल्ली	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
15.	पूर्व	हवड़ा-नई दिल्ली	4 दिन	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
16.		हवड़ा-देहरादून	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
17.	दक्षिण	चेन्नई-कोल्लम	दैनिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
18.		बेंगलूरू-कोट्टायम	एक दिन छोड़कर	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
19.		चेन्नई एगमौर-तिरूनेलवेली	दैनिक	कुर्सी यान सामान्य, सामन्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
20.		नागरकोइल-दादर	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, प्रथम श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
21.		चेन्नई-कोयमबतूर	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
22.		चेन्नई-दादर	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
23.		विरूदनगर-सेनगौट्टाई	दैनिक	सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
24.	पूर्वोत्तर	दरभंगा-दिल्ली	सप्ताह में दो बार	द्वितीय श्रेणी एवं सामान, स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी,
25.		कुर्ला-गोरखपुर	दैनिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, एवं सामान
26.	उत्तर	निजामुद्दीन-जम्मू तवी	5 दिन	सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
27.		नई दिल्ली-देहरादून	सप्ताह में दो बार	सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
28.		कालका-मुम्बई	4 दिन	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
29.		लखनऊ-काठगोदाम	सप्ताह में तीन बार	वातानुकूल कुर्सी यान, प्रथम श्रेणी कुर्सी यान, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
30.		निजामुद्दीन-चेन्नई	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
31.		बेंगलूरू-निजामुद्दीन	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
32.	दक्षिण पूर्व	हावड़ा-चेन्नई	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
33.		हवड़ा-मुम्बई	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान

1	2	3	4	5
34.		विशाखापत्तनम-चेन्नई	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर द्वितीय श्रेणी एवं सामान, रसोई यान
35.	पूर्वोत्तर सीमा	दादर-गुवाहाटी	पाक्षिक	स्लीपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान, रसोई यान
36.		गुवाहाटी-चेन्नई	पाक्षिक	स्लीपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान, रसोई यान
37.	दक्षिण मध्य	निजामुद्दीन-सिकंदराबाद	साप्ताहिक	स्लीपर श्रेणी, सामन्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
38.		सिकंदराबाद-दादर	साप्ताहिक	सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, स्लीपर श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
39.		सिकंदराबाद-अहमदाबाद	साप्ताहिक	वातानुकूल 2 टियर, सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं सामान
40.		वास्को-चेन्नई	सप्ताह में दो बार	स्लीपर श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल 2 टियर, द्वितीय श्रेणी एवं सामान

दूरदर्शन धारावाहिक 'शक्तिमान'

[हिन्दी]

***344. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती निगम दूरदर्शन से शक्तिमान धारावाहिक के प्रसारण को बंद करने के अपने निर्णय से पीछे हट गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) विभिन्न मंचों से प्राप्त शिकायतों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने 'शक्तिमान' धारावाहिक के प्रसारण को बन्द करने का निर्णय लिया था। तद्नुसार, इस आशय का एक नोटिस इस धारावाहिक के निर्माताओं को दिनांक 23.3.99 से इसका प्रसारण बन्द करने का अनुरोध करते हुए भेजा गया था। तथापि, निर्माताओं ने प्रसार भारती के इस निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.3.99 के आदेश के तहत इस मामले की समग्र रूप से जांच करने के लिए 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे आदेश दिया है कि उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक दूरदर्शन पर इस धारावाहिक का प्रसारण जारी रहेगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस समय इस धारावाहिक का प्रसारण किया जा रहा है।

बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था हेतु पृथक से कोष

***345. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बिना चौकीदार वाले सभी रेल फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने हेतु पृथक कोष बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कोष कब तक बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) जी हां। यह निधि चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने, व्यस्त समपारों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण तथा समपारों पर अन्य संरक्षा कार्यों के लिए होगी। वित्त मंत्री ने 1999-2000 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि रेलों को 2.6.98 से पेट्रोल पर पहले ही लगाए गए शुल्क के साथ-साथ डीज़ल पर । रुपया प्रति लिटर की दर से शुल्क लगाकर केन्द्रीय सड़क निधि में से निधियां मुहैया कराई

जाएंगी। तदनुसार, रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्री से रेलों के लिए इस निधि में से पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें

***346. श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें निजी कंपनियों को देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई बोलियां आमंत्रित की गई हैं और प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों को अपने पास रखने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। शुल्क मुक्त दुकानों को चलाने के लिए दिसम्बर, 1998 में पांचों अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्थल हेतु विश्वव्यापी टेण्डर आमंत्रित किए गए थे। चार पार्टियों ने अपने टेण्डर भेजे थे जिसमें से वित्तीय बोली खोलने के लिए केवल दो पार्टी ही योग्य थी। इन दोनों पार्टियों के प्रस्ताव रद्द कर दिए गए क्योंकि ये प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम रिजर्व लाइसेंस शुल्क से काफी कम थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों के धारावाहिकों के चयन हेतु मानदण्ड

***347. श्री जयराम आई॰एम॰ शेट्टी :**

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने बच्चों के धारावाहिकों के चयन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान चयन किए गए बच्चों के धारावाहिकों का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर पुनः विचार करने और बच्चों के लिए अच्छे स्तर के धारावाहिकों का चयन करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि मार्ग निर्देशों के अनुसार बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों सहित सभी कार्यक्रम प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होना अनिवार्य है। दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं जो अन्ध विश्वासों को बढ़ावा देते हों अथवा बच्चों को पीड़ित या कर्ता के रूप में हिंसात्मक कार्यों में संलिप्त करते हों या उन्हें इनके लिए प्रेरित करते हों।

(ग) और (घ) सामान्यतया, दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिकों से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। हाल ही में धारावाहिक 'शक्तिमान' इसका अपवाद रहा है जो बच्चों में अत्यधिक लोकप्रिय रहा है लेकिन फिर भी विभिन्न मंचों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। यद्यपि प्रसार भारती ने इस धारावाहिक को बन्द करने का निर्णय ले लिया था तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत इसे अभी प्रसारित किया जा रहा है।

बच्चों के कार्यक्रमों/धारावाहिकों की रूपरेखा बनाने और इनके निर्माण का कार्य इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन और शिक्षा के विवेकपूर्ण मिश्रण को सुनिश्चित किया जा सके। इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

टेलीविजन चैनलों हेतु विज्ञापन और कार्यक्रम संहिता

***348. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

श्री अमर पाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी टेलीविजन चैनलों हेतु राष्ट्रीय विज्ञापन और कार्यक्रम संहिता के संबंध में कोई विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विदेशी

चैनलों सहित सभी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता की परिधि में लाने की दृष्टि से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ग) इस समय कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन संबंधी सुविधाएं

***349. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ समय पूर्व उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सेना अधिनियम के अंतर्गत बर्खास्त कोई गैर-कमीशन प्राप्त सेना कर्मी पेंशन संबंधी किसी सुविधा का हकदार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के अधिनियमों के अंतर्गत बर्खास्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन संबंधी लाभ देने के क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आज तक रैंकवार तथा सेवावार कितने अधिकारियों को यह लाभ दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सैन्य कार्मिकों के लिए पेंशन विनियमावली के विनियम 113(क) के उपबंधों को बरकरार रखा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सेना अधिनियम के अंतर्गत बरखास्त किया गया कोई जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारी अथवा अन्य रैंक का सेना कार्मिक पेंशन संबंधी लाभों के लिए हकदार नहीं है।

सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंधित अधिनियमों के अधीन सेवा से बरखास्त किए, निकाले या हटाए गए कमीशनप्राप्त अधिकारियों को तीनों सेनाओं की अपनी-अपनी पेंशन विनियमावली में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अधीन पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं।

जो अधिकारी पिछले पांच वर्षों के दौरान बरखास्त किए या निकाले गए थे और जिन्हें पेंशन संबंधी लाभ दिए गए थे, उनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

जो कमीशनप्राप्त अधिकारी और अन्य रैंक सेवा से बरखास्त किए या निकाले जाते हैं उनकी पेंशन संबंधी हकदारी में असमानता दूर करने का मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कोंकण रेलवे को हुआ घाटा

***350. श्री मोहन रावले :**

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी॰ओ॰टी॰ योजना के अंतर्गत कोंकण रेल निगम (के॰आर॰सी॰) भारतीय रेलवे का पहला प्रयोग है;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेल निगम का एक वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात् इस योजना की अर्थक्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल योजना के अनुसार कोंकण रेलवे के माल यातायात का 40 प्रतिशत सामान्य ग्रांड ट्रंक मार्ग के बजाय कोंकण रेलवे द्वारा जाना था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या के॰आर॰सी॰ पर माल यातायात क्षमता से कम है;

(च) क्या कोंकण रेल निगम को भारी नुकसान हो रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इसकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) किसी अवसंरचना परियोजना के परिचालन के केवल एक वर्ष के पश्चात इसकी अर्थक्षमता का मूल्यांकन करना कठिन है। ऐसी परियोजनाओं की लम्बी परिपक्वता अवधि होती है और इनकी अर्थक्षमता आर्थिक गतिविधियों के विकास पर निर्भर करती है जो मामान्यतः रेलवे नेटवर्क की उपलब्धता के पश्चात होता है। इसलिए इस समय कोंकण रेल निगम की अर्थक्षमता का मूल्यांकन करना कठिन होगा।

(ग) जी हां। राइट्स की 1996 की रिपोर्ट के अनुसार कोंकण रेल निगम का लगभग 43 प्रतिशत माल यातायात भारतीय रेल से मार्ग परिवर्तित होकर प्राप्त होना था। बहरहाल, यह एक पूर्वानुमान था और इसे वास्तविक मार्ग परिवर्तन का आधार नहीं माना जा सकता।

(घ) प्राप्त होने वाले कुल यातायात, परिचालनिक सुविधा और कोंकण रेल निगम सहित उत्तर, दक्षिण की सभी लाइनों की क्षमता

के अनुसार माल यातायात का मार्ग परिवर्तन किया जा रहा है। अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने के लिए किए जा रहे और उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) 35 प्रतिशत वृद्धि के साथ बेलारी/होज़पेट के लौह अयस्क जिससे 25 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ रोहा के लिए प्रति दिन 2 रेक प्राप्त हो सकते हैं, के लिए मैसर्स निप्पोन एण्ड विक्रम इस्पात से सहमति के लिए संपर्क किया जा रहा है।

(2) एचपीसीएल-एमआरपीएल-ठोकूर से उत्तर की दिशा के लिए पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक के यातायात को विकसित करना।

(3) हाल ही में 'रौल ऑन-रौल ऑफ' यातायात योजना शुरू की गई है जो लोकप्रिय साबित हो रही है।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) वर्ष 1998-99 के लिए राजस्व और व्यय के अनुमानों के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा मोटे तौर पर आमदनी से परिचालन व्यय पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इस प्रकार निगम को कोई विशेष परिचालनिक हानि नहीं होगी। बहरहाल, बाजार ऋण के वित्तपोषण की लागत जो लगभग 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है और लगभग 60 करोड़ रुपए मूल्यह्रास के कारण वित्त वर्ष के अंत में निगम द्वारा 360 करोड़ रुपए की समग्र हानि वहन किए जाने की संभावना है। हानि के लिए मुख्य कारण ब्याज का बोझ है तथा साथ ही यह भी एक कारण है कि इस लाइन पर माल यातायात अभी बढ़ना है जो मुख्यतः इस लाइन के साथ स्थित उद्योगों द्वारा लाइन चालू होने के साथ गति नहीं बनाए रख पाना है।

(ज) इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) अन्य साधनों से यातायात का रुख अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपभोक्ता अनुकूल सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु कोंकण रेल को सुदृढ़ करना।

(2) नई सेवाएं शुरू करना जैसे कोंकण स्टार सेवा (एक उच्च श्रेणी की सुपर फास्ट एक्सप्रेस सेवा)

(3) यदि निप्पोन और विक्रम इस्पात, दोनों सहमत हो जाएं, तो 35 प्रतिशत वृद्धि के साथ बेलारी/होज़पेट के लौह अयस्क से दो रेक प्रतिदिन प्राप्त हो सकते हैं।

(4) एचपीसीएल-एमआरपीएल-ठोकूर से पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक के यातायात को उत्तर की दिशा के लिए विकसित करना।

[अनुवाद]

डीज़ल इंजन की प्रौद्योगिकी का उन्नयन

*351. **श्री मदन पाटील :**

श्री के॰ येरननायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत इंजन डीज़ल इंजन से महंगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रेलवे को वर्ष 1998-99 के दौरान आज तक विद्युत रेल इंजन के कारण कितनी धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा;

(घ) सरकार ने रेलवे को वाणिज्यिक रूप से और अधिक अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार डीज़ल इंजनों की एल्को (यू॰एस॰) प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) डीज़ल और बिजली रेल इंजनों की लागत नीचे दी गयी है :-

	यात्री	मालगाड़ी
डीज़ल	2.64 करोड़ रुपए (2300 अश्व शक्ति)	3.11 करोड़ रुपए (3100 अश्व शक्ति)
बिजली	3.17 करोड़ रुपए (5000 अश्व शक्ति)	3.32 करोड़ रुपए (5000 अश्व शक्ति)

(ग) कर्षण का चयन करते समय समग्र खर्चों में इंजन की लागत ही एक अकेला आधार नहीं माना जाता। ऐसा करते समय ऊर्जा की लागत, मरम्मत एवं रखरखाव, रेल इंजनों की उत्पादकता और परिचालनिक खर्चों आदि जैसे अन्य कारणों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए ऐसा कोई कदम उठाया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ङ) से (छ) विश्व निविदा के जरिए एल्को अभिकल्प के रेल इंजनों के ग्रेडोन्नयन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अर्थक्षमता और परिचालनिक लाभों के आधार पर यथासमय निर्णय ले लिया जाएगा।

विमान यातायात नियंत्रकों की हड़ताल

*352. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1999 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "फ्लाइट शैड्यूल्स गो हेवायर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विमान यातायात नियंत्रकों के धीमी गति से काम करने और अन्य आंदोलन कितनी अवधि तक चले और इस दौरान वायुयानों के उड़ान भरने और उतरने में कितनी बार और कितना विलम्ब हुआ और इस मामले के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार ने उन कारणों की जांच कराई है जिनके कारण सभी सरकारी और निजी विमानकंपनियों को घाटा हुआ और "मुक्त आकाश" नीति के अंतर्गत भारतीय आकाश में आई अधिकांश निजी क्षेत्र की विमान कंपनियां बंद हो गई या बंद होने के क़गार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विमान यातायात नियंत्रकों ने 1.2.99 से "धीमे चलो" और "नियम के अनुसार काम" का अनुसरण किया जिसके परिणामस्वरूप 18.2.99 तक उड़ाने अस्त-व्यस्त हो गई। इंडियन एयरलाइंस के संबंध में कुल 361 उड़ानों में विलंब हुआ और 6 रद्द हुई, इसके अलावा जेट एयरवेज के मामले में 1076, सहारा एयरलाइंस के मामले में 438 और एयर इंडिया के बारे में 608 उड़ानों के विलंब होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। स्थिति से निपटने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक आपातकालीन योजना तैयार की थी। एस्मा (अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम) के अंतर्गत दिल्ली क्षेत्र की राष्ट्रीय राजधानी सरकार ने 15.2.99 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें विमान यातायात सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में घोषित किया गया था। केन्द्र सरकार के कतिपय अधिकारियों को नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन संबंधी शक्ति प्रदत्त करने हेतु एक अधिसूचना भी जारी की गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने दिनांक 19.2.99 को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि उड़ान समयावलियों में कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों के छह आरोपियों को मुअत्तिल करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की है।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने जून, 1997 में नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्री पी॰के॰ ब्रह्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य निजी घरेलू विमान कंपनी उद्योग में रुग्णता संबंधी कारणों की जांच पड़ताल करना और इस संबंध में सिफारिश करना है। समिति ने उन सभी कारकों की गहराई से जांच-पड़ताल की जो विमानन उद्योग में रुग्णता के लिए जिम्मेदार रहे हैं और यह समिति निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची है :-

(1) वित्तीय प्रबंधन।

(2) विमानन अनुभव तथा व्यावसायिकता का अभाव।

(3) विमानों के अनुरक्षण तथा मरम्मत संबंधी आधारिक संरचना सुविधाओं का अभाव।

(4) प्रशिक्षित मानव संसाधनों विशेषकर विमानचालकों और इंजीनियरों की कमी।

(5) संवृद्धि को उद्दीपित करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं की अनुपलब्धता।

समिति ने एयरलाइन उद्योग में प्रवेश, संवृद्धि तथा क्रमिक विकास को समाविष्ट करते हुए अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

*353. **श्री तथागत सत्पथी :**

डा॰ सुशील इंदौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान जोन/राज्यवार किन-किन रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) इस कार्य पर प्रत्येक वर्ष जोनवार/राज्यवार कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) क्या इन रेल मार्गों पर रेलगाड़ियों को चलाने के लिए अपेक्षित बिजली की मात्रा का अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्रोतों से अपेक्षित बिजली प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) चालू विद्युत परियोजनाओं और उनकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है उनका जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) वर्ष 1996-97, 1997-1998 और 1998-1999 के दौरान विद्युतीकृत की गई रेलवे लाइनों का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

जोन/खंड	मार्ग कि॰मी॰	राज्य
1	2	3
वर्ष 1996-97		
पूर्व रेलवे		
टोरी-पतरातू-दनिया	119	बिहार
जमतारा-मधुपुर-जसीडीह बैद्यनाथधाम	77	बिहार
उत्तर रेलवे		
मंडीगोविंदगढ़-लुधियाना	56	पंजाब
अंबाला-जगाधरी कारखाना	43	हरियाणा
दक्षिण रेलवे		
वालायर-शोरूवण्णूर वतल्लाट्टोलनगर	85	केरल
दक्षिण पूर्व रेलवे		
करकेंद-जामादोबा	08	
बोंडामुण्डा-चांदीपोस	28	उड़ीसा
चांडिल-तिरूलदीह	33	बिहार
बरकाकाना-रामगढ़ हाल्ट	04	बिहार
दक्षिण मध्य रेलवे		
भीमाडोलू-राजमुन्द्री	71	आंध्र प्रदेश
सामलकोट-अनकापल्ली	118	आंध्र प्रदेश
जोड़	642	
वर्ष 1997-98		
पूर्व रेलवे		
दनिया-गुमिया-जारंगडीह	29	बिहार
जसीडीह-नरगुंजू	36	बिहार
झाझा-क्यूल	56	बिहार
निश्चिंतपुर-काशीपुर	09	पश्चिम बंगाल
दक्षिण पूर्व रेलवे		
दुव्वाड़ा-वडलापुडि	04	आंध्र प्रदेश
बोकारो स्टील सिटी राधागांव	04	बिहार
चांदीपोश-बिमलगढ़-बरसुआन	37	उड़ीसा
बिमलगढ़-रंगरा	21	उड़ीसा
तिरूलडीह-रामगढ़	89	बिहार
आद्रा-बांकुड़ा-भेदवासोल	60	पश्चिम बंगाल
सिम्हाचलम-कोट्वलासा-अलमंडा	39	आंध्र प्रदेश
दक्षिण रेलवे		
वतल्लाटोलनगर-पुंकून्नम	21	केरल
सेलम-सेलम मार्केट	04	तमिलनाडु
उत्तर रेलवे		
जगाधरी कारखाना-सहारनपुर	36	हरियाणा/ उत्तर प्रदेश
जोड़	445	
वर्ष 1998-99		
पूर्व रेलवे		
नारगुंजू-झाझा	8	बिहार
मोकामा-फतुहा	68	बिहार
मुगलसराय-कुचामन	7	उत्तर प्रदेश
जेरंगडीह-फूरसो	9	बिहार

1	2	3
दक्षिण पूर्व रेलवे		
अलमंडा-चिपुरूपल्ली-श्रीकाकुलम रोड	82	आंध्र प्रदेश
पालसा-तिलारू	48	आंध्र प्रदेश
सिम्हाचलम यार्ड	8	आंध्र प्रदेश
राधागांव-मूरी-किटा	64	पश्चिम बंगाल/बिहार
पुरूलिया-कोटशिला	36	पश्चिम बंगाल
रंगरा-किरिबुरू	20	उड़ीसा/बिहार
बोडामुंडा यार्ड	08	उड़ीसा
भेदुवासोल-चंद्रकोना रोड-सालबोरी	65	पश्चिम बंगाल
तालचेर-मेरामंडोल	16	उड़ीसा
हिजली-बखराबाद	24	पश्चिम बंगाल
भद्रक-केंदुआपदा	16	उड़ीसा
उत्तर रेलवे		
अंबाला-चंडीगढ़	42	पंजाब/हरियाणा
सरहिंद-मोरिंडा	24	पंजाब
सहारनपुर स्टेशन	2	उत्तर प्रदेश
कानपुर-पुल-उन्नाव	14	उत्तर प्रदेश
दक्षिण रेलवे		
पुकुन्नम-चोवरा	56	केरल
जोड़	617	

(ख) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विद्युतीकरण परियोजनाओं पर परियोजनावार किया गया खर्च इस प्रकार है :-

व्यय (करोड़ रुपए में)

जोन रेलवे	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
पूर्व	75.25	76.00	65.00
दक्षिण पूर्व	67.47	145.00	176.00
दक्षिण मध्य	66.02	8.00	-
दक्षिण	30.65	30.00	20.00
उत्तर	31.49	49.00	52.00
मध्य	10.94	5.00	-
पश्चिम	-	7.00	21.00
जोड़	281.82	320	334

(ग) जी हां।

(घ) विद्युतीकरण परियोजना के लिए, लगभग प्रत्येक 60 कि॰मी॰ के अंतर पर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सप्लाई स्थल (कर्षण सब स्टेशन) पर अपेक्षित बिजली की मात्रा अलग-अलग होती है, जो उस खंड पर चल रही गाड़ियों की संख्या पर निर्भर करती है। यह 5 मेगा वाट से 15 मेगावाट के बीच होती है। इन योजनाओं के लिए बिजली की सप्लाई विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त की गई जिनके क्षेत्राधिकार में कर्षण सब-स्टेशन स्थित हैं।

(ङ) चल रही रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	खंड	अनुमानित लागत	लक्ष्य
1	2	3	4
1.	सीतारामपुर-मुगलसराय	330.75	मार्च, 2000
2.	पुरूलिया-कोटशिला सहित बोकारो-बरसुआन	214.54	मार्च, 2001
3.	ईरोड-एर्णाकुलम	222.312	मार्च, 2000
4.	अंबाला-मुरादाबाद	152.21	10वीं योजना
5.	दिल्ली-लुधियाना, अंबाला-कालका और सरहिंद-नंगलडैम सहित	290.79	मार्च, 2001
6.	आग्रा-मिदनापुर	84.40	मार्च, 2000
7.	कानपुर-लखनऊ	47.87	मार्च, 2000
8.	खड़गपुर-भुवनेश्वर	310.19	10वीं योजना
9.	भुवनेश्वर-कोट्वलसा	292.87	10वीं योजना

1	2	3	4
10.	उधना-जलगांव	138.12	10वीं योजना
11.	कुसुंडा-जमुनियाटांड	16.42	मार्च, 2001
12.	लुधियाना-अमृतसर	97.79	10वीं योजना
13.	रेणिगुंटा-होसपेट	177.00	10वीं योजना
14.	खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर	89.21	कार्य लंबित
15.	एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम	157.68	10वीं योजना
16.	मुगलसराय-जाफराबाद (सुल्तानपुर के रास्ते मुगलसराय लखनऊ का चरण-1)	40.80	10वीं योजना
17.	पटना गया	36.80	10वीं योजना
18.	तांम्बरम-चेंगलपट्टू-विषुपुरम और चेंगलपट्टू-अरकोणम	35.06	10वीं योजना

(च) नौवीं योजना के शेष तीन वर्षों अर्थात 1990-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान जिन खंड़ों के विद्युतीकरण की योजना बनाई गई वे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	खंड	जोन/रेलवे	राज्य
1	2	3	4
1.	क्यूल-मोकामा	पूर्व रेलवे	बिहार
2.	फतुहा-आरा-कुछमन	पूर्व रेलवे	बिहार/उत्तर प्रदेश
3.	कुसुंडा-जमुनियाटांड	पूर्व रेलवे	बिहार
4.	पटना-तरेगना	पूर्व रेलवे	बिहार
5.	कीता-बोंडामुंडा	दक्षिण पूर्व रेलवे	बिहार/उड़ीसा
6.	भकराबाद-भुवनेश्वर	दक्षिण पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा
7.	मेरामंडल-कटक	दक्षिण पूर्व रेलवे	उड़ीसा
8.	पलासा-इच्छापुरम	दक्षिण पूर्व रेलवे	आंध्र प्रदेश
9.	सलबोनी-मिदनापुर	दक्षिण पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल
10.	रेणिगुंटा-ओबूलावरिपल्ली	दक्षिण मध्य रेलवे	आंध्र प्रदेश
11.	चोवरा-एर्णाकुलम	दक्षिण रेलवे	केरल
12.	एर्णाकुलम-कलावूर	दक्षिण रेलवे	केरल
13.	एर्णाकुलम-एट्टामानूर	दक्षिण रेलवे	केरल
14.	ताम्बरम-चेंगलपट्टू	दक्षिण रेलवे	तमिलनाडु
15.	चेंगलपट्टू-अरकोणम	दक्षिण रेलवे	तमिलनाडु
16.	मुगलसराय-वाराणसी	उत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश
17.	कानपुर-कानपुर पुल	उत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश
18.	उन्नाव-लखनऊ	उत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश
19.	चंडीगढ-कालका	उत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश
20.	मोरिंडा-नंगलडैम	उत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश
21.	सहारनपुर-रुड़की	उत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश
22.	लुधियाना-जालंधर	उत्तर रेलवे	पंजाब
23.	जलगांव-डोडयेचे	पश्चिम रेलवे	महाराष्ट्र
24.	उधना-नवापुर	पश्चिम रेलवे	गुजरात/ महाराष्ट्र

(छ) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान उपर्युक्त विद्युतीकरण कार्य पर 1146 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है।

इंडियन एयरलाइंस के पुराने विमानों को हटाना

*354. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**

श्री नरेश पुगलीया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में अधिकतर ए-300 और बोइंग विमान लगभग 20 वर्ष पुराने हैं और उन्हें अब हटाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस के बेड़े का नवीकरण करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब तक शुरू किया जाएगा और इस पर लगभग कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ए300 और बी737 बेड़े को बदलने के लिए उपयुक्त विमानों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए इंडियन एयरलाइंस ने एक समिति का गठन किया है। बेड़े के आधुनिकीकरण

कार्यक्रम को शुरू करने और पूर्व वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए इंडियन एयरलाइंस को समर्थ बनाने हेतु डा॰ विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने इंडियन एयरलाइंस के वित्तीय पुनर्संरचना की सिफारिश की। केलकर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा आवश्यकता से अधिक खरीददारी

***355. श्री के॰पी॰ मोहन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के पास 400 करोड़ रुपए मूल्य का सामान है तथा इसमें से अधिकांशत: आवश्यकता से ज्यादा कल-पुर्जे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा आवश्यकता से अधिक खरीद किए जाने की जांच कराये जाने के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइंस के पास 485.58 करोड़ रुपए मूल्य का कल-पुर्जों का सामान है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

विमान	राशि (करोड़ रुपए में)
ए-300	106.72
ए-320	246.97
बी-737	84.15
टर्बो प्रोप	15.87
अन्य इंजीनियरिंग स्टोर	31.87
जोड़	485.58

पूरे मामले की जांच चल रही है।

रेलवे भूमि पर भाण्डागारों का निर्माण

***356. श्री ए॰ वेंकटेश नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे भूमि पर टर्मिनलों और भाण्डागारों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे माल के सुविधाजनक परिवहन हेतु किस सीमा तक मदद मिलेगी;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम का बंगलौर में रेलवे भूमि पर भाण्डागार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। बहरहाल, निजी साइडिंगों का निर्माण उनके अपने कार्गो की सम्हलाई के लिए किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) जी हां। हाल ही में सिद्धांत रूप में यह विनिश्चय किया गया है कि सेंट्रल वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन को व्हाइटफील्ड, बेंगलूरू में पट्टा शर्तों पर एक पायलट परियोजना के रूप में मालगोदाम स्थापित करने की अनुमति दे दी जाए।

रेलगाड़ियों में रसोईयान

***357. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में रसोईयानों को चलाने के लिए लाइसेंस धारकों का चयन निविदाएं जारी करके किया गया था;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने प्रत्येक रसोईयान से कितना धन/राजस्व अर्जित किया;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटित इन रसोईयानों को चलाने के लिए दिल्ली और चेन्नई से एक बड़ा घोटाला चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन धोखेबाजीपूर्ण कार्यकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। रसोईयानों के प्रबंधन के लिए लाइसेंस अब तक प्रेस अधिसूचनाओं के जरिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी खानपान प्रबंधकों को दिए जाते थे, जिनका चयन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकारियों की एक समिति द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाता था।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि रसोईयान लाइसेंस प्रदान करते समय दो पैकेट निविदा शुरू की जाए। पैकेट 'ए' तकनीकी अपेक्षाओं यथा समग्र बिक्री, कंपनी की वित्तीय मजबूती, खानपान में अनुभव आदि का मूल्यांकन करेगा जबकि पैकेट 'बी' में लाइसेंस शुल्क के अनुसार वित्तीय बोली लगाई जाएगी। इस संशोधित प्रक्रिया से रेलों के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

(ख) वर्तमान नीति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर रसोईयान लाइसेंसधारियों से अनुमानित समग्र बिक्री के 2 से 5 प्रतिशत तक की दर से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जा रहा था। 1998-99 के दौरान लाइसेंसधारियों से 4.10 करोड़ रुपए का लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर नये राडार

*358. **श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अधिकांश घरेलू हवाई अड्डों पर लगे प्राथमिक राडारों की रेंज 50 समुद्री मील से अधिक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में निगरानी के लिए अधिक रेंज वाले (सैकण्ड्री) निगरानी राडार खरीदने का कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) इस समय केवल हैदराबाद, अहमदाबाद और गुवाहाटी स्थित तीन घरेलू हवाई अड्डों पर प्राथमिक राडार लगे हुए हैं जिनकी रेंज लगभग 60 नाटिकल मील (एनएम) है।

(ख) और (ग) जी, हां। पूरे देश में प्रमुख हवाई मार्गों में राडारों की व्यवस्था करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बेहरामपुर, नागपुर, वाराणसी और मंगलौर विमानपत्तनों पर 73.06 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2000 ई॰ तक सैकण्ड्री निगरानी राडारों को लगाने का निर्णय लिया है। चेन्नई, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहटी, मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली विमानपत्तनों पर सैकण्ड्री निगरानी राडारों को पहले से ही लगाया जा चुका है।

धनराशि जुटाया जाना

*359. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम ने भारतीय रेल के पट्टा किराये से प्राप्त नकदी प्राप्ति को प्रतिभूति में लगाने के संबंध में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास हेतु और अधिक धनराशि जुटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेल वित्त निगम इस मंत्रालय द्वारा अपने योजना परिव्यय के लिए बजटीय संसाधन बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार कर मुक्त और कर योग्य बंध-पत्र जारी करके, दीर्घकालिक ऋणों और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों जैसे विभिन्न माध्यमों से बाज़ार से धन जुटाती है जो बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस धन का उपयोग रेलवे के चल स्टॉक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में "आयकर अधिनियम के अंतर्गत अवसंरचना" की परिभाषा में शामिल नहीं है।

"एक्सप्लोर इंडिया-मिलेनियम ईयर"

*360. **श्री एन॰आर॰के॰ रेड्डी :**

श्री ए॰सी॰ जोस :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1999 के शुरू होने वाले "एक्सप्लोर इंडिया-मिलेनियम ईयर" के दौरान और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारत किया गया है तथा कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : पर्यटन मंत्रालय ने "एक्सप्लोर इंडिया मिलेनियम ईयर" के लिए कोई विशेष लक्ष्य तथा अलग बजट नहीं रखा है। तथापि, मंत्रालय ने वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान 110.00 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1999-2000 के लिए 160.50 करोड़ रुपए का योजनागत बजट आबंटित किया है।

[हिन्दी]

बिहार में होटलों का विकास

3491. **श्री राजो सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जाने वाले होटलों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर तथा जारी की गई है; और

(ख) उन होटलों के नाम क्या हैं जिनका चयन उक्त प्रयोजन हेतु किया गया?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित राशि स्वीकृत/रिलीज की है :-

(रु॰ लाखों में)

वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1996-97			
	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बी एस टी डी एस) के लिए		शून्य
1997-98			
1.	डिंघी टेंक, दरभंगा, बिहार में पर्यटक सुविधाओं का विकास	20.00	6.00
2.	भागलपुर, बिहार में पर्यटक परिसर	35.00	11.00
3.	विक्रमशिला में कैफेटेरिया	15.00	5.00
4.	वैशाली में पर्यटक परिसर	45.00	14.00
5.	बख्तियारपुर, बिहार में मार्गस्थ सुविधाएं	25.00	7.50
6.	गंगाघाट पर पर्यटक सुविधाएं	16.00	4.80
7.	रक्सौल में पर्यटक परिसर	45.00	13.50
1998-99			
1.	मुंगेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	15.00	5.00
2.	भागलपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	15.00	4.50
3.	होटल बिर्सा बिहार, रांची, बिहार का नवीकरण	20.00	6.00
4.	होटल रत्न बिहार, धनबाद, बिहार का नवीकरण	25.00	7.50
5.	सिंघेश्वर अस्थान, जिला माधेपुर में यात्रिका	19.39	6.00
6.	औरंगाबाद में पर्यटक परिसर	25.00	7.50

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस

3492. श्री सोडे रमैया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में तड़ेपल्लीगुडम हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुद्दे पर याचिकाकर्ता के नाम सहित केन्द्र सरकार को प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या याचिकाकर्ता से पहले भी इसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन की फिर से जांच करने और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्वक हल करने के बार में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) डॉ॰ पी॰ पुल्ला राव, पश्चिमी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश मे अभ्यावेदन के संबंध में सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ ही मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को संबोधित एक नोटिस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माध्यम से प्राप्त डॉ॰ पी॰ पुल्ला राव की याचिका में और उनसे सीधे ही प्राप्त हुए अभ्यावेदनों में भी, तड़ेपल्लीगुडम हवाई अड्डे की रक्षा भूमि पर रह रहे लगभग 20,000 अधिवासियों/विस्थापित लोगों के मामले की पैरवी की गई है। याचिका में यह कहा गया है कि ये लोग इस भूमि पर पिछले 50 वर्षों से बिना कानूनी अधिकारों के रह रहे हैं और वे अपने अधिकारों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं। याचिकादाता ने अपने अभ्यावेदन में संबंधित अधिकारी द्वारा इस स्थान का दौरा किए जाने का अनुरोध भी किया है।

(घ) इस मामले के तथ्यों के संबंध में सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा है। चूंकि उपर्युक्त भूमि 3.8.1987 को आंध्र प्रदेश सरकार को सौंप दी गई थी और इस भूमि की अभिरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है अतः यह मामला राज्य सरकार के साथ भी उठाया गया है।

अलाभकारी रेल लाइनें

3493. श्री के॰ कृष्णमूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभकारी रेल लाइनों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु जोन-वार किन खंडों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों के सहयोग से नई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) जी हां।

(घ) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी-II) के अंतर्गत रेल क्षेत्र की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मुंबई रेलवे विकास निगम (एम आर वी सी) की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, यह भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच इक्विटी भागीदारी के आधार पर 51:49 के अनुपात में होगा।

हिमाचल प्रदेश की बनीखेत हवाई अड्डा परियोजना

3494. श्री सुरेश वरपुड़कर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बनीखेत हवाई अड्डा परियोजना के वित्त पोषण से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता ने बनीखेत पर विमानपत्तन के विकास के विरुद्ध सलाह दी है जिसका मुख्य कारण निर्माण की उच्च लागत परिस्थितिकी को गंभीर क्षति, लगभग 5000 वृक्षों की कटाई की जरूरत, लगभग 80 परिवारों को हटाना, एक फील्ड फायरिंग रेंज का स्थानान्तरण और 181 बीघा वन-प्रदेश का अर्जन था इसके अलावा सरकार द्वारा अनुमोदित विमानपत्तन आधारिक संरचना संबंधी नीति के मुताबिक मौजूदा विमानपत्तन के 150 किलोमीटर के भीतर किसी अन्य विमानपत्तन का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू और गुग्गल में मौजूदा विमानपत्तन इस सीमा के भीतर हैं। इसलिए बनीखेत विमानपत्तन का प्रस्ताव इस नीति का उल्लंघन होगा।

श्रम संबंधी स्थायी समिति की 35वीं बैठक

3495. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री सुनील खां :
श्री विकास चौधरी :
श्री बासुदेव आचार्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम संबंधी स्थायी समिति की 35वीं बैठक के लिए सरकार द्वारा किन-किन अतिरिक्त संगठनों को आमंत्रित किया गया है,

(ख) क्या लघु उद्योग के अतिरिक्त प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस उद्देश्य के लिए भारतीय लघु उद्योग परिषद से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संगठन को आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यानारायण जटिया) : (क) से (घ) स्थायी श्रम समिति के 35 वें सत्र में भाग लेने के लिए फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ऐसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (ऐसोचैम) और लघु उद्योग भारती (एल यू बी) को भी निमंत्रित किया गया था। भारतीय लघु उद्योग परिषद के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में "पर्यवेक्षक" के रूप में भाग लिया था।

टोंक को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाना

3496. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान टोंक को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टोंक को रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी नवीनतम स्थिति क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण अभी प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(घ) रिपोर्ट के इस वर्ष के अंत में आने की आशा है।

पूर्वोत्तर रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि

3497. श्री रामविलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान पूर्वोत्तर रेल की रेल परियोजनाओं के लिये परियोजनावार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर आज तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 1998-99 के दौरान रेल परियोजनाओं के लिए कुल निर्धारित राशि तथा 31.3.1999 तक उन पर किए गए वास्तविक खर्च का परियोजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परिव्यय 1998-99	31.3.1999* तक खर्च
1	2	3	4
	नई लाइनें		
1.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	2.00	2.01
2.	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	1.00	1.5
3.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम-राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपर सड़क पुल	5.00	5.03
4.	कटरा-फैजाबाद	10.00	17.6
5.	सकरी-हसनपुर	2.00	14.0
	पुनर्स्थापन		
6.	बगहा-छितौनी	0.0370	93.41
7.	महाराजगंज-दुर्रौंधा	0.3430	0.34
	आमान परिवर्तन		
8.	हाजीपुर-बचवाडा	4.01	67.39
9.	मऊ-शाहगंज	1.00	56.01
10.	खड्डा-गोरखपुर	44.30	60.47
11.	नरकटियागंज-वाल्मिकी नगर	25.00	42.93
12.	छपरा-औंड़िहार	4.00	165.57
13.	कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली	35.65	39.65
14.	समस्तीपुर-खगडिया	0.0010	0.001
15.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	0.0010	0.001
16.	काशीपुर-लालकुआं	3.00	5.86
17.	सगौली-नरकटियागंज	11.80	48.59
18.	मथुरा-अचनेरा	0.01	0.1
19.	मानसी-सहरसा-फोरबिसगंज (चरण-1)	5.00	19.5
20.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ (चरण-1)	0.001	0.001
21.	आनंदनगर-नौतनवां सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	0.001	0.001
22.	इंदारा-फेफना	5.00	6.25
	दोहरीकरण		
23.	गोरखपुर-सहजनवां	1.11	1.11
24.	गोंडा-जरवल रोड	4.00	7.02

* यह मुहैया कराए गए परिव्यय पर आधारित है। 1998-99 तक वास्तविक खर्च का पता वर्ष 1998-99 के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चलेगा जिसके जून 1999 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

दिल्ली-भावनगर सेक्टर में सीधी उड़ान

3498. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से भावनगर के लिए कोई नई विमान सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं संबंधी अपेक्षा को मद्देनजर रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं की बेहतर विनियमन प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं, तथापि यह विमान कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे सरकार द्वारा जारी मार्ग सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं मुहैया करें।

इस समय इंडियन एयरलाइन्स मुंबई/भावनगर/मुंबई मार्ग पर सप्ताह में चार बार ए-320 सेवा का प्रचालन करती है, जिससे मुंबई से होकर दिल्ली और भावनगर के बीच दोनों दिशाओं में सुविधाजनक संपर्क स्थापित होता है।

बी॰डी॰आर॰ रेल लाइन का विस्तार

3499. **श्री सुनील खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी॰डी॰आर॰ रेल लाइन का विस्तार बर्दवान से हावड़ा तक का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने और पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) रायनगर के रास्ते वर्तमान से तारकेश्वर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। जब कभी यह लाइन तैयार होगी, पूर्व बी॰डी॰आर॰ लाइन का बर्द्धमान और हवड़ा के साथ वांछित सम्पर्क जुड़ जाएगा। बहरहाल, इस प्रस्तावित सम्पर्क पर आगे विचार करना चल रहे सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर ही संभव होगा।

दिल्ली-कुल्लू-शिमला उड़ान को चण्डीगढ़ तक बढ़ाना

3500. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली-कुल्लू-शिमला जैसी कुछ उड़ानों को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चण्डीगढ़ को किसी अन्य शहर से विमान-सेवा द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर प्रचालक किसी स्थान तक/किसी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। चंडीगढ़ से/तक कोई भी निजी अनुसूचित प्रचालक किसी उड़ान का प्रचालन नहीं कर रहा है। विमान क्षमता की उपलब्धता तथा प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए इंडियन एयरलाइंस चंडीगढ़ को कुल्लू/शिमला से विमान-संपर्क द्वारा जोड़ने पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

सम्पादकों/कैमरामैनों को मान्यता देने हेतु प्रक्रिया

3501. **श्री एच॰पी॰ सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं तथा समाचार और फोटो एजेंसियों के सम्पादकों/कैमरामैनों को मान्यता देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मान्यता देने में कितना समय लिया जाता है;

(ख) क्या बेरोजगार पत्रकारों को मान्यता देने के लिए कोई प्रक्रिया भी अपनाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संस्था द्वारा विज्ञापन एजेंसियों और समाचार एजेंसियों को किस आधार पर विज्ञापन दिए जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रत्यायन नियमों के अनुसार एक पाक्षिक या कम की आवधिकता रखने वाली समाचार एजेन्सियों, समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों/संवाददाताओं/कैमरामैनों को प्रत्यायन दिया जाता है। प्रत्यायन प्रदान करने में लगने वाला समय आवेदन के साथ पूर्व सूचना तथा कागजातों को जमा करने पुलिस से सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति और केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति की बैठक आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यता प्रत्यायन देने में आवेदन प्राप्ति की तारीख से लगभग 2-3 महीने का समय लग जाता है।

(ख) और (ग) बेरोजगार पत्रकारों को प्रत्यायन देने के लिए प्रत्यायन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी॰ए॰वी॰पी॰) लक्ष्य क्षेत्र, पाठकगण और बजटीय प्रावधानों आदि पर विचार करने के बाद अपने पास सूचीबद्ध समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन एजेन्सियों/समाचार एजेन्सियों को विज्ञापन जारी नहीं करता है।

[अनुवाद]

नेदुम्बस्सेरी (केरल) में हवाई अड्डा

3502. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केरल के नेदुम्बस्सेरी में हवाई अड्डे के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नये विमानपत्तन के मास्टर प्लान तैयार करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर 22 लाख रुपए व्यय किये हैं। प्राधिकरण ने नये विमानपत्तन पर

संस्थापन के लिए 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर संचार और दिक्चालन उपस्कर खरीदे हैं।

(ख) नदुम्बसेरी विमानपत्तन पर कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति नीचे बताई गई है :-

(1) **धावनपथ और सहायता पेवमेंट :**

धावनपथ, टैक्सीपथ, एप्रन का सारा कार्य लगभग पूरा हो गया है। भू-प्रकाशन प्रणाली का कार्य भी पूरा होने वाला है और इसके 25 अप्रैल, 1999 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) **टर्मिनल भवन :**

अंतर्देशीय टर्मिनल में सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है और इसके अप्रैल, 1999 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

(3) **कार पार्क :**

पार्किंग क्षेत्र से संबंधित कार्य पूरा हो गया है।

(4) **तकनीकी ब्लॉक व नियंत्रण टावर और अन्य उपयोगी भवन :**

सिविल और विद्युत कार्यों सहित तकनीकी ब्लॉक व नियंत्रण टावर और अन्य उपयोगी भवन के निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपस्करों और संचार सुविधाओं का संस्थापन कार्य प्रगति पर है और इसके 15 अप्रैल, 1999 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(5) **दिक्चालनात्मक सुविधाएं :**

दिक्चालनात्मक उपस्करों के रखे जाने के लिए सभी भवन के निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपस्करों की संस्थापन का कार्य प्रगति पर है।

विमानपत्तन के मई, 1999 के अंतिम सप्ताह में चालू हो जाने की संभावना है।

नागर विमानन में किराया प्रतिस्पर्धा

3503. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कार्य कर रही अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने 1994 से चल रही किराया प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने हेतु मुंबई में एक बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचार-विमार्श के दौरान, विमान कंपनियों ने किराया प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के विषय में अपनी-अपनी इच्छुकता दर्शाई थी लेकिन वास्तविक व्यवहार में विभिन्न कारकों विशेषकर अपर्याप्त यातायात की वजह से, वे विभिन्न किस्मों में प्रोत्साहन देकर किया संबंधी प्रतिस्पर्धाओं का सहारा लेते रहे हैं। राजस्व में सुधार लाने के विषय में सहमत स्तरों पर प्रोत्साहनों के कार्यान्वयन के प्रति सहमति जताने की दिशा में प्रमुख विमान कंपनियों को राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में पर्यटन विकास हेतु धनराशि

3504. श्री अर्जुन सेठी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए मंजूर की गई प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या संबंधित राज्य ने इस बीच आबंटित धनराधि का उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य में मंजूर की गई धनराशि में से कितनी धनराशि अनप्रयुक्त पड़ी है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों तथा धन की उपलब्धता के आधार पर पर्यटन अवसरंचना विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पर्यटन मंत्रलय, भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान 23 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 453.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है। वर्ष 1997-98 के दौरान 28 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 557 लाख रुपए तथा वर्ष 1998-99 के दौरान 5 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 210 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

(ख) और (ग) स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में दिया जाता है। बाद की किश्तें परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत राशि उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है। परियोजना को स्वीकृत होने के 30 माह की अवधि के अन्दर पूरा करना होता है।

[हिन्दी]

मोहन सराय और मुगल सराय के बीच बाई-पास का निर्माण

3505. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन वाराणसी (उ॰प्र॰) में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहन सराय से मुगल सराय तक बाई-पास का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के फरवरी-मार्च, 1999 की लक्षित तारीख तक पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) धनराशि नियमित और पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होने, सितंबर, 1995, अगस्त, 1996 और 1998 में अभूतपूर्व एवं लगातार वर्षा होने, नवंबर/दिसंबर, 97 और अक्तूबर, 98 के दौरान मौसम खराब रहने और सीमा सड़क संगठन को रेलवे ओवरब्रिज मार्ग सौंपे जाने के कारण निर्माण-कार्य की प्रगति में बाधा आई।

(ग) इस निर्माण-कार्य को 31 मई, 1999 तक पूरा किए जाने की योजना है

[अनुवाद]

तिरूअनंतपुरम के दूरदर्शन केन्द्र में बिजली की कटौती

3506. **श्री पी॰ शंकरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनंतपुरम के दूरदर्शन केन्द्र को बहुधा बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र को बिजली की लगातार पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार डीडी-4 पर रात को नित्य दिखायी जाने वाली फिल्म के पश्चात् प्रसारण के अंत में मुख्य समाचार बुलेटिन शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र तिरूअनन्तपुरम में विद्युत आपूर्ति दो स्वतंत्र फीडर लाइनों के जरिए उपलब्ध करायी जाती है और विद्युत की आपूर्ति के स्रोत को मुख्य लाइन से डीजल जनरेटर एवं विलोमतः बदलने के कारण सेवा में हर बार दो मिनट का व्यवधान आता है। विद्युत आपूर्ति फेल होने के कारण सेवा में कुल रुकावट सम्पूर्ण प्रसारण अवधि का आधा प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इसका कारण संसाधनों, जनशक्ति एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी है।

आकाशवाणी, दूरदर्शन के कर्मचारियों को प्रसार भारती निगम में स्थानांतरित किया जाना

3507. **डा॰ सुगुण कुमार चलामेला :**

श्री गुरूदास कामत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में ट्रांस्फर आफ ए॰आई॰आर॰, डी॰डी॰ स्टाफ टू प्रसार—प्रोपोजल्स पैडिंग बिफोर मिनिस्ट्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।

चीन द्वारा धमकी दिए जाने से इंकार

3508. **इंजीनियर शंकर पन्नू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1999 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "चाईना डिनाईज पोजिंग थ्रेट टू इंडिया कालस फार डायलॉग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही, यदि कोई हो तो, की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार को दिनांक 22.03.1999 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "चाइना डिनाई

पोजिंग थ्रेट टु इंडिया कालस फार डायलॉग" शीर्षक से छपे समाचार की जानकारी है।

सरकार चीन के साथ पंचशील के आधार पर मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, अच्छे पड़ोसी तथा परस्पर लाभकारी संबंध बनाने की इच्छुक है। भारत दोनों देशों के बीच मतभेदों के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार व आर्थिक कार्यकलाप, लोगों के बीच आपसी तथा कार्यात्मक आदान-प्रदान जारी है।

दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित सहयोग संबंधी प्रोटोकॉल के तहत 25 व 26 फरवरी, 1999 को भारत और चीन के विदेश कार्यालयों के बीच पहली बार विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे सकारात्मक व अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाएंगे तथा वे इस बात पर भी सहमत थे कि विभिन्न स्तरों पर वार्ता जारी रखी जाएगी।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

3509. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार विकलांग व्यक्ति हैं;

(ग) उन्होंने कब से रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं; और

(घ) वर्ष 1998 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया?

श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) वर्ष 1993, 1994, 1995 तथा 1996 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले विकलांगों की संख्या (नवीनतम उपलब्ध), यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, निम्नलिखित है:

(हजार में)

	अखिल भारत (31 दिसम्बर के अनुसार)	दिल्ली	उत्तर प्रदेश
	1	2	3
1993	337.6	5.2	25.6
1994	340.3	5.6	25.2
1995	352.7	5.6	23.7
1996	359.1	5.9	24.0

(ग) चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की अवधि से संबंधित सूचना रखी नहीं गई है।

(घ) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 1996 के दौरान रोजगार में नियोजित विकलांगों की संख्या लगभग 3900 थी।

[अनुवाद]

रेल सेवा क्षेत्र का निजीकरण

3510. **श्री सी॰पी॰एम॰ गिरियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल से संबंधित अपने कुछ सेवा क्षेत्रों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मानदंड तथा शर्तें क्या हैं;

(ग) इस निजीकरण से किस सीमा तक रेल को लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या निजीकरण के निर्णय का कुछ कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या रेल विभाग द्वारा सेवा क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्यों का निजीकरण किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (छ) जी नहीं। बहरहाल, 1994 में आमंत्रित विश्वव्यापी बोलियों के आधार पर, निम्नलिखित खंडों पर पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन के मैसर्स स्टर्लिंग हॉलीडे रिसार्ट (इंडिया) लि॰, चेन्नई को मंशा पत्र जारी किया गया था।

(1) दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी (खजुराहो)-वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली।

) बेंगलूरू-मैसूर-चेन्नई-कोडायकैनाल रोड-कन्याकुमारी-तिरूवनंतपुरम-कोचीन-मेट्टूपलायम (ऊटी)- बेंगलूरू।

अनुबंध के अनुसार परिचालक ढुलाई प्रभार तथा समग्र बिक्री का कतिपय प्रतिशत का भुगतान भारतीय रेल को करेगा, गाड़ी पर पूंजी निवेश परिचालक द्वारा किया जाएगा।

कोचीन एफ॰एम॰ स्टेशन से प्रसारण

3511. **श्री जार्ज ईडन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित एफ॰एम॰ स्टेशन से सुबह के कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोचीन एफ॰एम॰ स्टेशन से सुबह का प्रसारण पुनः शुरू करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण, प्रातःकालीन प्रसारण 27.2.99 से रोक दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रातःकालीन प्रसारण की तुरन्त पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पनडुब्बी घोटाला

3512. **श्री मोती लाल वोरा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार ने पनडुब्बी घोटाले के बारे में केन्द्र सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्पष्टीकरण दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। एच डी डब्ल्यु पनडुब्बियों की खरीद के मामले में, सी॰बी॰आई॰ ने जनवरी, 1998 में जर्मन गणराज्य को अनुरोध पत्र भेजे थे। उनके प्रत्युत्तर में जर्मन प्राधिकारियों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(ख) और (ग) मांगे गए स्पष्टीकरणों की सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच की जा रही है और जर्मन प्राधिकारियों को समुचित उत्तर जल्दी ही भेज दिया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सुधार

3513. **श्री टी॰आर॰ बालू** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के संबंध में अध्ययन और सलाह देने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) उच्च अधिकार समिति गठित करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से संबंधित निम्नलिखित दो विकास परिषदों का गठन पहले ही किया जा चुका है :-

1. प्रसंस्कृत फल और सब्जी, अनाज उत्पाद तथा बेवरीज विकास परिषद्।
2. डेरी उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मांस तथा पाल्ट्री उत्पाद विकास परिषद्।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की "पैन" (पी॰ए॰एन॰) के लिए योजना

3514. **श्री आर॰एस॰ गवई** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सभी सदस्यों के लिए "पैन" (पी॰ए॰एन॰) आरम्भ करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी सूचनाओं का कंप्यूटरीकरण करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) क॰भ॰नि॰ केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ने अब कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को स्थायी क॰भ॰नि॰ संख्या के साथ फोटो परिचय-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू में दो ई डी पी केन्द्रों की स्थापना के साथ 1989-90 में क॰भ॰नि॰ सं॰ में शुरू किया गया था। अब तक, क॰भ॰नि॰ के 98 क्षेत्रीय कार्यालयों में ई डी पी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कंप्यूटरों का प्रयोग भविष्य निधि खातों के रख-रखाव, वार्षिक लेखा विवरणों को तैयार करने, नियोजकों से प्राप्त

धन की गणना करने, लोक शिकायतों का निपटान करने, पेंशन भुगतान आदेशों को तैयार करने आदि के लिए किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के अधिकारी

3515. **प्रो॰ जोगेन्द्र कवाड़े** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अधिकारियों को आरोप पत्र दिए गए और बर्खास्त/निलम्बित अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक उपाय कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) 133

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों की पदोन्नति, तैनाती आदि से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

(घ) फरवरी, 1996 से आठ अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति के अधिकारियों को आरोप पत्र तामील किए गए तथा तीन को निलंबित किया गया। तथापित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारी को अभी तक बरखास्त नहीं किया गया है। अपेक्षानुसार, समीक्षा करके एक अनुसूचित जाति के अधिकारी का निलंबन पहले ही रद्द कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्यालयों में भी संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। क॰रा॰बी॰ संगठन से यह भी अपेक्षित है कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों के बारे में निहित रिपोर्ट विवरणी सरकार को प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण

3516. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र जयपुर की स्थापना की तिथि क्या है;

(ख) इसके द्वारा कौन-कौन से सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है;

(ग) उक्त केन्द्र को और उपयोगी बनाने के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं क्या हैं; और

(घ) उक्त केन्द्र द्वारा किन-किन भाषाओं में समाचार प्रसारित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन केन्द्र जयपुर ने 24.6.1987 से काम करना प्रारम्भ किया था।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विभिन्न अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों की भांति दूरदर्शन केन्द्र जयपुर भी राज्य में दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सांस्कृतिक/रचनात्मक कार्यक्रमों सहित विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। युवाओं तथा बच्चों के लिए अन्ताक्षरी, गा मेरे संग गा, प्रश्नोत्तरी, मिम्शार, सृजन तथा अन्य कार्यक्रम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनमें रचनात्मक/सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं।

(ग) प्रसार भारती ने यह सूचित किया है कि इस केन्द्र से गीत तरंगिणी, कला और कलाकार मार्ग दर्शन, आइना आदि जैसे कई नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस केन्द्र से प्रसारण करने के लिए राजस्थान के विभिन्न शहरों में मुशायरों, लोक संगीत तथा नृत्य कार्यक्रमों की ओ॰बी॰ कवरेज रूपरेखा बनायी जा रही है।

(घ) यह केन्द्र हिंदी में समाचार प्रसारित कर रहा है। किसी दूसरी भाषा में समाचार प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह केन्द्र हिंदी क्षेत्र में स्थित है।

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

3517. **श्री सोहनवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए राज्यवार कितने निवेदन प्राप्त किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क उपरि पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सड़क उपरि पुलों का कब तक निर्माण किये जाने की संभावना है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति न देने तथा उनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क)

राज्य रेलवे	कुल
1	2
असम	1
आंध्र प्रदेश	42
बिहार	10
दिल्ली	2
गुजरात	6
गोवा	4
हरियाणा	4
केरल	20
कर्नाटक	7
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	45
उड़ीसा	22
पंजाब	12
राजस्थान	10
तमिलनाडु	58
उत्तर प्रदेश	27
पश्चिम बंगाल	11
जोड़	295

(ख)

क्र.सं.	राज्य	कार्य का नाम	रेलवे
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	बेलगाम में समपार संख्या 3[illegible] के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे.
2.	आंध्र प्रदेश	महबूबाबाद में समपार संख्या 82 के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे
3.	आंध्र प्रदेश	खम्माम में समपार संख्या 104 के बदले ऊपर सड़क पुल	द.म.रे.
4.	आंध्र प्रदेश	कुप्पम के निकट 251/13-14 कि.मी. में समपार संख्या 101 के बदले ऊपरी/निचली सड़क पुल	द.रे.
5.	आंध्र प्रदेश	विथापुरम में समपार संख्या 429 के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे.
6.	आंध्र प्रदेश	बायावाराम में समपार संख्या 480 के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे.
7.	आंध्र प्रदेश	पालासा-मनदास के बीच ऊपर सड़क पुल	द.पू.रे.
8.	आंध्र प्रदेश	श्यामाचीली में समपार संख्या 475 के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे.
9.	आंध्र प्रदेश	सीताफलमंडी में समपार संख्या 1 के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे.
10.	आंध्र प्रदेश	मनदासा-बोरूवा के बीच ऊपरी सड़क पुल	द.पू.रे.
11.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर में समपार संख्या 250 के बदले ऊपरी सड़क पुल	द.म.रे.

1	2	3	4
12.	असम	8/0-1 कि.मी. में चनसारी समपार संख्या एक के/2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	पू.सी.रे.
13.	असम	35/3-4 कि.मी. पर रंगिया में समपार संख्या 13 के बदले ऊपरी सड़क पुल	पू.सी.रे.
14.	असम	93/3-4 कि.मी. में अठगांव में समपार संख्या एस टी/9 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	पू.सी.रे.
15.	बिहार	दिदारगंज, मिठापुर राहगढ़पुर में मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	पू.रे.
16.	बिहार	टाटानगर पर ऊपरी सड़क पुल	द.पू.रे.
17.	बिहार	526/3-4 कि.मी. में किशनगंज में समपार संख्या एक के/317 के बदले ऊपरी सड़क पुल	पू.सी.रे.
18.	हरियाणा	करनाल में निचला सड़क पुल	उ.रे.
19.	कर्नाटक	रामानगरम के निकट समपार संख्या 36 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
20.	कर्नाटक	चेनापटना के निकट समपार संख्या 48 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
21.	कर्नाटक	बेनलदूर रोड बनासवाडी रोड पर समपार संख्या 138 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
22.	केरल	वारकाला के निकट 179/13-14 कि.मी. में समपार संख्या 561 के बदले ऊपरी/ निचला सड़क पुल	द.रे.
23.	केरल	शोरूवण्णूर और थिरूपुनीथुरा स्टेशन (कठरीकाडऊ) श्री रंगम-पिटचंद्र के बीच कि.मी. ई क्यू 1/11-12 पर समपार संख्या 1 के बदले ऊपरी निचला सड़क पुल	द.रे.
24.	मध्य प्रदेश	1126/11012 कि.मी. पर दामोह में समपार संख्या 59/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
25.	मध्य प्रदेश	1048/4-5 कि.मी. पर सागर में समपार संख्या 23/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
26.	मध्य प्रदेश	देवास में समपार संख्या 29 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	प.रे.
27.	महाराष्ट्र	260/3-4 कि.मी. पर दौंड में समपार संख्या 18/बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
28.	महाराष्ट्र	60/4-5 कि.मी पर नवादे रोड में समपार संख्या 12/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
29.	महाराष्ट्र	22/11-12 कि.मी. पर विखरौली में समपार संख्या 14/सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
30.	महाराष्ट्र	13/12-13 कि.मी. पर चूनाभट्ठी में समपार संख्या 1 (स्पेशल) के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
31.	महाराष्ट्र	792/2-3 कि.मी. पर हिंगनघाट में समपार संख्या 14/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
32.	महाराष्ट्र	505/12-13 कि.मी. निम्बोला में समपार संख्या 175/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
33.	महाराष्ट्र	विरार-सूरत में समपार संख्या 51 के बदले ऊपरी सड़क पुल	प.रे.
34.	महाराष्ट्र	218/8-9 कि.मी. पर निफाद में समपार संख्या 99/बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
35.	महाराष्ट्र	286.99 कि.मी. पर नंदगांव में समपार संख्या 114/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
36.	महाराष्ट्र	7-3/4 कि.मी. पर सेवारी में समपार संख्या 7(स्पेशल) के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
37.	महाराष्ट्र	चर्चगेट-विरार में समपार संख्या 35 के बदले ऊपरी सड़क पुल	प.रे.
38.	महाराष्ट्र	450/3-4 कि.मी. पर फेकरी में समपार संख्या 1/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
39.	महाराष्ट्र	433/15-18 कि.मी. पर नसिराबाद में समपार संख्या 54/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.

1	2	3	4
40.	उड़ीसा	चेनपाल में ऊपरी सड़क पुल	द.पू.रे.
41.	पंजाब	सुनम में समपार संख्या 76-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
42.	पंजाब	सरहिंद में समपार संख्या 144-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
43.	पंजाब	राजपुरा में समपार संख्या 135-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
44.	पंजाब	लुधियाना में समपार संख्या ए-2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
45.	पंजाब	जलंधर में डुमोरिया निचले सड़क पुल के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
46.	पंजाब	कोथापुरा में समपार संख्या 25-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
47.	पंजाब	जलंधर कैंट में समपार संख्या 68-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
48.	राजस्थान	इंदोरा-देवास उज्जैन में समपार संख्या 216-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	
49.	राजस्थान	रायकाबाग में निचला सड़क पुल	उ.रे.
50.	राजस्थान	कोटा-मथुरा में समपार संख्या 109 के बदले ऊपरी सड़क पुल	प.रे.
51.	राजस्थान	जयपुर-रिंगस में समपार संख्या 87 के बदले ऊपरी सड़क पुल	प.रे.
52.	तमिलनाडु	श्रीरंगम-पिचानदरकोइल में समपार संख्या 246 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
53.	तमिलनाडु	विरूद्धनगर-शंकरालिंगापुरम में समपार संख्या 406 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
54.	तमिलनाडु	267/4-6 कि.मी. पर मोरप्पुर स्टेशन श्रीरंगम-पिचानदरकोइल स्टेशन पर समपार संख्या 100 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
55.	तमिलनाडु	तिरूपदिरीपुलीयूर में समपार संख्या 159 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
56.	तमिलनाडु	2-3 कि.मी. पर करूर के निकट समपार संख्या 37 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
57.	तमिलनाडु	247/2 कि.मी. पर चिदम्बरम के निकट समपार संख्या संख्या 202 के बदले ऊपरी/ निचला सड़क पुल	द.रे.
58.	तमिलनाडु	पर सदापेट में बाजार रोड के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
59.	तमिलनाडु	श्रीरंगम-पिचानदरकोइल में समपार संख्या 241 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
60.	तमिलनाडु	26/1-2 कि.मी. पर मिटगेट में समपार संख्या 28 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
61.	तमिलनाडु	पलकाराय में समपार संख्या 85 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
62.	तमिलनाडु	तेनुर हाई रोड में समपार संख्या 84 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
63.	तमिलनाडु	तिनडीवनम में समपार संख्या 96 के बदले ऊपरी/निचला सड़क पुल	द.रे.
64.	उत्तर प्रदेश	महीबुल्लाहपुर यार्ड में लखनऊ सिटी में समपार संख्या 10 के बदले ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.
65.	उत्तर प्रदेश	डालीगंज और बादशाह नगर के बीच लखनऊ सिटी में समपार संख्या 7 मि.ला. के बदले ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.
66.	उत्तर प्रदेश	डालीगंज और हबीबबुल्लापुरा के बीच समपार सं. 6 के बदले लखनऊ सिटी में ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.

1	2	3	4
67.	उत्तर प्रदेश	सिरसा मंडी में समपार संख्या 25-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.
68.	उत्तर प्रदेश	रामपुर में समपार संख्या 403-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
69.	उत्तर प्रदेश	सहरसा में समपार संख्या 31 स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
70.	उत्तर प्रदेश	चुकदी में समपार संख्या 28 स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.
71.	उत्तर प्रदेश	बादशाहाघर-मल्हौर में समपार संख्या 3 एमएल के बदले ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.
72.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी में समपार संख्या 180-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो.रे.
73.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद में समपार संख्या 154-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
74.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ में समपार संख्या 109-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
75.	उत्तर प्रदेश	सकोती टांडा में समपार संख्या 40-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
76.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर में समपार संख्या 50-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
77.	उत्तर प्रदेश	बरेली में समपार संख्या 358/स्पेशल और समपार सं. 250ए/3-7 के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
78.	उत्तर प्रदेश	हथरस में समपार संख्या 95-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
79.	उत्तर प्रदेश	कानपुर में समपार संख्या 79-डी के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
80.	उत्तर प्रदेश	1341/10-12 कि.मी. पर इरादतगंज में समपार संख्या 430/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	उ.रे.
81.	पश्चिम बंगाल	बिराती और सोनारपुर में मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	म.रे.
82.	पश्चिम बंगाल	मौडीग्राम में ऊपरी सड़क पुल	पू.रे.

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने के बाद रेलवे पुल खास का निर्माण करती हैं। बहरहाल, समूचे कार्य को शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाएं पूरा करते हुए ठोस प्रस्ताव के समय पर प्राप्त न होने तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध न कराने तथा सापेक्ष प्राथमिकता न दिए जाने के कारण प्रस्तावों को रेलवे बजट में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

ब्रेक ब्लाक्स

3518. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राने एंड कंपनी द्वारा निर्मित कम्पोजिट ब्रेक ब्लाक्स को पश्चिम रेलवे के अंतर्गत बडोदरा मंडल के बाजुवा सीएंडडब्ल्यू डिपो तथा एम-ई-एम-यू- कार शेड द्वारा क्रमशः बी-टी-पी-एन- रेक्स में तथा एम-ई-एम-यू- बोगियों में लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्हील ट्रीड पर अत्यधिक नुकसान/क्षति पायी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई उपचारी उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) निकट परिपथ पर चालू 20 बीटीपीएन रेकों में राने कंपनी के कंपोजिट ब्रेक ब्लाक लगे हुए हैं।

मेमू कार शेड के पिछले 2 वर्षों के दौरान मैसर्स राने द्वारा 8000 तथा मैसर्स हिन्दुस्तान कंपो द्वारा 7250 कंपोजिट ब्रेक ब्लाक्स सप्लाई किए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) परंपरागत कास्ट आयरन ब्रेक ब्लाक्स की तुलना में कंपोजिट ब्रेक ब्लाक्स का निष्पादन बेहतर है।

[हिन्दी]

असैनिक विमानों का रिकार्ड

3519. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय देश में मौजूद सभी असैनिक विमानों और हेलीकॉप्टरों का रिकार्ड रखता है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों के विमानों और हेलीकॉप्टरों की किस्मों सहित उनके उत्पादन वर्ष, कीमतों तथा उनकी खरीद की तिथियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां। सभी सिविल पंजीकृत विमानों और हेलीकॉप्टरों के रिकार्ड का रख-रखाव नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा किया जाता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम की पर्यटन परियोजनाएं

3520. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998-99 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस पर अब तक परियोजना-वार क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु परियोजना-वार कुल कितना आवंटन किया गया?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) से (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान, असम सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए 15 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें से 14 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। एक परियोजना अपूर्ण तथा मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं थी। परियोजना का विवरण तथा स्वीकृत राशि इस प्रकार है :-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1.	असम के नागांव स्थित चपनल्ला झरने पर पिकनिक स्पॉट तथा पर्यटक सुविधा केन्द्र का विकास	19.58
2.	असम के पोबिटोरा में वर्तमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार	44.19
3.	असम के गोहाटी में वशिष्ठ आश्रम का विकास	34.23
4.	असम के काज़ीरंगा में वर्तमान पर्यटक लांज का उन्नयन	40.00
5.	असम के ओरंग स्थित राजीव गांधी वन्यजीव पार्क में पर्यटक परिसर	35.00
6.	असम के चापड़ में छोटे होटल/ मार्गस्थ सुविधाएं	34.15
7.	काज़ीरंगा स्थित अरण्य लांज में बच्चों के बाह्य मनोरंजन की सुविधाएं	17.80
8.	गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी मुहाने का सौन्दर्यीकरण	35.00
9.	पर्यटन मेलों एवं महोत्सव के लिए सहायता	
	(क) चाय-पर्यटन महोत्सव	5.00
	(ख) ब्रह्मपुत्र तट महोत्सव	4.00
10.	काकोपाथर में यात्री निवास	30.00
11.	काज़ीरंगा में पर्यटक परिसर	50.00
12.	विश्वनाथ (पर्यटक स्थल) का विकास	24.00
13.	खासपुर में यात्री निवास	18.00
14.	जलधारा नौकायन उपस्कर की खरीद	26.27
	जोड़	417.22

बीजापुर हवाई अड्डे का विकास

3521. श्री एम-बी- पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार की बीजापुर हवाई अड्डे (कर्नाटक) को विकसित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) किसी एयरलाइन आपरेटर ने अभी तक इस विमानपत्तन हेतु किसी अपेक्षा का प्रस्ताव नहीं किया है।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीतागार सुविधा प्रदान करना

3522. **श्री जी॰ गंगा रेड्डी :**

श्री एन॰आर॰के॰ रेड्डी :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

श्री एस॰एस॰ ओवेसी :

श्री के॰एस॰ राव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीतागार सुविधा हेतु आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) हैदराबाद विमानपत्तन पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) को भूमि का आवंटन कर दिया है जिससे कि इस सुविधा की स्थापना की जा सके, इसके चालू वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरा होने की संभावना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एपीईडीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा प्रचालन आरंभ करने के लिए कोल्ड स्टोरेज भवन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

रेल भाड़े में अंतर

3523. **श्री सीताराम यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली से अन्य स्थानों के बीच रेल भाड़े तथा वहां से दिल्ली के लिए वापस के रेल भाड़े में अन्तर होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस तरह की विसंगति को दूर करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) किराए जंक्शन दूरी सारणी के अनुसार गाड़ी चलाने वाली क्षेत्रीय रेलवे द्वारा आकलित दूरी के अनुसार प्रभारित किए जाते हैं। अतः कुछ मामलों में, प्रस्थान और आगमन की यात्राओं के लिए प्रभार्य दूरियों में अंतर होता है जिसके परिणामस्वरूप किरायों में अंतर आ जाता है। ऐसे मामलों में विसंगतियों को ध्यान में आते ही उन्हें शीघ्र दूर किया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस की अतिरिक्त उड़ानें

3524. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान इंडियन एयरलाइंस से कुछ चुने हुए मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें आरंभ करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो चलाए जाने वाले प्रस्तावित नये मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन पुराने मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भुवनेश्वर के लिए कोई नई उड़ान प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ङ) जी नहीं, तथापि, इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एअर ने अनेक मार्गों पर क्षमता/आवृति में वृद्धि की है और उन्होंने 29 मार्च, 1999 से प्रभावी ग्रीष्मकालीन अनुसूची में घरेलू नेटवर्क पर नए हवाई सम्पर्कों की भी व्यवस्था की है। शीतकालीन अनुसूची, 1998 की तुलना में ग्रीष्मकालीन अनुसूची, 1999 में मुख्य-मुख्य परिवर्तनों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण में दर्शाई गई है।

इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर से प्रचालित सेवाओं पर क्षमता/आवृति में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :-

मार्ग	शीतकालीन 98 अनुसूची (साप्ताहिक आवृति)	ग्रीष्मकालीन 99 अनुसूची (साप्ताहिक आवृति)
हैदराबाद/भुवनेश्वर/कलकत्ता	2ए-320	3बी-737
विजाग/भुवनेश्वर	3बी-737	7बी-737

विवरण

1999 की ग्रीष्मकालीन समय-सारणी में मुख्य-मुख्य परिवर्तन

आवृति/उपस्कर में परिवर्तन मार्ग	1998 की शरदकालीन आवृति/सप्ताह	1999 की ग्रीष्मकालीन आवृति/सप्ताह
बंगलौर-त्रिवेन्द्रम-बंगलौर	3ए320	7ए320
बंगलौर-अहमदाबाद-बंगलौर	3बी737	7बी737
मुम्बई-दिल्ली-मुम्बई	21ए300	14ए300
	21ए320	49ए320
	6बी737	5बी737
मुम्बई-चैन्ने-मुम्बई	7ए300	7ए300
	7ए320	14ए320
मुम्बई-हैदराबाद-मुम्बई	21ए320	21ए230
		7बी737
मुम्बई-जामनगर-मुम्बई	5बी737	7बी737
मुम्बई-विजाग-मुम्बई	4बी737	10बी737
कलकत्ता-पटना-लखनऊ-दिल्ली	4बी737	7बी737
कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	11ए320	10ए320
		2बी737
कलकत्ता-अहमदाबाद-कलकत्ता	6बी737	7बी737
कलकत्ता-पोर्टब्लेयर-कलकत्ता	4बी737	5बी737
चैन्ने-बंगलौर-चैन्ने	3बी737	10बी737
	11ए320	18ए320
चैन्ने-कलकत्ता-चैन्ने	7ए300	7ए300
	3ए320	3ए320
		3बी737
चैन्ने-अहमदाबाद-चैन्ने	3बी737	7बी737
दिल्ली-विजाग	3बी737	7बी737
दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली	5ए320	7ए320
हैदराबाद-बंगलौर-हैदराबाद	14बी737	14ए320
नये संपर्क		
मुम्बई-लखनऊ		
मुम्बई-पटना		
मुम्बई-रांची		
दिल्ली-कोयम्बतूर		
दिल्ली-कलकत्ता		
लखनऊ-वाराणसी		

[हिन्दी]

राजभाषा हिन्दी की स्वर्ण जयंती

3525. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सितम्बर, 1999 से शुरू होने वाली राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का है जिससे राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करने के प्रति लोग जागरूक हो सकें: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) राजभाषा हिंदी स्वर्ण जयन्ती समारोह कार्यक्रम के बारे में संबंधित नोडल विभाग, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर इस मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

बकाया धनराशि

3526. श्री कल्लाप्पा आवाडे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी रेल पुलिस पर हुए खर्च के कारण बकाया राशि के भुगतान से संबंधित महाराष्ट्र सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) राजकीय रेल पुलिस के संबंध में बिल तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में 31.3.99 को महाराष्ट्र राज्य सरकार को भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि इस प्रकार है :-

मध्य रेलवे	8.37 करोड़ रुपए
दक्षिण मध्य रेलवे	1.02 करोड़ रुपए
दक्षिण पूर्व रेलवे	0.61 करोड़ रुपए
पश्चिम रेलवे	2.39 करोड़ रुपए
जोड़	12.39 करोड़ रुपए

(ग) 12.24 करोड़ रुपए का बिल महाराष्ट्र राज्य सरकार से लेखा परीक्षा के प्रमाण की अनुपलब्धता के कारण बकाया है और 0.15 करोड़ रुपए के बिल पर कार्रवाई चल रही है। रेलों को इस संबंध में बिलों की शीघ्र क्लियरेंस करने के स्थायी अनुदेश दिए हुए हैं।

खानों में जांच अभियान

3527. **श्री विक्रम केशरी देव :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा॰ अशोक पटेल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में गहन जांच अभियान चलाने के निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) एक आंतरिक समीक्षा के दौरान, खान सुरक्षा महानिदेशालय को निर्देश दिया गया था कि वे दुर्घटना-संभावित खानों का गहन निरीक्षण करें ताकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खान अधिनियम के उपबंधों तथा खान अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन संगठनों के प्रदर्शन की समीक्षा पूर्णतः प्रशासनिक मसला है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

आकाशवाणी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

3528. **श्री प्रभाष चंद्र तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आकाशवाणी द्वारा स्थापित किए गए उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ट्रांसमीटरों ने राज्य-वार किन-किन स्थानों पर कार्य करना शुरू कर दिया है और उनकी प्रसारण रेंज कितनी है; और

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी के इन उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को कहां-कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) 1.1.96 से देश में मीडियम वेव बैंड में 6 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों, शार्ट वेव बैंड में 4 उच्च शक्ति ट्रासमीटरों तथा एफ एम बैंड में 5 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को चालू किया गया है। स्थलों तथा ट्रांसमिशन क्षमता के राज्य वार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षमता	कि.मी. में अनुमानित रेंज			
				उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
I. मीडियम वेव ट्रांसमीटर							
1.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	100 किवा. मी.वे.ट्रां.	*	166	180	153
2.	पंजाब	जालंधर	2x100 कि.वा. मी:वे.ट्रां.	175	261	166	*
3.	मध्य प्रदेश	जगदलपुर	100 कि.वा. मी.वे.ट्रां.	148	112	103	112
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	200 कि.वा. मी.वे.ट्रां.	261	288	315	256
5.	उड़ीसा	सम्बलपुर	100 कि.वा. मी.वे.ट्रां.	166	153	85	162
6.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	200 कि.वा. मी.वे.ट्रां.	243	*	*	211
II. शार्ट वेव ट्रांसमीटर							
1.	दिल्ली	दिल्ली	3x50 कि.वा. शा.वे.ट्रां.				

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	नागालैण्ड	काहिमा	50 कि.वा. शा.वे.ट्रां.				
3.	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	50 कि.वा. शा.वे.ट्रां.				
4.	उड़ीसा	जयपोर	50 कि.वा. शा.वे.ट्रां.				
III. एफ.एम. ट्रांसमीटर							
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	10 कि.वा. एफ.एम. ट्रां. (वी.बी.)**	32	32	32	32
2.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	10 कि.वा. एफ.एम. ट्रां. (रिले.)	28	28	28	28
3.	गुजरात	अहमदाबाद	10 कि.वा. एफ.एम. ट्रां. (वी.बी.)**	22	22	22	22
4.	केरल	कोचीन	10 कि.वा. एफ.एम. ट्रां. (सी.बी.एस.)@	30	30	30	30
5.	तमिलनाडु	नागरकोईल	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.	52	*	52	*

@ कवरेज हमारी सीमाओं से अधिक है।

** वी.बी. - विविध भारती

सी.बी.एस. - वाणिज्यिक प्रसारण सेवा

विवरण-II

राज्य	स्थल एवं स्कीमें		
1	2		
आन्ध्र प्रदेश	1.	विशाखापत्तनम	- 2×5 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. (वा.प्र.से.)
असम	2.	गुवाहाटी	- 100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	3.	गुवाहाटी	- 2×5 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. (वा.प्र.से.)
बिहार	4.	रांची	- 50 कि.वा. शा.वे.ट्रा.
गोवा	5.	पणजी	- 2×250 कि.वा. शा.वे. ट्रा.
गुजरात	6.	राजकोट	1000 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	7.	राजकोट "ख"	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	8.	वडोदरा	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
जम्मू एवं कश्मीर	9.	श्रीनगर "ग"	- कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	10.	जम्मू	- 50 कि.वा. शा.वे.ट्रा.
	11.	जम्मू	- 2×5 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
कर्नाटक	12.	मंगलौर	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	13.	धारवाड़ "ख"	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	14.	बंगलौर "ख"	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
केरल	15.	कालीकट "ख"	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	16.	अल्लीपे	- 2×100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
मध्य प्रदेश	17.	इन्दौर	- 200 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	18.	जबलपुर	- 2×5 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
महाराष्ट्र	19.	अमरावती	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	20.	नागपुर	- 300 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
मणिपुर	21.	इम्फाल	- 300 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	22.	इम्फाल	- 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा. (स्टीरियो)

1	2			
नागालैण्ड	23.	कोहिमा	–	100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
राजस्थान	24.	जोधपुर	–	300 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
तमिलनाडु	25.	तिरूचिरापल्ली	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	26.	धर्मपुरी	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	27.	कोड़ाईकनाल	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	28.	कोयम्बटूर	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
त्रिपुरा	29.	अगरतला	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा. (स्टीरियो)
उत्तर प्रदेश	30.	नजीबाबाद	–	200 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	31.	अलीगढ़	–	2×250 कि.वा. शा.वे. ट्रा.
पश्चिम बंगाल	32.	पुरूलिया	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	33.	दार्जिलिंग	–	10 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.
	34.	सिलीगुडी	–	2×5 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.
दिल्ली	35.	खामपुर	–	2×250 कि.वा. शा.वे. ट्रा.
	36.	खामपुर	–	3×250 कि.वा. शा.वे. ट्रा.
संघ शासित क्षेत्र :				
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	37.	पोर्टब्लयेर	–	100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.

उच्च/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना

3529. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजो सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में उच्च/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने और इनका उन्नयन और विस्तार कम करने हेतु इन राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन द्वारा दूरदर्शन नेटवर्क की स्थापना, उन्नयन और विस्तार करने संबंधी स्कीमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता, संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार बनायी जाती हैं। केन्द्रीय योजना होने के नाते इन स्कीमों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव नहीं मांगा जाता। तथापि, स्कीमों को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों तथा जन-प्रतिनिधियों सहित विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्रतियावेदनों/प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है। दूरदर्शन ने जन-प्रतिनिधियों से 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से उत्तर प्रदेश के संबंध में ऐसे 60 प्रत्यावेदन तथा बिहार के संबंध में 24 प्रतियावेदन प्राप्त किए हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में विभिन्न शक्तियों के 106 ट्रांसमीटर तथा बिहार में 52 ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। टी.वी. कवरेज का और अधिक विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश में 31 ट्रांसमीटर (8 उ.श.ट्रा. सहित) और बिहार में 9 ट्रांसमीटर (4 अ. श.ट्रा. सहित) इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

3530. श्री के•एस• राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय कार्यबल ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय रणनीति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकार की गई और लागू की गई सिफारिशों की संख्या क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) विशेष रूप से पर्यटन अवसंरचना पर कोई राष्ट्रीय कार्यबल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए इंडियन एयरलाइंस की सेवा

3531. डा• असीम बाला :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता को केन्द्र बनाकर

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए वायुसेवा हेतु योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वायुमार्गों पर विमान सेवा की मांग के अध्ययन हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन भी कराए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता तथा हांगकांग के बीच सेवा साध्यता संबंधी अध्ययन के विषय में एक यातायात संबंधी सर्वेक्षण कर रही है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने बंगलौर-बैंगकॉक सेक्टर पर प्रचालनों के संबंध में योजना बनाई है, बंगलौर तथा कुआलालम्पुर के बीच सेवा साध्यता संबंधी अध्ययन करने के विषय में यातायात संबंधी सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लखनऊ में उपरिपुल का निर्माण

3532. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रेलवे पुल सं. 469 की आधारशिला रखे जाने के शीघ्र बाद उसके निर्माण कार्य के क्रियान्वयन को रेल विभाग द्वारा स्थगित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2001 तक।

[अनुवाद]

बंगलौर की उल्सूर झील का विकास

3533. **श्री के-सी- कोंडय्या** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में उल्सूर झील खर-पतवार से भर गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से इस झील की सफाई करने के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार का इस झील की सफाई पर चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) यद्यपि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बंगलूर स्थित उल्सूर झील के एक हिससे का उपयोग समय-समय पर प्रशिक्षण के उद्देश्य से करता है तथापि उल्सूर झील बंगलूर शहर नगरपालिका के प्रबंधनाधीन है।

(ग) सफाई कार्य के लिए मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने कर्नाटक सरकार या बंगलूर शहर नगरपालिका से सम्पर्क किया है न कि भारत सरकार ने।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का खेल चैनल

3534. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

श्री तेजवीर सिंह :

श्री अशोक प्रधान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दूरदर्शन के नये 'खेल चैनल' की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो नये 'खेल चैनल' की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का दूरदर्शन पर खेल कमेन्ट्री के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा विदेशों में लाखों खेल प्रेमियों की रुचि को पूरा करने के लिए दूरदर्शन ने दिनांक 18.3.99 को एक समर्पित 'खेल चैनल' शुरू किया था। इसके प्रसारण समय जो कि आरम्भ में प्रतिदिन छः घंटे था, को दिनांक : 25.3.99 से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। मध्य पूर्व, सी.आई.एस. एवं पड़ोसी क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र

तथा आफ्रीकी क्षेत्र के 34 देशों में फुटप्रिन्ट्स वाले पी.ए.एस.-4 उपग्रह से प्रचालित किये जा रहे इस चैनल से विभिन्न प्रकार के खेल प्रसारित किए जाएंगे जिनमें भारतीय खेल आयोजनों, स्वदेशी खेलों, ग्रामीण खेलों आदि को विशेष महत्व दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी कूचबिहार-न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी रेल लाइन का दोहरीकरण

3535. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू कूचबिहार-न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी बड़ी रेल लाइन का दोहरीकरण करने के लिए कितने संसद सदस्यों द्वारा रेलवे को अनुरोध किया गया है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न संसद सदस्यों से बार-बार प्राप्त होने वाले अनुरोधों सहित बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अक्सर माननीय संसद सदस्यों के पत्रों में कई परियोजनाओं का संदर्भ दिया जाता है। माननीय संसद सदस्यों के प्रत्येक अनुरोध पर अलग-अलग कार्रवाई की जाती है और यथोचित ध्यान दिया जाता है। बहरहाल, ऐसे अभ्यावेदनों का समेकित परियोजना-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) अनुरोध पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं। दालखोला और किशनगंज के बीच थोड़ी से दूरी को छोड़कर जहां कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा, मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी खंड का दोहरीकरण पूरा हो गया है।

न्यू जलपाईगुडी-सिलीगुडी-न्यू बोंगाईगांव का आमान परिवर्तन शुरू किया गया है। इस लाइन के बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाने के पश्चात् न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू बोगाईगांव के बीच दोहरी लाइन उपलब्ध हो जाएगी। इस लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की योजना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी के बीच जोगीघोपा के रास्ते एक नई लाइन निर्माणाधीन है और इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। इन दो बिन्दुओं के बीच ये 2 लाइनें उपलब्ध हो जाने से दोहरीकरण का प्रयोजन पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट खान में न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन

3536. **श्री सोम मरांडी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकुर (बिहार) की काली ग्रेनाइट खान के निजी मालिक और सुरक्षा संबंधी/नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खान मालिक श्रम विवादों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए श्रम आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलयात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति

3537. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के मुगलसराय मंडल ने दिनांक 11 मई, 1998 के हिन्दुस्तान में मुगलसराय तथा गया में क्रमशः दो तथा तीन रेलयात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में एक विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्वी रेलवे द्वारा क्या योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या तत्कालीन वरिष्ठ आर.सी.एम. ने अपने स्थानान्तरण से पूर्व उक्त एजेंटों की गया में जल्दबाजी में नियुक्ति कर दी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या गया में नियुक्त एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नियम 4 के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 30.4.1998 को प्रमुख हिंदी दैनिकों में पूर्व रेलवे के मुगलसराय मंडल द्वारा मुगलसराय में दो रेल यात्री एजेंट तथा गया में तीन रेल यात्रा सेवा एजेंट नियुक्त करने के लिए विज्ञापन दिया गया था।

(ख) रेल यात्री सेवा एजेंट की नियुक्ति के लिए मापदंड निम्नानुसार हैं :-

एक व्यक्ति जो :

(1) अद्यतन आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र का धारक हो।

(2) शहर में पर्याप्त सुविधाओं के साथ उपयुक्त रूप से सुसज्जित कार्यालय तथा परिसर का धारक हो ताकि उपभोक्ताओं की पर्याप्त संख्या को संभाल सके; तथा

(3) नैतिक चरित्रहीनता वाले किसी आपराधिक मामले में सजायाफ्ता न हो।

एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए रेल यात्री सेवा एजेंट प्राधिकार नियम 1985 के नियम 4 के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में छाया युद्ध

3538. श्री रवि सीताराम नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1999 को 'दक्कन हेराल्ड' में "पाक टोल्ड टु ऐंड प्रोक्सी वार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती उपाय किये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार निरंतर यह मांग करती रही है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद को सहायता देना तथा उसे भड़काना बद करे और आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान में मौजूद आधारभूत अवसंरचनाओं को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए। हाल ही में प्रधानमंत्री की 20-21 फरवरी, 1999 की पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंसा का मार्ग व्यर्थ तथा निरर्थक है और जो हिंसा का उपदेश देते हैं, हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तथा हिंसा को बढ़ावा देते हैं उन्हें शांति और सौहार्द के सच्चे मार्ग को समझना चाहिए। 26 फरवरी, 1999 को संसद के दोनों सदनों में अपने एक स्वतः प्रेरित कथन में विदेश मंत्री ने संविधान की मर्यादा बनाए रखने की सरकार की इच्छा को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि देश की एकता और प्रादेशिक अखंडता पर कभी भी आंच नहीं आने दी जाएगी।

उक्त यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए जोकि दोनों देशों की शांति व सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक घटना है। लाहौर घोषणा-पत्र में दोनों प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देश आपसी बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास तेज करेंगे, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलदांजी तथा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हर तरह के आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे, परमाणु शस्त्रों के गैर-इरादतन और अप्राधिकृत इस्तेमाल के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल उपाय करेंगे तथा युद्ध से बचने के उद्देश्य से परमाणु व परम्परागत शस्त्रों के क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपाय किए जाने के मद्देनजर सुरक्षा संकल्पनाओं और सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। लाहौर घोषणा-पत्र में दोनों देशों ने अपने इस संकल्प को भी दोहराया है कि वे शिमला समझौते को पूरी तरह से लागू करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के निर्वाह के लिए यह बुनियादी समझौता है।

सरकार म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल तथा अन्य पड़ोसी देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी पूरी तरह से सुव्यवस्थित प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

"टेकास" उपकरण रहित विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध

3539. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने "टेकास" उपकरण रहित विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने यह उपकरण लगाने के लिए कोई रियायत दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय ने पहली जनवरी, 1999 से ये अनुदेश जारी किए हैं कि उन सभी विमानों में जो भारतीय वायुक्षेत्र के लिए/से होकर सेवा प्रचलित कर रहे हैं उनके लिए 30 यात्रियों से अधिक प्रमाणित सीटिंग क्षमता अथवा 3 टन भार से अधिक पे-लोड क्षमता वाले विमानों में एयरबोर्न कोलीजन एवायडेंस प्रणाली (एसीएएस) -2 स्थापित की जानी अनिवार्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के फैडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में एसीएएस प्रणाली को टीसीएएस (ट्रैफिक कोलीजन एवायडेंस सिस्ट-:) कहा जाता है। तथापि, नागर विमानन अपेक्षा के अनुसार 10 से 30 तक अधिकतम प्रमाणित सीटिंग कंफीगरेशन अथवा एक से तीन टन भार की अधिकतम पे-लोड क्षमता वाले विमान के प्रचालन की 31.12.2003 तक एसीएएस-1 के संस्थापन के बगैर अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) कोई आम छूट नहीं दी गई है। तथापि, एसीएएस-2 के संस्थापन के बगैर पृथक-पृथक उड़ानों के प्रचालन की अनुमति देने संबंधी प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार किया जाता है और उन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

प्रभावित परिवारों को रोजगार

3540. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे ने जम्मू-उधमपुर रेल मार्ग के निर्माण करने में जितने परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया उनके कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है;

(ख) सरकार के अधीन रोजगार के लिए कितने आवेदन लंबित हैं और इनके लंबित होने के कारण क्या हैं; और

(ग) इन परिवारों के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) बड़े पैमाने की रेल परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों/उनके परिवार के सदस्यों को कतिपय अनुबंधों के तहत रोजगार के लिए प्राथमिकता देने का विचार करने हेतु रेलों पर अनुदेश विद्यमान हैं। जम्मू-उद्यमपुर रेल सम्पर्क (53.2 कि.मी.) का अभी निर्माण किया जा रहा है और इसलिए इस लाइन के लिए ग्रुप "ग" और "घ" कोटि में कोई भर्ती नहीं की गई है। जब कभी इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना जारी होगी भूमि देने वालों या उनके आश्रितों की प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति के उनके आवेदन प्राप्त होने पर मौजूदा नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिक

3541. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिक परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार की नीति और प्रत्येक परियोजना पर की गई कार्रवाई क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार करने की अनुमति पाने वाले भारतीय निर्माताओं की संख्या और प्रसारण अनुमति हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीय उद्यमियों को दूरदर्शन कार्यक्रम/धारावाहिक तैयार करने हेतु इस प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, अनिवासी भारतीयों से कमीशंड कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :-

(1) यू.के. के श्री विजय राणा द्वारा संग्रहालयों पर 13 कड़ियों का कार्यक्रम "बियोन्ड दा सीज"।

(2) सुश्री ललिता कृष्णा, कनाडा द्वारा वृत्तचित्र 'थ्री आर्टिस्ट्स' प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। चाहे वे भारतीय नागरिकों से प्राप्त हों या अनिवासी भारतीयों से।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश के विभिन्न भागों से निर्माताओं को दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार कमीशंड कार्यक्रमों के लिए बुक किया जाता है। इस प्रकार के निर्माताओं के बारे में ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। कार्यक्रम इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सौंपे जाते हैं।

(घ) प्रसार भारती ने बताया है कि कार्यक्रम दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार होने पर परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलांइस के बोर्डों के सदस्य

3542. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के बोर्डों में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनमें से कितने सदस्य वेतन पर और कितने अवैतनिक आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त संगठनों को उनके वेतन का भुगतान करने और उन्हें अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान इन बोर्डों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

	एअर इंडिया बोर्ड	इंडियन एयरलाइंस बोर्ड
बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की संख्या	6	6

केवल प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लि॰ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, जो मुख्य कार्यकारी है, को इन संगठनों द्वारा वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। बोर्डों के गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2000 रु॰ का भुगतान किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

एन॰सी॰सी॰ प्रशिक्षण यूनिट्स

3543. **श्री मोहन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार एन॰सी॰सी॰ के कितने प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा वर्ष में जूनियर और सीनियर स्तरों पर कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या 13 से 21 वर्ष आयु के सभी छात्रों को एन॰सी॰सी॰ प्रशिक्षण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान समय में कितने प्रतिशत छात्रों को एन॰सी॰सी॰ प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ङ) क्या एन॰सी॰सी॰ प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को सेना में भर्ती करते समय प्राथमिकता दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) इकाइयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं। एन॰सी॰सी॰ कैडेटों के जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन में क्रमशः 7,59,147 और 4,33,413 कैडेट हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) देश में छात्रों की कुल संख्या के अनुमानतः 4 प्रतिशत से भी कम छात्र एन॰सी॰सी॰ का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ङ) और (च) (1) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रत्येक सीधी भर्ती पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "सी" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 32 स्थान आरक्षित हैं।

(2) अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में अल्प सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर के "सी" प्रमाण-पत्र धारकों (न्यूनतम "बी" ग्रेड के साथ) के लिए भी 50 स्थान आरक्षित हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में नहीं बैठना पड़ता है अपितु उन्हें चयन के लिए सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।

(3) सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमाण-पत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	यूनिटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	बिहार	43
3.	दिल्ली	18
4.	गुजरात	35
5.	जम्मू-कश्मीर	09
6.	कर्नाटक	49
7.	गोआ	03
8.	केरल	38
9.	मध्य प्रदेश	51
10.	महाराष्ट्र	59
11.	असम	26
12.	मेघालय	04
13.	मणिपुर	02
14.	नागालैंड	04
15.	त्रिपुरा	03
16.	अरूणाचल प्रदेश	01
17.	मिजोरम	01
18.	उड़ीसा	23
19.	पंजाब	31

1	2	3
20.	हरियाणा	17
21.	हिमाचल प्रदेश	12
22.	चंडीगढ़	04
23.	राजस्थान	35
24.	तमिलनाडु	50
25.	पांडिचेरी	06
26.	उत्तर प्रदेश	122
27.	पश्चिम बंगाल	50
	जोड़	754

गोरखपुर-नई दिल्ली के बीच विमान सेवा

3544. श्री पंकज चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब तक आरम्भ हो जाएगी?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया है। तथापि, यह विमान कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर रहते हुए विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं मुहैया करें।

[अनुवाद]

धर्मपुरी में सड़क के उपरि पुल का निर्माण

3545. श्री के•पी• मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे धर्मपुरी रेलवे स्टेशन के निकट सड़क के उपरि पुल के निर्माण का विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में रेलवे को भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार उक्त पुल के निर्माण के लिए अपने हिस्से का योगदान करने पर राजी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बीड़ी मजदूर

3546. श्री के• करूणाकरन :

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेष रूप से उड़ीसा में असंगठित क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का उनके लिए कोई कल्याण योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा• सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में, मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में आने वाले, लगभग 44 लाख बीड़ी कामगार हैं। इनमें 1.6 लाख बीड़ी कामगार उड़ीसा राज्य में हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में पहले ही योजनाएं तैयार की हुई हैं। ऐसी योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सूची

क. स्वास्थ्य

1. स्थिर-सह-सचल/स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
3. टी.बी. ग्रस्त बीड़ी कामगारों के लिए घरेलू उपचार की योजना।

4. कैन्सर पीड़ित बीड़ी कामगारों के उपचार की योजना।

5. मानसिक रोग ग्रस्त बीड़ी कामगारों के उपचार की योजना।

6. कुष्ठ पीड़ित बीड़ी कामगारों (घरा-खाता कामगार सहित) के उपचार की योजना।

7. चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता अनुदान।

8. महिला बीड़ी कामगारों के लिए प्रसूति लाभ योजना।

9. बीड़ी कामगारों को बंध्याकरण के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान की योजना।

10. हृदय रोग के मामले में बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

ख. सामाजिक सुरक्षा

1. समूह बीमा योजना

ग. आवास

1. अपना घर स्वयं बनाओ योजना।

2. बीड़ी कामगारों के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आवास योजना।

3. वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की कॉपरेटिव सोसाइटी को आर्थिक सहायता अनुदान।

4. समूह आवास योजना।

घ. शिक्षा

1. बीड़ी कामगारों (घर-खाता कामगार सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति।

2. बीडी कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सैट ड्रैस, स्लेट, कापियों तथा किताबों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता की व्यापक योजना।

3. हाई स्कूल से विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

4. बीड़ी कामगारों की स्कूल जाने वाली बालिकाओं को, उनकी प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर, एक रुपए की प्रोत्साहन राशि/वित्तीय सहायता की योजना।

ङ मनोरंजन

1. दृश्य-श्रव्य सैटों की स्थापना/सिनेमा वैन/फिल्मों का प्रदर्शन।

2. बीड़ी कामगारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन।

3. बीड़ी कामगारों के लिए अवकाश गृह योजना।

4. बीड़ी कामगार औद्योगिक सहकारी समितियों को टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

5. बीड़ी कामगार आवासीय कॉलोनी में रंगीन टी.वी. युक्त सामुदायिक भवन की स्थापना।

काली सूची में रखे गए बैंक

3547. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कुछ बैंकों को काली सूची में रखा है और उनके क्रेडिड कार्डों का प्रयोग सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार हेतु रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों के पास कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1998 के अंत में उत्तर रेलवे द्वारा बैंकों से खातों के मिलान न होने के कारण 20 लाख रु॰ (लगभग) की धनराशि वसूली की जानी थी। इसलिए खातों की निकासी के लिए उत्तर रेलवे ने ऋण कर्जे के बदले लेन-देन को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया था। चूंकि लगभग 24 लाख रु॰ की बकाया धनराशि का समाधान हो गया था, इसलिए सिटी बैंक और विजया बैंक के ऋण कार्डों के एवज में लेनदेन को 21.2.99 से फिर से चालू कर दिया गया क्योंकि इसके खाते स्पष्ट थे। उत्तर रेलवे विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और पुराने बकाया धनराशि के समाधान के लंबित रहते बाकी बैंकों के ऋण कार्डों के बदले लेनदेन को 15 अप्रैल तक पुनः चालू कर देने की संभावना है।

दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3548. डा॰ शकील अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपने दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु 1 नवंबर 1998 को आधारशिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी और अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना को जल्दी पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है और बाकी धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। इस परियोजना के लिए 1999-2000 के बजट में 10 करोड़ रु॰ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) कार्य की प्रगति आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्राथमिकता तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी।

(घ) स्थिति को उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

3549. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री महेश कनोडिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, लापरवाही और अक्षमता के दोषी पाये गये एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जांच और कार्यवाही की गयी?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेना का परित्यक्त टैंक

3550. श्री अमन कुमार नागरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महरौली जिले में छतरपुर मंदिर से करीब 14 किलोमीटर दूर भाटी माईन्स में परित्यक्त पड़े टैंक की जानकारी है, जैसाकि 1 मार्च, 1999 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो टैंक वहां किस प्रकार पहुंचा;

(ग) यह टैंक वहां पर किस तारीख से है, तथा इसे वहां रखने के पीछे किसका हाथ है;

(घ) क्या सेना द्वारा टैंक को अपने नियंत्रण में लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) यह टैंक ब्रिटिश मूल का है और यह टैंक द्वितीय विश्व युद्ध से भी पहले का है। इस टैंक में किसी भी प्रकार की प्रणाली अर्थात् मैकेनिकल/आर्मामेंट हिस्से न होने की वजह से इस परित्यक्त टैंक का केवल स्क्रैप मूल्य शेष है।

(ग) यह टैंक कम से कम 1975 से इसी स्थान पर उसी स्थिति में वैसे ही पड़ा हुआ है और इससे पहले इसे फायरिंग अभ्यास के दौरान कठिन लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

(घ) और (ङ) सेना मुख्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस टैंक का यथास्थाने निपटान करना चाहता है।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों के स्वामित्व वाले विमान

3551. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी निजी एयरलाइनें कार्यरत हैं और इनके स्वामित्व में कितने वायुयान और हेलीकाप्टर हैं; और

(ख) इन निजी विमान कंपनियों ने अपने वायुयान और हेलीकॉप्टर किन-किन देशों से और किस कीमत पर खरीदे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित निजी विमानकंपनियों द्वारा स्वामित्व वाले विमानों/हेलीकॉप्टरों के बारे में सूचना

क्र. सं.	अनुसूचित निजी विमान कंपनियों के नाम	विमान की किस्म	विमान संख्या	जिस कंपनी से खरीदे गए उनका नाम
1.	जेट एयरवेज	बी-737-400	6	यू.के. तथा ब्रिटिश वेस्ट-इंडीज
		बी-737-800	2	में अवस्थित कंपनियों से किराया क्रय करार के अधीन
2.	अर्चना एयरवेज	एल-410	2	चेक रिपब्लिक
3.	सहारा इंडिया एयरलाइंस	बी-737-200	2	जर्मनी

विमान/हेलीकॉप्टर की लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया की विमान परिचारिकाओं के साथ अलग दर्जा

3552. श्री विकास चौधरी :

श्री सुनील खां :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के कार्यपालकों व हवाई परिचारिकाओं के साथ विमान में उड़ान के दौरान कामगारों जैसा व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर उन्हें कार्यकारी जैसा दर्जा देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यही नियम केबिन कर्मीदल के पुरुष कर्मचारियों पर भी लागू होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो केबिन कर्मीदल के पुरुष और महिला कार्यकारिणी में इस तरह के भेदभाव के कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) कार्यकारी विमान परिचारिकाएं उड़ान ड्यूटी करते समय लाइन विमान परिचारिकाओं की हैसियत से उड़ान भरती हैं।

(ख) महिला केबिन कर्मीदलों को प्रोन्नति के पश्चात् उनके प्रबंधन वर्ग में प्रविष्टि के आधार पर भूमि पर कार्यपालक के रूप में कार्यालय का कार्य सौंपा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रबंधन और एअर इंडिया केबिन कर्मीदल एशोसिएशन (मान्यताप्राप्त यूनियन) के बीच दिनांक 17.11.83 के रिकार्ड नोट के मुताबिक ऐसी सहमति हुई थी कि उड़ान ड्यूटी करते समय कार्यकारी विमान परिचारिकाएं लाइन विमान परिचारिकाओं की हैसियत से उड़ान भरेंगी।

[हिन्दी]

सीटों पर अवैध कब्जा

3553. श्री प्रदीप कुमार यादव :

श्री तारीक अनवर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे कर्मचारी रेलवे सुरक्षा बल की साठगांठ से अनारक्षित रेल डिब्बों में सीटों पर कब्जा करके इन्हें धन लेकर यात्रियों को देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में दोषी पाये गए कर्मचारियों के नाम क्या-क्या हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सीटों पर कब्जा करने के ऐसे मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। बहरहाल, 22.3.99 को नई दिल्ली स्टेशन पर 2554 डाउन वैशाली एक्सप्रेस के अनारक्षित डिब्बे में स्थान दिलाने के चक्कर में उत्तर रेलवे का श्री सुखवीर सिंह, सफाईवाला पैसा लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(घ) प्रमुख स्टेशनों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी अनारक्षित सवारी डिब्बों को यार्ड/धुलाई लाइनों से विधिवत तालाबंद करके प्लेटफार्मों पर लगाया जाता है। प्लेटफार्मों पर गाड़ियों में चढ़ने के लिए यात्रियों की कतारें बनाई जाती हैं जिससे कि वे अपने बारी आने पर अनारक्षित डिब्बों में चढ़ सकें।

लोकप्रिय गाड़ियों में कतारें चल अवरोधकों और रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस की मदद से सुनिश्चित की जाती हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज का निर्माण

3554. श्री अभयसिंह एस॰ भोंसले :

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर सतारा और धुले जिलों में कुल कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) किन-किन रेलवे फाटकों पर अभी तक सड़क ब्रिज या सड़क अंडर ब्रिज बनाये गये हैं;

(ग) किन-किन रेलवे फाटकों पर सड़क ओवर ब्रिज या सड़क अंडर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रकार के पुलों के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) महाराष्ट्र में 2653 समपार हैं जिनमें से 78 धुले जिले में और 63 सतारा जिले में पड़ते हैं।

(ख) (1) नीरा और लोनांद स्टेशन के बीच 91/6-71 कि.मी. पर पुल सं. 157

(2) जारनदेश्वर और सतारा स्टेशनों के बीच 144/11-12 कि. मी. पर पुल सं. 276

(3) अदरकी-वाथर स्टेशनों के बीच 116/0-1 कि.मी. पर पुल सं. 203

(4) अदरकी-वाथर स्टेशनों के बीच 118/1-2 कि.मी. पर पुल सं. 208

(5) शिवरवदे और करद के बीच 203/3-4 कि.मी. पर पुल सं. 382

(ग) राज्य सरकार द्वारा करद-चिकल थाना सड़क पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) राज्य-सरकार निर्माण, परिचालन और हस्तानान्तरण योजना के आधार पर करद-चिकलथाना पर ऊपर राड़क के निर्माण पर विचार कर रही है। अगली कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

श्रीनगर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाना

3555. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक अलग टर्मिनल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रीनगर विमानपत्तन पर पहले ही पृथक सिविल टर्मिनल है जिसकी प्रबंध व्यवस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एच॰ए॰एल॰ में रख-रखाव एवं ओवरहाल की सुविधा

3556. श्री ए॰ सिदराजू : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलूर में हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड विमानपत्तन में रखरखाव एवं ओवरहाल सुविधा इकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इकाई के स्थापित किए जाने हेतु अनुमानित व्यय क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) बंगलूर में एच ए एल विमानपत्तन के पास रखरखाव एवं ओवरहाल सुविधा पहले ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा चुकी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में एअर इंडिया के कर्मचारियों की तैनाती

3557. श्री राजनारायण पासी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एअर इंडिया के कितने अधिकारी और स्टाफ चार वर्ष से अधिक समय से विदेशों में किन-किन स्थानों पर तैनात हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : एअर इंडिया के केवल दो अधिकारी ही चार वर्ष से अधिक समय तक विदेशी नियुक्तियों पर रहे हैं। वे इस समय लंदन में नियुक्त हैं।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार

3558. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक लोगों को आकृष्ट करने हेतु सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी चैनलों के दूरदर्शन कार्यक्रमों को पूरे देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में प्रसारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन के कार्यक्रम संबंधी मामले प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में आते हैं जो कि एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन का सदैव कार्यक्रमों में अधिक से अधिक नवीनता लाने और दर्शकों के विभिन्न वर्गों की भिन्न-भिन्न रुचि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रयास रहता है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने बताया है कि दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के कार्यक्रम महाराष्ट्र सहित समस्त देश में उपग्रह मोड में उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में 85 ट्रांसमीटर (डी डी 1—83, डी डी में 2—2) कार्यरत हैं और आगे स्थलीय कवरेज के लिए 28 ट्रांसमीटर (डी डी 1—27, डी डी 2—1) कार्यान्वयनाधीन हैं।

[हिन्दी]

मनमाड-धुले-नरदाना-इंदौर रेल लाइन का निर्माण

3559. श्री डी॰एस॰ अहिरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड-धुले-नरदाना-इंदौर रेलवे लाइन के निर्माण की मांग महाराष्ट्र के नासिक और धुल जिलों तथा मध्य प्रदेश के खैरगांव तथा इंदौर जिलों के लोगों के द्वारा 1955 से की जाती रही है;

(ख) क्या उक्त रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पहले ही किया जा चुका है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त रेलवे लाइन के लिए रेल बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) उस रेलवे लाइन को रेल बजट में कब तक शामिल कर लेने और निर्माण कार्य कब तक शामिल कर लेने और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) से (च) शिरपुर तक विस्तार सहित मालेगांव और धुले-नरदाना के रास्ते मनमाड-धुले के बीच नयी लाइनों का सर्वेक्षण अभी हाल ही में पूरा हुआ है। सर्वेक्षण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं :-

परियोजना	लंबाई	लागत	प्रतिफल की दर
1. मालेगांव नई लाइन के रास्ते मनमाड-धुले	98 कि.मी.	152 करोड़ रु॰	(-) 1.73 प्रतिशत
2. शिरपुर तक विस्तार सहित धुले-नरदाना नई लाइन	62 कि.मी.	104 करोड़ रु॰	(-) 2.19 प्रतिशत

चालू नई लाइन परियोजना के भारी थ्रो फारवर्ड और लाइनों की अत्यधिक अलाभकारी प्रकृति होने के कारण परियोजनाओं पर आगे विचार नहीं किया जा सका।

नरदाना-इंदौर प्रस्तावित लाइन लगभग 240 कि.मी. लंबी होगी और आज की तारीख में इसकी कीमत 500 करोड़ रु॰ से कम नहीं बैठेगी। पहले से ही हाथ में ली गई लाइन परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण और इस समय रेलवे द्वारा महसूस की जा रही अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्तावित लाइन पर विचार करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

बिहार से पर्यटन परियोजनाएं

3560. श्री विजय कुमार "विजय" : क्या पर्यटन मंत्री 18.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तरह से प्राथमिकता दी गयी 12 परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजनावार 325 लाख रुपए की राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना का विकास कार्य परियोजनावार कब तक शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान बिहार राज्य सरकार को 325.00 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई 12 परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	रुपए लाखों में
1.	औरंगाबाद में मार्गस्थ सुविधाएं	25.00
2.	सिंधेश्वर स्थान (मधेपुरा) में यात्री निवास	26.00
3.	भागलपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	15.00
4.	मुंगेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	15.00
5.	निम्नलिखित स्थानों पर विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन-व-विस्तार :	
	*i. जीवन बिहार, राजगीर	50.00
	ii. बिराला विहार, रांची	20.00
	iii. रत्न विहार, धनबाद	25.00
	**iv. कोटिल्य विहार, पटना (चरण-2)	10.00
6.	विक्रमशिला में स्मारकों का सौंदर्यीकरण	25.00
7.	स्वास्थ्य रिजार्ट के रूप में राजगीर गर्म सोतों (हाटस्प्रींग) का विकास	40.00
***8.	महाबोधि मंदिर, बोधगया की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	30.00
9.	बुद्ध विहार, बौंधगया का उन्नयन एवं नवीकरण	17.00
10.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन नालंदा वैशाली, पटना और राजगीर में बौद्ध स्थलों पर आगमन द्वार/ नोटिस बोर्ड, बिजली के खम्भे और बेंच	20.00
11.	राजगीर उत्सव	10.00
12.	सोनपुर मेला	3.00
	कुल	325.00

* परियोजना स्वीकृत नहीं हो सकी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया परियोजना प्रस्ताव अधूरा था।

** इस परियोजना के स्थान पर राज्य सरकार ने गर्म सोते क्षेत्र (हाट स्प्रींग एरिया) के पास राजगीर में भूदृश्यांकित पार्किंग प्लाजा खडंजें के लिए 19.52 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्तुत की।

*** इस परियोजना के स्थान पर राज्य सरकार ने गिधकूट हिल के विकास और राजगीर में बेनुबन के आगे के पहुंच मार्ग के आसपास पर्यावरण के उन्नयन हेतु 8.16 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्तुत की।

दोनों मामलों में सरकार से मास्टर प्लान तैयार करने के पश्चात् राज्य वित्त निगम से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामले पर कार्रवाई करने और वित्तीय पैटर्न पर स्थिति स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया गया है।

(ख) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 30 महीनों की अवधि के भीतर पूरी होनी चाहिए। उपर्युक्त परियोजना वित्तीय वर्ष 1998-99 की अंतिम तिमाही में स्वीकृत की गयी थी।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

3561. श्री महेश कनोडिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों द्वारा बाल श्रमिकों के पुनर्वास के कार्यक्रमों को लागू न किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) बाल श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लागू न किए जाने के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बालकों को कार्य से निकालने तथा उनका पुनर्वास करने के संबंध में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में बाल श्रम संबंधी कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन किए जाने, बाल श्रमिकों के माता-पिता के लाभ के लिए सेवाओं का अभिकेन्द्रण करने ताकि उनकी आर्थिक दशाओं में सुधार हो सके एवं बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजनाओं के अंतर्गत, पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था की गई है। अभी तक बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में 1.5 लाख बालकों को शामिल करने के लिए 77 बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। परियोजना कार्यकलापों की आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करके तथा केन्द्र राज्य एवं जिला स्तरों पर समीक्षाएं करके परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबोधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, प्रबोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय प्रबोधन समिति भी गठित की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग

3562. श्री मनोरंजन भक्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम,

1986 के अंतर्गत भारत के सिर्फ 10 प्रतिशत बाल श्रमिक आते हैं और यह देश में विशेषकर कारखानों तथा कालीन उद्योग में बाल श्रम को रोकने में बुरी तरह विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारी तथा शोषण के संबंध में सरकार द्वारा गठित आयोग से अलग एक राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग गठित किए जाने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के दो प्रयोजन हैं। यह खतरनाक उद्योगों/व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है तथा ऐसे उद्योगों/व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को विनियमित करता है जो खतरनाक नहीं हैं अधिनियम की अनुसूची के भाग "अ" तथा "ब" में ऐसे उद्योगों/व्यवसायों/प्रक्रियाओं की एक सूची दी गई है जिनमें बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित की गई तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर इस अनुसूची को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। आज की तारीख में, 13 व्यवसायों तथा 51 प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। कालीन उद्योग में रोजगार अधिनियम की अनुसूची के भाग "अ" में दिए गए 13 व्यवसायों की सूची में शामिल है। अधिनियम में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने की दशा में दण्ड के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्रतिषेध तथा विनियमन दोनों ही संबंध में कानून के प्रावधानों का प्रवर्तन करने के लिए सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के पास प्रवर्तन तंत्र हैं। केन्द्रीय सरकार आवधिक विवरणियों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का प्रबोधन करती है।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम मंत्री हैं तथा 10 मंत्रालयों/विभागों के सचिव, सदस्य हैं। क्षेत्र में प्रतिषेध एवं विनियमन दोनों के संबंध में स्थिति का जायजा लेने के लिए समय-समय पर समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को कार्य से निकाला जाता है और अनौपचारिक शिक्षा, पोषणाहार, स्वास्थ्य देखरेख एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अधीन उनका पुनर्वास किया जाता है। अभी तक बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में 1.5 लाख बालकों को शामिल करने के लिए 77 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

बाल श्रम का उन्मूलन किसी एक मंत्रालय/विभाग या एजेन्सी का ही कार्य नहीं हो सकता है। यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। सरकार की राष्ट्रीय कार्य-सूची में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्रमिक उपायों को करने संबंधी एक मद रखा गया है। श्रम मंत्रालय जो इस प्रयोजन के लिए नोडल मंत्रालय है, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास शहरी, मामले एवं रोजगार, शहरी क्षेत्र एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि जैसे, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ घनिष्ट समन्वयन एवं सहयोग रखता है।

भारत सरकार "अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम" (आइपेक) के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करती है।

(ग) और (घ) बंधुआ एवं बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय आयोग कठित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की ओर से मांग प्राप्त हुई है। इस मुद्दे को 1992 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष रखा गया था जब 13 राज्य श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। चूंकि यह समिति कई कारणों से अपनी बैठक आयोजित नहीं कर सकी, अतः 18.5.99 को राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यह मतैक्य हुआ कि अब जब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है अतः बंधुआ एवं बाल श्रमिकों के संबंध में अब किसी पृथक आयोग का गठन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने एक नियत कार्यकाल के साथ द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है।

नया उपनगरीय स्टेशन

3563. डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में मध्य रेल उपनगरीय नेटवर्क में सायन और माटुंगा रेलवे स्टेशनों के बीच एक नया उपनगरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु किसी पार्टी या संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दूरदर्शन पुनः चाटुकारिता की ओर

3564. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1999 के 'इण्डियन एक्प्रैस' में डी.डी. इज रिटर्निंग टु साइकोफैन्सी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार सहित दूरदर्शन द्वारा प्रसारित मंत्री कार्यक्रमों संबंधी मामले, सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में आते हैं और सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उसके समाचार बुलेटिन पूर्ण रूप से खबरों के समाचार की दृष्टि से महत्व और इसके नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। यह भी सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि संवेदनशील मामलों विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले मामलों को उनकी कवरेज के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेवार तरीके से कवर किया जाए। जब कभी प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण और मुख्य समाचार के रूप में शामिल करने की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होते हैं तो उन्हें प्रसारित किया जाता है।

नवसृजित जोनों का कार्यकरण

3565. **श्री रंजब बिस्वाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नवसृजित जोनों ने पूरी तरह कार्य करना आरंभ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनमें कार्य शुरू करने के लिए आधारभूत सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जाएंगी;

(ग) क्या नवसृजित जोनों के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) पांच वर्षों की अवधि में जोनों को चरणबद्ध आधार पर गठित करने की योजना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में वायु सेना का फ्लाइंग स्टेशन

3566. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए वायु सेना का फ्लाइंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्टेशन के कब तक स्थापित किए जाने और कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमिकों के लिए चिकित्सालय

3567. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी और सीमेन्ट उद्योगों में कार्यरत अधिकतर श्रमिक तपेदिक, खून की कमी, कुपोषण और कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की अनुमानित संख्या और उपचार के अभाव में असमय मृत्यु को प्राप्त श्रमिकों की अनुमानित राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में बीमारी को रोकने हेतु नए चिकित्सालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) देश में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि बीड़ी तथा सीमेंट उद्योगों में कार्यरत लोग स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, किन्तु यह सत्य नहीं है कि बीड़ी व सीमेंट उद्योगों में कार्यरत अधिकतर मजदूर रक्ताल्पता, कुपोषण तथा कैंसर के शिकार हो जाते हैं। बीड़ी कामगारों को सांस की तकनीफ हो जाती है और वे फेफड़े संबंधी रोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा, कुछ तो तम्बाकू के सांस में चले जाने के कारण होता है और कुछ अस्वच्छ तथा अस्वास्थ्यकर कार्य दशाओं के कारण। सीमेंट उद्योग में प्रदूषण मुख्यतः चूना-पत्थर, कोयला तथा झांबा की पिसाई के कारण होता है। सभी सीमेंट संयंत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण निवारक साधन अपनाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति के बगैर किसी भी कारखाने को प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि सीमेंट उद्योग के मजदूर तपेदिक, रक्ताल्पता, कुपोषण तथा कैंसर से पीड़ित हुए हों। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमेंट संयंत्रों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण के स्तर का नियमित रूप से अनुवीक्षण करते रहे हैं। 1994-95 तथा 1995-96 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार श्रम कल्याण संगठन अस्पतालों/औषधालयों में फेफड़े संबंधी रोग का उपचार कराने वाले बीड़ी तथा खान कामगारों की अनुमानित संख्या क्रमशः 1,68,477 तथा 1,78,277 थी। रक्ताल्पता, तपेदिक, कुपोषण तथा कैंसर से मरने वाले बीड़ी व सीमेंट कामगारों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) तपेदिक से अत्यंत गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। घरेलू उपचार से इस रोग का प्रभावी रूप में निदान किया जा सकता है और यही उपचार की अनुशंसित विधि है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्रामीण जिलों में जिला तपेदिक केन्द्रों (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ समेकित (के माध्यम से तथा नगरों/बड़े शहरों में तपेदिक क्लीनिकों के माध्यम से किया जाता है। संशोधित कार्यनीति को लागू कर इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की जा रही है। संशोधित कार्यनीति के दायरे में 271 मिलियन लोगों को चरणबद्ध रूप में लाया जाना है। बीड़ी व खान कामगारों के लिए औषधालय अस्पताल चलाने वाले श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन ने बीड़ी कामगारों के लिए देश के विभिन्न भागों में 51 नए औषधालय खोले जाने की मंजूरी दी है। बीड़ी कामगारों के लिए धुलियान (पश्चिम बंगाल) में भी 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल निर्माणाधीन है। साथ ही, बीड़ी कामगारों के लिए सागर (म॰प्र॰), मुक्कुदल (तमिलनाडु) तथा बिहारशरीफ (बिहार) में 30 बिस्तरों वाले एक-एक अस्पताल की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन की आय में गिरावट

3568. **श्री गुरूदास कामत :**

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की आय में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन की आय में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। दर्शकों की कमी तथा उपग्रह चैनलों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व में कमी होने की सम्भावना है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपनी वाणिज्यिक राजस्व आय को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, दूरदर्शन ने गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रसारित करने, और अधिक वाणिज्यिक केन्द्र खोलने, वाणिज्यिक विज्ञापन प्रभारों को तर्कसंगत बनाने, दूरदर्शन को अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाने के लिए विज्ञापकों को प्रोत्साहन देने आदि के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली और गुजरात सरकारों द्वारा पेश की गई पर्यटन परियोजना

3569. **श्री जयसिंहजी चौहान :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार और गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राज्यवार कितनी परियोजनाएं पेश की गईं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनमें से अब तक राज्यवार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) इनसे संबंधित शेष परियोजनाओं को रद्द करने के परियोजनावार क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) :

(क) प्राप्त परियोजनाएं

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
दिल्ली	3	8	23
गुजरात	11	7	18

(ख) स्वीकृत परियोजनाएं

दिल्ली	3	8	21
गुजरात	11	7	18

(ग) अस्वीकृत परियोजनाएं

दिल्ली	-	-	2

नंद प्रयाग में मार्गस्थ सुविधाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त ट्रेकिंग और शिविर उपकरणों को लाने-ले-जाने के लिए टैम्पों की खरीद की परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि वे अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटित निधियां

3570. **श्री वैद्य विष्णु दत्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कौन-कौन से हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार संवर्द्धन हेतु विदेशों में हुई संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/व्यापार संबंधी बैठकों आदि में

सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने हिस्सा लिया था तथा प्रत्येक दौरे में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) विदेशों में हुई इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को वर्ष 1999-2000 के लिए कितनी निधि आवंटित की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) इस मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एन एफ डी सी) तथा ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड (बी ई सी आई एल) दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एन एफ डी सी) तथा ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड (बी ई सी आई एल) को विदेशों में समारोहों में भागीदारी के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है। ये कंपनियां अपने स्वयं के स्रोतों से खर्चों को पूरा करती हैं।

विवरण

उन विदेशी आयोजनों का ब्यौरा जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और ब्राडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड ने भाग लिया

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

क्र.सं.	दौरे का उद्देश्य/ दौरा किया देश	प्रतिनिधि मण्डल का संघटन	किया गया व्यय (रुपये में)
1	2	3	4
1996-97			
1.	केन्स फिल्म समारोह, फ्रांस	3	10,48,812.00
2.	अमरीकी फिल्म समारोह संयुक्त राज्य अमरीका	1	2,11,405.00
3.	मिपकॉम फिल्म समारोह, फ्रांस	2	6,89,104.00
4.	एम आई पी टी वी, फ्रांस	3	8,64,331.00
5.	ई ए एफ टी ए बी' 96 मलेशिया	1	18,100.00
6.	सिने एशिया सिंगापुर, सिंगापुर	1	54,440.00

उपर्युक्त समारोहों/बाजारों में भागीदारी के परिणामस्वरूप निर्यात से आय 56.29 लाख रु॰ थी। उपर्युक्त समारोहों/बाजारों में भागीदारी के परिणामस्वरूप आयातित फिल्मों की बिक्री से प्राप्त आय 265.71 लाख रु॰ थी।

1	2	3	4
1997-98			
1.	एम.आई.पी., फ्रांस	3	4,10,808.00
2.	केन्स फिल्म समारोह, फ्रांस	3	9,82,548.00
3.	सिडनी समारोह, आस्ट्रेलिया	1	1,01,326.00
4.	मास्को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म्स समारोह, रशिया	2	1,87,032.00
5.	पूर्वी एशिया टी.वी. फिल्म समारोह	1	50,552.00
6.	एम.आई.एफ.ई.डी.मार्केट, इटली	1	1,09,097.00
7.	एम.आई.पी.सी.ओ.पी. '97, फ्रांस	2	5,23,254.00
8.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट, ईरान	1	74,296.00
9.	16वीं एफ.ए.जे.आर. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, ईरान	1	83,864.00
10.	अमेरिकन फिल्म बाजार, संयुक्त राज्य अमेरिका	1	1,39,674.00

उपर्युक्त समारोहों/बाजारों में भागीदारी के परिणामस्वरूप निर्यात से आय 4.55 लाख रुपए थी। उपर्युक्त समारोहों/बाजारों में भागीदारी के परिणामस्वरूप आयातित फिल्मों की बिक्री से प्राप्त आय 225.27 लाख रुपए थी।

1998-99			
1.	एम.आई.पी.टी.वी., फ्रांस	2	4,41,056.00
2.	एन.ए.टी.पी.ई' 99 संयुक्त राज्य अमेरिका	1	2,50,582.00
3.	फिल्मार्ट' 98 हांगकांग	1	66,966.00
4.	केन्स इण्टरनेशनल फिल्म समारोह, फ्रांस	2	7,43,675.00
5.	एम.आई.एफ.ई.डी.'98 मार्केट, इटली	3	6,23,789.00
6.	एम.आई.पी.सी.ओ.एम. फिल्म समारोह, फ्रांस	1	1,78,972.00

उपरोक्त समारोहों/बाजारों में भाग लेने के परिणामस्वरूप निर्यात से 41.01 लाख रुपये की आय हुई थी। उपरोक्त समारोहों/बाजारों में भाग लेने के परिणामस्वरूप आयातित फिल्मों के बिक्रय से 172.98 लाख रुपये की आय हुई थी।

ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट इण्डिया लिमिटेड

क्र.सं.	दौरे का उद्देश्य/दौरा किया गया देश	प्रतिनिधि मण्डल का संघटन	किया गया व्यय (रुपयों में)	निष्कर्ष
1996–97				
1.	प्रसारण एशिया'96 प्रदर्शनी सिंगापुर।	1	2,35,103	क्षेत्र में प्रसारक के रूप में प्रख्यात ऐसी एक परामर्शदात्री कम्पनी की मौजूदगी बनाए रखना। परामर्श में कार्य रखने वाले विभिन्न स्थानों तथा बी.ई.सी.आई.एल. द्वारा किए जा रहे टर्न-की कार्यों के लिए अनुरोध प्राप्त करना।
1997–98				
	बी.ई.सी.आई.एल. ने किसी भी विदेशी कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया।			
1998–99				
1.	प्रसारण एशिया'98 प्रदर्शनी सिंगापुर।	2	2,87,302	पिछले वर्ष में तथा इस शो के दौरान प्राप्त किए गए प्रचार के कारण बी.ई.सी.आई.एल. ने निम्नलिखित विदेशी परियोजनाओं के लिए अनुरोध प्राप्त किए। 1. कुवैत में रेडियो/टी.वी. ट्रांसमीटरों का संचालन एवं अनुरक्षण। 2. सऊदी अरब में ओ.बी. वाहन की परियोजना। 3. नेपाल में आर.डी.एस. परियोजना। 4. थिम्पू, भूटान में टी.वी. स्टूडियो की स्थापना।
2.	एशिया मीडिया सूचना और संचार केन्द्र का 7वां वार्षिक सम्मेलन	1	यात्रा एवं आवास का खर्चा एशिया मीडिया सूचना और संचार केन्द्र द्वारा वहन किया गया	क्षेत्र में सृजित व्यवसाय के लिए नए अवसर
3.	रेडियो नेपाल के लिए आर डी एस सेवा के लिए परियोजना संभाव्यता अध्ययन	1	10,948	ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग केन्सलटेंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव रेडियो नेपाल के विचाराधीन है।
4.	थिम्पू, भूटान में टी.वी. प्रसारण केन्द्र स्थापित करना।	1	36,635	भूटान ब्राडकास्टिंग सर्विसिज को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव।

कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत सिलेसिलाए वस्त्र तैयार करने वाली इकाइयां

3571. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य-वार सिलेसिलाए वस्त्र तैयार करने वाली कितनी इकाइयों को लाया गया है;

(ख) ऐसी कितनी इकाइयों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है; और

(ग) सरकार ने इन कम्पनियों/इकाइयों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली विद्युत चालित फैक्टियों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली गैर-विद्युत फैक्टिरों तथा कतिपय अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्षेत्र-दर-क्षेत्र आधार पर एक चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। अधिनियम अपनी ओर से पहल करके लागू किया जाता है। तदनुसार, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित वस्त्र इकाइयों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट करें। क.रा.बी. निगम के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित सभी वस्त्र इकाइयां जिनके पास अपेक्षित संख्या के कर्मचारी हैं, पहले से ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में शामिल हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से क.रा.बी. निगम ने 1999-2000 के दौरान 61 नए क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना के क्रियान्वयन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। नियमित रूप से सर्वेक्षण भी किए जाते हैं ताकि चूककर्ता वस्त्र इकाइयों सहित अन्य चूककर्ता प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया जा सके तथा अधिनियम के अधीन परिपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन शामिल वस्त्र विनिर्माण इकाईयां

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	72
2.	बिहार	7
3.	पश्चिम बंगाल	88
4.	दिल्ली	2408
5.	महाराष्ट्र	
	(i) मुम्बई	3175
	(ii) पुणे	93
	(iii) नागपुर	4
6.	गोवा	11
7.	असम	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	46
9.	राजस्थान	141
10.	उत्तर प्रदेश	709
11.	उड़ीसा	7
12.	तमिलनाडु	
	(i) चिन्नई	1291
	(ii) मदुरई	28
	(iii) कोयम्बटूर	1996
13.	गुजरात	110
14.	केरल	55
15.	कर्नाटक	976
16.	पंजाब	439
17..	हरियाणा	248

यूनाइटेड एयरलाइन्स द्वारा सेवा बन्द करना

3572. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन्स ने भारत में सेवाएं बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण हमारे विमानपत्तनों पर सुरक्षा उपकरणों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो हमारे विमानपत्तनों के सुरक्षा मानकों का स्तर सुधारने और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) यूनाइटेड एयरलाइंस ने वाणिज्यिक कारणों की वजह से दिनांक 3.4.99 से भारत से अपने प्रचालन निलंबित कर दिए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

1986 से पूर्व सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को पेंशन में संशोधन

3573. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.1.1986 से पूर्व रक्षा सिविलियनों और सशस्त्र सेना कार्मिकों, विशेषकर पुनर्नियोजित पेंशनरों जिन्हें पुनर्नियोजन अवधि हेतु कोई पेंशन भुगतान नहीं किया गया, के संबंध में पेशन का संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों को अब तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है उनके पुराने मामलों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या समयबद्ध कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 1.1.1986 से पहले के पेंशनभोगियों सहित रक्षा सिविलियनों और सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। विहित प्रक्रिया के अनुसार पेंशनभोगियों से यह अपेक्षित है कि वे पेंशन के संशोधन के लिए अपने आवेदन-पत्र पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित कर दी गई है। पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई गई सारणियों के आधार पर उन्हें अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को संशोधित पेंशन का भुगतान करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। पेंशन के संशोधन पर नजर रखने के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

आयुध कारखानों का कार्यनिष्पादन

3574. श्री संदीपान थोरात : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998-99 के दौरान आयुध कारखानों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों, क्षमता उपयोग, उन्नयन, विस्तार, अखिल भारतीय, विशेषकर महाराष्ट्र स्थित इकाइयों हेतु कार्यक्रम विविधीकरण के रूप में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में रक्षा उत्पादन के आधुनिकीकरण/उन्नयन/विविधीकरण हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आयुध निर्माणियों के कार्यनिष्पादन की सतत मानीटरी कलकत्ता में आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड की समग्र रूप से तथा महाराष्ट्र समूह की निर्माणियों की उत्पादन उपलब्धि तथा क्षमता इस्तेमाल संबंधी ब्यौरे नीचे की तालिका I और II में दिए गए हैं :

तालिका-I

	1998-99	1997-98		1996-97	
	उपलब्धि (उत्पादन मूल्य करोड रुपये में)	उपलब्धि (उत्पादन मूल्य करोड़ रुपये में)	क्षमता का इस्तेमाल (प्रतिशत)	उपलब्धि (उत्पादन मूल्य करोड़ रुपये में)	क्षमता का इस्तेमाल (प्रतिशत)
सभी आयुध निर्माणियां	5527.00	4400.48	66.80	3945.87	65.99

तालिका-II

	1998-99	1997-98		1996-97	
	उपलब्धि (उत्पादन मूल्य करोड रुपये में)	उपलब्धि (उत्पादन मूल्य करोड़ रुपये में)	क्षमता का इस्तेमाल (प्रतिशत)	उपलब्धि (उत्पादन मूल्य करोड़ रुपये में)	क्षमता का इस्तेमाल (प्रतिशत)
महाराष्ट्र समूह की निर्माणियां (10)	1464.11	1327.24	60.80	1282.40	61.33

आयुध निर्माणी बोर्ड ने उनके लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। वर्ष 1998-99 के लिए उपलब्धि के आंकड़े अनंतिम हैं तथा ये आकंड़े महालेखा परीक्षक की जांच के अध्यधीन होंगे। वर्ष 1998-99 के लिए क्षमता के इस्तेमाल संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

नौवीं योजनावधि के दौरान लगभग 1241 करोड़ रुपये का कुल निवेश करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड ने एक कार्य योजना तैयार की है। नौंवी योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए निम्नलिखित निवेश पहले ही कर दिया गया है :-

वर्ष	कुल निवेश (करोड़ रुपये में)
1997-98	143.96
1998-99	170.00 (अनंतिम)

योजनावधि के आगामी तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए अनुसार निवेश किए जाने का विचार है :-

वर्ष	कुल निवेश (करोड़ रुपये में)
1999-2000	200.00
2000-2001	447.00
2001-2002	280.00

सभी मौजूदा आयुध निर्माणियों के लिए उपर्युक्त निवेश स्तर में से महाराष्ट्र समूह की आयुध निर्माणियों (10 निर्माणियों) का निवेश हिस्सा लगभग 35 प्रतिशत है। महाराष्ट्र समूह की निर्माणियों में अधिकांश निवेश विस्फोटक निर्माण सुविधाएं बढ़ाने और उन्हें आधुनिक बनाने, लघु शस्त्र गोलाबारूद के निर्माण के लिए सुविधाओं, रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विशेष किस्म की अल्यूमोनियम मिश्र धातुओं के लिए सुविधाओं पर किए जाने की योजना है।

रेल परियोजनाएं

3575. **श्री रामविलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन रेल परियोजनाओं को वर्ष 1997-98 के रेल बजट में शामिल किया गया था तथा इनमें से जिन-जिन परियोजनाओं को संसद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्रियान्वयन के लिए सी.सी.ई.ए. द्वारा किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और इनकी स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) 1997-98 के बजट में शामिल और संसद द्वारा अनुमोदित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाना है और उनकी स्वीकृति की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
	नई लाइन	
1.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	स्वीकृत
2.	बारामती-लोनाद	स्वीकृत
3.	पटना-गंगा पुल	स्वीकृत
4.	आरा-सासाराम	स्वीकृत
5.	गिरीडीह-कोडरमा	स्वीकृत
6.	मुंगेर में गंगा पर रेल पुल	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
7.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	स्वीकृत
8.	बोगीबील पुल	स्वीकृत
9.	दिफू-कारोंग	स्वीकृत
10.	चण्डीगढ़-लुधियाना	स्वीकृत
11.	इटावा-मैनपुरी	स्वीकृत अभी प्राप्त की जानी है
12.	मछेरला-नालगोंडा	स्वीकृत
13.	मुनीराबाद-महबूबनगर	स्वीकृत
14.	गुलबर्गा-बीदर	स्वीकृत
15.	अंगुल-सुकिंदा रोड	स्वीकृत
16.	धर्माबरम-पेमुकोंडा वाया पुहापार्थी	स्वीकृत
17.	बेंगलूरू-सत्यामंगलम	स्वीकृत
18.	अंगामाली-साबरीमाला	स्वीकृत
19.	कोट्टयम-इरूमालि	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है

1	2	3
	आमान परिवर्तन	
1.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	स्वीकृत
2.	समस्तीपुर-सगड़िया	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है।
3.	कानपुर-कासगंज-मथुरा	स्वीकृत
4.	गोंडा-गोरखपुर	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
5.	न्यू जलपाइगुड़ी-सिलिगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव	स्वीकृत
6.	कतरवल-भैरबी	स्वीकृत
7.	कटिहार-जोगबनी	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
8.	लूनी-बरमेड़-मुनाबाओ	स्वीकृत
9.	रिवाड़ी-सादुलपुर	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
10.	श्रीगंगानगर-सरूपसर	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
11.	सिकन्दराबाद-मुदखेड़ और जनखमपेट-बोधन	स्वीकृत
12.	धर्मावरम-पकाला	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
13.	नौपाड़ा-गुनुपुर	स्वीकृति अंभी प्राप्त की जानी है
14.	मैसूर-चामराडानगर	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
15.	कोल्लम-तिरूनेलवेली-त्रिचेन्दूर और तेनकासी-विरूदुनगर	स्वीकृत
16.	मदुरै-रामेश्वरम	स्वीकृत
	दोहरीकरण	
1.	जालन्धर-पठानकोट-जम्मूतवी	स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है
2.	गुदुर-रेणिगुंटा	स्वीकृत
3.	गोइलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोंडामुंडा खण्ड)	स्वीकृत
4.	बिलासपुर-उरकुरा	स्वीकृत
5.	सीतलागढ;-लांनीगढ़	स्वीकृत
6.	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर	स्वीकृत
7.	यशवंतपुर-तुमकुर	स्वीकृत
	रेलवे विद्युतीकरण	
1.	उधना-जलगांव	स्वीकृत
2.	लुधियाना-अमृतसर	स्वीकृत
3.	भुवनेश्वर-कोट्टावलासा	स्वीकृत
	महानगर परिवहन परियोजना	
1.	भांडुप-थाने पांचवीं और छठी लाइन	स्वीकृत

50 करोड़ रु॰ की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती इसलिए ऐसी परियोजनाओं को उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं किया जाता।

इन परियोजनाओं को बजट में इस व्यवस्था के साथ किया गया था कि अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इन पर कार्य शुरू किया जाएगा। उपर्युक्त कुछ मामलों में उस समय सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट पर मंत्रालय में जांच की जानी होती है और प्रायः क्षेत्रीय रेलों से स्वीकृति प्राप्त की जानी होती है। उसके बाद योजना आयोग द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और आर्थिक मामलों संबंधी विस्तारित बोर्ड/मंत्रिमंडल समिति द्वारा विचार किया जाना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगता है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

3576. श्री राजो सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वर्ष 1992-93 में "ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास" संबंधी स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक मंत्रालय द्वारा कुल 293 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई है, जिनमें से 160 ने आज की तारीख तक काम करना शुरू कर दिया है।

इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[अनुवाद]

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1998-99 की अवधि के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थापित खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की सं.
1.	अरूणाचल प्रदेश	1
2.	असम	18
3.	बिहार	13
4.	दिल्ली	6
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	5
8.	जम्मू एवं कश्मीर	6
9.	कर्नाटक	6
10.	केरल	5
11.	महाराष्ट्र	2
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	मणिपुर	2
14.	मिजोरम	6
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	2
17.	उड़ीसा	21
18.	पंजाब	1
19.	राजस्थान	2
20.	तमिलनाडु	11
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	31
23.	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	160

लघु बचत कार्यक्रम के विज्ञापनों पर रियायतें

3577. श्री एस॰एस॰ ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु बचत कार्यक्रम के विज्ञापन पर रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित विज्ञापनों पर राज्य-वार कितनी रियायत प्रदान की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने और अधिक रियायत प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को कितनी रियायत प्रदान की गई; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी रियायत प्रदान किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले लघु बचतों से सम्बन्धित स्पाटॅस के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत की छूट देता है। यह छूट सभी राज्यों को एक समान रूप से दी जाती है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि यद्यपि आकाशवाणी को आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है तथापि, दूरदर्शन को इस प्रयोजनार्थ 75 प्रतिशत छूट देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जो उन्हें पहले से ही दी जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों राज्यों को दूरदर्शन द्वारा 75 प्रतिशत छूट और आकाशवाणी द्वारा 25 प्रतिशत छूट दी गई थी।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा दी जा रही छूट की वर्तमान दर को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रखे जाने की सम्भावना है।

कालीकट-मुंबई-कालीकट सैक्टर में और उड़ानें

3578. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से कालीकट-मुंबई-कालीकट सैक्टर पर उड़ानों की बारम्बारता में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में प्रसारण केन्द्र का कार्यकरण

3579. **श्री जार्ज ईडन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कोचीन का व्यावसायिक प्रसारण केन्द्र काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या वहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (घ) कोचीन की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा में एक स्टूडियों एवं 2×5 कि.वा. का ट्रांसमीटर है जिसका औपचारिक रूप से 15.2.96 को उद्घाटन किया गया था। तब से यह विविध भारती सेवा रिले कर रहा है। दिनांक 28.6.95 को शुरू की गई पेजिंग को बाद में दिनांक 1.8.96 से वाणिज्यिक प्रसारण सेवा ट्रांसमीटर पर स्थानांतरित कर दिया गया था और विविध भारती तथा राष्ट्रीय चैनल कार्यक्रम दोनों को 24 घंटे रिले किया गया था। वाणिज्यिक प्रसारण सेवा स्टूडियों कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इसके लिए कोई स्टॉफ स्वीकृत नहीं किया गया है।

शीतल पेय उद्योग से राजस्व

3580. **श्री एन जे॰ राठवा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न शीतल पेय योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) शीतल पेय कंपनियों विशेषकर भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है; और

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31 दिसम्बर, 1998 तक उत्पादित शीतल पेय की कीमत क्या थी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) शीतल पेय (मृदु वातित जल) के निर्माण में लगी यूनिटों को अभी तक मंत्रालय की किसी योजना/स्कीम के तहत कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ख) शीतल पेय (मृदु वातित जेल) उद्योग एक लाइसेंस मुक्त उद्योग है और उद्यमी केवल उन मामलों को छोड़कर जहां प्रतिबंधित क्षेत्र/स्थान में यूनिट की स्थापना करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है, सरकार को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश करके यूनिटों की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा शीतल पेयों (मृदु वातित जल) की सभी यूनिटों के लिए फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार शीतल पेयों (मृदु वातित जल) का उत्पादन जोकि वर्ष 1996-97 में 445 करोड़ बोटल था, वर्ष 1997-98 में बढ़कर 492 करोड़ बोटल हो गया है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर के लिए नये भवन का निर्माण

3581. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर सुविधाजनक स्थान पर स्थित है और क्या इस केन्द्र के लिए नये भवन के निर्माण संबंधी कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) उक्त केन्द्र द्वारा लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और इस संबंध में भावी योजना क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जयपुर में आकाशवाणी केन्द्र एक उपयुक्त स्थान पर स्थित है। इसे नए स्थान पर शिफ्ट करने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) आकाशवाणी जयपुर, लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम नामतः "शख्सियत", "गोरबन्द" "सहेलियां री बारी", "राजस्थली" और "कहकशां" आदि प्रसारित करता रहा है। इन कार्यक्रमों में प्रतिष्ठित हस्तियों एवं कलाकारों के साथ साक्षात्कार किया जाता है, स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द पर लक्षित कार्यक्रम, गीतों पर आधारित कार्यक्रम तथा लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों के कलाकारों के लोग संगीत की विभिन्न तेजी से विलुप्त होती जा रही शैली को अभिलेखागार प्रयोजनार्थ रिकार्ड करने हेतु राज्य की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था "जवाहर कला केन्द्र" के सहयोग से एक परियोजना पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

जर्मन डेवलपमेंट बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण

3582. **डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे दो वर्ष पहले जर्मन डेवलपमेंट बैंक के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा मंजूर किए गए 185 मिलियन डालर (ड्यूक मार्क) का ऋण प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऋण पर प्रतिमाह प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन परियोजनाओं जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। । अगस्त, 1997 को हस्ताक्षरित ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटेनस्टेल्ट फर विडरफबाऊ (के.एफ.डब्ल्यू) जर्मनी ने दिल्ली और कानपुर के बीच सिगनल व्यवस्था के आधुनिकीकरण की परियोजना के लिए 185 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण स्वीकृत किया है। ऋण का आहरण प्रौद्योगीकरण विकल्प सहित परियोजना के अंतिम चरण पर रेल मंत्रालय और के.एफ.डब्ल्यू के बीच समझौते के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

(ग) ऋण समझौते के अनुसार बिना वितरित ऋण की राशि की 0.25 वार्षिक का वचनबद्धता प्रभार देय है। बहरहाल सरकार ने इस ऋण के लिए अभी तक के.एफ.डब्ल्यू./जर्मनी को किसी वचनबद्धता प्रभार का भुगतान नहीं किया है क्योंकि वचनबद्धता प्रभार का पहला भुगतान प्रथम ब्याज भुगतान के साथ देय होगा।

(घ) सरकार में मौजूदा कठिनाईयों और भारतीय रेल की परिचालनिक परिस्थितियों के दृष्टिगत परियोजना के क्षेत्र में आशोधन का प्रस्ताव किया है और इस पर सहमति देने के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से अनुरोध कर रही है।

कोल्लम-सेनगोतई रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3583. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्लम-सेनगोतई मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) यह कार्य कब तक शुरू होने और पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कोल्लम-शेलगोट्टै-तिरूनेलवेली-तिरूचेन्दूर और तैनकासी-विरूदुनगर परियोजना की अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपये है और कार्य शुरू करने के लिए 1999-2000 के बजट में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंधन किए जा रहे हैं। पूरा करने का कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्य में प्रगति की जाएगी तथा पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आगामी वर्ष में संसाधन उपलब्ध हों।

केबल और उपग्रह उद्योग की मांगें

3584. **श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केबल और उपग्रह की आवश्यकता पूरी करने के लिए केबल के बढ़ते प्रचार-प्रसार और उसके परिणामस्वरूप हार्डवेयर उद्योग की असमर्थता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा के चिकित्सालय और औषधालय

3585. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा के कितने चिकित्सालय एवं औषधालय कहां-कहां स्थित है; और

(ख) इनमें से किन-किन चिकित्सालयों और औषधालयों में सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. आदि जैसी उपचार सुविधा उपलब्ध है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) बेलटाटा, गुवाहटी में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है। औषधालयों के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालयों में सीटी स्कैन, एम.आर.आई. आदि के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

तथापित दूसरे अस्पतालों के माध्यम से लाभाधिकारियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है तथा इस संबंध में नियमानुसार प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों का ब्यौरा

असम

1.	उजानबजान	गुवाहटी
2.	कालापहाड़	गुवाहटी
3.	नूनमती	गुवाहटी
4.	दिसपुर	गुवाहटी
5.	नारांगी	गुवाहटी
6.	चंदरापुर	गुवाहटी
7.	झालूकबोरी	गुवाहटी
8.	अमीन गांव	गुवाहटी
9.	लोकरा	गुवाहटी
10.	सिलघाट	
11.	चाऊदुर	
12.	तेजपुर	
13.	धुबडी	
14.	जोगीधोपा-धुबड़ी	
15.	जोरहाट	
16.	मुसीयानी-जोरहाट	
17.	तिनसुसकिया	
18.	माकुम-तिनसुकिया	
19.	एडल-तिनसुकिया	
20.	दिबसुधर-तिनसुकिया	
21.	मंधेसिता तिनसुकिया	
22.	मोढो तिनसुकिया	
23.	जांयपुर तिनसुकिया	
24.	नवगांव	
25.	जागीसोद-नवगांव	
26.	बोंगियागांव	

मेघालय

1.	कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, शिलांग-1	लोअर लाखेमेयर

रूस के रक्षा मंत्री की यात्रा

3586. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री मुगन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के रक्षा मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके साथ किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) उन वार्ताओं के क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रूसी संघ के रक्षा मंत्री मार्शल आई.डी. सर्गेयेव ने 19 से 23 मार्च, 1999 तक भारत का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा से जुड़े अन्य मामलों सहित रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने और इसे और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा, रूसी संघ के सैन्य शैक्षिक संस्थानों में भारतीय सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक सामान्य करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

रूस के रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री से मुलाकात की। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की।

रक्षा प्रणालियों पर "वाई-2के" का प्रभाव

3587. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की रक्षा प्रणाली पर "वाई 2 के" के प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रक्षा प्रणालियों में वाई-2के के अनुपालन तथा वाई-2के संबंधी समस्याओं का पता लगाने संबंधी मुद्दे पर मंत्रालय में समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

2. रक्षा प्रणालियों में वाई-2के संबंधी मुद्दों की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखितानुसार व्यवस्था की गई है :-

(1) महत्वपूर्ण ई डी पी प्रणालियॉं (प्रचालन व अनुप्रयोग सॉफ्वेयर सहित)

(2) माल-सूची प्रबंधन

(3) वेतन-पत्रक प्रबंधन

(4) रक्षा सेनाओं की वे अंतस्थापित जिन पर वाई-2के समस्याओं का दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

3. रक्षा मंत्रालय में रक्षा सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणियों तथा अंतर सेवा संगठनों के लिए उपर्युक्त मुद्दों का समाधान खोजा जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न मूल उपस्कर विनिर्माता विक्रेताओं से संपर्क किया गया है तथा रक्षा अनुसुधान व विकास संगठन व भारत इलेक्ट्रीकल लिमिटेड बंगलौर की केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को लेकर गठित वाई-2के विशेषज्ञ सेल द्वारा परिशोधन के लिए अनुसंधान व विकास संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं।

4. सभी महत्वपूर्ण ई डी पी प्रणालियों को छांटकर उनमें से अधिकांश को वाई-2के अनुपालन के लिए पहले ही परिशोधित और संधोधित कर दिया गया है। मालसूची व वेतन पत्रक प्रबंधन के मामले में भी ऐसा ही किया गया है।

5. अंतःस्थापित प्रणालियों के मामले में शस्त्र, टोही व दिशा निर्देशन प्रणालियां सम्मिलित हैं। अंतःस्थापित प्रणालियों से जुड़ी वाई-2के समस्याएं बड़ी जटिल हैं। इनकी पहचान व समाधान के लिए अत्यंत दक्षता तथा मूल उपस्कर विनिर्माताओं की अधिक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इन प्रणालियों के संबंध में कार्य चल रहा है।

6. विभिन्न संगठनों में जैसे ही परिशोधन कार्य पूरा हो जाता है, उस कार्य का सत्यापन करने के लिए तकनीकी परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

हांगकांग के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

3588. श्री मदन पाटील :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी हवाई सेवायें हांगकांग तक बढ़ाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापनों पर व्यय

3589. श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय और मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विमान सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार के बदले मीडिया के द्वारा विज्ञापन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) ऐसे व्ययों में मितव्ययता सुनिश्चित करने, कुल रिक्त क्षमता, साल-दर-साल विमान यातायात और विमान के लिए खाली समय में वृद्धि के लिए क्या कदम उठायें गए या उठायें जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीविजन ट्रांसमीटरों को चालू करना

3590. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री अजीत जोगी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान राज्य-वार ट्रांसमीटर चालू करने पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) इन ट्रांसमीटरों के रख-रखाव और प्रचालन पर वर्ष-वार कितना व्यय किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान चालू किए गए ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना की पूंजीगत लागत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये है जबकि एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की लागत लगभग 1 करोड़ रु॰ और एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की लागत 0.8 करोड़ रु॰ है।

(ख) एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर लगभग 45 लाख रुपये, एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पर 20 लाख रु॰ तथा एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पर 3 लाख रु॰ वार्षिक व्यय होता है।

विवरण

वर्ष 1998 तथा 1999 (मार्च, 1999 तक) के दौरान चालू किए गए टी.वी. ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या

राज्य	उ.श.ट्रा	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल
आन्ध्र प्रदेश	–	7	1	8
अरूणाचल प्रदेश	–	1	20	21
असम	–	3	–	3
बिहार	–	4	–	4
गुजरात	–	9	1	10
हरियाणा	–	1	–	1
हिमाचल प्रदेश	–	2	7	9
जम्मू एवं कश्मीर	–	6	5	11
कर्नाटक	1	3	1	5
केरल	–	1	–	1
मणिपुर	–	–	2	2
मध्य प्रदेश	–	5	2	7
महाराष्ट्र	–	6	3	9
मिजोरम	–	1	–	1
उड़ीसा	1	4	6	11
नागालैण्ड	–	–	1	1
पंजाब	1	1	–	2
राजस्थान	–	1	2	3
सिक्किम	–	–	2	2
तमिलनाडु	–	2	–	2
त्रिपुरा	–	2	–	2
उत्तर प्रदेश	–	7	5	12
पांडिचेरी	–	1	–	1
पश्चिम बंगाल	–	–	1	1
	3	67	59	129

[हिन्दी]

रेल यात्री पत्रिका

3591. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का विचार राज्यभाषा के क्रियान्वयन के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य को देखते हुए, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य सभी विभागों का मार्ग निर्देशन करने तथा "रेल यात्री" पत्रिका प्रकाशित करने का है, तथा 14 सितम्बर, 1999 से राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह आरम्भ करने का भी विचार है; और

(ख) क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम की रूप रेखा कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। रेल यात्री पत्रिका को यात्रियों के लिए गाड़ी में पढ़ने के लिए प्रारंभ में शताब्दी/राजधानी गाड़ियों में शुरू किया जाएगा। यह पर्यटन संस्कृति, भोजन, स्वास्थ्य, साहित्य, कला, जीवन शैली आदि तिमाही विशेषांकों वाला अंक होगा, प्रत्येक अंक में परिवहन संबंधी विषयों पर समर्पित एक कहानी होगी। पत्रिका द्विभाषिक अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में होगी। कुछ लेख अंग्रेजी में होंगे जबकि अन्य लेख हिंदी में होंगे। 14 सितम्बर, 1999 से राजभाषा का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

(ग) रूप रेखा जून, 1999 के अंत तक तैयार हो जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वेतन नीति

3592. श्री तथागत सत्पथी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई राष्ट्रीय वेतन नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नई राष्ट्रीय वेतन नीति को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में सेना भर्ती केन्द्र

3593. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के भागलपुर जिले में सेना भर्ती केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 01 अप्रैल, 1998 से लागू संशोधित भर्ती नीति के अंतर्गत शाखा भर्ती कार्यालय की अवस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सभी भर्ती, संबंधित जोनल भर्ती कार्यालय द्वारा तैनात किए गए भर्ती दलों द्वारा केवल खुली रैलियों (ओपन रैलीज) के जरिए की जाती है।

समूह "ख" के अधिकारियों को समूह "क" के पदों के लिए परिकलन प्रक्रिया

3594. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूह "ख" के अधिकारियों की समूह "क" के रिक्त पदों पर प्रवेश के लिए परिकलन करने हेतु क्या प्रक्रिया/फार्मूला निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) इस प्रक्रिया में अंतिम संशोधन कब किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कनिष्ठ वेतनमान ग्रुप "क" की रेल सेवा में प्रत्येक वर्ष भरे जाने वाले पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती और पात्र ग्रुप "ख" रेलवे अधिकारियों की पदोन्नति समान रूप से विभाजित किए जाते हैं।

(ख) रेलवे ग्रुप "क" सेवा (आई.आर.पी.एस. के अलावा जहां यह अनुपात 50:50 है) के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती का अनुपात 60:40 था। अनुपात को 31.7.97 से परिवर्तित करके सभी ग्रुप "क" की सेवाओं के लिए 50:50 कर दिया गया है। इससे ग्रुप "ख" के और अधिक अधिकारियों के ग्रुप "क" अधिकारी बनने की संभावना है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

3595. श्री के॰एस॰ राव :

श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिनियमों में किए जाने वाले संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पाद अधिनियम, 1970 और श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में सामाजिक भागीदारों और आर्थिक सुधारों के साथ सामंजस्य की जरूरतों के आधार पर विभिन्न संशोधन प्रस्तावित हैं। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित किए जाने से पूर्व संशोधन के प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया कार्रवाई की जाती है। संशोधनों का ब्यौरा अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के बाद, सार्वजनिक किया जा सकेगा।

निजी क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन

3596. डा॰ असीम बाला :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री वी॰वी॰ राघवन :

श्री कमल नाथ :

डा॰ शकील अहमद :

श्री नरेश पुगलीया '

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1999 "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्राइवेट ट्रेन्स कुडबी ऑन इंडियन ट्रैक्स नैक्स्ट इयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी संचालकों को कौन-कौन से मार्ग दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1994 में आमंत्रित विश्वव्यापी बोलियों के आधार पर मै. हॉलीडे रिसोर्ट (इंडिया) लि., चेन्नई को निम्नलिखित सैक्टरों में पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन के लिए मंशा पत्र दिए गए हैं :-

1. दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी (खजुराहो) वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली।
2. बेंगलूरू-मैसूर-चेन्नई-कोडैकनाल रोड-कन्याकुमारी-तिरूवनंतपुरम-कोचीन-मेट्टुपालयम (ऊटी)-बेंगलूरू।

(घ) समझौते के अनुसार ऑपरेटर भारतीय रेलों की ढुलाई प्रभार तथा सकल टर्न ओवर का कुछ प्रतिशत अदा करेगा। गाड़ी पर पूंजी निवेश ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा।

स्क्रीन से एयर इंडिया के विमान का गायब होना

3597. **श्री आर•एस• गवई :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री मोती लाल वोरा :

श्री आर• साम्बासिवा राव :

श्री सुरेश वरपुडकर :

डा• सरोजा वी• :

श्री एम• वागा रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" "एयर इंडिया का विमान 40 मिनट तक लापता रहा" और दिनांक 4 मार्च, 1999 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी.जी.सी.ए. प्रोब लाइकली इन्टू मिसिंग एयर इंडिया प्लैन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार का तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 21 फरवरी, 1999 को भारतीय समय 1005 बजे के लगभग क्षेत्र और टावर आवृत्ति का रेडियो टेलीफोन संचार सम्पर्क पूर्ण रूप से बन्द हो गया था। फ्रीक्वेंसी को की जा रही पावर सप्लाई के बंद हो जाने के कारण पावर स्टेबलाइजर के दोषपूर्ण कार्य करने का कारण था जिसके बाद पावर हाऊस से न तो वाणिज्यिक सप्लाई और न ही वैकल्पिक सप्लाई हो सकी, स्टेबलाइजर से प्राप्त हो रही सप्लाई ट्रांसमीटरों का उपलब्ध नहीं हो सकी थी। इससे वैकल्पिक बैटरी सप्लाई को भी स्विच ओवर नहीं किया जा सका। तथापित, चूंकि टावर की फ्रीक्वेंसी (118.1 एमएचजेड) कार्य कर रही थी, जो अलग बैटरी बैक अप पर थी । अतः इसका प्रयोग एयर इंडिया के विमान और तीस ऐसे अन्य विमानों के लिए किया गया जिन्होंने बिना किसी दुर्घटना के दिल्ली विमानपत्तन पर अवतरण किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एरिया और पहुंच फ्रीक्वेंसी के लिए बैटरी बैक-अप प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। इससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा।

संयुक्त अरब अमीरात से रक्षा सहयोग

3598. **डा• टी• सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री एम• वागा रेड्डी :

श्री आर• साम्बासिवा राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फ्रांस की खाड़ी में रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने प्रयास के रूप में पहली बार अपने विमान वाहक पोत विराट को संयुक्त अरब अमीरात भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आबू धाबी के लिए रवाना हुए नौसेना के तीन जहाजों ने संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के जहाजों के साथ युद्धाभ्यास किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या एक दूसरे के प्रशिक्षण संस्थानों में रक्षाकर्मियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास कराए जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ रक्षा वार्ता की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो भारत की संयुक्त अरब अमीरात किस सीमा तक एक दूसरे को रक्षा सहयोग के लिए राजी हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) तीन भारतीय नौसेना पोत 9-12 मार्च, 1999 के दौरान आबू धबी गए थे किंतु उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के पोतों के साथ किसी भी अभ्यास में भाग नहीं लिया। तथापि, संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वायुयान वाहक पर किए गए एक उड़ान प्रदर्शन को देखा था।

(ग) और (घ) संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के साथ रक्षा सहयोग एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

ग्वालियर-छपरा एक्सप्रैस रेलगाड़ी की दुर्घटना

3599. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जनवरी, 1999 को मैजापुर के निकट गोंडा-लखनऊ रेल लाइन पर 1144 अप ग्वालियर-छपरा एक्सप्रैस रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने जानोमाल का नुकसान हुआ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। 31.1.1999 को 1144 अप की ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। बहरहाल, 30.1.99 को 1144 अप छपरा-ग्वालियर मेल गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के एकल ब.ला. खंड गोंडा-बाराबंकी पर गोंडा कचहेरी और मैजापुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई थी।

(ख) दुर्घटना के कारण की रेल सुरक्षा आयुक्त/पूर्वोत्तर सर्किल द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जान माल और रेल संपत्ति की हानि इस प्रकार है :-

हताहत-मारे गये	-	1
गंभीर रूप से घायल	-	4
मामूली रूप से घायल	-	10

1,05,66,300 रु॰ की क्षति हुई थी।

(घ) इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :-

(1) चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेलपथ की गहन जांच की जाती है।

(2) बेहतर और उन्नत रेलपथ अनुरक्षण के लिए परम्परागत मैन्युअल अनुरक्षण के स्थान पर मशीनों द्वारा रेलपथ का अनुरक्षण उत्तरोत्तर शुरू किया जा रहा है।

(3) हाथ से किए जाने वाल यू.एस.एफ.डी. टेस्टरों तथा एस. पी.यू.आर.टी. (स्वनोदित पराश्रव्य रेल परीक्षण कार) द्वारा पूर्व निर्धारित बारम्बारता के अनुसार पटरियों की नियमित जांच की जा रही है।

(4) भेदय मौसमों यथा ग्रीष्म, मानसून और सर्दी के महीनों के दौरान गैंग मैनों द्वारा रेलपथ पर नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है।

(5) दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए वरिष्ठ अधिकारियों सहित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की जाती है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए रेल कर्मचारियों पर सेवा के निलंबन/बर्खास्तगी की सीमा तक कड़ी शास्ति लगाई जा रही है।

(6) पटरियों की गुणवत्ता में सुधार हेतु उन्नत सुविधाओं की स्थापना तथा शुरू करने के लिए रेलें सेल/बी.एस.पी. का प्रभावशाली ढंग से अनुसरण कर रही है।

खमरिया आयुध कारखाना में अवकाश यात्रा रियायत के फर्जी दावे

3600. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश में खमरिया आयुध कारखाने के कतिपय कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत के फर्जी दावे किए जाने के कारण मुअत्तल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु किसी नीति पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आयुध निर्माणी, खमरिया के 18 कर्मचारियों ने कपटपूर्ण तरीके से छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया था। इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और केन्द्रीय सिवित सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सुविधाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए नियम और प्रक्रियाएं पहले ही विद्यमान हैं।

2. भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए आयुध निर्माणी, खमरिया द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :-

(1) प्रत्येक कर्मचारी, जिसे छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो अधिकारी द्वारा उसे सलाह दी जाती है कि यदि यात्रा न करने के मामले में वह ली गई पेशगी को समय पर वापस नहीं करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्क कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी, जिसे छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी स्वीकृत की गई है, की यात्रा आरंभ करने से पूर्व यात्रा

टिकट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होती है। टिकट नं॰ कार्यालय में बनाए गए रजिस्टर में नोट किया जाता है।

(3) नियमों के अंतर्गत, छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं का लाभ उठाने वाले कर्मचारी को यात्रा आरंभ करने के लिए एक महीने के अंदर यात्रा संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करने होते हैं। ब्यौरे प्राप्त करने के बाद निर्माणी कुछ यादृच्छिक तौर पर चुने गए टिकटों को पुष्टि के लिए स्थानीय रेलवे कार्यालय को भेजती है।

3. आयुध निर्माणी, खमरिया द्वारा उठाए गए उक्त कदमों को एक परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों की जानकारी में लाया गया है।

बंगलौर में पार्किंग हेतु रक्षा भूमि

3601. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर निगम ने रक्षा मंत्रालय से बंगलौर में परेड ग्राउंड का एक हिस्सा वाहनों की पार्किंग हेतु मांगा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि बंगलौर शहर निगम को सौंपने का प्रस्ताव है; यदि कोई है; और

(ग) बंगलौर शहर निगम इसके बदले में मुआवजे के तौर पर कितनी धनराशि का भुगतान करेंगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वाहनों की पार्किंग हेतु परेड ग्राउंड में 300 × 700 भूमि दिए जाने के लिए बंगलौर महानगर पालिका के महापौर की ओर से एक प्रस्ताव नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री के माध्यम से मार्च, 1999 में प्राप्त हुआ है। इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

पाकुड़ स्टेशन में आरक्षण कोटा

3602. श्री सोम मरांडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मगध-विक्रमशिला एक्सप्रेस एवं फरक्का-भिवानी एक्सप्रेस में पाकुड़ के लिए कितना कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) क्या दोनों रेल गाड़ियों में पाकुड़ के लिए आवंटित कोटा यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्टेशन में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इस समय पाकुड़ स्टेशन पर मगध-विक्रमशिला एक्सप्रेस और माल्दा टाउन-भिवानी-फरक्का एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में 2 बर्थों का कोटा उपलब्ध है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल परियोजना का खटाई में पड़ना

3603. श्री सत्यपाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1999 के "दि ट्रिब्यून" के चंडीगढ़ संस्करण में "रेल प्रोजक्ट्स रन्स इनटू रफ वेदर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है और यह कब तक पूरी होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) यह खबर चंडीगढ़-लुधियाना नयी लाइन परियोजना से संबंधित है। चंडीगढ़ प्रशासन से पहले 30 लाख रु॰ प्रति एकड़ की उच्च दर से इस गलियारे के लिए अपेक्षित सरकारी भूमि की कीमत मांगी थी। उनके द्वारा मामले पर अब पुनर्विचार किया गया है और भूमि की दर को कम करके एक लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया है। अब कोई समस्या नहीं है और भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है।

(ग) भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के लिए अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

लम्बी दूरी की पेट्रोल पनडुब्बी

3604. श्री रवि सीताराम नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार पाक मे स्टील मच ओवर इंडिया इन लांग रेंज पैट्रोल सबमेरीन" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) यह विदित है कि पाकिस्तान फ्रांस से तीन अदद पनडुब्बियों का अर्जन कर रहा है जिनकी सुपुर्दगी वर्ष 1999-2004 के बीच की जानी है। इसके अतिरिक्त यह भी विदित है कि केवल तीसरी पनडुब्बी में ही 'एयर इंडिपेन्डेट प्रोपल्शन प्रणाली' फिट किए जाने की संभावना है।

(ग) पनडुब्बियों का अर्जन करने और उनका स्वदेशी रूप से निर्माण करने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इस संबंध में और सूचना प्रस्तुत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

3605. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में मार्च, 1998 से मार्च, 1999 के बीच चतुर्थ श्रेणी में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलग-अलग कितने उम्मीदवार हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चिनाव पर पुल का निर्माण

3606. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) ने जम्मू और कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में चिनाब पर दूसरे पुल का निर्माण आठवें दशक के अंत से अब तक पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी आरंभिक अनुमालित लागत कितनी थी और इसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या थी तथा इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इस पर आज तक कितना कार्य हुआ है; और

(घ) इसके पूरा होने की संशोधित लक्ष्य तिथि क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और इसमें असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) इस पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 1978 से आरंभ किया गया था। इसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) धारा के तीव्र प्रवाह के कारण स्तंभ लगाने के वास्ते बनाए गए गड्ढ़ों के बह जाने और/अथवा भर जाने की वहज से सॉविदाकार पुल पूरा नहीं कर सके।

(ग) इस निर्माण कार्य की आरंभिक लागत 77 लाख रुपए प्राक्कलित की गई थी। यह कार्य दिसंबर 1981 तक पूरा किया जाना था। जून 1994 में दूसरे संविदाकार द्वारा इस परियोजना को छोड़े जाने के समय तक 193.51 लाख रुपए का निर्माण कार्य निष्पादित किया जा चुका था।

(घ) तकनीकी समिति, जिसको पुल के निर्माण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए गठन किया गया था, ने यह सिफारिश की है कि बहती धारा में स्तंभों का निर्माण न कराया जाए। सीमा सड़क संगठन पुल की संशोधित योजना बना रहा है। इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने और कार्य के वास्ते संविदा किए जाने के बाद ही अनुमानित लागत और उसे पूरा किए जाने की संशोधित निर्धारित तारीख का पता चलेगा। विलंब के कारणों को इस प्रश्न के उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया की परिचालन लागत

3607. डा॰ सुशील इन्दौरा :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया की उड़ानों की परिचालन लागत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो पृथकतः तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुण्ड हेतु वायुयान सेवा

3608. श्री पंकज चौधरी :

श्री राम पाल सिंह :

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुण्ड के लिए वायुयान सेवा आरम्भ करने हेतु सरकार किसी प्रस्ताव पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड में विमानपत्तन नहीं हैं, इसलिए यात्री विमान से विमान सेवा प्रचालित करना संभव नहीं है। तथापि, गढ़वाल मंडल विकास निगम की बद्रीनाथ-केदारनाथ-रूद्रप्रयाग सेक्टर में हेलीकाप्टर सेवाएं आरंभ करने की योजना है जिसके लिए पवन हंस हेलीकाप्टर लि॰ वेट लीजआधार पर एक हेलीकाप्टर (5 सीटर) की व्यवस्था करेगा। हेलीकाप्टर को पट्टा पर लेने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम से अनुमोदन प्राप्त होने पर 15 मई, 1999 से शुरू में एक महीने की अवधि के लिए सेवाएं शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल में रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

3609. **श्री के॰ करूणाकरन :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चालू परियोजनाओं के तहत रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के संबंध में परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) ब्यौरा निम्नानुसार है :

दोहरीकरण

(1) *तिरूवनंतपुरम-कोल्लम* :- 31.3.1999 तक 64 कि.मी. में से 27 कि.मी. पूरा हो गया है। 31.3.1999 तक 106.16 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और 1999-2000 में 26.98 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। यह कार्य मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा।

(2) *मंगलोर-शोरूवब्बूर* :- इस दोहरीकरण के कार्य को तेजी से प्रगति की जा रही है और 1997-98 में चार ब्लॉक खंड पूरे किए गए थे (29 कि.मी.) वर्ष 1998-99 में अन्य 48 कि.मी. पूरे किए गए थे। 1999-2000 के दौरान अन्य 68 कि.मी. पूरे किए जाएंगे। 31.3.1999 तक 184.48 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

रेल विद्युतीकरण :

ईरोड-एर्णाकुलम खंड :- वालायार-चौवारा खंड (164 कि.मी.) पूरा हो गया है। चौवारा से एर्णाकुलम 30 कि.मी. के शेष खंड को मार्च 2000 तक पूरा करने की योजना है। 31.3.1999 तक 161.60 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। 1999-2000 के बजट के 36 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम :- यह कार्य 157 करोड़ रुपए की लागत पर 1999-2000 के बजट में शामिल किया गया है और अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात शुरू किया जाएगा।

रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं

3610. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान जिन-जिन रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा किया जाना था उनमें से अभी तक कितनी परियोजनाएं पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) इन्हें पूरा किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं में परियोजना-वार कितनी लागत शामिल है;

(घ) परियोजनावार लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कोई भी रेल विद्युतीकरण परियोजना, जिसे 1997-98 में पूरा किया जाना था, अभी तक लम्बित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संवाददाता सम्मेलन में भूतपूर्व एडमिरल द्वारा लगाए गए आरोप

3611. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1999 के 'पायनीर' में 'भागवत ड्रैग्स मलिक्स नेम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने 'भागवत ड्रैग्स मलिक्स नेम' नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है जो 23 फरवरी, 1999 को 'पायनीयर' में प्रकाशित हुआ था। सेनाध्यक्ष जनरल वी.पी. मलिक के विरुद्ध लगाए गए आरोप इस प्रकार थे : (1) जनरल मलिक ने मुंबई में सेना दिवस अलंकरण समारोह में श्री बाल ठाकरे को बुलाया; (2) जनरल मलिक ने 28.5.98 को वीर सावरकर पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की, और (3) जनरल मलिक की सेवा बढ़ाई गई।

(2) उपर्युक्त रिपोर्ट दिल्ली में 22.02.99 को प्रैस क्लब ऑफ इंडिया में पूर्व एडमिरल विष्णु भागवत द्वारा मीडिया के साथ बातचीत करने के परिणामस्वरूप प्रैस में छपी थी। सेनाध्यक्ष जनरल वी.पी. मलिक ने पूर्व एडमिरल विष्णु भागवत द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और इस संबंध में उन्होंने 9.3.99 को एक प्रैस वक्तव्य जारी करके स्थिति स्पष्ट की :

(1) सेना दिवस अलंकरण समारोह, एक सार्वजनिक समारोह था जो 15 जनवरी, 1996 को मुंबई में आयोजित किया गया था, उस समय जनरल वी पी मलिक, जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिण कमांड थे, और इस समारोह में सैन्य तथा सिविल लोगों ने भाग लिया था। यह परेड शिवाजी पार्क में आयोजित की गई थी ताकि जनसाधारण हमारे बहादुर और असाधारण सिपाहियों के सम्मान में आयोजित की गई परेड और अलंकरण समारोह देख सकें। इस परेड का प्रचार मीडिया / बैनरों द्वारा करके जनसाधारण को आमंत्रित किया गया था। राज्य सरकार के पदाधिकारियों, सार्वजनिक नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को बड़ी संख्या में आमंत्रण पत्र भी जारी किए गए थे। श्री बाल ठाकरे के परिवार के कुछ सदस्य इस परेड को देखने आए थे। समारोह के अंत में श्री बाल ठाकरे वहां आए और वीरता पुरस्कार विजेताओं के निकट संबंधियों से मिले। जनरल मलिक ने स्पष्ट किया कि वे श्री बाल ठाकरे से इस समारोह से पहले और बाद में कभी नहीं मिले और पूर्व एडमिरल भागवत ने आमंत्रिती के रूप में स्वयं यह पूर्ण परेड और समारोह तथा उससे जुड़े अन्य समारोह भी देखे थे । पूर्व एडमिरल भागवत ने यह मुद्दा जनरल मलिक के साथ न तो उस अवसर पर और न ही उसके बाद कभी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उठाया।

(2) **वीर सावरकर पुरस्कार**

यह पुरस्कार, स्वतंत्र भारत की रक्षा तैयारी से संबंधित विषयों पर सामरिक अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लोकोपकार की भावना से, एक निजी व्यक्ति श्री माधव केशव रानाडे द्वारा स्थापित रूना विमोचन ट्रस्ट द्वारा चलाया गया है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत बचत में से 10 लाख रुपए दान किए थे। यह पुरस्कार सामरिक अध्ययन संबंधी केन्द्र के तत्वावधान में दिए जाते हैं। पूर्व नौसेनाध्यक्ष, एडमिरल जे.जी. नाडकर्णी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय समिति बनाई गई थी जिसमें ले॰ जनरल बी.टी. पंडित (सेवा निवृत्त) और एयर मार्शल एस. कुलकर्णी (सेवा निवृत्त) भी थे। इस समिति को ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या संस्थान का चयन करना था जिन्होंने सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहला वीर सावरकर पुरस्कार श्री के॰ सुब्रहमण्यम ने प्राप्त किया था और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एस॰ रॉय चौधरी ने 1997 में इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की थी। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। दूसरे पुरस्कार समारोह के लिए जनरल मलिक से उसकी अध्यक्षता करने के लिए अनुरोध किया गया था जो उन्होंने 28 मई 1998 को की थी। न तो पुरस्कार संचालन ट्रस्ट का और न ही पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का राजनीति से कोई संबंध है।

(3) पूर्व नौसेनाध्यक्ष द्वारा जनरल मलिक की सेवा अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में लगाए गए आरोप की सच्चाई यह है कि सरकार ने रक्षा सेनाओं के सभी कार्मिकों की सेवा निवृत्त की आयु में दो वर्ष की बढ़ोत्तरी करने का नीतिगत निर्णय मई 1998 में तीनों सेनाओं की विशिष्ट सिफारिश के आधार पर लिया था। यह निर्णय सिविल कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में दो वर्ष की बढ़ोतरी करने के साथ लिया गया था। रक्षा सेनाओं के तीनों सैन्य अध्यक्षों के संबंध में सरकार ने 60 वर्ष की आयु या 3 वर्ष का कार्यकाल, इनमें से जो भी पहले हो, को संशोधित करके 62 वर्ष की आयु या तीन वर्ष का कार्यकाल, इनमें से जो भी पहले हो, किया गया था। जनरल मलिक को कोई विशेष सेवा विस्तार नहीं दिया गया था।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कम किराया प्रभारित किया जाना

3612. श्री के॰ कृष्णामूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण घरेलू विमानपत्तनों के उपयोग हेतु इंडियन एयरलाइन्स से निजी एयरलाइनों की तुलना में बहुत कम किराया ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिरूअनंतपुरम तथा कालीकट विमानपत्तन

3613. श्री पी॰ शंकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूअनंतपुरम तथा कालीकट विमानपत्तन की राजस्व अर्जित करने तथा यात्रियों की "हैंडलिंग" करने की दृष्टि से स्थिति क्या है;

(ख) क्या कालीकट विमानपत्तन में "नाईट लैडिंग सिस्टम" उपलब्ध कराये जाने सहित इसका विकास किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी समय सीमा की आवश्यकता होगी?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) 1997-98 में तिरूवनन्तपुरम और कालीकट विमानपत्तनों के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

	तिरूवनन्तपुरम	कालीकट
राजस्व	25.28 करोड़ रुपए	7.28 करोड़ रुपए
व्यय	26.37 करोड़ रुपए	5.75 करोड़ रुपए
लाभ/हानि	1.09 करोड़ रुपए (हानि)	1.53 करोड़ रुपए (लाभ)
यात्री हैंडलिंग	11.45 लाख	5.00 लाख

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कालीकट विमानपत्तन पर आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार किये हैं :-

(1) धावनपथ के 6000 फुट से 7500 फुट पर विस्तार करने का कार्य पूरा हो गया है और यह चालू हो गया है और इसे आगे 9000 फुट तक विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है और इसके जनवरी, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) वर्तमान धावनथ पर रात्रि अवतरण सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं परन्तु आस-पास के वातावरण के कारण, नागर विमानन महानिदेशालय ने कालीकट में रात्रि प्रचालन किये जाने की अनुमति नहीं दी है। तथापि, धावनपथ के 9000 फुट तक विस्तार हो जाने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसकी संवीक्षा की जाएगी।

कर्नाटक में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

3614. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने शिमोगा-होलेहोन्नूर मार्ग और शिमोगा होन्नाली मार्ग के रेलवे फाटकों पर दो सड़क ऊपरिपूलों का निर्माण का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कब से लंबित हैं;

(ग) राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु कितनी धनराशि की मांग की है; और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक मंजूर कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी का स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान

3615. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी के क्षेत्रीय स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) कहां-कहां स्थापित है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1999-2000 के दौरान कुछ नए स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान विशेषतः श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दिल्ली और कटक में दो कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों (कार्यक्रम) के अलावा आकाशवाणी के 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) अहमदाबाद, हैदराबाद, शिलांग, लखनऊ तथा तिरूवनन्तपुरम में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णा में डीज़ल लोको शेड का बंद किया जाना

3616. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-मध्य रेलवे के पूर्णा में डीज़ल लोको शेड को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। पूर्णा में कोई डीज़ल शेड नहीं है। बहरहाल, एक मीटर लाइन का सैटेलाइट डीज़ल शेड जो आमान परिवर्तन के कारण बेकार हो गया है, बड़ी लाइन के डीज़ल इंजनों की छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए आशोधित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कन्नूर हवाई अड्डा

3617. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नूर हवाई अड्डे की स्थापना हेतु कोई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रस्तावित हवाई अड्डे को सरकारी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम या निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक प्रारंभिक तकनीकी साध्यता अध्ययन किया गया है। एक उच्च स्तरीय दल ने 15.12.1998 को मूरखापुरम्बा के निकट एक स्थल का दौरा भी किया था और उसने कन्नूर में नये विमानपत्तन के निर्माण के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष दिए हैं :-

(1) 08/26 के विमुखीकरण सहित केवल 6600 फुट लम्बा एक धावनपथ संभव है।

(2) सभी मौसम में प्रचालनों के लिए धावनपथ के पहुंच पथ में पहाड़ की ऊंचाई पर टीवी/माइक्रोवेयर एंटीना को हटाने की आवश्यकता है। यदि इस व्यवधान को दूर नहीं किया जाता है तब प्रचालन एकदिशात्मक ही किये जा सकते हैं अर्थात् एक दिशा में अवतरण और अन्य दिशा से उड़ान भरना।

(3) धावनपथ विमुखता में 30 डिग्री तक परिवर्तन से धावनपथ की लम्बाई और अधिक उपलब्ध हो सकती है परन्तु भारी वायु दबाव के कारण एफ-27 जैसे छोटे विमानों से प्रचालन किया जाना संभव न हो सकेगा। यह एक भारी लागत वाली परियोजना हो सकती है क्योंकि किनारों पर गहरी खाई के कारण अधिक जमीन भराई किया जाना आवश्यक है। इसलिए 7500 फुट लम्बे धावनपथ का विकास किया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता हैं।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है।

विमान परिचारिकायें

3618. **श्री सुनील खॉं** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिचारिकाओं को उड़ानों में तैनाती के दौरान अधिक वेतन मिलता है और विमानपत्तनों पर तैनाती के समय कम वेतन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और साथ ही उनको उड़ान के दौरान और विमानपत्तनों पर तैनाती के समय प्रति माह दिये जाने वाले वेतन, भत्तों तथा पदनाम का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) विमान परिचारिकाओं सहित सभी केबिन कर्मीदल को उनके ग्रेडों के अनुसार उड़ान संबंधित भत्ते दिए जाते हैं। ये भत्ते उनके लिए तब लागू नहीं होते हैं जब विमान परिचारिकाएं उड़ानगत ड्यूटी न कर भूमिगत ड्यूटी ही करती हैं। फ्लाइंग ड्यूटी तथा ग्राउंड ड्यूटियों के दौरान केबिन कर्मीदल के प्रति माह वेतन व भत्ते निम्नानुसार हैं :-

		वरिष्ठ प्रबंधक (केबिन कर्मीदल) (रुपयों में)	प्रबंधक (केबिन कर्मीदल) (रुपयों में)
उड़ान पर	न्यूनतम	77142	72280
	अधिकतम	78824	74802
भूमि पर	न्यूनतम	41434	34892
	अधिकतम	43385	37230

मिग-21 की दुर्घटना

3619. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 गत

वर्ष 15 फरवरी को ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या ऐसी विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में छबुआ में दिनांक 15.03.99 को तकनीकी खराबी के कारण एक मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना की दुर्घटना की दर जो पिछले दशक में प्रतिवर्ष लगभग 30 थी तह इस दशक में घटकर औसतन 22 रह गई है। वर्ष 1998-99 के दौरान कुल 22 विमान नष्ट हुए हैं। तथापि, इन दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी जिसने सितंबर, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दुर्घटना दर को कम करने के लिए इस समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संगठनात्मक ढ़ांचे, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन लाने होंगे। संबंधित एजेंसियों/विभागों को समिति की सिफारिशों के संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

किलिक निक्सन एण्ड कम्पनी द्वारा रेलमार्ग का चलाया जाना

3620. **प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किलिक निक्सेन एण्ड कम्पनी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेल मार्गों संबंधी कार्य अपने हाथ में ले कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य रेलवे ने इन मार्गों को ठेका आधार पर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे इन रेल मार्गों को ठेको पर लिये जाने के कारण घाटे में चल रही है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कारण सरकार ने कितना घाटा उठाया है; और

(छ) इन रेल मार्गों का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) महाराष्ट्र निजी स्वामित्व वाली तीन रेलवे लाइनें सेन्ट्रल प्रोविन्सेस रेलवे कंपनी लिमिटेड की है जिसके प्रबंधन एजैन्ट्स मै. किलक निक्सन एंड कंपनी है।

(ख) इन रेलवे लाइनों में निम्नलिखित खंड आते हैं।

1.	मूर्तिजापुर-यावतमल	113 कि.मी.
2.	मूर्तिजापुर-आयलपुर	77 कि.मी.
3.	पुलगांव-अरबी	35 कि.मी.

(ग) मध्य रेल इन लाइनों को सेन्ट्रल प्रोविन्सेस रेलवेज कंपनी लि. के साथ एक समझौते के तहत परिचालित कर रही है।

(घ) समझौते के निम्नलिखित मुख्य शर्तें हैं :

1. मध्य रेलवे संचालन एजेंसी के रूप में संचालन व्ययों के लिए प्रतिवर्ष सकल आमदनी का 45 प्रतिशत इन लाइनों की शुद्ध आमदनी समझी जाती है।
2. सकल आमदनी का शेष 55 प्रतिशत अपने पास रखती है।
3. यदि प्रबंधन खर्चों के लिए शुद्ध आमदनी कंपनी द्वारा निवेशित अंश पूंजी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल जमा 21,000/- रुपए प्रतिवर्ष पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो उसका घाटा मध्य रेलवे गारंटीशुदा प्रतिफल के रूप में पूरा करती है।
4. यदि शुद्ध आमदनी उपर्युक्त गारंटीशुदा प्रतिफल से अधिक होती है तो इसे मध्य रेलवे और सेन्ट्रल प्रोविन्सेस रेलवेज कम्पनी लि. के द्वारा बराबर बांटा जाता है।

(ङ) जी हां।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य रेलवे द्वारा उठाई गई हानि इस प्रकार है :

1995-96	3.60 करोड़ रुपए
1996-97	3.64 करोड़ रुपए
1997-98	4.36 करोड़ रुपए

(छ) 1996 में पिछली दस वर्षीय वित्तीय समीक्षा के समय यह विनिश्चय किया गया था कि खरीद विकल्प नहीं रखा जाए बल्कि वित्तीय आधार पर मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जाए क्योंकि राष्ट्रीयकरण से मुख्य भारतीय रेल प्रणाली के साथ इन अलाभप्रद लाइनों के ग्रडोन्नयन और समुचित एकीकरण के लिए भारी पूंजीनिवेश करना होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी क्रियाकलापों में भागीदारी

3621. **श्री वैद्य विष्णु दत्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने गत तीन वर्षों के दौरान समुद्रपार देशों में व्यापार में वृद्धि के लिए संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रदर्शनी/व्यापार सभाओं जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रत्येक दौरे में कितनी धनराशि लगी और क्या परिणाम निकला; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान समुद्रपार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपॉग) : (क) पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत पर्यटन विकास निगम एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को कोई धन नहीं दिया है। तथापि, भारत पर्यटन समिति विकास निगम ने वर्ष 1999-2000 के बजट में अपने अधिकारियों के लिए विदेश में आयोजित होने वाले आयोजनों तथा अन्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए हवाई किराया तथा यात्रा एवं दैनिक भत्ते की खर्च की भरपाई के लिए 90 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान व्यापार संवर्धन के लिए विदेश में आयोजित आयोजनों में भागीदारी के ब्यौरे

दौरों की क्रम सं.	भागीदारों की संख्या	यात्रा का प्रयोजन तथा स्थान	भागीदारों के हवाई किराया/यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता आदि पर हुआ व्यय	दौरे का परिणाम
1	2	3	4	5
1996-97			(लाख रुपये)	
1.	03	थाईलैण्ड में पी ए टी ए ट्रेबल मार्ट (यात्रा व्यवसायिकों का सम्मेलन) में भाग लेना	1.74	
2.	06	सिंगापुर में खाद्य एवं पेय/होटल, रेस्तरां तथा खानपान उपकरण आपूर्ति तथा सेवाओं की 10वीं एशियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा 10वें एफ एच ए अंतर्राष्ट्रीय सैलून कलिनेयर के सम्मेलन में भाग लेना।	5.60	
3.	03	बैंकाक, थाईलैण्ड में पी ए टी ए के 45वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	1.31	
4.	01	दुबई में अरबीयन ट्रेबल मार्ट टेबल फ्री में भाग लेना	0.66	
5.	02	सिंगापुर में मै. ड्यूटी फ्री न्यूज इंटरनेशनल द्वारा आयोजित टैक्स फ्री एशिया पैसिफिक कान्फ्रेल तथा प्रदर्शनी में भाग लेना	1.80	
6.	02	स्वीट्जरलैंड में ई आई बी टी एम 96 (यूरोपियन इंसेटिव एण्ड बिजिनेस ट्रेबल एण्ड मीटिंग एग्जीविशन 96) में भाग लेना	1.67	
7.	02	सिंगापुर में कान्फ्रेंस एण्ड एम्जीबिशन इंटरमीडिया/इंटरनेट एशिया 96 में भाग लेना	1.32	
8.	01	श्रीलंका के पर्यटन एवं यात्रा उद्योग के आमंत्रण पर एफ ए एम टूर में भाग लेना	0.24	

1	2	3	4	5
9.	01	भारत को एक पर्यटत गंतव्य स्थल के रूप में संबंधित करने की दृष्टि से सिंगापुर में आयोजित रोड शो के लिए आस्ट्रेलियाई यात्रा अभिकर्ता परिसंघ के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेना	1.77	
10.	01	भारत को एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में संबंधित करने के लिए आस्ट्रेलिया और सिंगापुर में आस्ट्रेलियाई यात्रा अभिकर्ता परिसंघ के वार्षिक सम्मेलन एवं रोड शो में भाग लेना	1.56	
11.	03	पीटर्सबर्ग, रूस में सी आई एस ट्रेबल मार्केटिंग कान्फ्रेंस में भाग लेना	4.69	
12.	03	बैंकाक, थाईलैण्ड में 66वीं ए एल टी ए वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लेना	2.05	
13.	02	फ्रांस में टैबल फ्री वर्ल्ड कान्फ्रेंस और प्रदर्शनी में भाग लेना	2.86	
14.	01	एअर इण्डिया द्वारा आमंत्रित दुबई के लिए संवर्धनात्मक टूअर	0.21	
15.	05	लंदन, यूनाइटेड किंगडम में डब्ल्यू टी एम वर्ल्ड में भाग लेना	5.97	
16.	02	आर आई सी ब्राजील में 36वीं आई सी सी ए असैम्बली में भाग लेना	1.58	
17.	03	स्पेन में एक आई टी यू आर में भाग लेना	3.87	
18.	01	मानदीव में ए एल टी ए पैसिफिक मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेना	0.59	
19.	02	वी आई टी मिलान, इटली में भाग लेना	1.25	
20.	04	आई टी बी बर्लिन, जर्मनी में भाग लेना	5.85	
1997-98				
21.	03	चीन में पी ए टी ए ट्रेबल में भाग लेना	4.93	
22.	03	46वें पी ए टी ए वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	4.03	
23.	04	कोलम्बों, श्रीलंका में एस ए ए टी ई, 97 में भाग लेना	2.93	
24.	03	जिनबा, स्विट्जरलैंड में ई आई बी टी एम 97 में भाग लेना	4.71	
25.	01	सेन फ्रांसिस्को, यू एय ए में पी ए टी ए चेप्टर वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लेना	1.60	
26.	01	सिंगापुर में आतिथ्य प्रबंधन पर सेमीनार में भाग लेना	0.36	
27.	01	पाकिस्तान में पी ए टी ए निदेशक बोर्ड की बैठक में भाग लेना	0.22	
28.	05	श्रीलंका में 46वीं टी ए ए आई वार्षिक समागम में भाग लेना	1.42	
29.	05	वर्ल्ड ट्रेबल मार्ट, लंदन, यू.के. में भाग लेना	2.70	
30.	02	टोक्यो, जापान में जापान कांग्रेस इंटरनेशनल ट्रेबल एंड ट्रेड शो में भाग लेना	2.28	

1	2	3	4	5
31.	04	बर्लिन, जर्मनी में आई टी बी, 98 में भाग लेना	4.58	
32.	01	फिलीपीन्स में 10वें वार्षिक पी ए टी ए चेप्टर वर्ल्ड कांग्रेस और 47वें पी ए टी ए वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	1.59	
1998-99				
33.	05	सिंगापुर में पी ए टी ए मार्ट, 98 में भाग लेना	3.89	
34.	02	जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ई आई पी टी एम, 98 में भाग लेना	2.68	
35.	01	नेपाल में 12वीं पी ए टी ए एशिया चैप्टर मीटिंग में भाग लेना	0.31	
36.	01	कैन्स, फ्रांस में कर मुक्त विश्व प्रदर्शनी का दौरा	1.36	
37.	03	लंदन, यू.के. में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, 98 में भाग लेना	5.05	
38.	02	मेड्रिड, स्पेन में एफ आई टी यू आर, 99 में भाग लेना	2.15	
39.	02	बर्लिन, जर्मनी में आई टी बी, 99 में भाग लेना	2.24	
40.	01	टोक्यो, जापान में आठवें विश्व यात्रा मेला, 98 में भाग लेना	0.84	

* विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने से, उत्पादों के संवर्धन/विपणन हेतु क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच व्यापारिक पारस्परिक प्रभाव हेतु मंच मिलता है। इसके अतिरिक्त, यह चल रहे कारोबारी रूझानों, नए परिणामों आदि की पूरी जानकारी लेने का अवसर प्रदान करता है।

अन्य मदों अर्थात् पंजीकरण शुल्क और बूथ आदि स्थापित करने के लिए जहां लागू हो, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए व्यय से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

शब्द-संक्षेप का पूर्ण अंश

ए एस टी ए	अमेरिकन सोसाइटी आफ ट्रेवल एजेंट्स	जे ए टी ए	जापान एसोसिएशन आफ ट्रेवल एजेंट्स
पी ए टी ए	पैसेफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन	आई एच ए	इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन
डब्ल्यू टी ओ	वर्ल्ड टूरिज्म आर्गनाइजेशन	वी आई टी	वोर्ल्ड इंटरनेशनल डेल टूरिज्मों (इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सचेंज)
आई सी सी ए	इंटरनेशनल कांग्रेस एण्ड कनवेंशन एसोसिएशन		
डब्ल्यू टी एम	वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट	एफ एच ए	फूउ एण्ड होटल एशिया
आई टी वी	इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स	एफ ए एम टूर	फेमिलियराइजेशन टूर
एफ आई टी यू आर	फेरिया इंटरनेशनल-डी टूरिज्मों (इंटरनेशाल टूरिज्म ट्रेड फेयर)	सी आई एस	कामनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स
		एस ए टी टी ई	साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज
ई आई बी टी एम	यूरोपियन इंसेंटिज एंड बिजनिस ट्रेवल एण्ड मीटिंग्स एग्जीविशन	टी ए ए आई	ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया

राज्य की राजधानियों से जनपद को जोड़ना

3622. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में राज्य की राजधानियों से एकल/दोहरी मेट्रो रेल लाइन द्वारा जुड़े जनपदों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या राज्य की राजधानी से शेष जनपदों को भी जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) रेलों द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ.ओ. का उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु मानदंड

3623. **श्री राजो सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के शेखपुरा जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कोई उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) क.भ. नि. संगठन के अन्तर्गत उप-क्षेत्रीय कार्यालय कुछ निश्चित मानदण्डों को ध्यान में रख कर खोले जाते हैं ये मानदण्ड प्रतिष्ठानों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, प्राप्त/निपटाए गए दावों की संख्या, क्षेत्र में अंशदाताओं की सेवा आदि हैं। प्रस्ताव पर विचार करते समय, क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाता है। बिहार में शेखपुरा में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें

3624. **डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों के लिए बोलीदाताओं से 1500 करोड़ रुपये की न्यूनतम पाँचवर्षीय विक्रय प्रतिभूति और 420 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिभूति और रायॅल्टी के लिए निर्धारित धनराशि शुल्क मुक्त व्यापार से गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित राजस्व से कहीं अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों हेतु अगले पांच वर्षों के लिए बोली की धनराशि में वृद्धि के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विश्वव्यापी बोलीदाताओं से 127.99 मिलियन अमरीकी डालर (537.56 करोड़ रुपये) न्यूनतम आरक्षण लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त करने चाहे जो पॉच वर्षों के लिए स्थान लाइसेंस शुल्क और प्रायोजित कुल टर्न-ओवर के लिए है, जो शुल्क मुक्त शॉपिंग क्षेत्र के लिए पॉच अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नै, मुम्बई, तिरूवनन्तपुरम, और छः सीमा-शुल्क अंतर्देशीय विमानपत्तन, अहमदाबाद, कालीकट, हैदराबाद, वाराणसी, बंगलौर और गोवा में 1992.22 वर्गमीटर स्थान के लिए है।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क की राशि का निर्धारण अगस्त, 1996 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्राप्त उच्चतम वित्तीय बोली पर आधारित था जो पॉच अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर पॉच वर्षों के लिए 1380 वर्गमीटर के अतिरिक्त शुल्क मुक्त शॉपिंग क्षेत्र के लिए 72.65 मिलियन अमरीकी डालर (3.05 करोड़ रुपये) था।

अमेरिका द्वारा भारतीय डिजिटल फ्लाइट नियंत्रण कंप्यूटर देने से मना करना

3625. **श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण :**

श्री विजय हान्दिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के लड़ाकू विमान पर काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक इसके 'डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर' को सॉफ्टवेयर वैधता हेतु अमरीका ले गए थे;

(ख) क्या पोखरण-II की घटना के बाद अमरीकी अधिकारियों ने उपकरण को अपने पास रख लिया है भारतीय वैज्ञानिकों को बिना उपकरण भारत लौट जाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका से उपकरण को प्राप्त करने के लिए क्या कदम, यदि कोई हों, उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) हल्के युद्धक वायुयान के लिए उड़ान नियंत्रण प्रणाली का संयुक्त रूप से डिजाइन तैयार करने, उसका विकास करने और परीक्षण करने हेतु एक करार के अंतर्गत डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के दो प्रयोगशाला मॉडल प्रणाली एकीकरण तथा सत्यापन परीक्षणों के लिए अमरीकी सहयोगकर्त्ता कम्पनी की प्रयोगशाला में अमेरीका ले जाए गए थे।

(ख) पोखरण परीक्षणों के तत्काल बाद अमरीकी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके परिणामस्वरूप सहयोगी अमरीकी कंपनी ने संविदा के तहत संयुक्त कार्य जारी रखने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इसलिए वहां पर कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों के दल को वापस बुला लिया गया था। अमरीकी कंपनी ने डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के दो प्रयोगशाला मॉडलों का भारत को पुनः निर्यात करने में भी अपनी असमर्थता प्रकट की थी।

(ग) भारत ने अमरीका स्थित अपने दूतावास के माध्यम से इस मामले को अमरीकी कंपनी के साथ उठाया है ताकि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के दो प्रयोगशाला मॉडलों का पुनः निर्यात भारत को किया जा सके। अमरीकी कंपनी को आगे का भुगतान रोक दिया गया है। विकास कार्य देश में ही पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय दल गठित किया गया है।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

3626. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काम करने वाले स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने में बरती जाने वाली ढिलाई को प्रकाश में लाने के लिए 26 फरवरी, 1999 को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय महिला परिसंघ की दिल्ली समिति द्वारा आयोजित कार्यशाला की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाए गए विशिष्ट मामले कौन-कौन से थे; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनानुसार, भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय परिसंघ की दिल्ली राज्य समिति ने फरवरी, 1999 में एक कार्यशाला का आयोजन किया तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर विचार-विमर्श किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने पहले ही कई उपाय किए हैं। इन उपायों में दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के सभी सचिवों/राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रधान को दिशानिर्देशों का परिचालन किया जाना शामिल है। तबसे, दिशानिर्देशों का पालन किए जाने संबंधी जवाब काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले आचरण नियमावली में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1976 में संशोधन की कार्रवाई भी शुरू की गई है ताकि ये दिशा निर्देश निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकें।

वित्तीय और विधिक सलाहकारों की नियुक्ति

3627. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**

श्री एस॰एस॰ ओवेसी :

श्री सी॰डी॰ गामीत :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का निगम का दर्जा देने के लिए वित्तीय और विधिक सलाहकारों की नियुक्ति हेतु कितनी निविदाएं प्राप्त की गई है;

(ख) इस प्रक्रिया में कितनी विदेशी पार्टियों ने हिस्सा लिया था;

(ग) क्या इन निविदाओं की जांच कर इनको अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विमानपत्तनों की निगम का दर्जा दिए जाने संबंधी कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) 1 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार, 20 वित्तीय परामर्शदाताओं और 33 कानूनी परामर्शदाताओं ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट के लिए आमंत्रण का प्रत्युत्तर दिया है। इनमें से अधिकांश भारतीय और विदेशी भागीदार दोनों के कंसोर्टियम/समूह के हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न पार्टियों की आफॅर की जांच की जा रही है और मई, 1999 तक चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है और इन विमानपत्तनों को कारपोरेट दर्जा दिये जाने का कार्य इसके पश्चात आरंभ किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राजभाषा की स्वर्ण जयन्ती मनाना

3628. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग ने स्वयं राजभाषा की स्वर्ण जयंती मनाने का कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक इस विषय में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

ताल्चेर-हिंडोल रोड रेल लाइन का दोहरीकरण

3629. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ताल्चेर-हिंडोल रोड रेल लाइन के दोहरीकरण की अनुमानित मूल लागत कितनी है;

(ख) इन लाइन के दोहरीकरण के लिए वर्षवार कितना आवंटन किया गया है;

(ग) आज तक इस परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इस लाइन के दोहरीकरण को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 26.25 करोड़ रुपए।

(ख) स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	आबंटन करोड़ रुपए में
1991-92	2.00
1992-93	1.46
1993-94	22.24
1994-95	6.71
1995-96	3.85
1996-97	1.00
1997-98	4.35
1998-99	1.75

(ग) कार्य पूरा हो गया है और खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय नीति

3630. **श्री आर-एस- गवई :**

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी हां।

(ख) इस नीति को तैयार करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

पनडुब्बियों के पुर्जे

3631. **डा- टी- सुब्बारामी रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एक एच.डी.डब्ल्यू. फ्रंट कंपनी को पनडुब्बी पुर्जों के लिए सामान्य मूल्य से बहुत अधिक मूल्य चुका रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया और क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स एच डी डब्ल्यू (जर्मनी) से दो एस एस के पनडुब्बियां खरीदी गई थी। ऐसी ही दो और पनडुब्बियों को मैसर्स एच डी डब्ल्यू के सहयोग से माझगांव डॉक लिमिटेड (मुंबई) में असेम्बल किया गया था। वर्ष 1987 में मैसर्स एच डी डब्ल्यू पर किकबैक के आरोप लगाए जाने के कारण सरकार ने उसके साथ लेन-देन बंद कर दिया था। नौसेना अन्य कंपनियों से इन पनडुब्बियों के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की मांग पूरी करती आ रही है। इन अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की खरीद नौसेना मुख्यालय द्वारा उसे प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सुपरिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। नौसेना मुख्यालय द्वारा की गई खरीद के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय ने नवम्बर, 1997 में एक शक्ति प्राप्त शिष्टमंडल जर्मनी भेजा था, जिसमें नौसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे। संविदाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय की गई थीं और तत्पश्चात् नौसेना मुख्यालय द्वारा आदेश दिए गए थे। नौसेना मुख्यालय इस संबंध में मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ सौदा करता आ रहा है। मूल उपस्कर निर्माता का पता न होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ज्ञात एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। न्यूनतम और तकनीकी दृष्टि से समुचित दर के अनुसार आदेश दिए जाते हैं। नौसेना मुख्यालय के अनुसार इन कंपनियों में से एक कंपनी मैसर्स एच डी डब्ल्यू तथा दूसरी कंपनी मैसर्स फोरस्टॉल के आंशिक रूप से स्वामित्व में है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की खरीद मैसर्स एच डी डब्ल्यू की मुख्य कंपनियों से अत्यधिक कीमत पर की गई है।

पवन हंस लिमिटेड के हेलिकॉप्टर्स

3632. श्री रवि सीताराम नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा और आर्थिक हानियों के कारण खड़े कर दिए गए पवन हंस लिमिटेड के हेलिकॉप्टरों की विमानपत्तन-वार संख्या कितनी है;

(ख) बेचे गए हेलीकॉप्टरों की संख्या कितनी है और उससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) इस बिक्री के कारण राजकोष को कितनी प्राकलित हानि हुई;

(घ) क्या इस कंपनी का विलय किसी अन्य कंपनी में करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) फरवरी, 1991 में संरक्षा और गैर-किफायती कारणों की वजह से कुल 19 वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों को जमीन पर खड़ा कर दिया गया था। इनमें से 13 हेलीबेस मुम्बई में और शेष 6 सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में जमीन पर खड़े हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इंवेंटरी के साथ-साथ इन हेलीकॉप्टरों की 9,00,000 पौंड स्टर्लिंग अर्थात 6.17 करोड़ रुपये (लगभग) में बिक्री करने की स्वीकृति दे दी है। चूंकि एक स्वतंत्र सर्वेक्षक ने सम्पूर्ण वेस्टलैंड बेड़े को यथार्थ कीमत 5.28 करोड़ रुपये आंकी थी, इसलिए इसमें कोई घाटा नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पश्चिम रेल जोन का अधिकार क्षेत्र

3633. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पश्चिम रेल जोन में कौन-कौन से डिवीजन शामिल हैं;

(ख) क्या गुंतकल डिविजन दक्षिण-पश्चिम रेल जोन में शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुंतकल डिविजन को दक्षिण-मध्य रेल जोन में ही शामिल रखने हेतु कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) दक्षिण-पश्चिम रेलवे का विस्तृत क्षेत्राधिकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

जम्मू रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

3634. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू रेलवे स्टेशन पर 16 जनवरी 1999 को यार्ड से प्लेटफार्म की ओर आते समय मालवा एक्सप्रेस के चार डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए किन-किन स्टेशनों पर क्रेन उपलब्ध है; और

(घ) ऐसी घटनाओं से निबटने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर इन आपात उपकरणों को उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। कैबिन के बेसमेंट में काटे के लॉक बाउल के टूटने से गाड़ी पटरी से उतर गई थी।

(ग) उत्तरी रेलवे में आपात स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित स्टेशनों पर क्रेनें उपलब्ध हैं।

स्टेशनों के नाम

दिल्ली, लखनऊ, लुधियाना भटिंडा, अंबाला, मेड़ता रोड़, मुरादाबाद, कानपुर, रोजा, चुरू, लालगढ़, हनुमानगढ़, रेवाड़ी, समदडी।

(घ) क्रेन जैसे आपातकालीन उपकरण बीच में स्थित स्टेशनों पर मुहैया कराए जाते हैं जहां से संबद्ध स्टेशनों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। जम्मू तवी स्टेशन के लिए क्रेनें पठानकोट स्टेशन पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

कैमरामैनों के खाली पद

3635. श्री रामविलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशालय में कैमरामैनों के पद काफी लंबे समय से खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खाली पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) दूरदर्शन निदेशालय में कैमरामैन का कोई पद नहीं है। तथापि, पूरे भारत के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कैमरामैन ग्रेड-2 के 225 पद खाली पड़े हुए थे जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने कार्मिकों को भर्ती करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु आयोग ने केवल 132 अभ्यार्थियों के एक पैनल की सिफारिश की है जिन्हें अब नियुक्ति दे दी गई है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि शेष रिक्तियों को भरने के लिए वे आवश्यक कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन से सेवाएं आरम्भ किया जाना

3636. श्री के॰ करूनाकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर एयरलाइंस त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अपने सेवाएं आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेतु अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) अभी तक सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में कोई अनुसूची प्रस्तुत नहीं की गई है। त्रिवेन्द्रम को पहले ही विमान सेवा करार के अंतर्गत सिंगापुर की नामित विमानकंपनी के लिए अवतरण-स्थल के रूप में मंजूर किया जा चुका है।

रेवाड़ी-दिल्ली के बीच रेल सेवा

3637. डा॰ शकील अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल एक लाइन के आमान परिवर्तन के बाद से रेवाड़ी-दिल्ली सैक्शन तक प्रतिदिन यात्रियों को लाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आमान परिवर्तन से पूर्व मंत्रालय ने इस सुविधा को पुनः बहाल करने का विचार किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या दूसरी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिल्ली से अन्य क्षेत्रों की भांति उपर्युक्त खंड में ई.एम.यू./डी.एम.यू. सेवा लागू करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाइक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेवाड़ी-दिल्ली खंड के आमान परिवर्तन से पूर्व रेवाड़ी और दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए 16 जोड़ी गाड़ियां थीं जबकि आमान परिवर्तन के पश्चात् बड़ी लाइन/मीटर लाइन दोनों पर इस खंड में 18 जोड़ी गाड़ियां उपलब्ध हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) कार्य प्रगति पर है और नौवीं योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

3638. श्री टी॰ गोविन्दन :

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ हमारे प्रत्येक सैन्य बल द्वारा किए संयुक्त सैन्य अभ्यास का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें प्रत्येक पर कुल कितना खर्च आया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ हमारी तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यासों और इन अभ्यासों पर हुए व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

सेना	नौसेना	वायुसेना
ब्रिटेन- भारत ब्रिटेन की सेना के साथ सेना के सहयोग कार्य-कलापों के हिस्से के रूप में 18 से 25 अक्तूबर, 1996 तक दो अफसरों ने ब्रिटेन में अभ्यास में भाग लिया था। इस पर 2,06,770/- रुपए खर्च हुआ था। - ब्रिटेन के तीन अफसरों ने 17 से 23 नवंबर, 1997 तक भारत में अभ्यास में भाग लिया था। इस पर 70,000/-रु॰ खर्च आया था। **संयुक्त राज्य अमरीका-भारत-** अमरीकी मिलिटरी परस्पर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 03 से 23 अप्रैल, 1997 तक भारतीय सेना और अमरीकी सेना की भागीदारी में भारत-अमरीकी संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इन पर 55,000/- रु॰ का व्यय हुआ था। - भारत के तीन अफसरों ने 2 से 7 जून, 1997 के बीच नेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, पांट इरविन कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमरीका) में प्रेक्षक के रूप में अभ्यास में हिस्सा लिया। इस पर 2,60,000/- रुपए खर्च हुए थे।	भारतीय नौसेना ने वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान सिंगापुर अमरीका, आस्ट्रेलिया, केन्या, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, बंग्लादेश थाईलैंड, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिसिली, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, फिलीपींस और मालद्वीव की नौ-सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किये थे। ये अभ्यास भारतीय नौसेना के जलयानों को विदेशी राष्ट्रों की सद्भावना यात्राओं और विदेशी नौ-सेना के जलयानों की सद्भावना यात्रा तथा पोर्टब्लेयर में मिलन-97 और मिलन-99 के दौरान किए गए थे। चूंकि ये दौरे भारत/मिलन के सद्भावना दौरों/विदेशी दौरों के एक हिस्से के रूप में किए गए थे, इसलिए इन दौरों/मिलन के वास्ते समग्र व्यय के सिवाय इन अभ्यासों को करने में कोई विशिष्ट व्यय नहीं हुआ था।	रायॅल वायु सेना ने 14 से 18 अप्रैल, 1997 के दौरान भारतीय वायुसेना के चुनिंदा पायलटों के साथ एलिमेन्टरी एयर टु एयर रिफ्युलिंग" प्रशिक्षण आयोजित करने के वास्ते भारतीय वायुसेना बेस को वी.सी. 10 ए के-3 टैंकर भेजे थे। इस पर 53,78,026/- रुपए खर्च हुए थे।

कर्नाटक को रक्षा विभाग की भूमि दिया जाना

3639. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने भंत्री महोदय को ट्रिनिटी सर्किल में एक ग्रेड सैपेरेटर के निर्माण हेतु रक्षा विभाग की कुछ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण संख्या 1849 तथा 1850 में लगभग 1,100.25 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र की मांग की गई है। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कश्मीर पर कार्यक्रम का कवरेज

3640. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कश्मीर पर कार्यक्रम के अतिरिक्त कवरेज का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन के कार्यक्रमों संबंधी सभी मामले स्वायत्तशासी सांविधिक निकाय प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में आते हैं प्रसार भारती ने बताया है कि उन्होंने राष्ट्रीय नेटवर्क (डी.डी.-1) और डी.डी.-2, डी.डी. इन्टरनैशनल एवं दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर पर कश्मीर संबंधी कार्यक्रमों की अतिरिक्त कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डीडी-1, डीडी-2, डीडी-इन्टरनैशनल तथा दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर से प्रसारित करने के उद्देश्य से दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1997-98 में प्रसारण हेतु वर्ष 1996-97 में 270 कड़ियों वाले 67 कार्यक्रम कमीशन किए गए थे और वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में लगभग 700 कड़ियों वाले 129 कार्यक्रम कमीशन किए गए हैं। इनमें निहित मुद्दे संस्कृति, पर्यटन, इतिहास, स्मारकों, क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं के पुनर्निमाण, नींव स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों के पुनरूज्जीवन, विकासात्मक कथाओं, विद्रोह और सीमापार से भारत के विरुद्ध प्रचार आदि का मुकाबला करने से संबोधित हैं।

बिना टिकट यात्री

3641. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की समस्या के बारे में कोई व्यापक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों द्वारा मंडलवार, वर्षवार पकड़े गये लोगों की संख्या क्या है तथा उनसे कितनी दंड राशि अर्जित की गयी;

(ग) बिना टिकट यात्रा करने की समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या टिकट निरीक्षकों की कमी के कारण बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न मंडलों में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा परिस्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एच.पी.टी. और एल.पी.टी. चालू करना

3642. श्री एस॰ एस॰ ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने एच.पी.टी. और एल.पी.टी. टी.वी. ट्रांसमीटर चालू किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने एल.पी.टी. और एच.पी.टी. में परिवर्तित किये गये;

(ग) क्या इन ट्रांसमीटरों को चलाने के लिए कर्मचारियों की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान 18 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। अपेक्षित संख्या में स्टाफ जिसे अभी स्वीकृत किया जाना है, न होने के कारण 8वीं योजना अवधि के दौरान चालू किए कुछ ट्रांसमीटर अंशकालिक प्रसारण कर रहे हैं। अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित विभिन्न दूरदर्शन प्रतिष्ठानों की समग्र स्टाफ आवश्यकता का परिकलन करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक से उक्त प्रतिष्ठानों संबंधी स्टाफ मानकों का शीघ्र अध्ययन करने का अनुरोध किया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक की इन सिफारिशों के प्राप्त होने पर अपेक्षित पदों के सृजन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी प्रतिष्ठानों में उपयुक्त रूप से कर्मचारी तैनात किए जा सके और इन्हें पूरी तरह से चालू किया जा सके।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान चालू किए गए टी.वी. ट्रांसमीटर

राज्य	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	4	33	5
अरूणाचल प्रदेश	–	1	3
असम	–	11	1
बिहार	–	15	1
गोवा	–	1	–
गुजरात	2	16	1
हरियाणा	–	4	–
हिमाचल प्रदेश	1	02	16

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	1	6	16
कर्नाटक	1	16	2
केरल	1	9	2
मध्य प्रदेश	2	18	6
महाराष्ट्र	1	26	6
मेघालय	–	3	1
मिजोरम	1	1	1
उड़ीसा	1	39	6
मणिपुर	–	1	1
पंजाब	–	2	–
नागालैण्ड	1	1	1
राजस्थान	3	27	11
सिक्किम	1	1	–
त्रिपुरा	–	1	1
तमिलनाडु	2	14	4
उत्तर प्रदेश	2	19	10
पश्चिम बंगाल	1	10	2
चंडीगढ़	–	1	–
दिल्ली	1	2	–
लक्षद्वीप	–	1	1
पांडिचेरी	–	1	–
अण्डमान एवं निकोबार	–	1	4
दमन एवं दीव	–	1	–
दादरा एवं नगर हवेली	–	1	–

छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों हेतु किराए में छूट

3643. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने छात्रों के लिए शैक्षणिक दौरों के लिए छूट देने संबंधी योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी हां। 17 जुलाई 1998 से इन्डियन एयरलाइन्स शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए अध्ययन दौरे पर 15 छात्रों के समूह में यात्रा करने वाले छात्रों को एक स्थल से दूसरे स्थल तक सामान्य प्रचालन पर 50 प्रतिशत की छूट आफॅर कर रही है।

- समूह के साथ जाने वाले शिक्षक भी 50 प्रतिशत छूट का हकदार है।
- यह छूट अगात्ती, पोर्टब्लेयर और लेह तक/से यात्रा के अतिरिक्त सभी घरेलू सेक्टरों में किफायती वर्ग में दी जाती है। किन्तु अगात्ति, पोर्टब्लेयर और लेह में अध्ययनरत छात्र इस छूट के हकदार हं। यह छूट मान्यताप्राप्त "शिक्षण संस्थान" के प्रधान के द्वारा छपे लेटर हेड पर अनुरोध करने पर दी जाती है जिसमें (शैक्षणिक दौरे) पर जाने वाले शिक्षक के साथ छात्रों के समूह के पूर्ण यात्रा विवरण का उल्लेख हो।
- यह अनुरोध संबंधित महाप्रबंधक/क्षेत्र के (वाणिज्यिक) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो सीट-गुणक और मौजूदा विपणन स्थिति पर विचार करने के उपरांत छूट को अनुमोदित करता है।
- टिकटें इन्डियन एयरलाइन्स अथवा इसके द्वारा अनुमोदित ट्रेवल एजेंटों द्वारा जारी की जा सकती हैं।
- यह छूट 31 जुलाई 1999 तक लागू हैं।

नागपुर दूरदर्शन केन्द्र में अपलिंकिग सुविधा

3644. प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर दूरदर्शन केन्द्र को मुबंई, अहमदाबाद की तरह पूर्ण रूप से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या मुंबई/दिल्ली दूरदर्शन केन्द्रों को समाचार भेजने के लिए नागपुर में कोई अपलिकिंग सुविधा उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं का संवर्धन किया जा रहा है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई और अहमदाबाद जो राज्यों की राजधानियां है कुछ अधिक सुपरिष्कृत सुविधाएं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

3645. श्री राजो सिंह :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल स्थान-वार कहां-कहां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक होटल को कितना लाभ और घाटा हुआ; और

(ग) सरकार ने इन होटलों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने जा रही है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपॉग) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम सम्पूर्ण देश में 26 होटलों का स्वामित्व रखता है और प्रचालन करता है। पिछले 3 वर्षों के लिए होटलों की स्थान-स्थिति/राज्य वार नाम और उनकी लाभदायकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) होटलों का लाभदायकता में सुधार लाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं :-

- उद्यमशील विपणन प्रयास
- परिसम्पत्तियों का उन्नयन/नवीकरण ताकि उन्हें समसामयिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके
- मूल्य नियंत्रण को कड़ाई से प्रयोग में लाना
- ऑपरेटिंग मैनुअल्स लागू करना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/स्थान स्थिति-वार भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में प्रचलित किए जा रहे होटलों के नाम और प्रत्येक होटल द्वारा अर्जित लाभ और उठाई गई हानि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।

रु॰ लाखों में

एकक/स्थान स्थिति का नाम	राज्य	1996-97		1997-98		1998-99 अनुमानित	
		कारोबार	कुल लाभ/ हानि	कारो-बार	कुल लाभ/ हानि	कारो-बार	कुल लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
पाटलिपुत्र अशोक, पटना	बिहार	163.20	6.45	197.09	10.16	217.10	3.48
बोधगया अशोक, बोधगया	बिहार	103.63	18.62	81.23	2.51	92.20	10.70
अशोक होटल, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5385.83	2126.53	5326.44	1390.41	4237.49	-154.84
सम्राट होटल, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1683.36	422.00	1442.27	80.27	1098.76	-213.61
कुतुब होटल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	925.60	488.70	920.81	396.46	754.42	210.85
कनिष्का होटल, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2144.27	670.28	2111.57	462.71	1707.13	16.10
जनपथ होटल, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1071.98	200.68	1077.13	89.88	998.03	-102.61
लोधी होटल, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	842.26	295.63	758.18	127.21	672.37	20.32
रणजीत होटल, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	255.17	-118.17	250.71	-167.93	275.95	-148.92
अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	718.14	4.38	755.53	-63.21	758.28	-90.58
मनाली अशोक, मनाली	हिमाचल प्रदेश	26.41	-33.76	29.88	-27.67	26.77	-26.58
जम्मू अशोक, जम्मू	जम्मू और कश्मीर	67.17	-31.12	76.22	-25.15	79.64	-41.76

1	2	3	4	5	6	7	8
ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	कर्नाटक	557.30	254.64	518.15	204.02	527.84	144.55
होटल अशोक, बंगलौर	कर्नाटक	1632.41	351.42	1605.59	168.03	1486.39	-69.54
हासन अशोक हासन	कर्नाटक	152.53	42.21	132.71	18.20	146.50	18.13
कोवलम अशोक बीच रिज़ार्ट, कोवलम	केरल	1137.73	279.86	1003.17	174.00	1085.67	121.47
औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	78.99	-47.23	73.97	-55.41	69.41	-66.30
खजुराहों अशोक, खजुराहो	मध्य प्रदेश	31.37	-58.75	39.12	-62.21	41.32	-49.41
कलिंक अशोक, भुवनेश्वर	उड़ीसा	174.61	-31.12	188.02	-29.78	196.27	-38.66
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	राजस्थान	316.88	110.36	362.18	111.26	222.21	-18.90
जयपुर अशोक, जयपुर	राजस्थान	173.50	-61.27	183.90	-84.09	150.49	-120.94
टेम्पल बे अशोक बीच रिज़ार्ट, मामल्लापुरम	तमिलनाडु	160.04	22.93	168.96	9.26	179.00	6.99
मदुरै अशोक, मदुरै	तमिलनाडु	126.23	-3.37	130.42	-18.59	127.99	-32.65
आगरा अशोक, आगरा	उत्तर प्रदेश	134.65	-70.44	146.21	-72.50	156.35	-72.24
वाराणसी अशोक, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	148.72	-99.35	170.19	-90.90	150.62	-123.07
एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1293.45	221.23	1244.39	127.57	1146.00	-4.16
		19505.41	4961.34	18994.04	2674.53	16604.97	-820.18
भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा अर्जित लाभ			5515.92		3371.97		552.59
भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा उठाई गई हानि			-554.58		-697.44		-1372.77
शुद्ध लाभ			4961.34		2674.53		-820.18

[अनुवाद]

मुम्बई हवाई अड्डे पर दूसरी धावन पट्टी को दुबारा खोलना

3646. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गत दो वर्षों से बंद मुम्बई हवाई अड्डे की धावन पट्टी को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो धावन पट्टी को फिर से शुरू करने के क्या कारण हैं; और

(ग) धावन पट्टी को फिर से शुरू करने से पूर्व विमानों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1997 में वैकल्पिक धावनपथ को बंद कर दिया गया था चूंकि ये आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि नए नियंत्रण टावर की ऊँचाई से इस धावनपथ पर विमानों के सुरक्षित प्रचालनों के संबंध में रूकावट हो सकती है। चूंकि इस संबंध में और विस्तार से जॉच-पड़ताल की जानी अपेक्षित थी, इसलिए इस बारे में अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ भेजने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया था। विमानपत्तनों की सभी सूचनाओं और निरीक्षण की जॉच पड़ताल करने के बाद, इकाओ विशेषज्ञ ने अक्तूबर, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परामर्शदाता तथा इकाओ द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। सिफारिशों के अनुसार विमान प्रचालन सुरक्षा में अड़चन नहीं आएगी यदि प्रचालनात्मक टिप्पणियां दोनों उपमार्ग क्रिया

विधि चार्टों के संबंध में तथा वैमानिकी सूचना प्रकाशन (एआईपी) के संबंध में जोड़ते हुए और विमान प्रचालन प्रतिबंधों को लगाते हुए सुरक्षा के समतुल्य स्तर की व्यवस्था की जाती है। चूंकि ये सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई है इसलिए नए धावनपथ को बढ़ते विमान आवागमन को सुकर बनाने की दृष्टि से फिर से खोल दिया गया है।

(ग) इकाओ परामर्शदाता की सिफारिशों के अनुपालनार्थ विमान प्रचालनों को उस समय सीमित करना जब बादल 500 फुट या उससे अधिक हो, विमानक्षेत्र के उत्तर खंड में दृश्य रूम से मंडराने के लिए विमानों को अनुमति नहीं देना, रात्रि को दिखाई दिये जाने के लिए टावर पर प्रकाश व्यवस्था करना, नक्शों और चार्टों पर इसकी अवस्थिति अधिसूचित करना जैसे विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपाय किए गए हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से रेलवे को हुई हानि

3647. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री एस॰एस॰ ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रत्येक मंडल में प्रभावित रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पुलों और रेल लाइनों को कुल कितनी क्षति पहुंची;

(ग) क्या ऐसी क्षतिग्रस्त रेल लाइनों और पुलों की मरम्मत कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो किस सीमा तक यह कार्य हुआ है;

(ङ) इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(च) क्षति और दुर्घटनाओं के कारण अलग-अलग कितने दिनों के लिये रेलगाड़ियां रद्द की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क)

रेलवे	1996-97 खंड	1997-98 खंड	1998-99 खंड
1	2	3	4
मध्य			इटारसी-नागपुर कल्याण-कसारा कल्याण-करजत
पूर्व			मालदा-नयू फरक्का न्यू फरक्का-अज़ीमगंज महाराजपुर-साहिबगंज कहलगांव-एकचारी
उत्तर रेलवे	जोधपुर-जैसलमेर	जोधपुर-जैसलमेर लूनी-मारवाड़ पठानकोट-जम्मूतवी पठानकोट-जोगिंदरनगर फुलेना-जोधपुर	
पूर्वोत्तर रेलवे	मथुरा-वृंदावन सकरी-झंझारपुर झंझारपुर-निर्मली	झंझारपुर-निर्मली सहरसा-पूर्णिया	मधाना-ब्रहमवर्त. गेसारी गौंडा-गोरखपुर झंझारपुर-निर्मली सकरी-झंझारपुर दरभंगा-नरकटियागंज

1	2	3	4
			सहरासा–पूर्णिया समस्तीपुर–दरभंगा बहमनखी–बिहारीगंज नरकटियागंज– भिखनाथोरी मानसी–सहरसा
पूर्वोत्तर सीमा	अलिपुरद्वारा–सिलीपुड़ी रंगापाड़ा मुरकोंगसलेक	रंगापाड़ा–(एन)–मुरकोंगसलेक (एन)–कटिहार–तेजनारायणपुर	दार्जिलिंग–सिलीपुड़ी कटिहार–तेजनारायणपुर फारविशगंज–जोगबानी न्यू जलपाईगुड़ी–बरसोई बरासोई–राधिकापुर कुमदपुर–ओल्ड मालदा कुमदपुर–कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी– नयू कुचबिहार न्यू बोंगाईगांव–गुवाहाटी सिलीगुड़ी–अलीपुरद्वार रॉगिया–मुरकोंगसलेक लमडिंग–बदरपुर
दक्षिण रेलवे	विल्लूपुरम–तिरूच्चिरापल्ली मेट्टूपल्लवम–उदागमेंदलम	दिंडिगुल–मदुरै तिरूतुरायपुंडी–करायकुड़ी मेट्टूपल्लायम–उदागमेंदलम	त्रिवेद्रम–नागरकोइल दिंडिगुल–मदुरै मदुरै–मन्मादुरै मदुर–बोदीनयाकन्नूर मेट्टूपल्लायम– उदागमेंदलम
दक्षिण मध्य रेलवे	द्रोणाचलम–नंदई महबूबनगर–द्रोणाचलम गुडूर–विजयवाड़ा		लोंडा–वास्कोडिगामा मुदखेड़–सिकंदराबाद मनमाड–सिकंदराबाद वाडी–सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे		जबलपुर–गोंदिया	
पश्चिम रेलवे	अलवर–मथुरा बांदीकुई–आगराफोर्ट भरतपुर–मथुरा कोटा–रूथियाई कोटा–नागदा	मलिया मियाना–सुरबारी मलिया मियाना–विदर्भा झुंड–बजाना झुंड–खरगोदा नाडियाड–कपडवंज वीरमगाम–सुरेन्द्रनगर अहमदाबाद–हिम्मतनगर मेहसाना–पालनपुर मेहसाना–पाटन कलोल–विजापुर विजापुर–अंमबियासन	गांधीधाम–न्यू कांडला पोर्ट गांधीधाम–ओल्ड कांडला पोर्ट अमरेली–तलाला राजकोट–हापा कलाल–काटोसम रोड–पाटन मेहसाना–रानजु–पाटन हिम्मतनगर–उदयपुर अलवर–मथुरा उद्धना–जलगांव कोसंबा–सूरत

1	2	3	4
		वीरमगाम-मेहसाना रायका-ढांडोका बोटाद-साबरमती मेहसाना-तरंगा हिल्स हिम्मतनगर-खेरब्रह्मा भाभड़-राधनपुर भाभड़-देवगाम सेन्द्रा-बार गोधरा-रतलाम दाहोद-रतलाम गोधरा-यार्ड वडोदरा-गोधरा वडोदरा-अहमदाबाद आनंद गोधरा	

(ख)

रेलवे/वर्ष में लागत	1996-97	1997-98	1998-99
मध्य			9,18,000
दक्षिण मध्य	7,24,48,927		59,02,000
पूर्वोत्तर सीमा	2,19,00,000	12,13,00,000	10,00,00,000
दक्षिण पूर्व		2,00,000	
उत्तर रेलवे	8,03,500	8,85,000	17,00,000
पूर्व रेलवे			55,50,000
दक्षिण	4,21,00,000	2,43,00,000	2,38,00,000
पूर्वोत्तर	1,79,000	51,000	57,10,000
पश्चिम	3,00,00,000	8,25,00,000	5,00,00,000
कुल	16,74,31,427	22,92,36,000	19,35,80,000

(ग) और (घ) मेहसाना-पाटन खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों पर मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। इस खंड पर लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और दिसंबर, 1999 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

(ङ) लगभग 150 लाख रुपए।

(च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोफोर्स तोप के कलपुर्जे

3648. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियार बनाने वाली आस्ट्रीयाई फर्म "मसचिनेन फैबरिक लिजेन" ने 410 बोफोर्स तोपों के लिए 25 करोड़ रुपये मूल्य के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या बताए गए हैं;

(ग) क्या इस हेतु वैकल्पिक बाजार खोज लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) 155 मि.मी. एफ.एच. 77 बी तोप प्रणाली के हिस्से-पूर्जों की आपूर्ति के लिए मैसर्स मशीनेनफेब्रिक लाइजेन यू.इन.डी. जाइस्सरी जी.ई.एस.एम.बी.

(एम.एफ.एल.) आस्ट्रिया के साथ 25.7.98 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, जबकि इस संविदा में ऐसा कोई अनुबंध नहीं था, लेकिन मैसर्स एम.एफ.एल., आस्ट्रिया ने बाद में रेखाचित्रों और तकनीकी दस्तावेजों के रूप में क्रेता की सहायता मांगी, ताकि वह संविदा का निष्पादन कर सके। चूंकि मैसर्स एम.एफ.एल. आस्ट्रिया के अनुरोध को मान लेने में विधिक परिणाम अन्तर्ग्रस्त थे, अतः मैसर्स एम.एफ.एल., के साथ संविदा के कार्य को आगे न बढ़ाए जाने की राय बनाई गई। क्योंकि विक्रेता द्वारा संविदागत हिस्से-पुर्जे बोफोर्स के लिए जाने की आशंका थी जिसके साथ लेन-देन पर प्रतिबंध है। हालांकि उपर्युक्त कंपनी ने हाल ही में इस आशय का एक अनुरोध किया है, लेकिन यह संविदा अभी तक रद्द नहीं की गई है। हिस्से पूर्जों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

गोवा में हवाई अड्डे का विस्तार और आधुनिकीकरण

3649. श्री रवि सीताराम नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा सरकार ने नागर विमानन नेटवर्क के विकास/विस्तार और आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) गोवा में उपलब्ध नागर विमानन की वर्तमान ढांचागत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) डबोलिम पर वर्तमान नौसैनिक विमानपत्तन के एक विकल्प के रूप में पणजी के उत्तर में मौंपा के निकट एक नये विमानपत्तन के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी दौरान, वर्तमान नौसैनिक विमानपत्तन के स्तरोन्नयन के लिए एक निर्णय लिया गया है जिससे इसे चौबीसों घंटे प्रचालनात्क स्थिति में रखा जा सके।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो वर्तमान विमानपत्तन पर सिविल एन्कलेव का अनुरक्षण करती है, ने अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवनों एप्रन और टैक्सीपथों सहित विमानपत्तन आधारिक संरचना के विकास के लिए खर्च किया है। एक ही समय पर, दो एबी-300, दो एबी-320 और बी-737 विमानों को पार्क किया जा सकता है। विमानपत्तन सीमित अंतरराष्ट्रीय चार्टर उड़ानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है।

जम्मू दूरदर्शन केन्द्र के लिए कर्मचारी

3650. श्री चमन लाल गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू दूरदर्शन केन्द्र में स्थापित उपकरणों/सुविधाओं के इष्टतम उपयोग हेतु आवश्यक श्रम शक्ति/कर्मचारी उपलब्ध करा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक श्रम शक्ति कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (घ) कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, जम्मू के लिए आंशिक स्टाफ मंजूर किया गया है। दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर से कुछ स्टाफ की पुनः तैनाती करके इसकी और पूर्ति की गयी है। सभी दूरदर्शन संस्थापनों की स्टाफ समस्या का समाधान करने के लिए, वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक से विभिन्न दूरदर्शन संस्थापनों के स्टाफ संबंधी मानदण्डों का शीघ्र अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिश प्राप्त होने पर अपेक्षित संख्या में पदों को सृजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी संस्थापनों में उपयुक्त रूप से कर्मचारी तैनाती किए जा सके और इन्हें पूरी तरह से चालू किया जा सके।

एयर इण्डिया के वित्तीय हानि वाले वायुमार्ग

3651. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के उन वायु-मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर भारी वित्तीय घाटा हो रहा है; और

(ख) घाटे को कम करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) अप्रैल/सितम्बर, 1998 की अवधि के अनंतिम वित्तीय परिणामों के अनुसार भारत/खाड़ी मार्ग को छोड़कर प्रायः सभी मार्गों पर एअर इंडिया को निबल प्रचालनात्मक घाटा हुआ है। घाटा होने वाले मार्ग निम्नानुसार हैं :-

भारत/संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत/यूनाइटेड किंगडम

भारत/महाद्वीपीय

भारत/रूस

भारत/पूर्वी अफ्रीका

भारत/दक्षिणपूर्व एशिया

भारत/हांगकांग

भारत/जापान

(ख) घाटे को कम करने के लिए विमानकंपनी द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :-

(1) अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयासों में तेजी लाई गई है।

(2) मार्ग लाभप्रदता पर जोर देते हुए नेटवर्क युक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण।

(3) और अधिक इन-हाउस रिपेयर्स शुरू करके विमानों के वाह्य रिपेयर्स पर हो रहे व्यय में कटौती।

(4) विदेश स्थित भारतीय अधिकारियों के विभिन्न पदों को समाप्त कर दिया गया है।

कर्नाटक में विमानपत्तनों का विकास

3652. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के विमानपत्तनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मांगने के संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि कर्नाटक में पाँच विमानपत्तनों हेतु निम्नलिखित निधि संबंधी प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को किया गया था :-

गुलबर्ग	50 करोड़ रुपये
मैसूर	50 करोड़ रुपये
हुबली	35 करोड़ रुपये
बेलगांव	35 करोड़ रुपये
हासन	25 करोड़ रुपये
कुल	195 करोड़ रुपये

योजना आयोग ने सूचित किया है कि उक्त प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निधियों की उपलब्धता, परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा अन्य विमानपत्तन परियोजनाओं की तुलना में परस्पर प्राथमिकता हो।

राइट्स एवं इरकॉन का कार्य निष्पादन

3653. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राइट्स एवं इरकॉन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राइट्स एवं इरकॉन द्वारा 1999-2000 के दौरान किन-किन नई परियोजनाओं को आरंभ किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। वित्त वर्ष की शुरूआत में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) राइट्स और इरकॉन के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

राइट्स

(आकंड़ें करोड़ रुपयों में)

	1996-97	1997-98	1998-99 (संशोधित अनुमान)
समग्र लाभ	35.13	29.64	11.40
कारोबार	134.73	132.89	128.20
प्राप्त आदेश	98.60	117.71	*54.00
लाभांश	1.00	1.29	अभी घोषित किया जाना है।
मूल्यांकन		उत्कृष्ट	अभी विनिश्चय किया जाना है।

इरकॉन

(आकंड़े करोड़ रुपयों में)

	1996-97	1997-98	1998-99 (संशोधित अनुमान)
समग्र लाभ	56.25	60.55	46.60
कारोबार	466.74	459.38	396.50
प्राप्त आदेश	254.17	382.35	*450.00
लाभांश	1.98	8.66	अभी घोषित किया जाना है।
मूल्यांकन		बहुत अच्छा	अभी विनिश्चय किया जाना है।

*बजट अनुमानों के अनुसार

(ग) 1999-2000 के दौरान राइट्स और इरकॉन द्वारा शुरू करने हेतु प्रस्तावित नई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

राईट्स

- मयंमार रेलवे को डीज़ल रेल इंजन का पैकेज निर्मित
- म्यंमार से मिजोरम राज्य तक अंतर्देशीय जलमार्गों/सड़क परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहार्यता अध्ययन
- वियतनाम रेलवे को रेलवे चल स्टाक उपस्करों की आपूर्ति

इरकॉन

- आंध्र प्रदेश में सिंदरी (विशाखापत्तम) में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्र के लिए एक नई रेलवे साइडिंग का निर्माण
- जम्मू और कश्मीर में काजीगुंड-श्रीनगर-बारामूला नई ब.ला. रेलवे लाइन का निर्माण

"राइट्स" द्वारा परामर्श सेवाएं

3654. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राइट्स" ने पर्यावरण प्रबंध तंत्र पर आई.एस.ओ. 14000 में प्रमाणीकरण के लिए परामर्श सेवाएं देना शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। राइट्स पर्यावरण प्रबंधन तंत्र पर आई एस ओ 1400। मानक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्रियता से परामर्श सेवाएं मुहैया करा रहा है। मैसर्स गोदरेज सोप्स लि., मालनपुर एम पी ने राइट्स की परामर्श सहायता से ही प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आई एस ओ 1400। प्रणाली में परामर्श सेवाएं निम्नलिखित संगठनों को मुहैया कराई जा रही है :-

1. रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला
2. हाई-टेक कार्बन, गुडमडीपुंडी, तमिलनाडु
3. एल जी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्राइवेट लि., ग्रेटर नोएडा
4. मैसर्स ग्वालियर पोलीपाइन्स लि., ग्वालियर

काम्पटी से अबाझाड़ी तक सर्कुलर गाड़ी

3655. प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े महानगरों में स्थानीय रेल सेवा शुरू करने हेतु नीति निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जहां सरकार का स्थानीय रेल सेवाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागपुर में सर्कुलर गाड़ी चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ए एन-32 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

3656. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री मोहन रावले :
श्री के॰एस॰ राव :
श्री प्रमथेस मुखर्जी :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री विट्ठल तुपे :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का विमान ए एन-32, 7 मार्च, 1999 को दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें मारे गए अधिकारियों और असैनिक व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में गठित की गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस दुर्घटना में मारे गए विमान दल के सदस्यों तथा असैनिक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसमें होने वाले विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) एक ए एन-32 वायुयान 7.3.99 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इस वायुयान में सवार वायुसेना के 18 कार्मिकों और भूमि पर तीन सिविलियनों को घातक चोटें आई।

(ग) और (घ) इस संबंध में बिठाई गई जांच-अदालत का कार्य अभी चल रहा है।

(ङ) और (च) इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों के प्रतिपूर्ति संबंधी दावों पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, मारे गए सिविलियनों के निकट संबंधियों को अनुग्रहपूर्वक अंतरिम राहत का भुगतान किया जा चुका है, जो इस प्रकार है :-

मारे गए व्यक्ति	संख्या	भुगतान की दर	कुल धनराशि (रुपए)
वयस्क	1	10,000/- रुपए	10,000/-
बच्चे	2	5,000/- रुपए की दर से	10,000/-

मनोरंजन उद्योग को प्रोत्साहन

3657. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मनोरंजन उद्योग को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय को अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय का विचार है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्र के रूप में मनोरंजन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का वहन करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनोरंजन क्षेत्र को सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र के समान माना जाना चाहिए ताकि सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र को उपलब्ध सभी लाभ मनोरंजन क्षेत्र को समान रूप से प्रदान किए जा सकें। इस बारे में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

(1) फिल्मों, टेलीविजन और संगीत उद्योग के लिए व्यावसायिक उपकरण पर सीमा शुल्क की दरों को सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र के लिए निर्धारित शुल्क ढ़ांचे के समान किया जाए।

(2) रंगीन कच्ची सामग्री (पोजेटिव एवं नेगेटिव फिल्म रोल्स सहित) पर सीमा-शुल्क तथा प्रतिलाभ शुल्क समाप्त किया जाए क्योंकि इसका निर्माण भारत में नहीं होता है।

(3) पूर्व-रिकार्डिड वीडियों कैसेटों पर सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट पूर्वपेक्षी प्रभाव से दी जाए।

(4) कम्पैक्ट डिस्क्स पर उत्पाद-शुल्क समाप्त किया जाए जैसा कि पूर्व-रिकार्डिड कैसेटों के मामले में किया गया है। इससे अधिकृत सी.डी. के निर्माताओं को अनुचित मूल्य लाभ से वंचित किया जा सकेगा।

(5) देश के सिनेमाघरों एवं बहुविध के प्रतिष्ठापनों को भी आयकर अधिनियम की धारा 80-1-क के लाभ प्रदान किए जाएं।

(6) वर्ष 1999-2000 के लिए बजट में घोषित नई धारा-80 एच.एच.एफ. के लाभ, मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्माण के लगे स्वामियों व्यक्तियों आदि के मामले में भी लागू किया जाए और ऐसे लाभ पूर्वोपेक्षी प्रभाव से उपलब्ध कराए जाएं।

"अग्नि" का परीक्षण

3658. श्री रवि सीताराम नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1999 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "आर्मी टू आपरेट ओन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) "अग्नि" प्रेक्षपास्त्र का परीक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा सेवाओं को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। अभी हाल ही में सेना को सामान की खरीद, निर्माण कार्यों, सूचना प्रोद्यौगिकी आदि के लिए बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय

प्रत्यायोजन के अलावा राजस्व तथा पूंजीगत अधिकारियों के लिए अलग-अलग अधिप्राप्ति नियोजन बोर्ड गठित किए गए हैं।

(ग) "अग्नि" का परीक्षण 11 अप्रैल, 1999 को किया जा चुका है।

केरल में विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योग

3659. **श्री टी॰ गोविन्दन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का विचार विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) केरल सरकार के अधीन केरल बागवानी विकास कार्यक्रम ने एर्नाकुलम में मुवथ्थुपुजबा के पास नाडुकरा में एक फल प्रसंस्करण फैक्टरी लगाई है। उक्त कार्यक्रम के लिए निधि यूरोपीय संघ और केरल सरकार द्वारा दी गई है। यह कार्यक्रम केरल में कृषि की प्रचुर संभावनाओं का इस्तेमाल करने और ऐसी अधिक मूल्य वाली बागवानी की खेती को बढ़ावा देता है जिसमें प्रमुख लाभ किसानों को मिले।

उक्त फैक्टरी के लिए आयातित संयंत्र और मशीनरी की लागत प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय संघ ने वहन की है। अनुमान है कि फैक्टरी में वाणिज्यिक उत्पादन जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

फैक्टरी के प्रबंधन/प्रचालन में विदेशी सहयोग निहित नहीं है।

मिग-21 विमानों के स्थान पर नए विमान खरीदना

3660. **श्री उमर अब्दुल्ला : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंटर और मिग-21 विमान पुराने हो गए हैं और इनको बदलने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। हंटर बेड़े की उपयोगिता अवधि पहले ही पूरी हो गई है तथा मिग-21 बेडा भी पुराना पड़ता जा रहा है।

(ख) इन विमानों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाने के लिए जगुआर, सुखोई-30 विमानों को वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मौजूदा विमानों की प्रचालनात्मक क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए मिग-21 बिस उन्नयन जैसा उन्नयन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य विमानों को वायुसेना में शामिल किए जाने की योजना भी बनाई जा रही है।

(ग) यह समस्त प्रक्रिया वर्ष 2003-05 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

विमानपत्तनों पर शीतगार सुविधा

3661. **श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पूर्वी तट पर नश्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई हेतु विमानपत्तनों पर शीतगार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) तथा कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने कलकत्ता विमानपत्तन पर शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के निर्यात हेतु एक 20 फुट वाक-इन-कूलर की व्यवस्था की है।

कमीशण्ड धारावाहिक और कार्यक्रम

3662. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.ई.ओ., महानिदेशक और सम्बद्ध अधिकारीगण ने पिछले दस वर्षों के दौरान नब्बे करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कमीशण्ड धारावाहिकों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी है, अब भी उसका प्रसारण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम कमीशन किए जाते हैं तथा उसके बाद कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रकाशनों के पंजीकरण के लिए मानदण्ड

3663. **श्री चमन लाल गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक अर्धसाप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबारों/पत्रिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्यवार कितने विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में नया प्रकाशन शुरू किया है;

(ग) नये प्रकाशनों के पंजीयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई पत्रों विशेषकर जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित पत्रों द्वारा राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की जा रही है तथा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और तोड़-फोड़ की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पत्रों की आय तथा व्यय के स्रोतों की कभी जांच की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों का राज्यवार तथा आवधिकतावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1996, 1997 तथा 1998) तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय समाचारपत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या क्रमशः 6264 तथा 735 है। वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान पंजीकृत समाचारपत्रों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1998 तथा 1999 के लिए राज्यवार ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं।

(ग) प्रकाशक को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घोषणा को प्रमाणित करवाना है तथा निर्धारित अवधि में प्रथम संस्करण के प्रकाशन के बाद प्रकाशक प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत यथा अपेक्षित दस्तावेज भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को प्रस्तुत करने के बाद समाचारपत्र/पत्रिकाओं को पंजीकृत करवाया जा सकता है। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अपेक्षित दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रकाशन को एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-I

31.12.1997 को पंजीकृत समाचरपत्रों की कुल संख्या

(राज्य/संघ शासित क्षेत्र और आवधिकतावार)

राज्य/सं.शा. क्षेत्र	दैनिक	त्रि/द्वि. साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान एवं निकोबार	4	0	17	7	8	36
आंध्र प्रदेश	281	7	583	303	610	1784
अरूणाचल प्रदेश	2	1	3	0	1	7
असम	30	8	167	59	84	348
बिहार	404	33	684	146	235	1502
चंडीगढ़	35	1	66	27	109	238
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	0	0	1
दमन एवं द्वीप	0	0	0	1	0	1
दिल्ली	244	49	997	780	2519	4589
गोवा	13	0	14	9	27	63
गुजरात	106	5	486	140	395	1132
हरियाणा	87	8	307	183	187	772
हिमाचल प्रदेश	8	0	48	20	39	115

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू एवं कश्मीर	70	4	181	30	28	313
कर्नाटक	371	11	462	283	740	1867
केरल	211	4	184	180	813	1392
लक्षद्वीप	0	0	0	1	1	2
मध्य प्रदेश	425	8	2199	139	359	3130
महाराष्ट्र	422	36	1322	372	1304	3456
मणिपुर	46	3	12	11	37	109
मेघालय	4	4	32	6	15	61
मिजोरम	38	11	32	6	15	102
नागालैण्ड	2	0	9	0	1	12
उड़ीसा	84	2	138	84	279	587
पांडिचेरी	3	1	10	4	18	36
पंजाब	122	13	386	132	292	945
राजस्थान	403	22	991	1050	324	2790
सिक्किम	0	2	10	1	1	14
तमिलनाडु	357	49	430	246	953	2035
त्रिपुरा	22	2	52	7	11	94
उत्तर प्रदेश	781	31	4238	866	1126	7042
पश्चिम बंगाल	144	10	682	561	974	2371
कुल	4719	325	14743	5654	11505	36946

विवरण–II

वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान भारतीय समाचारपत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचारपत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	1996	1997
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	55	106
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	20	20
4.	बिहार	26	22
5.	दिल्ली	238	306
6.	गोवा	1	1
7.	गुजरात	74	161
8.	हरियाणा	37	43
9.	हिमाचल प्रदेश	2	10
10.	जम्मू और कश्मीर	11	12
11.	कर्नाटक	64	94
12.	केरल	21	53

1	2	3	4
13.	मध्य प्रदेश	187	234
14.	महाराष्ट्र	86	248
15.	मणिपुर	5	4
16.	मेघालय	1	1
17.	मिजोरम	2	7
18.	नागालैण्ड	1	–
19.	उड़ीसा	21	41
20.	पंजाब	15	37
21.	राजस्थान	99	129
22.	सिक्किम	3	2
23.	तमिलनाडु	29	79
24.	त्रिपुरा	1	2
25.	उत्तर प्रदेश	678	616
26.	पश्चिम बंगाल	66	58
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	5
28.	चंडीगढ़	6	9
29.	दादरा एवं नागर हवेली	–	–
30.	दमन एवं द्वीप	–	–
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–

विमानपत्तनों की भूमि को पट्टे पर दिए जाने संबंधी नियम

3664. डा॰ सरोजा वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तनों की प्रमुख भूमि को पट्टे पर देने के लिए अपने नियमों में संशोधन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तीन सदस्यीय समिति द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो समिति ने अन्तिम अनुमोदन हेतु अपनी रिपोर्ट बोर्ड के पास प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के फलस्वरूप विमानपत्तनों पर भूमि को पट्टे पर दिए जाने हेतु मानकीकृत प्रतिमानों के लिए नीति बनाने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। आरंभ में समीक्षा करने तथा नयी भूमि पट्टा नीति की सिप रिश करने के लिए एक समिति गठित गई थी। तथापि बाद में भूमि को पट्टे पर दिए जाने संबंधी नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए एक बाहरी परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। परामर्शदाता द्वारा अंतिम प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नवापुर टी.वी. टावर में कर्मचारियों की कमी

3665. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नवापुर टी.वी. टावर कर्मचारियों की कमी के कारण पूरी तरह से चालू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पूरी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां। अल्प शक्ति ट्रांसमीटर नवापुर, महाराष्ट्र से इस समय अंशकालिक प्रसारण किया जा रहा है क्योंकि अभी पूरी संख्या में स्टॉफ स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित दूरदर्शन प्रतिष्ठानों की समग्र स्टाफ आवश्यकता का परिकलन करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक से उक्त प्रतिष्ठानों संबंधी स्टाफ मानकों का शीघ्र अध्ययन करने का अनुरोध किया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक की इन सिफारिशों के प्राप्त होने पर अपेक्षित पदों के सृजन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी प्रतिष्ठानों का उपयुक्त रूप से कर्मचारी तैनात किए जा सके और इन्हें पूरी तरह से चालू किया जा सके।

[अनुवाद]

भूतपूर्व कर्मचारियों का वेतन जारी करना

3666. **श्री गोरधन भाई जावीया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के किसी भूतपूर्व कर्मचारी को नवम्बर, 1993 से जून, 1994 तक लगभग 3 महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय श्रम आयोग ने 28 दिसम्बर, 1998 के आदेश के तहत यह टिप्पणी की है कि उन्हें वेतन और अन्य बकाया देय है; और

(घ) यदि हां, तो वेतन और बकाया जारी करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) दूरदर्शन के एक भूतपूर्व मेक-अप कलाकार को 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 31.10.93 को सेवा-निवृत्त कर दिया गया था। तथापि, उन्होंने एक कर्मकार होने के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अपनी सेवा को जारी रखने के लिए अभ्यावेदन किया था। विचार करने पर उक्त कर्मचारी को पुनः कार्यभार संभालने की अनुमति दी गई थी तथा 7 माह से अधिक की मध्यवर्ती अवधि को देय एवं स्वीकार्य अवकाश या अकार्य-दिवस, जैसा मामला हो के रूप में मानने का निर्णय लिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त के आदेश पर की जाने वाली आगे की कार्यवाही संबंधी मामला विधि मंत्रालय इत्यादि के परामर्श से विचाराधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर में वृद्धि

3667. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि का ब्याज दर में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ई.पी.एफ. आयुक्त के दौरे

3668. **श्री अमन कुमार नागरा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रत्येक के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक दो माह में एक बार दिल्ली में बुलाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान ऐसी कितनी बैठकें हुई और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त घरेलू/विदेशी दौरों पर जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप इन दौरों पर कितना व्यय हुआ?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए, केन्द्रीय कार्रवाई योजना के तहत तिमाही समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(ख) 1998-99 में नई दिल्ली में 4 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी, जिन पर 6.43 लाख रुपए खर्च किए गए।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (के.भा.नि.आ.) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्य अधिकारी होता है। यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होती है कि देश भर के 2 करोड़ भविष्य निधि अंशदाताओं की संतुष्टि के लिए ऐसे सभी कार्यालय जो मुख्यतः लोक व्यवहार कार्यालय होते है संतोषजनक ढ़ंग से काम करें। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जेनेवा स्थित इंटरनेशनल सोशल सिक्यूरिटी एसोसिएशन का एसोसिएट सदस्य है। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त आई एस एस ए की भविष्य निधि संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त सहित कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन के अधिकारियों से यह अपेक्षित होता है कि वे आई एस एस ए की बैठकों में भाग लें क्योंकि ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हित के लिए होते हैं। 1998-99 के दौरान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों का 31 बार दौरा किया तथा चार बार विदेश का दौरा किया। इस पर 5.90 लाख रुपए का व्यय हुआ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आपरेशन "लीच"

3669. **डा॰ सरोज्ञा बी॰ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तीनों सेनाओं

द्वारा फरवरी, 1998 में संयुक्त रूप से की गई विवादास्पद "आपरेशन लीच" की कार्यवाही में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) विदेशियों को उनके शस्त्रों, गोला बारूद तथा उपस्करों सहित पकड़ने के लिए तीनों सेनाओं ने फरवरी 1998 में एक कार्रवाई आरंभ की। इस संबंध में सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन, अंडमान में अपराध सं. 50/98 के तहत 18.2.98 को एक मामला दर्ज किया गया था।

2. कतिपय सूचना के आधार पर और "आपरेशन लीच" के संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के मद्देनजर यह वांछनीय समझा गया कि इस घटना की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा कराई जाए। तदनुसार भारत सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया। तदनुसार विशेष अपराध शाखा, कलकत्ता में दिनांक 27.2.98 को आर.सी. 1 (एस.)/98-कलकत्ता के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

विदेशी कार्यक्रमों में सरकारी उपक्रमों द्वारा भाग लिया जाना

3670. **श्री वैद्य विष्णु दत्त** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/व्यापारिक बैठकों इत्यादि जैसे व्यापार संवर्द्धन कार्यक्रमों में कितने सरकारी उपक्रमों ने भाग लिया और प्रत्येक ट्रिप पर कितना व्यय हुआ और उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रत्येक सरकारी उपक्रम को 1999-2000 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में रसोई यान जोड़ा जाना

3671. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में रसोई-यान जोड़ने संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1993 की याचिका सं. 213 में रसोई-यान जोड़ने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 10 सितम्बर 1993 को पारित आदेश का अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तत्कालीन कार्यकारी निदेशक (कोचिंग) की टिप्पणी पर रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 4 अप्रैल, 1995 को रसोई-यान जोड़ने के बारे में सलाहकार (खानपान और पर्यटन) को दिए गए अनुवर्ती निदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) जी, हां।

कतिपय लंबी दूरी वाली गाड़ियां जो 30 घंटे से ज्यादा समय लेती हैं, में पैंट्री कार सेवाएं मुहैया कराई जाती है बशर्ते कि गाड़ियों में पैंट्री कार को गलियारे से जोड़ने की जगह हो। बहरहाल, राजधानी/शताब्दी और कतिपय इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में यहां तक कि कम यात्रा समय लेने वाली गाड़ियों में भी इनकी महत्ता, इनके ठहराव की अवधि और मार्ग में खान-पान सेवाओं की पर्याप्तता के मद्देनजर रखते हुए पैंट्री कार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

उपर्युक्त नीति राष्ट्रीय उपभोक्ता और विवाद निवारक आयोग के निर्णय के अनुरूप है जिसके अनुसार उन सभी सुपरफास्ट गाड़ियों में जिनके यात्रा समय 30 घंटे से ज्यादा लगता है। पैंट्री कार सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अंबाला छावनी में कथित भ्रष्टाचार

3672. **श्री अमन कुमार नागरा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "द इंडियन एक्सप्रेस" में 25 नवम्बर, 1998 में प्रकाशित समाचार के अनुसार आर.ए. बाजार, अम्बाला छावनी में सामुदायिक भवन गिर गया/ध्वस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को अंबाला छावनी बोर्ड के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) प्रबलित कंकरीट-सीमेंट के जमने से पहले ही ठेकेदार के मजदूरों द्वारा शटरिंग को समय-पूर्व हटाने के कारण सामुदायिक हॉल के एक ओर का एक हिस्सा गिर गया था। इस समाचार के प्रकाशित होने से पहले ही छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ने इस घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।

(ख) से (घ) जब कभी सरकार और रक्षा संपदा महानिदेशालय को भ्रष्टाचार के बारे में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी तत्परता से जांच-पड़ताल और छानबीन की जाती है। सभी छावनी बोर्डों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

मैं प्रस्ताव के पक्ष में कुछ बोलना चाहूंगा लेकिन बोलने से पहले मैं सुनना चाहूंगा। प्रतिपक्ष क्या चाहता है, प्रतिपक्ष मेरी सरकार को हटाना चाहता है, यह तो स्पष्ट है लेकिन इसके बाद की तस्वीर स्पष्ट नहीं है मैं चाहूंगा कि इस विवाद में यह तस्वीर स्पष्ट हो जिससे सदन फैसला कर सके, देश फैसला कर सके। वैसे अगर चाहे तो प्रतिपक्ष पर चुप भी रह सकता है क्योंकि अंत में तो दिग्विजय हमारी होने वाली है और उसका नक्शा प्रकट भी होने वाला है लेकिन लोक तंत्र का तकाजा है कि जो सरकार को हटाना चाहते हैं, वे यह बताएं कि वे किस तरह की सरकार लाना चाहते हैं। उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा मैं इसलिए प्रतिपक्ष को मौका दे रहा हूँ कि वह बोले और फिर मैं अंत में विस्तार से जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

> "कि यह सभा मंत्रिमंडल में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, सदन के सामने जो प्रस्ताव सदन के नेता जी ने प्रस्तुत किया है...(*व्यवधान*)

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर) : विपक्ष के नेता खड़े हुए और किसी ने ताली नहीं बजाई।...(*व्यवधान*)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हम किराए के बजन्तरी नही हैं, चापलूस नही है।...(*व्यवधान*)

श्री शरद पवार : मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध के साथ-साथ मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, तो विरोध के साथ किस तरह से विकल्प दे सकते हैं, इस बारे में हमारे मन में बिल्कुल साफ राय है। जो हमारे साथी इस काम के लिए हमें सहयोग देने वाले है, सभी ने मिलकर इस पर बात की है और जैसा कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा...(*व्यवधान*) देश के ऊपर जो सरकार का बोझ हुआ है, वह साम्प्रदायिक सरकार जाने के बाद हम पांच मिनट में बैठकर इसका रास्ता निकालेंगे और देश के सामने एक विकल्प देंगे।...(*व्यवधान*) यह विश्वास प्रस्ताव की नौबत आई कैसे?...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बोलने में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : हम लोगों ने जो कहा है, पांच मिनट तो पांच मिनट, एक मिनट में हम लोग घित करते हैं...(*व्यवधान*)

श्री शरद पवार : महोदय, सदन में श्रीकृष्ण जी की वाणी यहां हुई है, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नही है। एक बात हम सभी साथियों को माननी चाहिए कि सभी साथियों को, तेरह महीने पहले चुनाव का निर्णय भारत की जनता ने देशवासियों के सामने रखा था, किसी भी पोलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस देश की जनता ने नहीं दिया। वोटिंग पैट्रन किसी को नहीं दिया था। प्रधान मंत्री जिस पोलिटिकल पार्टी से हैं, उनको 25-25.5 परसेंट से ज्यादा वोट नहीं मिले। उनके समर्थन देने वाले जो बाकी साथी हैं, उन सभी के वोट देखने के बाद भी स्पष्ट मैनडेट इस देश की जनता ने नहीं दिया था। मगर इसके साथ-साथ मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि हम लोगों को भी मैनडेट नहीं दिया था। इसलिए जब सरकार बनाने की बात आई, तो एक साझा सरकार हो सकती थी और सरकार बनाने के लिए सहयोगी पार्टियां आगे आयेंगी। उनकी मदद से सरकार बन सकती थी। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के बीच में था। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उस समय प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री पद की शपथ देने की तैयारी रखी, तब उनका पूरा ध्यान नम्बर पर था। जयललिता जी का समर्थन का लैटर दो दिन डिले मिल गया... (*व्यवधान*) इसलिए प्रधान मंत्री को शपथ देने के लिए राष्ट्रपति जी ने तैयारी नहीं रखी। चेन्नई से खत कब आता है, इसकी राह देखनी पड़ी और चेन्नई से खत आने के बाद ही उन्होंने प्रधान मंत्री जी के शपथ देने की तैयारी रखी। इस सरकार को सुब्रहमण्यम स्वामी जी, सरदार बूटा सिंह, चौटाला जी और एआईएडीएमके, सभी का समर्थन प्राप्त था। जिस दिन सभी पोलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उस क्षण इन्हें सरकार चलाने का अधिकार इस देश में नहीं रहा, वह अधिकार इन्होंने खो दिया। अटल जी की राजकीय जिन्दगी पूरे देश के सामने है, उनका सार्वजनिक जीवन पूरे देशवासी जानते हैं। इन्होंने हमेशा एक मौरल बेस्ड पोलिटिक्स करने की तैयारी दिखाई। जब समर्थन वापस लेने का काम कुछ साथियों ने किया तब हमें लगता था कि वह शायद खुद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदन के सामने यह नौबत नहीं लाएंगे। ठीक है, इन्होंने दूसरा रास्ता स्वीकार किया, इसकी भी परिस्थिति दो दिन में पूरे देशवासियों

[श्री शरद पवार]

के सामने आने वाली है, जो काम यह कल कर सकते थे लेकिन इन्होंने नही किया। वह परिस्थिति शायद शनिवार को इस सदन में बहुमत देखने के लिए इनके ऊपर आएगी। देशवासी देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति का सामना दूसरी बार अटल जी को करना पड़ रहा है। हम लोगों ने 13 दिन की सरकार भी देखी और अब 13 महीने में भी देख लिया है। मैं सोच रहा था,

[अनुवाद]

कि इस सरकार की वास्तविक उपलब्धि क्या है? इस सरकार ने पिछले बारह या तेरह महीनों में क्या किया है? इस सरकार की एक मात्र उपलब्धि यह है कि अनेक अन्तर्विरोधों के बावजूद यह सरकार चलती रही। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह या तेरह महीनों में इस सरकार का कोई भी योगदान मुझे दिखाई नहीं पड़ता।

[हिन्दी]

यह सरकार 13 महीने बच गई। आज पूरी दुनिया की एक अलग परिस्थिति हो गई है। आज जगह-जगह 21वीं सदी में जाने की बात हो रही है। सभी सोच रहे हैं कि इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, हमारे देश में जो गरीबी एवं बेरोजगारी है, उसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसे मजबूत हो सकती है, आधुनिक विज्ञान और तंत्र को स्वीकार करके हम कैसे 21वीं सदी में जा सकते हैं, आज यह विचारधारा दुनिया में प्रस्तुत हो रही है। संपूर्ण देश को एक रख कर, इसमें शायद हम कुछ कर सकते थे, मगर 13 महीने के अटल जी के कारोबार को देखने के बाद देश के हर व्यक्ति के मन में यह आ रहा है कि यह कमाई देशवासियों ने की। क्या आर्थिक परिस्थितियों के सुधार के लिए कोई खास कदम उठाये गये, मंदी के संकट से उबरने के लिए कोई मजबूत कदम उठाए गये। आर्थिक उत्पादन जो घट गया है वह और भी घट रहा है इसको दुरूस्त करने के लिए क्या कोई कदम उठाये गये, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए गये, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए गये या देश के राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गये? यह देश के अहम सवाल हैं। चाहे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजूकेकशन का सवाल हो या महिलाओं का समानता देने का सवाल हो, ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर क्या कोई कदम उठाए गये। मुझे दुख होता है कि इन सभी सवालों का जवाब "न" है। इन 13 महीनों में इस बारे में कोई सख्त कदम उठाया गया हो, ऐसी परिस्थिति देशवासी देख नही रहे हैं।

भारत जैसे देश में जब हम समस्याओं पर बात करके आगे चलने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उद्योग बढ़ाने की बात करते है, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, देश को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज होता है कि हम अपने समाज को एक कैसे रख सकते हैं, समाज में एकता कैसे रख सकते हैं। पिछले 12-13 महीनों में जो परिस्थितियां देशवासियों ने देखीं, खासकर छोटे वर्गों और अल्पसंख्यकों ने देखीं, वह पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखी थीं। इसकी एक मिसाल में देना चाहता हूं। ईसाइयों पर जितने हमले पिछले 50 सालों में हुए...(*व्यवधान*) उनके 50 प्रतिशत से ज्यादा हमले इन 13 महीनों में हो गये...(*व्यवधान*) यह क्या शर्मनाक बात नहीं है।...(*व्यवधान*) जो परिस्थिति हमने उड़ीसा में देखी, क्या यह प्रशंसा करने वाली परिस्थिति है। आस्ट्रेलियन मिशनरी और उनके मासूम बच्चों को वहां पर जिस तरह से जलाया गया, इससे क्या दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब ऐसी परिस्थिति होती हैं और उनके लिए जो शक्तियां और संगठन जिम्मेदार होते हैं उनको समर्थन देने का काम हमारे गृह मंत्री जी करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं उन संगठनों को जानता हूं और उनके द्वारा वहां कोई गुंडागर्दी या कोई क्रिमनल एक्टीविटी करने के बारे में कोई बात नहीं है। उन्होंने बिना कोई जांच कराये उनको सर्टिफिकेट दे दिया। रक्षा मंत्री जी ने इस बारे में क्या कहा। दो घंटे में उन्होंने उड़ीसा में जाकर सारी परिस्थितियां देखीं और देश को बताया कि वाजपेयी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह विदेशी साजिश है। अभी इन्वेस्टीगेशन पूरा भी नहीं हुआ था और दो घंटे में यह विदेशी साजिश हो गयी। पूरे देशवासियों को मालूम है कि इस साजिश में इस सरकार को मदद करने वाली कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां-संगठन हैं, उन लोगों का हाथ है। इसलिए इस सरकार को रहने का कितना अधिकार है इस पर बोलने पर हमें आवश्यकता है।

मैं समझता था कि ऐसी परिस्थिति में कम से कम प्रधान मंत्री जी देशवासियों को नया रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने इस बारे में बात शुरू की और कहा कि कनवर्शन पर बहस हो जाए, धर्मान्तरण पर बहस हो जाए। इस देश में इतनी गम्भीर स्थिति पैदा हुई। पिछले 50 सालों से ईसाइयों की स्थिति हम सब देख रहे हैं। एक धर्म ऐसा है जिस की आबादी दिन-ब-दिन कम हो रही है जबकि बाकी सभी धर्मों के लोगों को आबादी बढ़ रही है और ईसाइयों की पापुलेशन कम हो रही है।. ..(*व्यवधान*) सब आंकड़े सरकारी हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधान मंत्री ने देश के सामने कनवर्शन के इशू पर नेशनल डिबेट का विषय रखा। मैं उनकी यह बात समझ सकता था कि अगर वह कहते कि बेरोजगारी के इशू पर नेशनल डिबेट की बात हो, स्टेट और सैंट्रल फंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसिडी के बारे में क्या हो सकता है। इन इशूज पर नेशनल डिबेट हो सकती थी मगर ये इशूज प्रधान मंत्री जी को महत्वपूर्ण नहीं लगे। उन्हें कनवर्शन का इशू महत्वपूर्ण लगा। उनकी देश के बारे में जो सोच है, वह सोच दिल्ली में बैठ कर पूरे देश का नक्शा मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखने की आवश्यकता थी लेकिन वह आवश्यकता प्रधान मंत्री जी ने नहीं दिखाई। शायद उनको नागपुर में संदेश आया था। उस संदेश का आधार लेकर उन्होंने कनवर्शन पर डिबेट करने की बात देशवासियों के सामने कही।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : इटली से नहीं आया था।

श्री शरद पवार : इसकी कोई जरूरत नही थी। जो परिस्थिति पैदा हो रही थी और जिस तरह से सरकार चल रही थी, उनकी सरकार को समर्थन देने वाले साथियों के मन में उसको लेकर नाराजगी थी। वह नाराजगी समर्थन देने वाले साथियों तक सीमित नही थी बल्कि उनके मंत्रिमंडल में काम करने वाले लोगों के मन में भी नाराजगी थी। मैं इसकी मिसाल मदन लाल खुराना जी का जो खत...(*व्यवधान*) अब सुषमा जी का चेहरा भी बदल गया है। उन्होंने लिखा

[अनुवाद]

"मैंने आडवाणी को पहले भी एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि केन्द्रीय नेता अपने कैरियर को ही सर्वोपरि मानने वाले लोगों और सत्ता के दलालों द्वारा घिरे हुए हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि निर्णय वस्तुपरक होने के बजाए व्यक्ति, स्थान और इच्छा के अनुरूप लिये गये हैं।"

[हिन्दी]

खुराना जी ने यह कहा। वह बेचारे तंग आ गए। उन्होंने सही कहा और इस्तीफा दे दिया। वह सदन में कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया। उनको आदेश हो गया कि इस पर नहीं बोलना है। मुझे विश्वास है कि वह आज या कल बोलेंगे और देशवासियों के सामने इस सरकार का अनुभव रखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि समाज के छोटे वर्गों को विश्वास दिलाने में यह सरकार विफल रही। बात हमेशा हिन्दुत्व की होती है। हम लोगों ने हिन्दुत्व के बारे में बचपन से जो सीखा उसमें सहिष्णुता की बात हिन्दुत्व में ज्यादा सीखी। सहिष्णुता जो हिन्दू धर्म की एक विचारधारा है, उस विचारधारा को. ..*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली-सदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आया है, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, मैंने उनकी बात नहीं मानी है।

अध्यक्ष महोदय : वे अपनी बात पर कायम हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : शरद जी, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अंग्रेजी में कहा लेकिन मैं पत्र तो हिन्दी में लिखता हूं, अंग्रेजी में नही लिखता। जो कुछ आप कह रहे हैं, उसका वह मतलब नही है। इसके अलावा में कुछ कहने वाला नहीं।

श्री शरद पवार : मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आपके मन में जो बात है, कभी तो इस सदन के सामने रखिये। जो कहना चाहते हैं, एक बार देशवासियों के सामने इस सदन के माध्यम से रखें। मुझे मालूम है आपकी पीड़ा क्या है?

श्री मदन लाल खुराना : मैं अपनी बात अपने शब्दों में रखूंगा, आपके कहने से नहीं रखूंगा।

श्री शरद पवार : ठीक है, आप अपने शब्दों में रखिये लेकिन जो पीड़ा है, वह पीड़ा तो रहेगी ही, मुझे इस बारे में विश्वास है। सवाल यह है कि इस सरकार का कंट्रीब्यूशन साढे बारह या 13 महीने में छोटे वर्ग का गैर-विश्वास की भावना के साथ साम्प्रदायिकता देना है। इनका हिन्दुत्व या हिन्दूवाद - सब चुनाव के लिये नारे थे जिसके बारे में देशवासियों को पता चला है।

माननीय प्रधानमंत्री जी, में 10 दिन पहले वाराणसी गया था। मैं सुबह उठकर गंगा घाट देखने के लिये गया। जो परिस्थिति मैंने वहां देखी, जो पानी देखा, जिस तरह से मरे हुये जानवर वहां देखे और वहां लोगों से जिस तरह से बात की, सब लोग कहते थे कि स्व. राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था, उस प्लान की तरफ चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। गंगा के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, वाराणसी का नाम लेकर राजनैतिक फायदा लेने का काम जिस पार्टी ने किया, कम से कम इस देश की जनता की भावनाओं का ध्यान रखकर सरकार ने कदम उठाया होता, ऐसा वहां की जनता ने कहा है। उनका यह भी कहना है कि पिछले 13 महीने के कामों को देखने के बाद इस सरकार पर बिल्कुल विश्वास नही रहा है, आप कोई दूसरा विकल्प जल्दी दीजिये, तब यहां की स्थिति सुधरेगी।

जहां तक देश की एकता का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण बात देश की आर्थिक स्थिति की समस्या है। आज औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है। मैं इस सदन में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पिम्परी, चिंचवड, टैलको, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर फैक्टरी और दूसरी मेजर इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नये कारखाने बंद हो गये हैं और मेजर इंडस्ट्रीज को मदद करने वाले छोटे कारखाने थे, खासकर एंसिलरी इंडस्ट्रीज जिसमें समाज का छोटा कारीगर अपने घर पर कारोबार चलाता था, 70 परसेंट से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हुई है। आज एक शहर में 50 हजार से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही है। यह परिस्थिति सबसे ज्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्री वाले शहर की है। आप बता सकते हैं कि पूरे देश की परिस्थिति क्या होगी। पब्लिक सैक्टर की क्या परिस्थिति होगी? इस बेरोजगारी को कम करने के लिये, कारखाने चलाने के लिये और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिसकी पूरी कीमत देशवासियों को चुकानी पड़ रही है।

हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से स्वदेशी का नारा दिया जा रहा है। इसकी परिस्थिति यह है कि आज पूरी दुनिया भारत को एक डम्पिंग ग्राउंड बना रही है। शक्कर के क्षेत्र में यही हुआ है। इस देश के किसान में देश के हर आदमी की जरूरत को पूरा करने की ताकत है। यहां गन्ना किसान का महत्व क्या है इस बात से साबित होता है कि हमारे देश में इतनी चीनी बनने के बाद भी बाहर से लाने के लिये इजाजत दे दी गई है। हमारे देश में चार करोड़ टन गन्ना पैदा करने वाला किसान की परिस्थिति खराब करने का काम इस सरकार की नीतियों ने किया है। ऐसा सभी क्षेत्रों में हो रहा है।

भारत आज डम्पिंग ग्राउंड हो रहा है और यह सरकार स्वदेशी का नारा दे रही है। आज यह परिस्थिति देखने के बाद की जनता को यह विश्वास नहीं कि इस सरकार को शासन चलाने का अधिकार रहे। मुझे याद है कि जब दिल्ली में चुनाव हुये तो उस समय प्याज की बात सारे देश में हुई थी। यहां दुनियाभर से प्याज 16-17-18 रुपये और यहां तक कि 30 रुपये किलो तक लाया गया था। आज प्याज की फसल ज्यादा हो गई है। नासिक तथा दूसरी जगहों के किसान यह मांग कर रहे हैं कि पहले हमारा प्याज दुनिया में बेचने के लिये इजाजत

[श्री शरद पवार]

दें। इस सरकार ने 25-30 हजार टन पर मंथ की इजाजत दी है इस सरकार ने इतना एक्सपोर्ट करने की इजाजत तब दी जब किसान द्वारा मंडी में प्याज बेचने के बाद और जब उसे कल्टीवेशन प्राइस तक नहीं मिली, व्यापारियों के पास माल जमा होने के बाद एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी और इस प्रकार से व्यापारियों को मुनाफा देने का पूरा प्रबंध किया तथा किसानों को तंग करने का काम इस सरकार ने किया। यही परिस्थिति आलू की रही। आलू उगाने वाले किसानों की यही परिस्थिति रही जिसका बुरा असर सारे देश पर हो रहा है। गांव में रहने वाला किसान तरस रहा है। जब-जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग पहला सवाल यह पूछते हैं कि ऐसी नौबत कब तक रहेगी और आप इसे कब तक दूर करेंगे। मुझे खुशी है कि सुश्री जयललिता ने कुछ समझदारी से ऐसा कदम उठाने की तैयारी की है और इस देश की जनता को इस सरकार से छुटकारा दिलाना चाहती है। इसकी प्रक्रिया आज शुरू हुई है।

अध्यक्ष जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। इनमें बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात बहुत बार की गई है। प्रधानमंत्री जी ने इस को महत्व दिया है मगर पिछले 13 महीने में जो पुराने बिजली के प्रकल्प थे, उन्हें पूरा करके इस देश को समर्पित किये गये हैं लेकिन देशवासियों के सामने कोई नया प्रकल्प लाने के लिये सरकार ने कदम उठाया हो, ऐसा हमारे सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक बिजली हर दिन नही मिलती है।...(*व्यवधान*) आपने बहुत बड़ा स्लोगन दिया कि पूरे देश में महामार्ग बनायेंगे, बिजली के केन्द्र बनायेंगे मगर पिछले 13 महीने में सभी क्षेत्र में दुनिया से इन्वैस्टमेंट आया था इस देश में तैयारी हुई, ऐसी मिसाल इस सरकार ने नहीं दी। इस सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बिलकुल नजरअंदाज करने का काम किया है।

मैं सोचता था कि टेलीकॉम पालिसी के बारे में यह सरकार थोड़ा ध्यान रखेगी लेकिन दुनिया से इनवैस्टमेंट नहीं हुआ है। थोड़ा कुछ काम किया है मगर जो किया है, वह पूरा नहीं किया है। यहां से पूरी दुनिया को यह मैसेज भेजने की आवश्यकता थी कि हम टेलीकॉम क्षेत्र को महत्व देते है क्योंकि दुनिया में कम्युनिकेशन फील्ड की काफी कीमत है और इस क्षेत्र में भारत बिल्कुल पिछड़ा नहीं रहना चाहिये। इस पर हमारा ध्यान है मगर वहां भी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच सरकार में बैठने वाले साथियों ने दिखाई, उससे पूरी दुनिया में यह मैसेज गया है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता। इससे पूरे देश का इनवैस्टमेंट क्लाईमेट खराब हो गया है और इस देश में नई पूंजी आने के सब रास्ते बंद हो गये हैं। इस सबकी जिम्मेदारी किस पर है? इस सरकार के बारे में दुनिया के मन में गैर-विश्वास की भावना आज देश में हम लोगों को देखने को मिल रही है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है। किसानों ने मेहनत की और फसल अच्छी निकली है। मगर इससे पहले भी इस सदन में बात हुई कि हुकूमत में आने के बाद हम किसानों के लिए एक नयी कृषि नीति जल्दी से जल्दी लाएँगे। 12 महीने में कृषि नीति लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हों इसके दर्शन इस सदन को नहीं हुए और न देश के किसानों को हुए।

सरकार चलानी हो तो प्रशासन को भी विश्वास में लेकर काम करने की आवश्यकता होती है। कई साल हम लोग भी सरकार में रहे। राज्यों में रहे और केन्द्र में रहे मगर इतने छोटे स्पैन में 12 महीने के स्पैन में सरकार में संबंधित लोगों ने यहां पर जो स्ट्राइक पर जाने का काम किया, इससे पहले कभी नही हुआ था। कौन लोग स्ट्राइक पर गए? ऐम्स के डॉक्टर्स, वहां के रिसर्च स्कॉलर्स के स्ट्राइक पर जाने की परिस्थिति पैदा हो गई। न्यायालय के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के स्ट्राइक पर जाने की नौबत आ गई। कृषि क्षेत्र में जो वैज्ञानिक हैं जो कभी स्ट्राइक की बात नही करते थे, उनके स्ट्राइक पर जाने की परिस्थिति आ गई। एन.टी.पी.सी. के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए। प्रसार भारती के कर्मचारी पिछले कुछ महीनों से सभी मेम्बर्स के पास, पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास, अखबार वालों के दरवाजे पर जा रहे हैं, मगर यह सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नही है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको विश्वास दिलाकर हम देश का प्रशासन ठीक तरह से चला सकते हैं, इस पर ध्यान देने की परिस्थिति आज इस संस्कार की नही है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उल्टे पिटाई हो रही है। मारा जा रहा है लाठियों से।

श्री शरद पवार : जी हां, उनको मारा जा रहा है।

विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जो अच्छे कदम उठाए गए, उसका इस सदन ने स्वागत किया है। लाहौर यात्रा का स्वागत पूरे सदन ने किया। अच्छी बात है, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है और इस बारे में अटल जी ने जो किया उसका स्वागत इस सदन ने किया।

आज अग्नि-2 की बात पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। इस देश के वैज्ञानिक और टैकनीशियन्स ने इस क्षेत्र में जो काम किया और कई सालों से जो प्रोग्राम हो रहे थे, वह आगे ले जाने के जो कुछ कदम उठाए, इसका स्वागत सभी लोगों ने किया है। मगर हम पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए जब कदम उठाते हैं और साथ-साथ इसी समय पर 'अग्नि' जैसे कदम उठाते हैं जो क्या यह कॉनफिडेन्स बिल्डिंग मीज़र्स है? आप इंडियन सब-कॉन्टिनेन्ट में आर्म्स रेस करना चाहते हैं? जिस दिन लोगों ने यह कदम उठाया, उसी शाम को पाकिस्तान ने कहा कि इस बारे में कुछ करेंगे और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने क्या किया। पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते सिन्सियरली रखना चाहते हैं, वह रिश्ते हमें चाहिए। भारत हो या पाकिस्तान हो या आस-पास के देश हों, सभी देशों की समस्या गरीबी की है, बेरोज़गारी की है। हमारा पूरा ध्यान इस पर रहने की आवश्यकता है। हमारा पूरा ध्यान आर्म्स रेस पर लगाएंगे तो सब-कॉन्टिनेन्ट के जितने गरीब लोग हैं, इनकी परिस्थिति में सुधार नहीं होगा। आने वाले समय में यह सब दुनिया के पिछड़े भूभाग होंगे और इसलिए मुझे मालुम नहीं कि जो समय अटल जी ने इसके लिए चुना, वह समय ठीक था या नहीं। इस बारे में उनको विचार करना पड़ेगा।

पड़ोसी देशों के साथ जब रिश्ते सुधारने की बात आती है तो वैसे पाकिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है, वैसे ही चीन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है। कई सालों से कदम उठाए जा रहे थे कि हम उनसे रिश्ते कैसे सुधार सकते हैं। पहले हमारे राष्ट्रपति वहां गए, राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे तो वह वहां गए। उनका डेलिगेशन आ गया और सबसे पहली शुरूआत अटल जी ने की थी जब वे फॉरेन मिनिस्टिर थे। जब हमारे रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए थे, जब अटल जी ने शुरूआत की थी और उसका स्वागत हम लोगों ने किया था। नरसिम्हा राव जी के जमाने में कुछ ऐग्रीमेंट हो गए और चाइना और भारत में एक तरह में विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था। मगर हमारे रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया। वैसे स्टेटमेंट देने की बहुत सालों से उनकी आदत है। वे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक शहर से आते थे, इसलिए दोनों ही ठीक तरह से एक दूसरे को जानते हैं। किसी के ऊपर बरसना है, एक बार उनके मन में आ गया तो कभी छोड़ते नहीं, यह सभी देशवासियों को भी पता लगा। उनका रास्ता ठीक हो या न हो मगर बरसने की बात एक बार मन में आ गई तो बरसते हैं। उन्होंने चाइना के ऊपर कुछ कहा और अटल जी के जमाने से कल तक जो रिश्ते दुरूस्त करने के लिए कदम उठाए थे, वह सब जो मेहनत हुई थी, वह मेहनत एक बयान से खत्म करने का काम उन्होंने किया। इसलिए मुझे मालूम है कि विदेश नीति के बारे में भी इस सरकार का कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप में क्या है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां 13 महीने में कछ किया हो? बहुत सी बातें की। समाज प्रबोधन की बात की, सामाजिक परिस्थिति दुरूस्त करने की बात की, महिलाओं के उत्थान की बात की। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि समाज की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। उनको अधिकार देने की बात इस सदन में कई बार की और उसकी तैयारियां हमारी हैं, यह बात आपने 50 बार यहां और बाहर कही होगी मगर इस बारे में आरक्षण देने की जो तैयारी करके सदन के सामने जिस बिल का प्रारूप लाने की आवश्यकता थी उस पर आज तक आपने कदम नही उठाया। सबसे ज्यादा गंभीर बात मेरे सामने यह है कि डिफेन्स पर्सोनल के साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं।

पूरी दुनिया में आज भारत की डिफेन्स के बारे में चर्चा हो रही है। भागवत् इश्यू पर मैं किसी का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं मगर जिस तरह से ये बातें अखबारों में आ रही थी जिस तरह से संघर्ष शुरू हुआ, वह देश की रक्षा के लिए ठीक नहीं है। यह सेन्सिटिव मिनिस्ट्री है। इस पर समझदारी से देखभाल करने की आवश्यकता थी। इससे पहले क्या ऐसा कभी नही हुआ था? इससे पहले भी हुआ था। जब जनरल कृष्णा मेनन थे और जनरल थिमय्या थे, जब भी संघर्ष हुआ और इस पर ध्यान दिया तब के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू जी ने थिमय्या को बुलाकर रास्ता निकाला। कृष्णा मेनन जी को जो बताने की आवश्यकता थी वह बताया और पर्लियामेंट के सामने उन्होंने कहा कि टैम्प्रामेन्ट प्रॉबलम्स हैं, दूसरी प्रॉबलम्स हैं। इससे पहले भी कई सवाल खड़े हुए थे मगर एक सीमा के बाहर प्रधान मंत्री या रक्षा मंत्री ने जाने की कोशिश नहीं की। मगर जिस तरह से ऐक्स नेवल चीफ का इश्यू हैण्डल किया गया, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से चीन की लड़ाई में हमारी डिफेन्स मिनिस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेज का जितना नुकसान नही हुआ, उससे ज्यादा नुकसान इस विभाग का इस इश्यू को गलत तरीके से हैण्डल करने से हुआ होगा। यह बात कई महीनों तक अखबारों में आती रहेगी। हमारे कई साथी इस इश्यू पर बहस करना चाहते थे। हम लोगों ने उनको निर्मंत्रित किया और बताया कि रक्षा से जुड़ा हुआ यह सवाल है, सेन्सिटिव इश्यू है, इस पर सदन में बहस करना ठीक नही होगा। मैंने और मनमोहन सिंह जी ने प्रधान मंत्री से मुलाकात करके जो कुछ हमारी भावनाएं इस बारे में थी, वह उनके सामने रखी। हमारी अपेक्षा यह थी कि इस पर वह ध्यान देकर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे जिससे रक्षा दल में काम करने वाले सभी साथियों के मनोबल पर बुरा असर न हो। मगर एक दिन सुनना पड़ा कि नेवल चीफ हेज बीन एक्सपेलड़। इसके मेरिट्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस इश्यू के बारे में कॉनफिडेन्शियल रेकार्ड, सीक्रेट पेपर्स पूरे देशवासियों के सामने गए, इसके शुरूआत हुई सेलेक्टिव लीकेज से। कुछ अखबारों को सेलेक्टिव लीकेज करने का काम जरूर किया गया। कुछ लीकेजिज ऐसी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने फाइलों के पेपर्स वहां उद्धृत किये हैं। रक्षा मंत्री के दो-तीन इंटरव्यूज देशवासियों ने देखे, 'मैट्रों'- में देखा, 'आपकी अदालत' में देखा और 'स्टार' तथा अन्य चैनलों पर देखा। वह वहां बैठे थे और बार-बार कागजात दिखाते थे और अमुक निर्णय लिया गया था और अमुक पत्र वहां उपलब्ध हैं। सीक्रेट पेपर्स और सैन्सिटिव पेपर्स का हम लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी कुछ मर्यादा होती है। और उस मर्यादा का सम्मान करने का जो काम रक्षा मंत्री जी का था, वह उन्होंने नही किया। यह बात मुझे यहां कहनी है। जिस तरह की बातें आई, मुझे याद है इंडियन एक्सप्रैस के मुख्य संपादक श्री शेखर गुप्ता ने लिखा था कि इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं उन्होंने लिखा था -

[अनुवाद]

> "इस विवाद के प्रत्येक पहलू से संबंधित दस्तावेज अब पूरी राजधानी में प्रचार माध्यमों के कार्यालयों से लेकर राजनयिकों तक निर्बाध रूप से पहुँच रहे हैं। तथाकथित सुपर-सीक्रेट आपरेशन लीच के बारे में ऐसी एक भी बात नहीं है जिसके बारे में कॉकटेल सर्किट को जानकारी न हो। मोरारजी देसाई द्वारा कथित रूप से फर्नान्डीज को लिखे गए उन पत्रों की प्रतियां निर्बाध रूप से परिचालित की जा रही हैं जिनमें उन्होंने फर्नान्डीज को लीबिया के साथ भारत के आणिवक सम्बन्धों के कतिपय पहलुओं पर उनकी सक्रियता के बारे में सतर्क किया था। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय में फोटोप्रतियां तैयार करने वालों ने भागवत की पुरानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों की फोटोप्रतियां तैयार करने में गत कुछ महीनों में सामान्य कार्य घंटों से कही बहुत अधिक समय तक कार्य किया है।"

इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य अनेक बाते और हैं।

[श्री शरद पवार]

[हिन्दी]

जितने जिम्मेदार अखबर हैं, उन सभी ने इस बारे में कुछ न कुछ लिखा था। जिस तरह से कागजों को बंटवारा हुआ, जिस तरह से इंफॉर्मेशंस लीक हुई और जिस तरह से उसका जवाब देने के लिए सरकार ने कदम उठाया, उससे गैर जिम्मेदारी साबित होती है। उनका जो पहला स्टेटमैंट आया था, मैं समझ सकता था। उन्होंने कहा –

[अनुवाद]

"आप मुझे मार सकते हैं परन्तु मैं राष्ट्र के व्यापक हित में कतिपय बातें नहीं बताऊँगा।"

[हिन्दी]

वहां तक उनकी भूमिका ठीक थी। मगर बाद में जिस तरह से उन्होंने बयान दिये, जिस तरह के स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज दिये, उनके चेहरे से लगता था कि यह कोई डैस्पिरेट आदमी हैं, कोई एक्सट्रीम लाइन लेकर खत्म करने के लिए जा रहा है – उन्होंने इस तरह के कदम उठाये। यह बात फर्नांडीज साहब के लिए नई नही हैं। जब एक बात वह मन में ठान लेते हैं तो आखिर तक लड़ाई करने का उनका स्वभाव है। मुझे याद है — मेरे विचार से वर्ष 1977 या 1978 में वे उद्योग मंत्री थे। 'फिक्की' में वह एक मीटिंग में आये और वहां जाकर उन्होंने रॉबर्स, रैट्स ऐसा कुछ कहा। वे उद्योग मंत्री की हैसियत से ऐसा कह रहे थे। कोई भी इश्यू हो, उसे लोगों के सामने बड़ी अच्छी तरह से रखने की उनकी हैसियत है, खूबी है। मुझे याद है एक गैलरी में बैठकर मैंने प्रैस में उनका भाषण सुना था। श्री मोरारजी देसाई के खिलाफ जब नो कांफीडेन्स मोशन आया था, उन्होंने क्या एग्रेसिवली भाषण किया था और 48 घंटे में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया।

डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी (मदुरै) : 48 नही 24 घंटे।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मुझे खेद है। मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूँ।

डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं उसका साक्षी रहा हूँ।

श्री शरद पवार : डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी उसके साक्षी रहे हैं।

[हिन्दी]

24 घंटे में उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अगर किसी का समर्थन करने की बात वह सोच लेते हैं या बड़ी अच्छी तरह से उसका समर्थन कर सकते हैं। और किसी को डिमोलिश करना हो, जिसमें कोई तथ्य हों, चाहे उसमें कोई आधार हो या न हो, वह डिमॉलिश भी बड़ी एग्रेसिवली कर सकते हैं और यह आप आज या कल देखेंगे। मगर इस वक्त सबसे गंभीर समस्या यह है कि जो भागवत ने इश्यूज रेज किये हैं, उनमें कहां तक सच्चाई है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं इसका समर्थन भी नहीं करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने अखबार वालों को कुछ कागजात दे दिये, वह भी गलत है, मैं इसका भी कभी समर्थन नहीं करूंगा। मगर जो इश्यूज उन्होंने बनायें और डिफेन्स मिनिस्टर ने मीडिया के माध्यम से गंभीर इश्यूज देश के सामने रखे, मुझे लगता है कि उनकी जांच होने की आवश्यकता है, किसी इंडिपेंडेन्ट एजेन्सी के माध्यम से उनकी जांच होने की आवश्यकता थी, इसलिए जे॰पी॰सी॰ की मांग हुई थी। मगर प्रधान मंत्री ने जे.पी.सी. हमें मंजूर नही, यह बात सदन के बाहर पहले ही कह दी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब इस सदन में छोटी-छोटी बातों को लेकर, सदन को दो-दो और तीन-तीन दिन तक ठप्प रखा गया, लेकिन जब देश के रक्षा के मामले में जे.पी.सी. बनाने और उसके माध्यम से जांच कराने का प्रश्न इस सरकार के सामने आया, तो स्पष्ट मना कर दिया गया। इससे इस सरकार की रक्षा के बारे में नीति और नीयत क्या है, इसकी जानकारी मिलती है और वह सारे देशवासियों के सामने आ गई है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पिछले 12 महीने के कार्यकलाप को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकार ने मजबूती के साथ कदम उठाया हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र को देख लें, चाहे यह आर्थिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या सामाजिक एकता को बनाए रखने का क्षेत्र हो, यह सरकार सभी क्षेत्रों में काम करने और लोगों को विश्वास में लेने में बिलकुल असफल रही है और इस असफलता का परिणाम दिल्ली में जनता ने दिखाया, राजस्थान में जनता ने दिखाया, मध्य प्रदेश में जनता ने दिखाया और आठ-नौ उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देकर दिखाया। इस सरकार ने देश में साम्प्रदायिक घृणा फैलाने का काम किया है। देशवासियों को विश्वास दिलाने और सभी क्षेत्रों में उन्नति करने की सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को इस सरकार ने नही निभाया और देश को पीछे ले जाने का काम किया। इसलिए इस सरकार को इस देश की बागडोर संभालने का एक मिनट भी अधिकार नही है। अतः मैं सभी विरोधी दल के भाइयों से उम्मीद रखता हूं कि वे इस विश्वासमत के विरोध में मत देंगे। मैं सभी विरोधी दल के लोगों से आशा करता हूं कि सैकुलरिज्म का समर्थन करने वाली इस सरकार के विरोध मत दें और इक्कीसवीं सदी में देश को ले जाने वाली मजबूत सरकार को विकल्प के रूप में बनाएं। यह विश्वास मैं इस सदन और इस सदन के माध्यम से पूरे देश को देता हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः इस प्रकार के विश्वास प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री जब प्रस्ताव रखते हैं, उसके साथ-साथ कुछ विस्तार से अपनी बात कहते हैं।.आज वाजपेयी जी ने प्रस्ताव के साथ-साथ अपनी सरकार के पिछले साल के काम का कोई आकलन प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन कुछ शब्दों में, दो-तीन वाक्यों में उन्होंने जो बात कह दी, वह वास्तव में आज की परिस्थिति की मूल समस्या है और मैं अपेक्षा करता था कि उन दो-तीन वाक्यों का कुछ विस्तार से उत्तर मुझे विपक्ष के नेता से मिलेगा और उन्होंने शुरू में कहा भी कि हमारी जवाबदारी है कि जिस समय किसी

सरकार का विरोध करें, तो उस समय हम क्या विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका भी जिक्र करें। इसलिए 45-50 मिनट तक शरद पवार जी बोलते रहे और मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता रहा कि कहीं मुझे उसकी कुछ झलक मिले।

अध्यक्ष जी, मुझे याद आता है कि आपके पूर्व अधिकारी श्री शिवराज जी पाटिल शायद सदन में होंगे, पीछे बैठे हैं, मैं उनका हमेशा आदर करता हूं। वे कभी-कभी बड़ी मौलिक बात सदन और देश के सामने विचार के लिए रखते हैं। उन्होंने एक बार बात कही थी जिसका अनुमोदन प्रधान मंत्री जी ने स्वयं किया था, शायद वे उस समय विपक्ष के नेता थे, जिस समय उन्होंने कहा कि दुनिया के संविधानों के अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं और उनमें से एक व्यवस्था जर्मनी में है। जर्मनी की व्यवस्था अच्छी है। वह इस कारण से बहुत अच्छी है कि वहां कभी भी अस्थिरता पैदा नहीं होगी। मैं जर्मन संविधान का उद्धरण लेकर आया हूं। यह है - बसुज 'सलेक्ट कांस्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड' उसके अनुच्छेद 67 में...(*व्यवधान*) यह महत्व की बात है और यह बात शिवराज पाटिल जी ने कही है इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। इसका संबंध है कि सदन सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से कर सकता है। जर्मनी के संविधान में व्यवस्था है कि अगर किसी सरकार के अविश्वास का प्रस्ताव रखना हो, तो—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 67 में यह व्यवस्था है :

> "बुण्ड्सटेग...", जिस का अभिप्राय है संसद, "... अपने सदस्यों के बहुमत से उत्तराधिकारी का चुनाव करके और संघीय राष्ट्रपति से फेडरल चांसलर को बरखास्त करने का अनुरोध करके फेडरल चांसलर में अपना अविश्वास व्यक्त कर सकती है।"

[हिन्दी]

नई सरकार चुनने से पहले वे किस सरकार को बनाना चाहते हैं, इसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध करना पड़ता है कि वर्तमान सरकार को हटा दो।

श्री मोहन सिंह : आपने इसी संविधान की कसम खाई है। ...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए सामान्यतः व्यवस्था इतनी है कि यहां पर अगर आपको सरकार पसंद नही है, सरकार को आप हटाना चाहते हैं या हटाना तो छोड़िये, हम लोग विपक्ष में तब रहे हैं, श्री वाजपेयी जी, मैं, सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के बहुत सारे लोग विपक्ष में थे, कहीं भी सरकार को हटाने की गुजांइश नही थी फिर भी हम अविश्वास का प्रस्ताव लाते थे। अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य यह होता था कि हम सरकार के काम से सर्वथा असंतुष्ट है और इसलिए अपना क्षोभ व्यक्त करना चाहते हैं। यह जानते हुए भी हमारे पास मैजोरिटी नहीं है, नम्बर्स नहीं हैं और नम्बर्स के परिणाम के आधार पर हमारा अविश्वास का प्रस्ताव छूट जायेगा, हार जायेगा, सोमनाथ जी यहां बैठे हैं, इन्द्रजीत गुप्ता जी यहां बैठे हैं, हम सब जब अविश्वास का प्रस्ताव लाते थे तो उसका परिणाम भी जानते थे, फिर भी लाते थे। मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले पांच-सात दिनों में इसकी काफी चर्चा चली है कि जब ए.आई.ए.डी.एम.के. अपना समर्थन वापिस ले लेगी तो अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा या विश्वास प्रसताव पर बहस होगी। राष्ट्रपति जी ने हमारी सरकार को, प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर भेजा, उसी के अनुसार प्रधान मंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा है लेकिन समझने की बात यह है कि विपक्ष जिसको पता है कि हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था तो है लेकिन विश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था नही है। विश्वास प्रस्ताव तो ट्रेडीशन से डैवलप हुआ है और वह ट्रेडीशन उस समय डैवलप हुआ जब शुरू-शुरू में राष्ट्रपति किसी को आमंत्रित करता है और उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उसको कहता है कि इतने दिनों में तुम अपना स्पष्ट बहुमत परिमाणित करो। इस तरह वह शुरू हुआ और वह शुरू होते-होते बीच में ऐसा काल भी आया जब सदन में चलते हुए किसी ने अपना समर्थन वापिस ले लिया तो उस समय भी राष्ट्रपति जी ने कहा कि आप अपना बहुमत परिमाणित करिये। उसी के अनुसार आज भी किया है। मैं उसकी बहस में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अविश्वास के प्रस्ताव या विश्वास के प्रस्ताव पर दो दिन या तीन दिन बाद जब बहस समाप्त होगी तो परिणाम वही निकलेगा जो हर सदन में पिछले साल भर में निकलता रहा और जो अभी-अभी इस सदन में बिहार के मामले को लेकर निकला था और आप यहां से निराश होकर निकलेंगे।...(*व्यवधान*) लेकिन महत्व की बात यह है कि इतना आग्रह क्यों था कि अविश्वास का प्रस्ताव न हो, विश्वास का प्रस्ताव हो? मैं जानता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति या लाने वाली पार्टी के ऊपर जवाबदारी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रमाणित करे, संख्या नही, प्रमाणित करे कि इस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, इतना खराब काम किया है कि इसे हटाना परम आवश्यक हो गया है। पूरी देर सारे विपक्ष को लगता था कि जिस सरकार ने पोखरण किया, जिस सरकार ने अग्नि किया, जिस सरकार ने अभी-अभी का बजट किया, जिस सरकार ने लाहौर की यात्रा की, जो सरकार कश्मीर में इतना परिवर्तन लाई, जो सरकार सारे एशिया में, जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं हिल-डुल गई थीं तब भी यहां पर स्थिरता लाई, उस सरकार के खिलाफ वास्तव में कहने को क्या है। कुछ नहीं। इसीलिए एक ही बात है कि आपके एक सहयोगी दल, जिसने समर्थन दिया था, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जी ने आपको बुलाया था, ने अब समर्थन वापिस ले लिया है। अब आप अल्पमत में रह गए हैं इसलिए आप त्याग पत्र दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं स्मरण कराना चाहूंगा, जिस समय पर ए.आई.ए.डी.एम.के. ने हमको समर्थन दिया था, उस समय भी हमारी कुल संख्या 252 थी, बहुमत नही था। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री शरद पवार ने स्वीकार किया कि उनको जनादेश नहीं मिला। लेकिन वे कहने की कोशिश करने लगे कि किसी को जनादेश नहीं मिला। मैं इससे सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र की इस

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली में जो सबसे बड़ा कौम्बीनेशन है, वह चाहे मैजोरिटी न भी हो, इसीलिए राष्ट्रपतिजी ने जिस समय वाजपेयी जी को इस सारे ऐलायंस के नेता के नाते बुलाया, उन्होंने जनादेश का आदर किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप मुझे पहले 272 दिखाइए, फिर मैं बुलाऊंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कोई जनादेश नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे स्मरण है जब ए.आई.ए.डी.एम.के. की नेता ने, जैसे बाकी सबने पत्र भेजे, समता पार्टी ने भेजा, अकाली दल ने भेजा, बीजू जनता दल ने भेजा, शिव सेना ने भेजा, तब भी उन्होंने अपना पत्र नहीं भेजा था। उस समय हमने आपस में विचार किया कि अब तो हमारी संख्या शायद 238 हो गई। हम राष्ट्रपति जी को कह दें कि आप किसी और को बुलाइए और वाजपेयी जी ने हिंट भी किया कि आप बुलाना चाहें तो किसी और को बुलाइए, जिनकी इससे बड़ी संख्या हो। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन इस बीच वह पत्र आ गया और हमारी 252 की संख्या के आधार पर शपथ दिलाई गई। तब भी हम अल्पमत में थे। आज 18 कम हो गए, 18 नहीं मैं एक और भी गिनूंगा, 19 कम हो गए।... *(व्यवधान)* इसीलिए मैं पहले इस बात पर बल देना चाहूंगा कि 1998 के लोक सभा के चुनाव में हिन्दुस्तान की जनता ने इस प्रणाली के अधीन एक मत व्यक्त किया और जो जनादेश है, वह स्पष्ट है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ऐलायंस की सरकार बने। यह देश का जनादेश है और 1996 से भिन्न है। 1996 में मुझे याद है कि वह जनादेश एक प्रकार से बी.जे.पी. के लिए था कि सबसे बडी पार्टी करके उभरे। इसलिए उस समय भी डा॰ शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी जी को बुलाया। लेकिन यह बात सही है कि उन दिनों स्थिति ऐसी थी कि और कोई पार्टी हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी सिवाए शिव सेना के, जो हमारे साथ चुनाव में भी थी और चुनाव के तुरंत बाद अकाली दल हमारे साथ आया था, चुनाव में वह भी नहीं था। ये परिवर्तन हिन्दुस्तान की राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होते रहे हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं। जिस पार्टी के पास आज से दस साल पहले 1989 में केवल दो सदस्य थे, आज उस पार्टी के साथ इतने सहयोगी दल जुड़े कि हम 252 की संख्या में पहुंचे। शक्ति परीक्षण हुआ तो कांग्रेस पार्टी और इधर बैठे हुए लैफ्टिस्ट लोग, एस.पी. और आर.जे.डी. सबको मिलाकर 29 वोटों से इसी सदन में पराजित किया और यह जनादेश ज्यों का त्यों है।

आज मुझे बहुत खुशी हुई श्री शरद पवार ने इस बात का जिक्र किया कि श्री वाजपेयी जी का पूरा जीवन राजनीति में सत्ता के लिए न होकर मूल्यों के लिए हुआ है। नैतिकता के ऊपर आधारित रहा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो अपेक्षा करता था कि जिस समय ए.आई.ए.डी.एम.के. अपना समर्थन वापस ले लेगी तो वाजपेयी जी तुरन्त जाकर इस्तीफा दे देंगे-यह उन्होंने कहा। अगर वाजपेयी जी इस्तीफा देते तो वे जनता की इच्छाओं का आदर नहीं करते। आज प्रातःकाल ही मैं देख रहा था, मेरे पास ये आज की क्लिपिंग्स हैं, जिसमें एक ओपिनियन पोल लिया गया है, जिस ओपिनियन पोल में. ..*(व्यवधान)* यह ओपिनियन पोल ए.आई.ए.डी.एम.के. के समर्थन वापस लेने के बाद लिया गया है। अध्यक्ष जी, इस ओपिनियन पोल के अनुसार अन्नाद्रमुक...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अपनी बात पर कायम हूं। अन्नाद्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद ओपिनियन पोल लिया गया है कि क्या वाजपेयी जी की सरकार को तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए या सत्ता में बने रहना चाहिए और द्रमुक व अन्य दलों का समर्थन जुटाना चाहिए, इस पर उन्होंने मत लिया। उसमें 22 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनको त्याग-पत्र देना चाहिए और 71 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनको त्याग-पत्र नहीं देना चाहिए और उनको डी.एम.के. और अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाकर जिस प्रकार से साल भार से वे देश की सेवा करते आये हैं, वैसे उनको करते रहनी चाहिए। इसीलिए मैं जानता हूं कि इस समय एक डैमोक्रेटिक लीडर के नाते जनादेश का आदर करते हुए वाजपेयी जी ने यह कहा और राष्ट्रपति के निर्देश को मानते हुआ कहा कि मैं सदन के सामने रखता हूं कि आप विश्वास के प्रस्ताव पर अपना मत दीजिए, जो भी आपका निर्णय होगा, उसे मैं शिराधार्य करूंगा।

शरद जी ने एक बात कही। उन्होंने हमारे खुराना जी को कहा कि अपनी पीड़ा व्यक्त करिये। हमारी पार्टी में किसी को अगर पीड़ा है, किसी को कष्ट है तो वह किसी नेता के पास आकर अपनी पूरी बात कह सकता है, लिख सकता है। यह आप जैसी स्थिति नहीं हैं कि आप अपनी पीड़ा इधर-उधर व्यक्त करते रहे, लेकिन आप अपने नेता को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए, व्यथा व्यक्त करते हुए चिट्ठी लिखने का साहस कभी नहीं कर सकते। यह पार्टी ऐसी है, जिस पार्टी में साधारण कार्यकर्त्ता भी बड़े से बड़े नेता के पास जाकर अपने दिल की बात कह सकता है। आपके यहां का वातावरण हमारे यहां नहीं है कि जिस वातावरण में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : श्री खुराना जी को अपना वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई? कृपया उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : खुराना जी, कभी भी कुछ कहना चाहें तो उनको कहीं कोई बंधन नही है। वे आपकी सारी की सारी पोल खोल देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : आप कुछ ही दिनों में वापस बारामती भेजे जाने वाले हैं।...(*व्यवधान*)

श्री शरद पवार (बारामती) : मैं वहां जरूर जाऊंगा। ...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस नाते तो बात सही है कि शरद जी ने और उनके कई साथियों ने या विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों ने पहले दिन से यह कहना शुरू किया है कि यह सरकार चलेगी नहीं, यह सरकार तो अभी गिरी। हर सैशन शुरू होता है तो हम यही बात अखबारों में सुनते हैं कि इस बार तो सरकार गई। अभी पिछले बजट अधिवेशन में कहना शुरू किया था कि बजट अधिवशेन कैसे पार करेंगे, तब से कहना शुरू किया था और इसीलिए शायद बहुत लोगों के लिए यह भी उपलब्धि लगती है। पिछली पांच सरकारें, वैसे तो कुल मिलाकर 1989 के बाद पांच गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री हुए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए, चन्द्रशेखर जी हुए, फिर इन्द्रकुमार गुजाराल जी हुए, देवेगौड़ा जी हुए और वाजपेयी जी हुए, इन पांच प्रधान मंत्रियों में से बाकी चारों प्रधान मंत्री एक साल नहीं बिता पाये। एक साल का कार्यकाल बिता पाये, वाजपेयी जी ने साल भर बिताया, इसी पर आपको आश्चर्य होता है, लेकिन मैं मानता हूं...(*व्यवधान*) मैं 1989 के बाद की बात कर रहा हूं। 1989 के पश्चात् गैर-कांग्रेसी दलों के पांच प्रधान मंत्री बने हैं। मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि केवल साल भर सरकार चलाना कोई उपलब्धि नहीं है। इस साल भर में हमने भारत में एक दूसरे प्रकार का वातावरण खड़ा किया है। भारत को विश्व भर में एक स्थान प्राप्त करवाया है, यह जो उपलब्धि है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तो इस कांग्रेस पार्टी पर ताज्जुब करता हूं कि जिसने पोकरण-II की आलोचना की और आज मैं सुनकर हैरान हुआ, जब अग्नि-II का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम एक और आर्म्स रेस शुरू कर रहे हैं। हमको इस बारे में कोई संकोच नहीं, पोकरण-II से लेकर अग्नि-II तक भारत को इस सरकार ने और सबल किया है, और अधिक मजबूत किया है। इस पर आपकी पार्टी अपोलोजेटिक हो सकती है, आपकी पार्टी आर्म्स रेस की बात कर सकती है...(*व्यवधान*)

श्री भजनलाल (करनाल) : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। क्या यह पोकरण वाला विस्फोट और अग्नि का परीक्षण आपकी देन है, इस देश को। यह कांग्रेस की नीतियों का फल है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है. ..(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : ये आपको मंत्री नहीं बनाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं जानता हूं कि हमारे विदेश मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी इस बार की बहस में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वे बोलेंगे तो निश्चित रूप से मई के महीने में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो-जो बयान हुए थे, जो-जो वक्तव्य दिये गये थे कि इस सरकार ने भारत को अलग-थलग कर दिया है, इस सरकार ने गांधी को, बुद्ध को भुला दिया है, इस सरकार ने पोकरण-II करके देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया है। दुनिया भर की अलग-अलग बातें कहीं। यहां पर नटवर सिंह जी होंगे, उनका बयान उठाकर पढ़िये, वे क्या-क्या बोले थे और उसके साल भर बाद, साल भर भी अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या स्थिति हुई है? आज कोई इस बात की आलोचना नहीं करता पोकरण-II न केवल भारत और भारतीयों द्वारा एक उपलब्धि मानी गई है अपितु सारे संसार में इसका सम्मान किया गया है।

श्री भजनलाल : यह आज की सरकार ने बनाया है क्या?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम उनमें से नहीं हैं, जो केवल विपक्ष में बैठकर आलोचना ही करें। जब इन्दिरा जी ने 1974 में पोकरण का पहला-पहला विस्फोट किया था तो शायद वाजपेयी जी सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उनकी तारीफ की थी और सरकार की तारीफ की थी। हम आपकी तरह नहीं करते और इसीलिए मुझे बड़ा दुख हुआ, जब आज खासकर पूर्व रक्षा मंत्री अग्नि-II के बारे में यह वाक्य बोलते हैं कि अग्नि-II का परीक्षण इस समय करने की क्या जरूरत थी, जब हमने एक हिस्टोरिक इनीशिएटिव लिया है, बस राइड करके पाकिस्तान से दोस्ती करने का तो पाकिस्तान को इस प्रकार से चिढ़ाने का क्या औचित्य था? मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान अपने को मजबूत करे, हिन्दुस्तान देश के अन्दर आतंकवाद को समाप्त करे और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करे, यह परस्पर विरोधी एप्राचिज़ नही हैं, ये परस्पर पूरक एप्रोचेज हैं।

मुझे याद आता है, आज से कई साल पहले, चार साल हो या पांच साल हों, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और पाकिस्तान में जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर बैरिंग्टन नाम के थे, वे यहां पर आये थे। वे जब मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्य रूप से आपसे हिन्दुस्तान पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में, कश्मीर समस्या के बारे में चर्चा करने आया हूं और आपका दृष्टिकोण, आपकी पार्टी का दृष्टिकोण मैं समझना चाहूंगा। उस चर्चा में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि मेरा यह विश्वास है, मेरा यह कन्विक्शन है और पाकिस्तान में जो एलीट है, उसका भी कन्विक्शन है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध सबसे अच्छे तब बनेंगे, जब नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। उन्होंने जब यह कहा तो फिर उन्होंने दुनिया भर की एनोलोजीज़ देते हुए कहा कि अमेरिका और चाइना के सम्बन्ध तब अच्छे हुए, जब प्रेजीडेंट निक्सन हुए, जिनके बारे में चीन में माना जाता था कि वे फार्मूसा समर्थक हैं, वे चीन के खिलाफ हैं, वे कट्टर एंटीकम्युनिस्ट हैं, वैसी ही धारणा बी.जे.पी. के बारे में, वाजपेयी जी के बारे में और आपके बारे में बनी हुई है। मुझे यकीन है जिस दिन आपकी सरकार आएगी, उस दिन निश्चितरूप से भारत-पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध सुधारने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मैं तारीफ करता हूं, वाजपेयी जी को बधाई देता हूं कि सालभर भी नहीं बीतने दिया, पोखरण के बावजूद, अग्नि की

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

तैयारी करने के बावजूद उन्होंने लाहौर की यात्रा की, जिसकी पाकिस्तान में तारीफ हुई, दुनिया भर में तारीफ हुई कि इतनी शानदार और ऐतिहासिक पहल और किसी देश की सरकार ने नहीं की। आप कर सकते थे, क्यों नहीं की, आप पोखरण में विस्फोट कर सकते थे, क्यों नहीं किया?

आज मैं देखकर हैरान होता हूं कि कम्युनिस्ट किस उत्साह से कांग्रेस की सरकार बनाने को तत्पर हैं। अजीब हैं सचमुच! आज से ढाई साल पहले आपका एक डाक्युमेंट मेरे पास आया था, क्योंकि मैं इस विषय पर कि आप सरकार के आलोचक हैं, ऐसा नहीं जानता था। इन दिनों जब मैं देखने लगा तो मुझे लगा कि आप कांग्रेस पार्टी के आलोचक केवल इस कारण नहीं कि कांग्रेस पार्टी करप्ट है, कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिक्योरिटी के बारे में उदासीन है, सुरक्षा के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। 1996 का सी.पी.आई.(एम) का एक पब्लिकेशन है।

[अनुवाद]

यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का 1996 का एक प्रकाशन है जिसका शीर्षक है :-

"रिकार्ड ऑफ कम्प्रोमाइजिंग इंडियाज सिक्युरिटी"

इसमें हमारे सी.पी.आई. (एम) के मित्र क्या कहते हैं-

> "भारत के सुरक्षा हितों के साथ विश्वासघात करने और उसकी प्रभुसत्ता के साथ समझौता करने को कांग्रेस के खिलाफ आरोप-पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पिछले पांच वर्षों में, यानी वर्ष 1991 से 1996 तक अमरीका और उसके मित्र देशों द्वारा भारत सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से अत्यधिक दबाव डाला गया है।

कांग्रेस सरकार ने बार-बार भारत के व्यापक हितों के साथ समझौता किया है।

> अमरीका ने भारत को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी विकसित करने से रोकने और हमारी आण्विक प्रौद्योगिकी पर रोक लगाने का पक्का इरादा कर लिया था और अपने एजेंडा में स्वतंत्र कश्मीर के लिए भारत के हितों के खिलाफ होकर वे भारत के सैन्य स्थापन के साथ सहयोगी बनने में सफल हो गये हैं। कांग्रेस (आई) सरकार की साम्राज्यवाद समर्थक नीति के लिए धन्यवाद।"

कोलैबोरेटर अमेरिकन हैं इनके या आप हैं कोलैबोरेटर इनके?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप अधिक बड़ा खतरा हैं।

डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी : वे कोलैबोरेटर हो सकते हैं परन्तु आपने तो आत्मसमर्पण कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोलैबोरेटर कौन हैं, इसीलिए मैं हैरान होता हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि इस सदन में...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : आडवाणी जी, मैं एक निमट लेना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं हमेशा आपका आदर करता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या आप बंगला देश को भूल गए, 95,000 को भूल गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नंही भूला हूं।

श्री बलराम जाखड़ : सातवां बेड़ा भी चला गया, क्या वह भी भूल गए, थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान करें। अगर यह नहीं होता तो बात दूसरी होती

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं भूला हूं। जाखड़ जी, जब बंगला देश स्वतंत्र हुआ था, आप शायद भूल गए कि तब वाजपेयी जी ने इंदिरा जी के बारे में क्या कहा था, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि आप इनके भरोसे चल रहे हैं, इनके भरोसे सरकार बनाने की कल्पना करते हैं, इनको पहचानिए और सारी दुनिया इनको पहचाने। मैं यह बताना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी पर मुझे गुस्सा कम आता है, मुझे इन पर दया आती है।...*(व्यवधान)* कल तक जो पार्टी यह सोचती थी कि...*(व्यवधान)* आधी दुनिया पर हमारा अधिकार है और थोड़े सालों बाद सारी दुनिया पर हमारा अधिकार हो जाएगा जिसमें भारत भी एक हिस्सा होगा, वहां की स्थिति यह है कि सारी दुनिया से साफ होकर केवल भारतवर्ष के दो कोनों में आकर सीमित हो गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा आपकी सहायता से या आपकी कृपा से नहीं हुआ है। श्री आडवाणी जी आपने भिन्न-भिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों की सहायता प्राप्त की है परन्तु हमारी सहायता नहीं ली है...*(व्यवधान)* हम आपको जवाब देंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह मैंने 1996 का आपको पढ़कर सुनाया है। यह 1996 का डॉक्यूमेंट था लेकिन 1998 का चुनाव जब हमारे लेफ्टिस्ट मित्रों ने लड़ा था तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो इश्यू किया था।

[अनुवाद]

वामपंथी दलों के 1998 के घोषणा पत्र, जो उन सब पर लागू होता है, में कहा गया था कि :

> "कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों ही

दृष्टि से पतन हो गया है। इस पार्टी का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि इसने सत्ता में रहकर ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाया है जो जनता के विरूद्ध हैं। इसने साम्प्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करके हमारी धर्मनिरपेक्ष विरासत के प्रति विश्वासघात किया है और इस पार्टी में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है।"

[हिन्दी]

यह पार्टी कहती है कि सरकार बना लो, हम आपको बाहर से समर्थन करेंगे। आपको हम अनकंडीशनली समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप अपने बारे में बोलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे बारे में हम बोलेंगे, आप अपने बारे में बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं फिर से उसी पर आता हूं। इस बहस में सार्थकता आएगी अगर आप कह दें कि हम इस सरकार को हटाकर क्या विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से कह दीजिए। सोनिया जी ने एक बार कहा कि अब यह कोएलिशन का जमाना नहीं है। पचमढ़ी में उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे और इसीलिए पिछले दिनों, पांच-सात दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो तब बनाएगी जब बाकी सब पार्टीज हमें बाहर से समर्थन देंगी। कोई कहे कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं वित्त मंत्री बनूंगा, मैं वह बनूंगा, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहां बैठे हैं और मैं इन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण आपसे ज्यादा साफ है। कम से कम उनकी नीयत साफ है। दृष्टिकोण भले ही साफ न हो लेकिन नीयत साफ है। आज से छः महीने पहले तक, सितम्बर के महीने तक, जब तक पचमढ़ी का आपका सम्मेलन हुआ था, तब तक उन्होंने क्या देखा था कि यह वाजपेयी जा की सरकार बनी और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बड़ी पार्टी ने कहा कि हम चिट्ठी राष्ट्रपति जी को नहीं भेजते, इस प्रकार के एलायंस से यह सरकार कैसे चलेगी? शुरू-शुरू में कह दिया कि जिसने चुनाव के साथ-साथ भाग लिया और वह चिट्ठी भेजने में आनाकानी करती है और फिर यहां से किसी दूत को भेजना पड़ता है। जसवंत सिंह जी को कष्ट करना पड़ता है कि वह जाकर उनको मनाए। यह सब चलाऊ रूख देखा। फिर उन्होंने यह भी देखा कि इस पार्टी में कई सारे लोग हैं, उनकी भी प्रधान मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हो सकती है। एक ही थोड़े ही है ना और कुछ नहीं तो कम से कम वाजपेयी जी और आडवाणी के बीच में दरार कैसे डाली जाए, लगातार मिसइफॉर्मेशन फैलाओ और उन्होंने यह बहुत ही सिस्टैमैटिकली किया, मानना पड़ेगा, यह मैं मानूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मदल लाल खुराना ने किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मदन लाल खुराना स्वयं देखेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आडवाणी जी, मैं आज वह खुशहाली देख रहा हूं, आपके चेहरे से लग रहा है जो पिछले एक साल में पहली बार ऐसी खुशहाली देखी है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : राजेश जी, यह पार्टी किस प्रकार की है, इसकी आपको कल्पना ही करनी पड़ेगी।

यह कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी में क्या हो सकता है, यह तो पिछले आपके अध्यक्ष जिस प्रकार से पूर्व अध्यक्ष को हटाकर बने, तब सबने देखा था। यह पार्टी वैसी नहीं है। हमारी पार्टी को ही छोड़िए, लेकिन हिन्दुस्तान भर में इस प्रकार का नेता आपको नहीं मिलेगा, देश को नही मिलेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इतना कद है, इतनी कदावर है और बावजूद इसके कि उनकी विचारधारा में कमिटमेंट होते हुए भी, मेरी विचारधारा में कमिटमेंट होते हुए भी, मैं कभी इस प्रकार की इमेज क्रीएट नहीं कर पाया, जिसमें लोग मुझे कट्टरवादी मानते हैं, जबकि कट्टरता इस विचारधारा में ही नहीं। शरद पवार जी ने सही कहा - हिन्दुत्व की सबसे बड़ी विशेषता है, तो उदारता है, वह सहिष्णुता है और सब लोगों को समेटकर चलने की बात है। अगर यह न होती, तो 1947 में जो संविधान के निर्माता बैठे, उन्होंने 1950 में संविधान न बनाया होता।...*(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : आप हिन्दुत्व की बात कह रहे हैं, आने रामराज्य की बात की थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि इतने बड़े समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि यह सरकार फन्डामैंटलिस्ट हो रही है। मुझे इस बात का खेद है कि बीजेपी की सरकार के आने के तुरन्त बाद से विश्वभर में इस बात का प्रचार किया गया है और हमारे ही लोगों ने किया है कि हिन्दुस्तान में फण्डामैंटलिज्म आ गया है। कोई फण्डामेंटलिज्म नहीं आया है और फण्डामेंटलिज्म आ ही नहीं सकता है। हिन्दुस्तान में सैक्युलरवाद है और यह हमारे यहां की धरती में है और जड़-जड़ में है।...*(व्यवधान)* मैं अध्यक्ष जी, निवासी उस भाग का हूं, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं सिंध का निवासी हूं। इस क्षेत्र से करोड़ों लोग बेघर होकर इधर आए। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो किस आधार पर हुआ? पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर कि कहां पर हिन्दुओं का बहुमत है और कहां पर मुसलमानों का बहुमत है। उसके आधार पर नक्शे खींचे गए और पाकिस्तान ने अपने को मजहबी राज्य घोषित किया कि हमारा इस्लामिक राज्य होगा। इस्लामिक राज्य और मजहबी राज्य का अर्थ है कि मुसलमान प्रथम दर्जा नागरिक है और बाकी द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। अगर भारत उस समय यही करता, तो शायद दुनिया हमको दोष नहीं देती, दुनिया कहती कि आखिर कांग्रेस पाटी पार्टिशन के खिलाफ थी। कांग्रेस पार्टी को पार्टिशन को स्वीकार करने

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

के लिए मजबूर किया गया। दुनिया चाहे दोष नहीं देती, लेकिन हम अपने को माफ नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान की परम्परा, हिन्दुस्तान का इतिहास, हिन्दुस्तान की संस्कृति कभी भी मजहबी राज्य की कल्पना स्वीकार नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती है। न पूर्व में किया और न भविष्य में करेगी। सैक्युलरिज्म का मतलब है, सभी धर्मों के साथ समान आदर, सभी मजहबों के समान आदर, सारे नागरिक किसी भी मजहब के अनुयायी हों, उनके लिए समान न्याय, समान सुरक्षा। सिक्योरिटी और सैक्युलरिज्म हमारे संविधान के हिस्से हैं। यह सरकार पूरी तरह से उनके प्रति प्रतिबद्ध है। इसमें कभी कोई विचलित होने का कारण नहीं है। दुनिया भर में आपने प्रचार किया और मुझे दुःख हुआ, आज जब शरद पवार जी ने ईसाई के मसले को उठाकर दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि ईसाइयों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं...(*व्यवधान*) मैं इसका जवाब एक बार विस्तार से दे चुका हूं, फिर नहीं दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम छः घटनायें दुनिया भर में ऐसी प्रचारित हुई, जिनका आधार ही नहीं था, तथ्य ही नहीं था। झाबुआ की घटना से, बारीपद में किसी नन के बलात्कार की घटना से लेकर जो क्रम शुरू हुआ, ये सारे प्रकरण गलत साबित हुए। ये कहीं नहीं छपे, इनका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं छपा।...(*व्यवधान*) मैंने कहा कि ऐसी छः घटनाएं हुई, इलाहाबाद, उड़ीसा आदि अन्य जगहों पर हुई। इन सारी घटनाओं में मैं यह स्वीकार करूंगा कि ये जो घटनाएं हुई हैं वे नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है कि कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय एवं अत्याचार न हो, खास कर अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो मेरी सरकार को अपने को जिम्मेदार मानती है, हमारा उनके प्रति खास दायित्व है। लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार हुए हैं, उनसे यह संशय पैदा होते हैं, जिनकी मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज ने अभिव्यक्ति की, मैंने नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कहूंगा तो कोई इस प्रकार का आरोप नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई षडयंत्र है और इसलिए सरकार ने पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में एक घटना को लेकर ऐसा किया। एक आस्ट्रेलियन नेशनल थे, जिनके दो बच्चों की हत्या हुई। उन्हें जिन्दा जलाया गया, वह बड़ा भयंकर भीषण कांड था। हमने कहा कि इसके लिए साधारण कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं, बल्कि जैसे राजीव गांधी की हत्या के समय कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होगा वैसे हम लेंगे। हमने विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश श्री आनन्द से अनुरोध किया कि यह घटना ऐसी है इसलिए इस घटना के कारण हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप किसी सिटिंग जज को स्पेयर करिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास वैसे ही सीटिंग जज कम हैं, मैं किसी रिटायर जज को ले लूंगा, आप सिटिंग जज का आग्रह क्यों करते हैं। तब हमने कहा कि नहीं, हम इस बारे में विश्वसनीयता पैदा करना चाहते हैं इसलिए आप सीटिंग जज को स्पेयर करिए। उन्होंने हमारी बात को माना और अब एक सिटिंग जज उसकी जांच कर रहा है। मैं उसके बारे में इस समय अन्य कुछ नही कहूंगा, सिवाए इसके कि जहां तक यह सरकार है, इस सरकार को इस बात का गर्व है कि पिछले दस सालों में 1989 से लेकर 1998 तक कभी भी साम्प्रदायिक घटनाएं इतनी कम नहीं हुई, साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, जिस प्रकार 1998 रहा। कुला मिलाकर यह वर्ष, 1998, दंगा मुक्त वर्ष रहा है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में से कोई वैकल्पिक सरकार नहीं उभर सकती, यह कांग्रेस पार्टी का भी कंविक्शन है। इसलिए ये सब को उकसा रहे हैं कि चलो, आपकी सरकार बन जाएगी, देवेगौड़ा की बन जाएगी, थर्ड फ्रंट बना ले, हमारी बना लो, हमें बाहर से समर्थन करो, उन्हें पता है कि कोई बाहर से समर्थन करके आपकी सरकार नहीं बनाएगा। इसलिए आप पहले हमारे साथ मिल कर इस सरकार को हटा दो। अगर कोई प्रमाण देना था तो शरद पवार जी के उत्तर में देना था। जैसे लालू प्रसाद जी ने कहा कि एक मिनट लगेगा, हम बैठ कर फैसला कर लेंगे।...(*व्यवधान*) यह तकलीफ आपको नहीं करनी पड़ेगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं अपने डीएमके के मित्रों का आभारी हूं, जिन्होंने सारी स्थिति को पहचान कर सही तरीके से निर्णय किया कि हमें चाहे जितना भी कठोर कदम उठाना पड़े लेकिन हम निश्चित रूप से देखेंगे कि यह जो सरकार को गिराने का षडयंत्र है वह विफल हो। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज तक तो हम समझते थे कि हिन्दुस्तन की राजनीति में हमें अछूत बनाने का प्रयत्न...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री आर• मुथैया (पेरियाकुलम) : इसी डी.एम.के. ने कहा था कि हम इस *पण्डारम* और *परदेशी* को तमिलनाडु में प्रवेश नहीं करने देंगे...(*व्यवधान*) इसी डी.एम.के. ने उन्हें *पण्डारम* और *परदेसी* कहा था...(*व्यवधान*)।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे तब बहुत अच्छा लगा। अब आज से दो दिन पहले इन्होंने मार्क्सवादी पार्टी का वक्तव्य देखा। हम अन्नाडीएमके के साथ नहीं जायेंगे। मैंने यह कहा कि यह क्या हो गया, क्या विचित्र बात हो गई। आज अन्नाडीएमके भी अनटचेबल हो गया। हमारे लिए कोई पार्टी अनटचेबल नहीं है, मार्क्सवादी भी नहीं है। हिन्दुस्तान की राजनीति डैमोक्रेटिक राजनीति है। हम किसी को भी अनटचेबल नहीं मानते हैं। यह अनटचेबल एप्रोच आपकी हो सकती है, कभी और किसी की हो सकती है, कभी कांग्रेस की भी हो सकती है। हमारे यहां हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आइडियोलोजी की शिक्षा दी। उन्होंने 1966 में जब पटना, बिहार में कम्युनिस्ट और हमारी मिलकर सरकार बनी थी, तो हमारे कुछ डैलीगेट्स ने कालीकट में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यह आपने क्या किया, यह कैसे स्वीकार किया कि कम्युनिस्ट और जनसंघ दोनों एक ही में रहें? उन्होंने कहा कि यह जो सरकार बनी है एक कार्यक्रम के आधार पर बनी है। हम कम्युनिस्टों से आइजियोलोजिकली मदभेद रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, उनके साथ राष्ट्र या बिहार के हित में कोई कार्यक्रम बनाकर उसको कार्यान्वित नहीं करेंगे, यह अस्पृश्यता का कार्य है, यह कभी कोई जनसंघ का व्यक्ति न मानें। ये उनके शब्द थे कि बड़ी विडम्बना है कि सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता को पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कुछ दल हैं, जो कहते हैं कि इसको अगर अस्पृश्य नहीं मानों, तो तुम पाप करते हो। इसलिए इसको अस्पृश्य मानो। मैं अन्नाडीएमके, डीएमके,

कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग को या किसी को भी अस्पृश्य नहीं मानता हूं। लेकिन हम यह मानते हैं कि इस समय देश की राजनीति जिस स्थान पर पहुंची है, उसमें से यह जो कल्पना कांग्रेस पार्टी करती है कि हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा क्या हाल है और बिहार में क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है। आज अगर लालू प्रसाद जी आपके साथ हैं, तो केवल इसलिए कि ऋण चुका रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं और अभी आपने उनको बचाया है। अन्यथा, उनका मेल आपके साथ नहीं है। वे कोशिश करेंगे कि आपका तिल भर भी वहां न हो और उनको पता है कि आपका वहां कुछ है नहीं, इसलिए आपका साथ दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी को थोड़ी चिन्ता है, सपा को थोड़ी सी चिन्ता है कि वे क्या करेंगे। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी आपकी दुर्गति है, उसके आधार पर यह कल्पना करना कि आपको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, यह कोरी कल्पना है और इस परिस्थिति से कुछ नहीं होना है। हां, इससे अच्छा होता कि आप सबको साफ कहते कि आज से छः महीने पहले जो स्थिति थी, लेकिन अब सरकार की लोकप्रियता खत्म हो रही है और यह नान-परफोर्मेंस गवर्नमेंट है। इन पिछले तीन-चार महीने में जिस प्रकार से इस सरकार ने लाहौर की बस यात्रा की, जिस प्रकार से बजट पेश किया, जिस प्रकार से बिहार के बारे में किया, जिस प्रकार से टैक्नोलाजी के बारे में कदम उठाए, जिस प्रकार से यह स्थिति लाकर खड़ी कर दी है कि वर्ल्ड बैंक को कहना पड़ा कि -

[अनुवाद]

"इस क्षेत्र में अब भारत उनका सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र है।"

[हिन्दी]

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार इस रीजन में जितना इन्वैस्टमेंट हुआ है, उसमें से 80 प्रतिशत भारत में हुआ है। इन सारी चीजों को देखकर आपको लगा कि स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है और यह सरकार चलने लगी तो दो-चार महीने में यह सरकार ऐसी स्थिति कर लेगी, जब तक आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव आयेंगे, तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी इस सरकार को गिरा सको, उतना अच्छा है। आप सबको कहते हैं कि चाहे आप अपनी सरकार बना लो, हम सरकार बना लें, कोई सरकार बना लें, कोई-न-कोई सरकार बननी चाहिए। इनकी नीयत है कि यह सरकार जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव हों। इस नीयत को पहचानना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग सोचेंगे और विचार करेंगे और इनको कहेंगे कि विकल्प प्रस्तुत करे। जो विकल्प प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि आप क्या करना चाहते हैं, वैसा विकल्प साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुमत आज भी इधर है। वह बहुमत शीघ्र प्रमाणित होगा, कल होगा, परसों होगा, वह तो अध्यक्ष पर निर्भर है। मैंने कुछ बातें नहीं कही हैं क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, हमारे अन्य सहयोगी उन सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे, जिनका जिक्र शरद पवार जी ने किया है। मैं कांग्रेस से ज्यादा अपेक्षा नहीं करता, मार्क्सिस्टों से ज्यादा अपेक्षा नहीं करता लेकिन और सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार करिये कि क्या यह उचित होगा...(*व्यवधान*) मार्क्सिस्टों से तो मैं अपेक्षा करता ही नहीं हूं, थोड़ी बहुत सी.पी.आई. से करता हूं, वह कभी-कभी समझदारी की बात करते हैं, बाकी कांग्रेस की तो दयनीय स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सिद्धान्तपरक राजनीति के खिलाफ हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इनकी स्थिति मैं समझ सकता हूं, अच्छी तरह से समझ सकता हूं, विपक्ष के नेता हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं। मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। जो अप्रोच आज से 6 महीने पहले आपने अपनाई थी और जिसकी प्रतिध्वनि हमको आपके पंचमढ़ी के प्रस्ताव में मिली थी, उसमें कुछ सूझबूझ लगती थी, कुछ बुद्धिमता लगती थी। उस आधार पर आप चलेंगे तो आप देश के लिए अधिक योगदान कर सकेंगे। जो इस समय नैगेटिव पॉलटिक्स आप खेल रहे हैं, वह देश के लिए तो अहितकर है ही, आपकी पार्टी के लिए भी अहितकर है। मैंने जो बात बिहार के बारे में कही थी...(*व्यवधान*) मैंने बिहार के बारे में कहा था कि आप बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार को वापस बैठा रहे हैं, वह बिहार के लिए अहितकर होगा और मेरी पार्टी के लिए लाभकर होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मेरी पार्टी का अहित करते हुए भी आप बिहार और देश का भला करें। उसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूं कि आप पुनर्विचार करिये। शरद पवार जी ने कुछ भी कहा हो लेकिन अगर आज शिवशंकर जी फैसला कर लें कि हम आज वाजपेयी जी की सरकार का समर्थन करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। इनका वजन ज्यादा है, शरद पवार जी का वजन नहीं है। शरद पवार जी तो औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता है, असली तो यह है और अगर असली आदमी अपनी बात कह दे तो सारा वातावरण बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत जोरदार ढंग से वाजपेयी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह भी इसका समर्थन करे।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी जो विश्वास का मोशन लाए हैं उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने बोलने से पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा कि क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे एक चिंतनशील व्यक्ति हैं। आज से चार दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक जब हम लोगों ने सुना कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं तो सब कार्यक्रम छोड़कर हम लोग टी.वी. के सामने बैठ गये और हम लोग इंतजार में थे कि वे चिंतनशील व्यक्ति हैं,

[श्री लालू प्रसाद]

अपराह्न 12.45 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

गलत कुसंगति में फंसे थे। अभी चेतना जगी। जैसे रहीम ने कहा "जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।" इसका यह मतलब हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं, अगर वे गलत कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नही होता है जैसे चंदन को विषधर लपेट लेता है तो भी चंदन पर उसका असर नहीं होता है लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हम जैसे लोगों को बताने वाले इस बात को नहीं समझते। सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की भूख ऐसी होती है न जाने कितने राजा-महाराजा और रूलर देश में आए और बोलते चले गए कि हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए और उन्होंने कहा कि वह स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे लेकिन धरती ज्यों की त्यों है और खामोश है। यह मन इतना मतवाला है... (*व्यवधान*) उसमें हम सब लोग हैं...(*व्यवधान*) मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे गफूर चाचा बैठे हैं, कहीं मेरे भाई नीतीश कुमार जी बैठे हैं। अब धर्म-अधर्म की बारी आई है। हमें आज आप लोगों की पीठ पर गदा चलाना पड़ा है। चिन्ता मत करो। यह मन मतवाला है। कही हमारे गुरू जार्ज साहब बैठे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी, यह मन मतवाला है, भोला है, ठुमक-ठुमक कर थिरकता है चाहे होली हो या कुछ और हो। जब आप थिरक रहे थे, हम कपड़ा फाड़ कर पटना और दिल्ली में गा रहे थे। धरती ज्यों की त्यों है और खामोश है। इस देश में सूफी-संत आए। अभी आडवाणी जी सूफी-संत की तरह पाठ पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं, आपका सत्यानाश कैसे हुआ और किस ने किया? उन दिनों में सूफी-संत हुए और भटकते इन्सान को, मतवाले इन्सान को जो बांध को बांध नही समझते, दूसरे की मां को मां नहीं समझते और दूसरे के बाप को बाप नहीं समझते तथा प्रणाम नहीं करते। सूफियों और मौलवियों ने कहा कि दौलत, दुनिया माल खजाना, सब यहीं रह जाएगा, इन्सान मुट्ठी बंद कर आया, हाथ पसारे चला जाएगा लेकिन मन मानता नहीं। रीता वर्मा जी, अब आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। उन्हें डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके।...(*व्यवधान*)

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : आप भी हाथ पसारे ऊपर जाएंगे।

श्री लालू प्रसाद : हमने 13 महीने के शासन में इनकी दशा देखी लेकिन हमारे गुरू जार्ज साहब के कपड़े-लत्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखते हैं कि हम टाइट कपड़ा पहनकर आते हैं और जॉर्ज साहब का पोशाक देख लीजिये जब बिहार जाते हैं तो आप वहां की पोशाक देख लीजिये। अब उनकी यह स्थिति रह गई है, अब उनका क्या दोष हो सकता है? आखिर उनका और स्यूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ है, यह बहुत सोच-समझकर हुआ है। जॉर्ज साहब की भ्रष्टाचार के बारे में जो सोच है और हम लोगों को बताते रहते हैं, जेल भिजवाते रहे हैं। राबड़ी देवी एक महिला मुख्यमंत्री हैं और जिसका नाम मुकदमें में न हो, फिर भी अपमान कराते रहे हैं। मेरे साथ राबड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलती हैं। प्रधानमंत्री जी ने माना कि बहुत गलत काम हुआ है और आपने कहा था कि मैं फिर आऊंगा। आपने यह कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम पशु-पालन का है। यहां सारे लोग बैठे हुये हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस मुल्क में कौन बचा है और कौन बेदाग बैठा हुआ है। मैं इस चीज से छेड़छाड़ करके किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं लेकिन बातें दबाई नहीं जा सकती हैं। चाहते जितनी बातें टी.वी. पर थापर साहब से कह डालें, बात दबती नहीं है, अभिलेख मिटता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने चिन्ता जतायी लेकिन गृहमंत्री जी ने आपका ग्रह खराब किया। आप मतवाले की तरह हैं। इसमें आपका ज्यादा दोष नहीं है। मैं किसी का अपमान करने के लिये नहीं कहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मेरा जन्म गोपालगंज जिला के फुलवड़िया गांव में हुआ। गांव में हम लोगों को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। गोसाई लोग एक ऐसा पशु बैल रखते थे जिसकी आंख पर माशा, पीठ पर पैर है, छोटा नाटा, जिसे उत्तर प्रदेश में नादिया कहते हैं लेकिन हमारे बिहार में बसाह बैल कहा जाता है यानी भोले बाबा, शंकर बाबा का अवतार बसाह कहते हैं। गोसाई उसी बैल पर कपड़ा ओढ़ाकर, गेरूआ वस्त्र पहनकर, हजारों सफेद कौड़ियां लगाकर रखता है और घुमाते रहते हैं। हमारे साधू बाबा यहां बैठे हुये हैं जो इसी रूप में आते हैं। वह बसाह बेचारा गरीब है। उनके गांव में घूमते हैं। एक दिन मेरे गांव में आया और मेरी मां बैठी थी, उसने कपड़ा धरकर बैठा दिया। मेरी मां ने पूछा, बाबा मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मैं अकेला नही हूं, गांव से लाखों लोग आते हैं जिन्हें इस बात की जानकारी है। गोसाई बाबा दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर पूछते हैं नौकरी मिलेगी या नहीं? इसमें नहीं मिलेगी तो जब दोनों मुट्ठी आगे करते हैं और गोसाई बोले देखो भोले इस हाथ में क्या लिखा है। बैल का स्वभाव है कि जब मुट्ठी आगे बढ़ाइये तो यह समझता है कि उसे खाने को कुछ दे रहे हैं। कभी बायें और कभी दायें हाथ को घूमता है। तब भोला बाबा समझ आता है कि वह हमें ठग रहा है, तथा गौसाई बोलता रहता है, पीठ ठोंकता रहता है जब हाथ नहीं घूमता तो गौसाई पीछे से कोदता है और बसाह घंटी झनझनाता है। आप कभी-कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए, लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले जाते थे। जो नादिया का हाल रहा वही 13 महीने में आपका हाल हो गया। 13 महीने में आपको एक मौका था। आप कांग्रेस की बात करते, सी.पी.आई. सी.पी.एम. की बात करते। जार्ज साहब वहां बैठे हैं। सन् 1977 में छपरा से मैं एम.पी. बनकर लोक सभा में आया था। हम सब लोग एक साथ थे। सभी लोग भी जेल में थे और हम लोग भी जेल में थे। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय यशवन्त बाबू जेल में नहीं थे जो वित्त मंत्री हैं। ये क्या आप जेल में?...(*व्यवधान*) कभी जेल नहीं गए। आप तो बिना हारे कोई न कोई पद ही लेते हैं। चाहे उधर हों या इधर हों, दोनों पार्टियों में। उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। खैर छोड़िये उन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं हैं।

महोदय, मैं बताना चाह रहा था कि ये जार्ज साहब हैं। सन् 77 में हम लोगों को दिल्ली शाम समझ में नहीं आई। दिल्ली में हम लोग

जब आए तो राजनारायण जी, जार्ज साहब, चौधरी चरण सिंह जी थे। हम लोग उसी परिवार के लोग हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हों या और कोई हों, या नीतीश जी जो उधर चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत हैं, मगर नीतिश जी के पेट में दांत हैं जो उधर चले गए हैं। पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय, मैं सन् 77 की याद दिलाना चाहता हूं। हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, यह नयी बात नहीं है, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड-खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलौर में हम लोग जुटे तो नाम का सारा झगड़ा हो गया। लेकिन सन 77 की सत्ता को हम लोगों ने लात मारी थी। क्यों मारी? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था।...(*व्यवधान*) अरे, आप नये-नये मेम्बर आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग इन लोगों की वजह से जा रहे हैं। सन् 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल हम लोगों द्वारा मज़बूती से उठाया गया कि आर.एस.एस. में रहना है या जनता पार्टी में रहना है। जार्ज साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रखकर बोलें कि इन्होंने ही यह बात उठाई थी। हम लोग तो नये थे। उन्होंने कहा था कि या तो आर.एस.एस. में रहिये या जनता पार्टी में रहिये। दोहरी सदस्यता इस मुल्क में नहीं चलेगी और देश के सेक्यूलर कैरेक्टर फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा इसीलिए हम लोग टूटे। हम लोगों ने नारा दिया 'चरण नहीं तो चुनाव' और हम लोग चुनाव में गए। हमारी लड़ाई आपसे है। आपने कहा अब बताइए हिन्दुत्व-हिन्दुत्व और हिन्दू-हिन्दू का कौन विरोध करता है? हम लोगों के पुरोहित आडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? यह हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हमारी मां-बहिन, गांव गृहस्थ के सारे लोग पंडित से पूजा कराते हैं। यह ठेका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेक्यूलर कैरेक्टर सेक्यूलरिज्म है। इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्य मंत्री बनती है। देश की एकता-अखंडता के मामले में जब नाक तक पानी आया तो हमसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या करोगे। हमने एक कैलेण्डर कह दिया चूंकि वह रोज़ बोलते थे दिल्ली में कि नहीं-नहीं, जयललिता से पैच अप हो गया।

अपराह्न 1.00 बजे

लालू और मुलायम में विगत दिनों में लड़ाई हो गई, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। चूंकि हम पहले बोल देते थे। लेकिन इस बार हमने साईंटिफिक तरीके से काम किया है, चूंकि साइंस और टैक्नोलोजी का युग है। आप जनता पहनावा छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर गये और पोखरण विस्फोट किये तो हम लोगों ने भी अपने साईंटिफिक तरीके का इस्तेमाल किया। आप पूछ रहे हैं क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइये। अभी भी आपको मेरा सुझाव है, हालांकि आपकी उम्र के आदमी को सुझाव देने का हकदार हम अपने को नहीं समझते। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी आपने कहा था कि पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, सिम्पैथी लेने के लिए नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश के प्रधान मंत्री बनोगे। यह लिखा हुआ है, रिकार्ड में है, आपने कहा था। तो आप एक बार नही दो बार प्रधान मंत्री हो गये। नेहरू जी एक बार बोले, आप दो बार प्रधान मंत्री हो गये, अब तो मुल्क की जान छोड़िये।

आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। आडवाणी जी उठकर चले गये आप हमें पाठ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। जो हमारे मुल्क के आदरणीय चोटी के नेता थे जिनमें नेहरू जी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बहुत सारे अग्रिम पंक्ति के नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आप दो बाद प्रधानमंत्री हो गये। लेकिन अभी आपने इसी हाउस में अपने कार्यक्रमों की जो घोषणा की थी उसमें आपने जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया, रीनेम क्यों कर दिया, सारी चीजों को कम्पाइल क्यों कर दिया, इंदिरा आवास को आपने क्यों रीकम्पाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटाकर देश की जनता को लालच दिखा आर.एस.एस. की संस्कृति लादना चाहते हो...(*व्यवधान*) सत्ता में कौन क्या होगा, कौन मंत्री हो, किसका मंत्री हो? मंत्री आयेंगे और जायेंगे, लेकिन मुल्क एक बार मुट्ठी से निकल गया तो फिर बात संभाल से बाहर हो जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वोटिंग से पहले सीधे राष्ट्रपति भवन चले जाइये, आपने पहले भी यह काम किया है, ये लोग घेर-घेरकर आपका अपमान करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जीत जायेंगे, जीते कहां, आप तो हार चुके हो, आप गलतफहमी में मत रहना। यदि वोटिंग हुई तो इस बार वोटिंग खड़े होकर होगी, हम लोग टैक्नीकल काम में नहीं जायेंगे। उस बार भी गलती कर दी थी और हमारा बटन भी गलत दब गया था। इसलिए मेरा निवेदन है...(*व्यवधान*)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : जब एक बोगस वोट पड़ी थी, उसका क्या हुआ?

श्री लालू प्रसाद : अब की बार ऐसी दुरूस्त वोट पड़ रही है कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि इस बार पीला, लाल, हरा कागज नहीं होगा। जॉर्ज साहब को देखिये, देवेगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी, भाई रामविलास पासवान जी भी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में जब गंगा पर पुल नहीं बना तो वहां पर देश प्रधान मंत्री जी को ले जाकर क्यों उद्घाटन करवा दिया। नीतीश जी ने स्वीकार किया। पहले जहां बिहार शरीफ में प्रधान मंत्री जी गये। यह नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा, वहीं थर्मल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद में बिजली का प्रोजैक्ट था। हमारे मित्र श्री लोटन सिंह के पुत्र श्री राम नरेश भाई वहां से समता पार्टी के सांसद हैं। वहां जाकर देखिए आज समता पार्टी की क्या हालत है क्योंकि वहां से बिजली के कारखाने को नीतीश जी बाढ़ में ले गए। बाढ़ में जहां वाटर लागिंग की समस्या है, वहां थर्मल पावर नीतीश जी कैसे लगाएंगे? प्रधान मंत्री जी, नीतीश जी आपको लेकर वहां चले गए और उद्घाटन करा दिया। हमने प्रधान मंत्री से कहा और मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से सुझाव दिया कि राजेन्द्र सिंह जी से पूछो कि यह प्रोजैक्ट कब बनेगा, इसके लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया है? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हम कर सकते हैं वही काम हमें करना चाहिए। इस प्रकार से बिहार को कितना ठगा जाएगा बताइए?

[श्री लालू प्रसाद]

महोदय, अभी 14 तारीख को नीतीश जी, जार्ज साहब को लेकर राजगीर चले गए। राजगीर-नालंदा, हमारा वह पवित्र स्थान है जहां जरासंध का अखाड़ा है। वह विद्या का केन्द्र है, वहां शांति स्तूप है। इन्होंने वहां जाकर घोषणा कर दी कि वहां हम आर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे। जब आपको मालूम है कि आपकी विदाई हो रही है, तो आपको यहां एम.पी. वगैरह से आकर बात करनी चाहिए थी और अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप नालन्दा (बिहार) चले गए। वहां की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को भी आपने मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। जैसे पहले बिहार में जितने भी उद्घाटन हुए हैं वे काम पूरे हो गए हों। मेरा कहना है कि बिहार में हुए उद्घाटनों में से अधिकांश अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फिर क्यों बिहार के लोगों को ठगने का काम किया जाता है?

महोदय, भारत में फैडरल गवर्नमेंट है, संघीय प्रणाली है और एक राष्ट्रपति है। सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करने की जहां तक बात है, मैं कहना चाहता हूं कि आप उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस प्रदेश की मुख्य मंत्री को पता नही है। यह कैसे चलेगा? आप कब तक इस प्रकार से बिहार के लोगों को ठगते रहेंगे? बहन ममता जी के लिए बंगाल में आपने जो पैकेज दिया है, उस पर कहां तक कार्य हुआ है, उसके बारे में वे बताएंगी। इस प्रकार से आप बार-बार और जगह-जगह उद्घाटन कराके देश और विशेषकर बिहार की जनता को कब तक धोखे में रखेंगे? हमने हमेशा कहा है कि बिहार के लोग हमेशा ठगे जाते रहे हैं। आप बताइए आयुध कारखाना जहां लगता है, वहां पर सफीशिएंट वाटर होना चाहिए, लेकिन वहां पानी है ही नहीं और आप आयुध कारखाना लगाने का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आप बिहार की जनता को कब तक बुद्धू बनाते रहेंगे? अब आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है और आप कह देंगे कि हमने तो आयुध कारखाना खोल दिया था, लेकिन हमारी सरकार चली गई या इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया। इस बार फिर जोर लगाओ और हमारी सरकार लाओ, तो हम फिर कारखाना खोल देंगे। देश की भोलीभाली और विशेषकर बिहार की जनता के साथ इस प्रकार से धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जार्ज फर्नान्डीज साहब से पूछना चाहता हूं कि आयुध कारखाने के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है, कब वह तैयार होगा, कितने लोगों की जमीन ली जाएगी, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी?

महोदय, आप वहां आयुध कारखाना खोलने जा रहे हैं, और यहां से निकलिए, मोदीनगर से मुजफ्फनगर तक, हमारे मुलायम सिंह यादव जा रहे थे, वहां रैली निकल रही थी, पूरा मोदीपुरम स्वदेशी के नारो से पैक था। नारे लगाए जा रहे थे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा है और अमरीका की परवाह नहीं करता, इकनौमिक सैंक्शन्स की परवाह नहीं करता। हम भारत को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे और अपना विकास करेंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज आपने भारत की जनता को वाशिंगटन के हाथों में कैद कर दिया है। सारी स्वदेशी मिलें, कल कारखानें बंद हैं। बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनकी गरीबी और गुरबत बढ़ रही है। अन्य चीजों में, कन्ज्यूमर गुड्स के बारे में, अगर इनका शासन एक क्षण भी इस मुल्क में रहता है, तो न जाने कितना खामियाजा इस देश के माइनौरिटीज को, जो सर्वहारा हैं, उन सर्वहारा के देश के ऊपर हमला होने वाला है चाहे किसान हो, मजदूर हो। जो भारत के बेटे और बेटियां हैं, आपने कहा था कि कम से कम हम पीने के पानी का प्रबंध कर देंगे। जिस समय आपका सम्बोधन हो रहा था, पीने के पानी के सवाल पर अखबार वालों ने लिखा कि आगे लड़ाई है। देश के मोहल्ले-मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने पानी का प्रबंध नहीं किया है। पूरे 13 महीने में सारे लोग जो बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रहमचारी लोग हैं, हमको सत्ता की परवाह नही है। इन 13 महीनों में सत्ता की भूख में आपका सारा ब्रहमचार्य टूटा है। आडवाणी जी, हम लोगों के ऊपर यह तोहमत मत मढ़िये कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोगों ने पैदा की है। सत्ता ऐसी है, सत्ता की भूख ऐसी मतवाली है कि न जाने कितनी दरारें और टुकड़े आप में हो चुकी है। आप अपने भीतर निहारकर नहीं देख रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं, आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये लोग बैठे हुए हैं। हमारी बहन ममता बनर्जी कोई मामूली आदमी नहीं हैं। वह मजबूत आदमी हैं। उनकी ताकत है कि वे जहां से लड़कर आयें, ममता जी ने कहा था कि अगर आप हमें मंत्री बनाते हैं तो हम हम रेल मंत्रालय लेंगे। नीतीश जी बोले कि हम रेल मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे तब जार्ज साहब चाकरी करने चले गये कि भाई सरकार टूट जायेगी, नीतीश जी आप मान जायें। नीतीश जी ने जार्ज साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है। क्या?...*(व्यवधान)* यह स्थिति है। अभी आपने शकुनी चौधरी, हमारे चाचा श्री गफूर साहब क्या मामूली आदमी हैं? राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। हम उनके बेटे हैं, उनके वोटर हैं। वे गोपालगंज के हैं। वे हमारे चाचा हैं, उनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरजीह दी? आप लोगों को फंसाकर रखे हैं कि रूको-रूको अभी एक्सपैंश्न हो रहा हे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा हैं। जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी ने मेरा नाम मिनिस्ट्री के बारे में बोला है।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए केवल एक मिनट का समय लेना चाहती हूं।

श्री लालू प्रसाद : मैं सिट डाउन हो जाता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह बात सच नही है कि हमारी पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करना चाहती है। जो बात प्राइम मिनिस्टर ने हमारी पार्टी को पहले से कही, हम प्राइम मिनिस्टर के आभारी हैं। किसी ने पूछा था कि हमारी पार्टी का क्या ऑप्शन है तो हमने बता दिया था। लेकिन यह बात नहीं है कि हम लोगों ने मिनिस्ट्री में जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको मिनिस्ट्री की जरूरत है, हमें नही है।.

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टीफाइड और क्लीयर किया है। इनके सिद्धांत और उसूल पर अंगुली नहीं दिखा रहे हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि आपने रेल मंत्रालय मांगा था?

कुमारी ममता बनर्जी : हमने नहीं मांगा था।

श्री लालू प्रसाद : नहीं मांगा था तो अब कभी भी नहीं मिलेगा।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : लालू जी, आपको क्या चाहिए ...*(व्यवधान)* हमने सुनने की कोशिश की। लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, पावर ब्रोकर थे। अभी इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब मिलकर वाजपेयी जी को हटाना चाहते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं लेकिन देश की जनता इनको क्षमा नहीं करेगी। ये गलत बात कहते हैं, पार्लियामेंट को मिसलीड करते हैं। इश्वर के लिए इस सभा को गुमराह न करें। ऐसा नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप अपनी बात कहें। आप किसी को ठुकरा नहीं सकते। अगर आप ठुकराएंगे तो हम भी आपको ठुकराएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, आपकी बात समाप्त हो गयी है। उन्होंने अब उन्हें बोलने का अवसर दे दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : बिहार में दलितों की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैंने इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कहा, उधर कौन वित्त मंत्री, कौन क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है इधर है, इधर है उधर है। हमने जो आंख से देखा और कान से सुना है, लालू यादव ने नहीं देखा बल्कि दुनिया ने देखा है। हमने बहन ममता का अपमान नहीं किया, हमने कहा कि यह बात थी। आप बांधकर रखना चाहते हैं। हम लालू यादव और महिला का अपमान? हमसे बढ़कर महिला को कोई सम्मान नहीं देगा।...*(व्यवधान)* अपनी सीट दे दी, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं लिया, "न लोटा न थारी, पेट भरे गिरधारी"। हम उसूल वाले लोग हैं, यह आप समझ लीजिए। ये जो लोग बैठे हुए हैं,...*(व्यवधान)* वह भी है। उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं बचा सकेंगे, तुरंत आने वाला है। कहां-कहां कार जुटा, कितना घपला कितना लूटा, किसकी गर्दन कहां है, हयात होटल में 90 करोड़, अभी जो पकड़ाया है, हार्स ट्रेडिंग के लिए रुपया दबाया है। हम इस बात को कहना नहीं चाहते थे, ऐकेडैमिक डिस्कशन करना चाहते थे।...*(व्यवधान)* बीच में बोलेंगे तो हम इन चीजों को रखेंगे।...*(व्यवधान)* बात सुनिए।... *(व्यवधान)* आडवाणी जी सुधार देंगे। सीता स्वयंवर हो रहा था, कौन धनुष तोड़ेगा, डंका बज गया, भारी-भारी भोपू जुट गए, सीता हमारी मां, भारत की बेटी, हाथ में माला, चारों तरफ वीर लोग बैठे हुए हैं कि मेरी गर्दन में डालेगी, मेरी गर्दन में डालेगी, सब जगह से रिजैक्ट होते-होते...*(व्यवधान)*

ये बोलने नही देंगे इसलिए आज जल्दी से वोटिंग करवाइए। अभी हम इनका रिजल्ट सुना देते हैं।...*(व्यवधान)* उन वीरों में नारद जी भी थे। जब वे रिजैक्ट हो जाएं फिर आगे आकर बैठ जाएं। किसी ने कहा कि अपना चेहरा आइने में देखें।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : यह पार्लियामैंट है या मजाक हो रहा है।...*(व्यवधान)* सारे कांग्रेसी मजा ले रहे हैं।...*(व्यवधान)* एक आदमी लगातार नौटंकी कर रहा है और आप सब लोग हंस रहे हैं।...*(व्यवधान)* इतने सीनियर आदमी हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, एक घंटे से रामयण चाल रही है। देश का इतना पैसा और समय वेस्ट हो रहा है, मजाक बनाकर रखा है और आप सब लोग हंस रहे हैं। लालू जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैं तो बैठ ही जाऊंगा। शेयर ब्रोकर हैं, भागो, मुम्बई जाओ, मुम्बई में दलाली करो। लाटरी बेचो, लाटरी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बीच में मत टोकिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कृपया बैठ जाइये। वे अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तेजित मत कीजिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : यह मजाक की बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम नहीं बोलने देंगे। आज इनको बोलने नहीं देंगे।

श्री विजय गोयल : सारे लोग बैठकर हंस रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ये बोलने नहीं देंगे। वापस जाओ।

महोदय, प्रधान मंत्री जी अभी लालच में पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप ऐसा कीजिए, चूंकि हाउस को लंच के लिए एडजर्न नहीं किया है, इसलिए सब लोग उसका नतीजा भुगत रहे हैं, इसलिए जल्दी से खत्म कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : तो लंच के बाद रखिये। पहले हमको लंच खिलाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : मैं संक्षेप में बोल रहा था, एकेडेमिक डिस्कशन। प्रधान मंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा था कि आपके जितने साथी लोग हैं, आपको थाह लगने नहीं दे रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, आपकी जमीन खिसक चुकी है। आपको झूठ-मूठ के नारद मोह में डाले हुए हैं, आप नारद मत बनिये। जमीन नहीं हैं, जहां आप खड़े थे, वह जमीन खिसक गई। जयललिता जी का कितना अपमान आपने किया, मुकदमें पर मुकदमा, मुकदमें पर मुकदमा, लटकाकर रखो, क्लच में रखो। लोगों पर शासन करते रहे, इसलिए आपको मेरा सुझाव है। मैं फिर कहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : सुझाव सोनिया जी को दो।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सुनो, बैठो। आपको मेरा सुझाव है कि परसों ।। बजे वोटिंग है, खरवांस कल 14 तारीख को उतर गया। हम लोगों का, हिन्दू भाई लोगों का खरवांस उतर गया, सतवान होता है, आम का टिकोड़ा खाकर, सत्तू-वत्तू खाकर करते हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हिन्दुत्व है। उसके बाद से शुभ काम किया जाता है। अब खरवांस उतर गया। परसों भाषण करके बिना वोटिंग कराये राष्ट्रपति जी को इस्तीफा दे दीजिए। राष्ट्रपति जी अब हम लोगों से पूछेंगे कि वैकल्पिक सरकार कौन-कौन मिलकर बना रहे हो। यह हिसाब हम राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं देंगे। यही वैल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंटरी नोर्म में है। आपकी इसमें इज्जत बच जायेगी। पीठ में छुरा लगने से अच्छा है, सीधे जाकर वहां दे दीजिए। इससे आपकी इज्जत बच जायेगी कि आर.एस.एस. ने आपको चलाने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यनाश पर पहुंच गया। हम लोगों को और मुलायम सिंह यादव को कुछ नहीं चाहिए, सुन लीजिए, साम्प्रदायिकता के खिलाफ, एक-एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा और इस बार हम चाहते हैं, भारत से हमेशा के लिए साम्प्रदायिकता की विदाई हो। दोबारा फिर आप आने वाले नहीं हैं। हम लोग बनाएंगे या ये बनाएंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन आपकी कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है। आप क्या विश्वास मत लाये हैं, आप नहीं लाये हैं. वह तो राष्ट्रपति जी ने आपसे बोला। तीन महत्वपूर्ण पार्लिटिकल पार्टीज, चौटाला जी की पार्टी, चौटाली जी की पार्टी कोई मामूली पार्टी है? वह लोकदल है, बिहार, हरियाणा, यू.पी., चारों तरफ हम लोगों का ग्राउण्ड है। राजस्थान और गुजरात में हमारी ग्राउंड है, इनके पास तो मोरली ग्राउंड भी नहीं है। देश में तेज-तर्रार नेता सुब्रमणियम स्वामी साहब भी हमारे साथ हैं। इनके दल के सदस्यों की संख्या भले ही ज्यादा न हो, लेकिन ये ऐसे नेता हैं, जैसे हमारे बिहारी कवि के बारे में किसी ने कहा है-

सत सैय्या के दोहरे जो नावक के तीर
देखन में छोटे लागें घाव करें गम्भीर।

इस सरकार के तीन समर्थक दलों ने राष्ट्रपति जी के पास जाकर अपना समर्थन वापस ले लिया। बूटासिंह जी तो पहले ही इनसे अलग हो गए थे। अब ये तीन राजनीतिक दल हट गए हैं और ये हम पर ब्लेम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप समाप्त हो चुके हैं, देश की जनता को मालूम है कि यहां से भाषण देकर और चतुराई से यह कहकर अब काम नहीं चल सकता कि हम लोगों ने इनकी सरकार गिराई है। आपको जिनका समर्थन प्राप्त था, वे हट गए हैं, तो हम क्योंकि आपको गिराने लगे। हम सरकार गिराने के बाद क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसकी आपको क्यों चिंता है। हम तो भैंसे चराकर दूध पी लेंगे और बेच देंगे।

आपने आपने मन से यह विश्वासमत यहां नहीं रखा है। देश के प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास गए थे कि ऐसा न करें। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं, उनको ऐसा कहने के लिए। आपने वहां जाकर इसके लिए कुतर्क दिया और हम लोगों ने वहां जाकर तर्क दिया। वी॰पी॰ सिंह, देवेगौड़ा जी और गुजराल जी का उदाहरण है कि बिना हाउस के फ्लोर पर कांफीडेंस लिए आप बजट को हाथ में नहीं ले सकते। हमारा संविधान एक है, भारत एक है और राष्ट्रपति जी एक हैं, यह नहीं हो सकता कि बिहार में कुछ हो और यहां कुछ हो। आप बिहार के मसले पर राष्ट्रपति जी को कुतर्क देने गए थे, लेकिन राष्ट्रपति जी ने आपकी बात नहीं मानी। हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खत्म करें।

श्री लालू प्रसाद : मैं खत्म कर रहा हूं। उधर जो साधु बाबा लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इनसे निजात पाएं और एक नया भारत बनाएं। हमारे खुराना जी उधर हैं, बहन सुषमा जी की वहां क्या हालत हुई, सब जानते हैं। सुषमा जी को कितना टार्चर किया, जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी हम आपके हाथों में ज्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। इसलिए हम आपकी सरकार को सिर्फ झटका ही नहीं देना चाहते, एक मिनट में वोट से पटका देकर नई सरकार बनाएंगे और भारत की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आने देंगे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.35 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव–*जारी*

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने सदन में जो विश्वास मत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस चर्चा में अभी तक विरोध पक्ष की ओर से दो भाषण हुए हैं – एक भाषण विरोधी दल नेता का, जिसके बारे में अधिकांश सदस्य, जो इस तरफ बैठे हैं, उनका यह मत था कि मजा नहीं आया, जमा नहीं और दूसरा भाषण हमारे ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लालू प्रसाद जी का हुआ। जिसके बारे में सदस्यों की राय थी कि बहुत ही एन्टरटेनिंग भाषण रहा। उसमें कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नौटंकी वाला भाषण था, लेकिन यह मेरा कहना नहीं है। लालू प्रसाद जी ने स्वयं कहा कि उनका भाषण बहुत एकेडैमिक था। एकेडैमिक भाषण उन्होंने बहुत मतवाले मन से शुरू किया था। अभी तो उस डाल पर दो ही पंछी बैठे हैं – लालू प्रसाद और मुलायम सिंह – लेकिन जब वे बोल रहे थे, तो उनके बीच में स्वामी जी भी बैठे हुए थे। हो सकता है कि लालू जी का जो दार्शनिक भाषण हुआ, एकेडैमिक भाषण हुआ, उसमें कुछ स्वामी जी का भी इन्पुट हो।...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : स्वामी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। गुरूस्वामी तो आपको ले डूबे।...(*व्यवधान*)

श्री यशवन्त सिन्हा : आपको अभी तुरन्त पता चल जाएगा। हमारा जो स्वामी था, उससे तो हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन आप इस स्वामी के चक्कर में मत पड़िए, एक मित्र के नाते आपको सलाह दे रहा हूं।

लालू प्रसाद जी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, जिसका उत्तर दिया सके। लेकिन जो विरोधी दल के नेता ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने का उल्लेख किया। जो स्थिति देश की अर्थ-व्यवस्था से संबंधित है उनके मुताबिक पिछले 13 महीनों में अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में हमने ऐसा कुछ नहीं दिया, जिसका उल्लेख भी उनके द्वारा किया जा सके – ऐसा उनका मानना था।

महोदय, आज जब इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं इस सदन की तरफ आ रहा था, तो कई पत्रकार बंधु मुझे मिले, जिनको पिछले कई दिनों से एक ही चिन्ता खाए जा रही है, पूरे देश को परेशान कर रही है और वह चिन्ता है कि हमने जो बजट पेश किया है, उसका अन्जाम क्या होगा? वह इस सदन के द्वारा पास होगा या नहीं होगा? मैंने उनको आश्वासन दिया कि विश्वास मत जीतेंगे, बजट भी पास होगा, फाइनेंस बिल भी पास होगा। लेकिन चिन्ता तो लगी है और इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, वे चुनकर आए हैं।

लालू प्रसाद जी कह रहे थे कि बिना चूना फिटकरी लगाए, हम कोई-न-कोई पद पा लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सदन में मैं उनसे ज्यादा वोट से जीत कर आया हूं और चुनाव जीतने में कितना चूना-फिटकरी लगाना पड़ता है, यह उनको भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि बहुत दिनों से इस पापड़ को बेल रहे हैं। यह जरूर है कि मुझे उनकी तरह जेल में रहने की आदत नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : आप जेल जाने से कैसे बचिएगा, यह बता दीजिए।...(*व्यवधान*)

श्री यशवंत सिन्हा : देखिए न, आप बहुत कोशिश किए हैं, कम कोशिश नहीं किए हैं। हम बैठे हुए हैं, आप कहां बैठेंगे।

श्री लालू प्रसाद : *.. .*

श्री यशवन्त सिन्हा : आप की बद दुआ किसी को नहीं लगती है, क्योंकि किसी*...* की बद दुआ किसी को नहीं लगती है। जब से इस देश में राजनैतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है तब से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना कुप्रभाव पड़ा है, क्या हम सब लोगों को इसकी चिन्ता है? सरकार आएगी, जाएगी, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या हम सब लोग एक साथ मिल कर जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इस सदन में बैठे हुए सब लोगों का यही कर्तव्य है कि हम देश को रसातल तक पहुंचा दें, इसके भविष्य को कोई चिन्ता न करें। आप जानते हैं कि मुंबई स्टाक मार्केट का क्या हाल हुआ। रुपए के ऊपर इस राजनैतिक अस्थिरता के बाद कितना दबाव बढ़ा है। मैं तो अपने देश के समझदार लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस राजनैतिक अस्थिरता के बावजूद भी सूझ-बूझ से काम लिया और जो बात हाथ से निकल सकती थी उसको हाथ से निकलने से बचाया। आज भी हम मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर काबिज़ हैं लेकिन पिछले 12-13 महीनों में क्या हुआ, इसके बहुत सारे आंकड़े पेश होते हैं। मुझे याद है इस सदन में जब कभी हम अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करते थे, हमें बार-बार बताया जाता था कि आपको अर्थव्यवस्था को संभालना नहीं आता है। आप कुछ नहीं जानते हैं, आपने अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया, लगभग

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निका दिया गया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

यही बात विरोधी दल के नेता आज कह रहे हैं। यहां आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में मंदी का दौर 1996 के मध्य से शुरू हुआ था और इस मंदी के दौर के पीछे के कारण थे, वे सीधे वहीं हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां 1991 से लेकर 1996 तक थीं। आत शरद पवार जी बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग बंद पड़े हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी उद्योग बंद पड़े हैं, पब्लिक सैक्टर अंडरटैकिंग्स बंद पड़ी हैं। हमारी सरकार ने जोर देकर कहा है कि भारतीय उद्योगों की रक्षा करने के लिए हमें जो भी कारगर कदम उठाना पड़ेगा वह हम उठाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। भारतीय उद्योगों को आवश्यक रूप से नष्ट करके नये उद्योग बनाने की हमारी नीति नहीं हैं। आज तो लोग कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए आतुर हैं, जो उनके साथ मिल कर सरकार बनाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1991 से 1996 के बीच में जो नीतियां चलीं उस समय उनके विचार क्या थे, आज उनके विचार क्यों बदल गए?... (*व्यवधान*) आपके विचार बदल गए हैं। आप जब गठबंधन करेंगे, उनके साथ मिल कर सरकार बनाने की बात सोच रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि देश फिर उसी तरफ जा रहा है। हम देशी उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं, हम चाहते है कि जो हमारा दुनिया के साथ तालमेल है वह धीरे-धीरे आगे बढ़े, इसलिए हमने नेशनल एजेंडा फॉर गवनेंस में केलीब्रेटेड ग्लोबलाइजेशन की बात की है और हमने एक अंतर किया है- "माइंडलैस ग्लोबलाइजेशन" और "केलीब्रेटेड ग्लोबलाइजेशन"। पिछले साल जीडीपी की प्रगति दर पांच प्रतिशत थी, इस साल जब बजट पेश किया था उस समय मैंने कहा था कि यह 5.8 प्रतिशत होगी। अभी जो कृषि का आंकड़ा लिया था, इसमें फूडग्रेन प्रोडक्शन का आंकड़ा 195 मिलियन टन था। हमारे पास जो न्यूनतम आंकड़ा है, उसमें हम 200 मिलियन टन पर करेंगे और 5.8 प्रतिशत जो वृद्धि की दर है उसको अगर हम पार कर गए तो 1998-99 के जब आंकड़े आएंगे उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। सारी मंदी के बाद भी इसमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो प्रगति की दर है वह अपने आप में सारी बातों को देखते हुए अत्यंत ही संतोषप्रद मानी जाएगी।

हमारे ऊपर चार्ज लगाया गया कि मुद्रास्फीति के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कीमतें भाग रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। पाइंट टू पाइंट मार्च के आखिर में जो इस्तेमाल प्राइस इंडैक्स की दर थी वह पांच प्रतिशत मात्र थी और जो 1990 से यह दशक शुरू हुआ, उस समय 1995-96 में जब यह इंक्रीज 4.4 थी, उसको छोड़कर यह सबसे कम, पाइंट बाई पांइट साल के आखिर में पांच प्रतिशत है। ये पूरे आंकड़े इंफ्लेशन के 1990-91 के पूरे दशक के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1996-97 और 1997-98 के दो वर्षों में जबकि 1995-96 में मुद्रास्फीति की दर 6.4 प्रतिशत थी, 1997-98 में 4.8 प्रतिशत थी और अभी जो प्रॉविजनल आंकड़े हमारे पास हैं उनके मुताबिक 1998-99 में यह 6.7 प्रतिशत हो सकती है, जो इन दो वर्षों को छोड़कर नब्बे के दशक में सबसे कम है।

इसी तरह जो कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है वह 8.6 प्रतिशत 1997-98 के फरवरी में था और हमारा 8.6 प्रतिशत है। वहां भी भारी गिरावट मुद्रास्फीति की दर में आई है, उस पर नियंत्रण हमने पाया है।

उसी प्रकार जब हम विभिन्न प्रकार के बजट के घाटों की बात करते हैं तो उन पर भी निन्त्रयंण पाने का और आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है और यह भी नियंत्रण में है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : बजट तो पेश हो गया है।

श्री यशवंत सिन्हा : वह आप लोगों के समझने की बात नहीं है, उसके लिए बिहार विधान सभा में जाइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो 4.4 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर है और जो हमारे पास फूड-ग्रेन्स का स्टॉक है वह बहुत ही आरामदेह है। आज हमारे पास 89 लाख टन राइस का स्टॉक है, 87 लाख टन हमारे पास गेहूं का स्टॉक है। जो नोर्मस हैं उनसे कहीं ज्यादा हमारे पास स्टॉक है। रबी का फसल जब आयेगी तो कीमतें और नीचे होंगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़ें हैं उनके अनुसार और हमारे रैवेन्यू के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार हम एक अपटर्न जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में देख रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार यही हुआ है कि जब सब कुछ ठीक-ठीक लगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दो। इसी सदन में कहा गया कि हमारा जो करेंट एकाऊंट डैफिसिट है वह तीन प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा। जब मैं बजट भाषण का उत्तर दे रहा था तो मैंने कहा था यह जी.डी. पी. का 1.4 प्रतिशत होगा। मुझे स्कीन को बताने हुए खुशी हो रही है कि जो न्यूनतम आंकड़े हैं, चालू एकाउंट डैफिसिट सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी का नतीजा है कि 1998-99 में हमने 3.6 बिलियन डालर एड किया है। यह डर था कि विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। जब अमेरिका और दूसरे देशों ने परमाणु परीक्षण के बाद हम पर प्रतिबंध लगाए, जब दुनिया भर में क्राइसिज चल रहा था तो यहां पर कहा गया कि विदेशी मुद्रा के भंडार पर देश की इकॉनोमी रन होगी, हम रुपए की कीमत को बरकरार रखने में अक्षम होंगे, पता नहीं कहां जाकर यह देश ठहरेगा? उस समय हमारी तरफ से जो कहा गया उसका उल्लेख आडवाणी जी यहां कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ कहा मैं उसका यहां उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे वर्ल्ड बैंक के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने कहा है :

[अनुवाद]

> "भारत, जो कि इस क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्था है, का संरक्षण इसके विशाल घरेलू बाजारों और पूंजीगत लेखा प्रतिबंधों द्वारा किया गया था जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में हो रही उथल-पुथल के प्रभावों को निष्फल कर दिया है। हाल के अनुमानों से पता चलता है कि

वित्तीय वर्ष 1998--99 के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है।"

[हिन्दी]

शरद पवार जी कह रहे थे कि इनवैस्टमेंट नहीं हो रहा है, जितने फॉरेन इनवैस्टर्स थे, उनका दिल टूट गया है, वे इस देश में नहीं आना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है :

[अनुवाद]

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जोकि 1997 में 4.7 बिलियन था, घटकर 1998 में 4.4 बिलियन रह गया। भारत को इस क्षेत्र के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 80 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ जो कि आशा से अधिक था।

[हिन्दी]

जब सारी दुनिया में यह चल रहा था और एमर्जिंग मार्किट के ऊपर से फॉरेन इनवैस्टर्स का विश्वास खत्म हो रहा था, उस समय हमारी प्रगति और परफॉर्मेंस यह था। आज के दिन इस देश में 32.647 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक का सब से अधिक है, यह आज की स्थिति है। आज तक इतना विदेशी मुद्रा भंडार कभी इस देश में इकट्ठा नहीं हुआ था जितना आज के दिन इकट्ठा हुआ है, हमारे फॉरेन करेंसी ऐस्टेट्स गोल्ड और एस.डी.आर. जोड़ कर 32.6 बिलियन और विद्आउट गोल्ड ऐंड एस.डी.आर. 29.7 बिलियन डालर है। हमारे पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। इसलिए मुझे यह कहते खुशी हो रही है कि सारे बवंडर के बावजूद जितने इस दुनिया में स्टॉर्मस उठे, जितना दबाने का प्रयास दुनिया के देशों ने किया, यहां जो कुछ बात हुई, इस सदन और देश के भीतर हमारे अपने ही लोगों ने जितना हमारा दिल और मनोबल तोड़ने का काम किया, उसके बाद इस देश की आर्थिक व्यवस्था की यह स्थिति है। यदि नेता विरोधी दल श्री शरद पवार और अन्य लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कहूंगा कि वे आंख की जांच कराएं जिससे उन्हें दिखाई देने लगे कि सच्चाई क्या है? ये सब हमारे संतोष का कारण नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लालू जी और हम बिहार विधान सभा में बहुत बहस कर चुके हैं। उन्हें यह याद होगा।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप बताएं कि आंख की जांच किस अस्पताल में करानी है?

श्री यशवन्त सिन्हा : पटना अस्पताल को छोड़ कर सब अस्तपाल में इसकी जांच करानी है। यहां देश के उद्योगों की बात कही गई, स्वदेशी की बात कही गई, अनएम्पलायमैंट की बात कही गई। नेता विरोधी दल को चीनी उद्योग के बारे में बहुत चिन्ता हो रही थी। वह कह रहे थे कि इस देश में हमारी क्षमता है और इस देश की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति देश के भीतर जो उत्पादन होता है, उससे की जा सकती हैं। चीनी को ओपन जनरल लाइसेंस में रखने का काम किस सरकार ने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया था। चीनी को ओपन जनरल लाइसेंस पर रखने के बाद उस पर जीरो डयूटी इम्पोर्ट को एलाऊ करने का काम किस सरकार ने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया?

श्री यशवन्त सिन्हा : हमने आते ही उस पर 5 परसैंट इम्पोर्ट डयूटी लगाई। उसके ऊपर साढ़े आठ सौ रुपए प्रति टन काउंटर वेलिंग डयूटी लगाई। आज चीनी पर इम्पोर्ट डयूटी 25 परसैंट है। यह काम हमने किया। आपने क्या किया? क्या आपको यह कहने का हक बनता है?

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : सारी चीनी तो आ गई।

श्री यशवन्त सिन्हा : आ गई है तो फिर अभी क्यों चिन्ता कर रहे हैं? आ गई तो आ गई।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : किसान तो मर गया।

श्री यशवन्त सिन्हा : चव्हाण साहब, आप तो कांग्रेस पार्टी के बड़े भारी डब्ल्यू.टी.ओ. के एक्सपर्ट माने जाते हैं। जब टेलिविजन में चर्चा होती है तो आप आते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं। मैं उनका आदर करता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अधिकार है हम जब चाहें, उस चीज के आयात पर रोक लगा दें। हम डब्ल्यू.टी.ओ. में सस्टेन कर पाएंगे। डब्ल्यू.टी.ओ. पर किस ने दस्तखत किए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप रेट आफ डयूटी की बात कर रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : वह 25 प्रतिशत और कांउटर वेलिंग ड्यूटी उसके ऊपर हम लोगों ने लगायी है। माननीय नेता विरोधी दल जानकार व्यक्ति हैं। अगर आप कह रहे हैं कि चीनी इम्पोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दो, क्या यह संभव है। जब तक हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उस एग्रीमेंट पर दस्तखत आपने किये और उल्टा दोष हम पर लगा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने हम पर और देश पर आब्लीगेशन लगाया है।

उपाध्यक्ष जी, यहां अनएम्पलायमेंट की बात कही गई। कहा गया कि अनएम्पलायमेंट बढ़ता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्यों बढ़ रहा है। जो रिफार्म्स विदआउट ह्युमन फेस 1991-96 के बीच में हुआ, जो हमने मॉडल ग्रोथ अडाप्ट करने का फार्मूला लिया, उसके चलते इस देश में अनएम्पलायमेंट की स्थिति में बिगाड़ आया। क्यों आया? वर्ल्ड ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इस फार्मूले के बारे में कहा गया कि यह रोजगार विहीन विकास है। रोजगार नहीं बढ़ेंगे मगर आर्थिक विकास होगा। इसीलिये हमने अपने नेशनल एजेंडा फार गवर्नेंस में उस मॉडल को रिजैक्ट कर दिया, हमने स्वीकार नहीं किया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

हम चाहते हैं कि इस देश का आर्थिक विकास भी हो, रोजगार का सृजन हो, यह हमारा मॉडल है। अभी नेता विरोधी दल यहां नहीं हैं। हमारा संतोष इस बात से नहीं होता कि मुम्बई में सेनसेक्स बढ़ रहा हैं, हमारा संतोष मात्र इस बात से भी नहीं होता कि हमारा फारेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। हमारा संतोष मात्र इस बात से भी नहीं होता कि हमारी खेती की पैदावार बढ़ रही है। हमारा संतोष तो इस बात से होता है कि इस देश के जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जो सबसे निर्धन हैं, जो सबसे कमजोर हैं, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिये यह सरकार क्या कर रही है। हमारे लिये पिछले 12-13 महीने में सरकार द्वारा कृषि, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के क्षेत्र में जो कुछ किया गया, वह हमारे लिये सबसे ज्यादा संतोष की बात है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि स्वदेशी आप नहीं समझते हैं। आपके लिये स्वदेशी मात्र एक शब्द हो सकता है लेकिन हमारे लिये स्वदेशी हमारे और इस देश की आत्मा है। इसीलिये उस शब्द को बार बार रिपीट करूं या न करूं लेकिन आप कहते हैं कि बजट में स्वेदशी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ जबकि पूरा बजट स्वदेशी की अन्तरआत्मा से प्रेरित है और इसीलिये हमने यहां...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया।

श्री यशवंत सिन्हा : कोई हंगामा नहीं किया और कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप हमारी पार्टी के बारे में क्या जानते हैं? आप कहते हैं कि हंगामा हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया उन्हें बीच में मत टोकिए। उन्हें बोलने दीजिए। जब आपको अवसर दिया जाए उस समय आप बोल सकते हैं। उनके बीच में मत टोकिए।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष जी, यह सही है कि मैं कभी उन्हीं के साथ था। उधर जितने लोग बैठे हुये हैं, उनकी रग-रग को ज्यादा कोई नहीं जानता, जितना मैं उन लोगों को पहचानता हूं, उतना कम लोग पहचानते होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहचानते हैं मगर उन्हें प्रोवोक मत कीजिये, इससे हमें तकलीफ होती है।

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बजट पेश करते हुये कहा था कि हमें संतोष है कि कृषि क्षेत्र में...

श्री लालू प्रसाद : यह आप बोल चुके हैं, कोई नई बात बोलिये।

श्री यशवंत सिन्हा : हमने जो ऋण की व्यवस्था की, उसके अंतर्गत 1998-99 में 31 हजार करोड़ रुपए की जगह 38 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई है और जो रूरल इनफास्ट्रक्चर फंड है...

श्री बलराम जाखड़ : यह तो पिछले साल के बजट के खर्च के हिसाब से कम कर दिया। आप आंकड़े देखकर बोलिये। आपके कृषि मंत्री यह कहते हैं कि कम होता है। आप ऐसा मत कहिये और आप ऐसा क्यों कहते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : जो प्रश्न उठाया गया उसके मुताबिक मैं इंस्टीट्युशनल फाइनेंस के आंकड़े बता रहा था।

अपराह्न 3.00 बजे

जब हम कृषि को देखते हैं, कृषि के पूरे क्षेत्र को देखते हैं, उसमें जाखड़ जी को जानना चाहिए, अन्य सदस्यों को जानना चाहिए कि यह राज्य का विषय है और भारत सरकार का जो बजट है वह बहुत छोटा अंश है उस पूरे देश के बजट का जो कृषि के ऊपर हम खर्च करते हैं। इन्होंने कहा कि यह हमने कितना परसेंट कम कर दिया। मैं कहता हूं कि आर.आई.बी.एफ. को अगर हमने 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35000 करोड़ रुपये कर दिया, 1000 करोड़ रुपये की उसमें अगर वृद्धि हुई है तो यह पैसा क्या कृषि के क्षेत्र में नहीं जा रहा है?

श्री बलराम जाखड़ : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा, कि पिछले साल जो आबंटन किया था उसमें से खर्च नहीं हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : पिछले साल कृषि के क्षेत्र में 58 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

श्री बलराम जाखड़ : वह किया लेकिन खर्च नहीं हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : उसमें बहुत कुछ खर्च हुआ। वह आंकड़े चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री बलराम जाखड़ : मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने निकालकर दिये थे।

श्री लालू प्रसाद : आम आदमी को क्या मालूम है आंकड़े क्या होते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : आम आदमी को तब मालूम होता है जब वह आंकड़ों से प्रभावित होता है।...(*व्यवधान*)

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : 50 साल में जो हुआ उसके आंकड़े भी देख लें आप।

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष जी, आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। जब लालू जी और हम बहस करते थे तो एक दिन लालू जी को मैंने कहा कि आंकड़े छोड़िये, 'औक्का बौक्का तीन तड़ौक्का' खेलते हैं। आंकड़ों से क्या मतलब है?...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : आपसे कहा गया था -

"ताड़ काटो सत्तू काटो काटो रे बल ख्वाजा
हाथी पर गए घुंघरू, चमक चले राजा।"

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि छः लाख से अधिक, पिछले वर्ष जो कम समय हमें मिला, किसान क्रेडिट कार्ड हमने इस देश में बैंकों के माध्यम से बांटे। इस साल का टार्गेट 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटने का है। हमने माइक्रो क्रेडिट की

बात की। उसमें हमने बहुत जोर देकर बैंकों को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर माइक्रो क्रेडिट की व्यवस्था होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि पिछले साल 1998-99 में हमने जो लक्ष्य रखा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं, वह 10,000 का आंकड़ा था और हमने वर्ष के अंत तक 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस देश में ऑर्गनाइज़ किया। इस साल का जो आंकड़ा रखा है, 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसके माध्यम से हम उन सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जो फातमी जी पूछ रहे हैं। अंतिम व्यक्ति की मदद के लिए माइक्रो ग्रुप सेल्प हेल्प ग्रुप्स राज्स से नहीं होगा और इसलिए आवश्यक है कि हम उन तक पहुंचें। मैं कहना चाहता हूं कि यहां बिहार की बहुत चर्चा होती है। मैं अभी अपने क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की परफॉमेंन्स रेव्यू कर रहा था। मझे खुशी है यह कहते हुए कि अनपढ़ महिलाओं के सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स बने हुए हैं। 20-25 महिलाएं इकट्ठा होकर कुछ न कुछ काम करती हैं। उनको छोटी सहायता बैंकों से मिलती है और आपको जानकर खुशी होगी कि जो बिहार बहुत मामलों में बहुत बदनाम है लेकिन 96 प्रतिशत वहां पर रिकवरी रेट है। हमें तो बहुत खुशी हुई। इसी तरह बैंकों के पैसे को हम दें, बैंको के पैसे वापस आएं, हम उसमें हस्तक्षेप नही करें, तो बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारे लिए संतोष का विषय है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत तेजी के साथ इस क्षेत्र में हम काम को आगे बढ़ाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ अपनी चिन्ता नहों कर रहे हैं। हम अपना घर संवार लें और देश के बाकी राज्यों की चिन्ता न करें, यह सही नहीं होगा। क्योंकि जब कोई भी बाहर से इस देश को देखता है तो भारत सरकार का क्या फिस्कल डेफिसिट है, भारत सरकार किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रही है, वह यही नहीं देखता है। वह यह भी देखना चाहता है कि इस देश के जो विभिन्न राज्य हैं, उनमें अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, फाइनेन्शियल मैनेजमैंट कैसा चल रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने फरवरी में नेशनल डेवलपमैंट कौंसिल की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में राज्यों ने अपनी पीड़ा और तकलीफें हमारे सामने रखीं और पूरा विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि मैं वित्त मंत्री की हैसियत से कुछ चुने हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों को बुलाऊंगा और उनके साथ विचार-विमर्श करके हम आगे का रास्ता तय करेंगे। मुझे यह कहते खुशी हो रही है कि हमने किसी राजनीति से प्रेरित न होकर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को यह दायित्व दिया कि आप राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इकट्ठा कीजिए और स्टेट्स में आपस में जो टैक्स वार चलता है, जिसमें हम रेट कम करते जाते हैं, ताकि हमारे यहां उद्योग आयें, इस टैक्स वार को कम किया जाए, खत्म किया जाए। वह रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मैंने सारे राज्यों को सर्कुलेट किया है और यह कहा कि उसके अनुसार वे अगले बजट में काम करें। मेरे पास सूचना है कि बहुत सारे राज्यों ने सहमति के आधार पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में अनेकों राज्य हैं और 31 मार्च, 1999 तक उनका रिजर्व बैंक के पास बहुत ओवर ड्राफ्ट हो गया था। सारे लोग आये हुए हैं। वे पांचवें वेतन आयोग के बर्डन को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं।

शरद पवार जी कह रहे थे कि इस बीच में कितनी स्ट्राइक्स हुई, कितनी तरह के भारत भारत सरकार के मुलाजिम स्ट्राइक्स पर गये, लेकिन क्यों गये, चूंकि पांचवें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आई, उस पर पिछली सरकार ने जो कुछ किया है, उसके बावजूद उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि जिनके कारण कहीं न कहीं, कुछ न कुछ बखेड़ा पैदा होता रहा है। पांचवें वेतन आयोग का भार राज्यों पर भी पड़ा है। लालू जी कह रहे थे कि वे महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, जरूर करते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को मुख्य मंत्री बनाया, बहुत सम्मान किया। लेकिन लालू जी, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में पता नहीं कितने दिनों से वहां के मुलाजिमों की स्ट्राइक चल रही है कि हमें भी पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दो। बिहार में चार महीने से स्ट्राइक चल रही है। बिहार में वैसे भी काम-काम नहीं होता है। इसलिए वे स्ट्राइक पर रहें या काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहां पिछले चार महीनों से यह चल रहा है। लेकिन कितना बड़ा बोझ राज्यों पर इसका पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में राष्ट्रपति शासन है। इसी सदन में जब मैं गोवा का बजट पेश कर रहा था, तब मैंने कहा था कि 1997-98 में अगर गोवा में 20 करोड़ रुपये का राजस्व का घाटा था तो वह बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो गया यह केवल पांचवें वेतन आयोग के कारण हुआ। इस तरह हम राज्यों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जैसा हमने एन.डी. सी. की मीटिंग में तय किया, हम हर एक राज्य के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्हें कैसे बेल आउट किया जा सकता है, भारत सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है। इन सारी बातों को देखते हुए हमने इस बात को कहा है। हम जब कमरे में बैठकर बात करते हैं तो सही नतीजे पर पहुंचते हैं और हमने कई राज्यों के बारे में इस प्रकार की बातचीत कर ली है,

[अनुवाद]

भारत सरकार और राज्य सरकारों ने समूचे देश में एक प्रमुख राजकोषीय संशोधन कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में, इस वर्ष में हम बहुत ही सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था सही है, देश की अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ उठती दीख रही है। लेकिन हमें देश के साथ-साथ दुनिया की भी चिन्ता है। चिंता इसलिए है कि कहीं किसी दूसरे देश में कुछ हो जाए उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। कहीं किसी क्षेत्र में कुछ हो जाए, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं इस सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब इस बात की चर्चा होती है कि दुनिया भर में नया फाइनेन्शियल आर्कीटैक्चर कैसा हो,

उसमें भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। इन संस्थाओं में आज के दिन भारत की आवाज इज्जत के साथ सुनी जा रही है क्योंकि मैंने

[श्री यशवन्त सिन्हा]

उनसे कहा कि भारत न केवल-

[अनुवाद]

> इस संकट से न तो हम प्रभावित हुए हैं और न ही हम इसका कारण हैं, इसलिए हमारी आवाज सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी आवाज सुनी जा रही है। हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं एक बात अन्त में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम इंटरनेशनल से नैशनल और नैशनल से राज्यों तक सारी बातों को देख रहे हैं, लेकिन हमें एक बात की चिन्ता है और वह यही है कि भारत सरकार से जो पैसे राज्य सरकारों को जा रहे हैं उनका सही उपयोगा होना चाहिए, यह देखना हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल की जो रिपोर्ट आ रही है। उनमें से कई राज्यों की रिपोर्ट अत्यन्त भयानक हैं। सारा लेखा-जोखा देखने के बाद वे रिपोर्ट बता रही हैं कि राज्यों में ढील की वजह से, नियंत्रण की कमीं के बाद वे रिपोर्ट बता रही हैं कि राज्यों में ढील की वजह से, नियंत्रण की कमी की वजह से इन पैसों का दुरूपयोग हो रहा है। मैं यहां पर सारे सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह धन देश की जनता की गाढ़ी कमाई का है और इसको बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं पहुंचता है।

श्री लालू प्रसाद : पता नहीं, ये क्या बोल रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : हम जो बोल रहे हैं वह आपको खूब समझ में आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि हम जितने सदस्य यहां बैठे हैं वे सब इस बात की चिन्ता करें कि इस पैसे का सदुपयोग हो और पैसा सही रूप से सही व्यक्ति तक, सही काम के लिए पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं कि जो राज्य इस दिशा में सही काम करेंगे, अब जो नई व्यवस्था बनाई जा रही हैं, उसमें कोई न कोई ऐसा उपाय किया जाएगा जिससे उन राज्यों के हिस्से में अधिक पैसा जाएगा। जो राज्य पैसे का सदुपयोग करेंगे उनको अधिक पैसा जाएगा और जो दुरूपयोग करेंगे, उन राज्यों को कम पैसा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यहां विश्वास मत के लिए खड़े हैं। विश्वास मत पर लालू जी का जो निर्गुण भाषण हुआ, उसको सुनकर हमारे अखबार वाले भाइयों की भी यह मजबूरी रहेगी और उनको बड़ी मुश्किल होगी कि वे उसमें कहां से क्या निकालें और क्या छापें?

श्री लालू प्रसाद : हमारा यह भाषण स्वदेशी भाषण था। यही आपकी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : लालू जी खुद कह रहे थे कि विदेशिया था, तो क्या विदेशिया स्वदेशिया हो गया?

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : विदेशिया यदि स्वेदशिया हो जाएगा, तो स्वदेशिया लजा जाएगा।

श्री लालू प्रसाद : यशवन्त जी तो विदेशिया हो गए हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : देश की अर्थव्यवस्था किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था इस सारे सदन की जिम्मेदारी है। हम सब लोग सम्मिलित रूप से एक साथ इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए।

[अनुवाद]

हमें यह महसूस करना चाहिए कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इसमें योगदान देना है। इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस सभा को और पूरी संसद को अपना योगदान देना है। मैं सभी दलों और सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन सभी समस्याओं जिनका सामना हमारे देश ने किया है, के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक स्थिति में ला दिया है। अर्थव्यवस्था में जिसे 'फील-गुड फैक्टर' कहा जाता है, उस में सुधार हुआ है और अब देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

हमें इस सभा में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े।

[हिन्दी]

मैं सारे सदस्यों से, सारे राजनैतिक दलों से अपील करना चाहता हूं कि जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अपने दलीय मतभेदों को भुलाकर हमें उसकी चिन्ता करनी पड़ेगी। लालू जी ने एक बात कही थी, उसका उत्तर देना आवश्यक है। उन्होंने बिहार के बारे में कहा कि हमें बिहार को छलना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रधान मंत्री जी, जो बिहार गये थे, वहां उन्होंने कुछ कार्यक्रमों और कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया। कल हम लोग गये थे, बिहार की मुख्य मंत्री महोदया भी वहां थी। वहां पर राजगीर के पास एक आर्डिनैंस फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इंडीपैडेंट इंडिया में पहली बार एक आर्डिनैंस फैक्ट्री बिहार में बनने जा रही है। लालू जी, अगर बिहार के लिए जरा सा दर्द है तो आपको भी इस बात पर फख्र और संतोष होना चाहिए। 25 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उस राज्य में होने जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट के बार बिहार में सैंट्रल गवर्नमैंट का इन्वेस्टमैंट नहीं के बराबर है, इसकी चिन्ता हुई? किसने चिन्ता की है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : श्री रीलाल प्रसाद वर्मा जी कह रहे थे कि 15 वर्षों से जांच पड़ताल कोडरमा में हुई और शिलान्यास राजगीर में हो गया।...*(व्यवधान)* आज रीलाल प्रसाद वर्मा जी कलप रहे थे।...*(व्यवधान)* वह कहीं बैठे होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए।...*(व्यवधान)* सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी।...*(व्यवधान)* वह वहां बैठे हैं।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, तनिक आप बता दें।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : रघुवंश बाबू, हम लोगों के बीच में यही तो दिक्कत है। आज अगर बिहार पिछड़ा है, आज अगर बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : यशवन्त बाबू, विरोध की बात हमने नहीं की। बिहार में कहां रहे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत टोकिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : रघुवंश बाबू जी, आपके पीछे बैठे हैं, उनको समझाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी बात पर कायम नहीं हैं. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अपनी बात पर कायम हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आखिर यह 14 तारीख को खरवास में ही क्यों? किसान की चिन्ता, मजदूर की चिन्ता है लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि यह बिल्कुल आई वॉश है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जब आप अपनी बात पर कायम न रहें तब आपको ऐसा कहना चाहिए तभी मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ।

[हिन्दी]

लेकिन यहां पर नार्मल कर्टसी अगर नहीं है।...*(व्यवधान)* हम खड़े हैं और वे बोले जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैं भी अपने बैंच पर खड़ा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं खड़ा हूं, मैं अपने पांव पर हूं। लालू जी, आप बैठ जाइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूँ। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो तभी मैं उनका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति दूंगा। अन्यथा मैं उनका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं अपनी बात पर कायम हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ मानदंड होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं यह कह रहा था कि बिहार में पहली बार दशकों में एक अच्छे काम की शुरूआत हो रही है। क्या है यह, यह तर्क यहां इस सदन में दिया जा रहा है। वहां पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, यह निराशा का वातावरण है। इसी से बिहार पीछे पड़ा हुआ है। आपस के टक्कर की वजह से ही बिहार पीछे पड़ा हुआ है। हमको आपस में किसी पर कोई विश्वास नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, इससे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बजट में हमने पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इतना कन्सैशन दिया है, अगर वह सारा कुछ हो तो इस देश के जितने पिछड़े क्षेत्र हैं, वह औद्योगिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। यहां पर बहुत चिंता हो रही थी। लालू जी नहीं थे, उस दिन रात को बारह, साढ़े बारह बजे जब मैं बजट भाषण का उत्तर दे रहा था।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सरकार ही नहीं रहने वाली है, तो बिहार को कैसे आगे बढ़ायेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास अठावले, वे अपनी बात पर कायम हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बीच में मत टोकिए। वे अपनी बात पर कायम हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मुझे याद है, उस दिन रात साढ़े बारह बजे जब मैं बजट भाषण का उत्तर दे रहा था, आप भी यहां मौजूद थे। मैंने उस समय कहा था कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए मैंने जो टैक्स पैकेज की घोषणा की थी, मैं लक्ष्यद्वीप, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर में उसी टैक्स इन्सेटिव पैकेज को वहां पर लागू करूंगा। यह कौन सी चिन्ता है? यह चिन्ता हमारे दूर-दराज इलाकों की है। इन सारे इलाकों की तरक्की हो, वे आगे बढ़ें। मैं अभी दो दिन लेह में था। हमारे रक्षा मंत्री महोदय का यह विचार था कि हमें वहां जाकर अपने देश के जो प्रहरी हैं, जो सेना के लोग हैं, उनसे मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलने के लिए गया था। वहां पर मैंने देखा कि लेह जो दूर-दराज का इलाका

[श्री यशवन्त सिन्हा]

है, वहां क्या स्थिति है? कौन लेह के बारे में बोल रहा है? कौन सी चिन्ताएं हम लेह के बारे में दिखा रहे हैं। जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां खराब जमीन है, क्या वहां की चिन्ता की? आज श्री शरद पवार जी हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी का क्या होगा, इस देश में विकास का क्या होगा, इस देश में बंद उद्योगों का क्या होगा। पचास वर्षों में क्या हुआ, मैं यह सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। क्या आपको पचास वर्ष और पावर में रखना पड़ेगा तब आप इन समस्याओं के समाधान के बारे में कहीं पहुंच पाएंगे? आपको कितना टाइम चाहिए? कुछ दिनों के लिए युनाइटेड फ्रंट की दो सरकारें थी, अटल जी की 13 महीनों की सरकार, कोई और 11 महीने की सरकार, कोई और 22 महीने की सरकार, आप तुलना करते हैं। सबको जोड़कर भी जब तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही है, हम उसके आसपास पहुंचने की बात भी नहीं करते। मुझे अफसोस होता है जब यहां बैठे हुए हमारे वामपंथी मित्र, लोकतांत्रिक मोर्चे के लोग, अन्य लोग आज उनके पास जा रहे हैं कि सरकार बना लें, किसी तरह सरकार में आ जाएं। किस बात के लिए आ जाएं? पचास वर्षों तक इस देश में जो कुछ हुआ है, क्या उसी को आगे पचास वर्षों तक करने के लिए आ जाएं? कौन यहां पर खड़ा होकर कह सकता है? आज चिदम्बरम जी यहां नही हैं। मैं उनके साथ सहानुभूति जताना चाहता हूं, उन्होंने भी बजट पेश किया था और उस बजट के साथ भी खतरा पैदा हुआ था जो इस साल के बजट के साथ हुआ है।...(*व्यवधान*)

श्री बलराम जाखड़ : आप क्या कह रहे हैं, पचास वर्षों में कुछ नहीं हुआ?...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भी बलराम जाखड़ की बात को स्वीकार करते हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : मैं अपनी बात पर कायम हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़, मंत्री जी अपनी बात पर कायम हैं। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : पचास साल में यदि हुआ है तो केवल सोनिया गांधी पैदा हुई हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक श्री यशवंत सिन्हा इससे सहमत नहीं होंगे तब तक कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा आता ही है, ये जा रहे हैं इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है।...(*व्यवधान*)

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : उपाध्यक्ष जी, अगर पन्द्रह वर्ष का लड़का ढाई फीट का हो तो क्या उसको विकास कहते हैं?...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : स्वतंत्र भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दूसरी सरकार है जो बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के न केवल बनी है बल्कि सालभर से ज्यादा चली है, पहली सरकार जनता पार्टी की श्री मोरारजी देसाई की थी। लेकिन इस देश में होता क्या है। कांग्रेस पार्टी, सत्ता से कुछ दिन बाहर हुई कि बिन पानी के मछली की तरह छट-पट करने लगती है। इनके सत्ता के बाहर 6-8 महीने गुजरे, इनको कुछ-कुछ होने लगता है।...(*व्यवधान*) उसके बाद जोड़-तोड़, उठा-पटक, कहीं लालू जी को लगाओ, लालू जी कह रहे हैं कि एक मिनट में चित्त करेंगे, धोबिया पाट मारेंगे। किसलिए मारेंगे, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। आपके खिलाफ उन लोगों ने केस किया, आपको जेल कोर्ट ने भेजा, हमारे खिलाफ तो हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर आ रहा है कि तेजी नहीं कर रहे हैं। कुछ-कुछ हो रहा है उन लोगों को और मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इनके फेर में मत पड़ें, एक बार हम पड़कर देख चुके हैं। चंद्र शेखर जी यहां नही हैं। जब देवेगौड़ा जी की सरकार बनी थी, मुझे याद पड़ता है कि उस समय इंडियन एक्सप्रैस में मैंने एक लेख लिखा था। मैंने चन्द्र शेखर जी की सरकार के अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि देवेगौड़ा जी की बहुत मजबूत सरकार बन गई है, चलेगी नहीं, सालभर पूरा नहीं होगा। मुझे लोगों ने कहा कि क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, यह सही नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है।...(*व्यवधान*) मैंने कहा था देवेगौड़ा जी की सरकार सालभर पूरा नहीं करेगी क्योंकि उनके सालभर पूरा करने से पहले कांग्रेस को कुछ-कुछ होने लगेगा और हुआ। गुजराल साहब उसी तरह चले गए। लालू जी कह रहे हैं एक मिनट में बनाएंगे। क्या बनाओगे ताश के पत्तों का घर बनाओगे? उनके साथ जो बैठेगा, मित्रों, वह बर्बाद होगा, याद रखो। अगर खुद का अनुभव नहीं है तो हमारे अनुभव से सीखो और अगर उसके बाद भी नहीं सीखना चाहते हो तो चूल्हे में जाओ।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा (तुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 20 मार्च, 1998 को जब प्रधान मंत्री ने इस सभा का विश्वास मांगा था, मैंने इस सभा को याद दिलाया था और मैं उसे उदधृत करता हूँ :

> "पिछले 22 महीनों के दौरान यह पांचवा विश्वास मत है। मैं नहीं जानता कि निकट भविष्य में इस सभा के समक्ष कितने विश्वास प्रस्ताव आने वाले हैं लेकिन मुझे

विश्वास है कि एक वर्ष से कम समय में कम से कम ऐसा एक और प्रस्ताव आ सकता है।"

मैं गलत था। मैंने एक वर्ष से कम समय में विश्वास मत की आशा की थी लेकिन आज यहां एक वर्ष से कुछ अधिक समय में यह एक और विश्वास प्रस्ताव आ गया।

अपराह्न 3.27 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

आज सुबह चर्चा में भाग लेते हुए माननीय गृह मंत्री ने जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ वैकल्पिक सरकार का प्रस्ताव होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आज यह सभा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। आज हम प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। अतः विपक्ष का इस सभा के सामने विवरण देने का प्रश्न कहां है? मुझे प्रधान मंत्री से यह आशा थी कि वह इस सभा को बतायेंगे कि यह विश्वास प्रस्ताव कैसे आया है। इसके क्या कारण हैं? भारत के राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को इस सभा का विश्वास हासिल करने को क्यों कहा? मेरे विचार से सारा देश आशा कर रहा था कि प्रस्ताव पेश करने के बाद प्रधान मंत्री अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इस सम्माननीय सभा को विश्वास मत हासिल करने के कारण बता देंगे। प्रधान मंत्री ने कहा कि वह पहले बोलने की बजाय सुनना पसंद करेंगे। मेरे विचार से विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भ्रम है। आज हम अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं बल्कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

1998 में आम चुनाव के दौरान भाजपा का नारा था, 'एक योग्य प्रधान मंत्री और स्थिर सरकार'। इस सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर कार्यभार संभाला। इस सरकार के पिछले 13 महीनों में मैंने न तो स्थिरता देखी और न ही शासन। मेरे विचार से इन 13 महीनों में देश ने कुशासन को ही देखा हैं। पिछली बार विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मैंने इस देश में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता के बारे में विस्तार से बात की थी, मैंने इस बात पर बल दिया था कि जहां तक हमारे राष्ट्र का संबंध है, यहां पर स्थिरता से अधिक महत्वपूर्ण शासन है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

> "क्या हमारे देश के लिए एक ऐसी स्थिर सरकार का होना पर्याप्त है चाहे वह शासन न करे? मेरे विचार से आज केवल स्थिरता महत्वपूर्ण नहीं है। आज अच्छा शासन एक मुद्दा है।"

मैंने आगे कहा था :-

> "मैं श्री वाजपेयी सरकार की स्थिरता के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मैं केवल इस अठारह दलों की सरकार के शासन के बारे में चिन्तित हूं।"

मैं वित्त से संबंधित मामलों की बात करना चाहता था। लेकिन उस समय मुझे वित्त के बारे में अधिक अनुभव नहीं था। अर्थव्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री ने अभी दावा किया है मेरे विचार से कल उन बातों का कोई जवाब दे देगा। मैं भी इसके बारे में कुछ बाते जानता हूं। मैं वित्त मंत्री से मतभेद करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन, कौन नहीं जानता कि आज इस देश की स्थिति क्या हैं? आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं अथवा विदेश नीति की बात करते हैं। निःसंदेह मैं विदेश नीति की बात नहीं करूँगा। यद्यपि सुबह गृह मंत्री महोदय ने इसका हवाला दिया था, मेरे सहयोगी श्री नटवर सिंह कल अथवा आज देर शाम को विशेष रूप से विदेश नीति पर ही चर्चा करेंगे।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति देखिए और सम्पूर्ण राष्ट्र की मनोदशा को देखिए। मैं नहीं मानता कि हमारे पास उपलब्ध इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तथा इस देश में आम उपलब्ध सूचना प्रोद्यौगिकी के होते हुए इसे किसी को बताने की आवश्यकता है। इससे कुछ नहीं होता कि श्री संगमा इस सभा में क्या बोल रहे हैं। लोग पहले से ही जानते हैं लोग इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि संगमा सच बोल रहे हैं अथवा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन सब बातों का जिक्र नही करूँगा तथा इन सब मुद्दों का जवाब नहीं दे रहा हूं।

आज मैंने सोचा कि मैं विशेष रूप से चिन्ता के एक विषय की ही बात करूंगा। हमारे देश में संस्थानों के स्तर में आ रही गिरावट चिन्ता का विषय है। जिस ढंग से हमारे संस्थानों को कमजोर बनाया जा रहा है, जिस ढंग से हमारे संस्थानों को अस्थिर किया जा रहा है तथा जिस ढंग से हमारे संस्थानों में गिरावट आ रही हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। यदि हम अपने संस्थानों को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते है तथा उन्हें मजबूत बना सकते हैं और यदि हम अपनी प्रणाली को मजबूत और सुरक्षित कर सकते हैं तो देश सरकारों की अस्थिरता के बावजूद भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इटली में 50 वर्षों में 51 सरकारें आई। लेकिन वह प्रगति कर रहा है। ऐसा ही स्थिति विश्व के अनेक अन्य भागों की है। इसलिए हमारे देश में याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने संस्थानों को सुरक्षित, संरक्षण, और सुदृढ़ता कैसे प्रदान कर सकते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले तेरह महीनों में हमारे संस्थानों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है और मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री को दोषी ठहराने का साहस नहीं कर सकता हूं। मुझे उन पर विश्वास है लेकिन यह कैसे हुआ? क्या यह जान-बूझकर अथवा अचानक अथवा सचेत अथवा अचेत अवस्था में हुआ है? शायद यह शासन में अनुभव की कमी के कारण हुआ। राष्ट्रपति के स्वयं के कार्यालय को देखिए। सभा में चर्चा के लिए राष्ट्रपति के नाम को इतना अधिक खींचा गया कि अगले दिन संसदीय कार्य मंत्री को यह कहते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा कि अध्यक्ष महोदय रिकार्ड देखेंगे और उन सभी टिप्पणियों को कार्यवाही से निकालेंगे। यह बहुत बुरा अनुभव था भारत का राष्ट्रपति और सरकार सूचना का आदान-प्रदान करते हैं। उनके बीच गोपनीय पत्राचार होता है। लेकिन आज हमारे सामने यह

[श्री पूर्णो ए॰ संगमा]

बात आई है कि सरकार और राष्ट्रपति के बीच गोपनीय सूचनाएं भी प्रैस को लीक की जा रही हैं। क्या हम राष्ट्रपति के कार्यालय के स्तर को नहीं गिरा रहे हैं?

एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी के तरीके को देखिए। भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है लेकिन हमें प्रैस के माध्यम से पता चला है कि इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति से सलाह भी नहीं ली गई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : इसका अनुमोदन करने अथवा हस्ताक्षर करने का प्रश्न नहीं था। सरकार ने क्या किया? प्रधान मंत्री जी हमने यही समाचार पत्रों में पढ़ा। यदि यह सच नहीं है और फिर भी हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आपने इसके बारे में कभी संसद को नहीं बताया। मैं यह आरोप आप पर और लगाना चाहता हूं। आपने कभी भी संसद को नहीं बताया कि क्या हो रहा है तथा हमें इसके बारे में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया से मालूम हुआ। लेकिन आरोप है कि राष्ट्रपति को केवल "सूचित" किया गया था। मैं इस बारे में चिन्तित हूं। प्रधान मंत्री जी मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि आपके विरूद्ध मेरा कोई आरोप नही है क्योंकि आपने जान-बूझकर ऐसा नहीं किया तथा ऐसा हो भी नहीं सकता। आप संसद में इस पर चर्चा कर सकते थे।

संसद में क्या हो रहा है? मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज संसद निष्क्रिय हो गई है। पिछले सत्र में 17.29 प्रतिशत समय व्यवधान के कारण नष्ट हुआ था। मैं जानता हूं कि आप पूछोगे कि यह व्यवधान किसने डाला। क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। आप मुझसे यह विधिसम्मत प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि विपक्ष यह समस्या पैदा कर रहा था तो क्या यह सदन प्रबंधन में आपकी असफलता नहीं थी? क्या आपने कभी सोचा है कि सदन का प्रबंधन कैसे किया जाए? यदि सभा पक्ष के पास विपक्ष को सुनने का धैर्य, नहीं है यदि संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष को उत्तेजित करते हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ बात भी नहीं करते हैं तथा उन पर अपने निर्णय और इच्छा सौंपना चाहते हैं तो आप संसद के सदन का प्रबंध, कैसे करेंगे? संसद में सदन प्रबंधन केवल सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है। यदि आज पूरा देश सदन में नारेबाजी देख रहा है यदि सारा देश सभा में अध्यक्ष के आसन के पास सदस्यों को आते हुए देख रहा है और यदि सारा देश सभा की कार्यवाही में व्यवधान को देख रहा है तो मैं इसके लिए शासक दल को जिम्मेदार मानता हूं। यह सदन प्रबंधन में सरकार की असफलता है।

भारत की संसद क्या है? भारत की संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं...(*व्यवधान*)

श्री विजयशंकर (मैसूर) : जाली मतदान के बारे में भी क्या आप चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लें?...(*व्यवधान*)

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मैं गंभीर मामला उठा रहा हूं। मैं पूर्णतः आपको दोष नहीं दे रहा हूं। शायद हम भी आंशिक तौर पर जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपको अधिक जिम्मेदार मानता हूं। यह देश के गंभीर मामले हैं। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। मुझे विश्वास है माननीय प्रधान मंत्री मेरी बात से शत प्रतिशत सहमत हैं।

मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो भी हुआ है वह जान-बूझकर नहीं हुआ है क्योंकि श्री वाजपेयी ने इन सबकी इजाज़त नहीं दी थी। इसीलिए मैं इसे शासन का अभाव और देश में शासन करने के अनुभव की कमी मानता हूं। मैं आप पर यही आरोप लगा रहा हूं। इसलिए आप इसे सीखें।

प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक का क्या हुआ?...(*व्यवधान*)

श्री एम॰ मास्टर मथान (नीलगिरी) : आपके पास पचास वर्ष का अनुभव है। आप अच्छे शासन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अध्यक्ष के आसन के पास क्यों जाते हैं?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक का क्या हुआ? इसे लोक सभा में पारित किया गया था। सरकार ने इसे राज्य सभा को न भेजने का निर्णय लिया था। क्या यह संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक अपेक्षा का उल्लंघन नहीं है। क्या सरकार संसद को मनमाने तरीके से चला सकती है? यह सोचती है कि संसद के उच्च सदन का कोई महत्व नहीं है। क्या ऐसा ही बिहार में अनुच्छेद 356 लगाने के संबंध में नहीं हुआ था? क्या यह देखना सरकार का कर्तव्य नहीं था कि इसके इस सभा में पारित होने के बाद यह स्वतः ही राज्य सभा में जाना चाहिए था? लेकिन सरकार ने इसे राज्य सभा को न भेजने का निर्णय लिया क्योंकि तकनीकी तौर पर सरकार अपना निर्णय वापस ले सकती है। क्या हम तकनीकी रूप से ही कार्य कर रहे हैं? क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना लोक सभा अथवा राज्य सभा में केवल चर्चा का ही विषय है? क्या हमारे पास भारत का संविधान नहीं है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

पिछले तेरह महीनों में क्या हुआ? मैं अपन मित्र श्री प्रमोद महाजन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल उन्हीं के कारण हो रहा है। श्रीमती सुषमा स्वराज यहां उपस्थित हैं। मेरे बाद वह बहुत अच्छी सूचना और प्रसारण मंत्री थी...(*व्यवधान*)

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : आप यह क्यों नही कहते कि वह आपसे बेहतर थी?...(*व्यवधान*)

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मैं वाणिज्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आयात निर्यात की बात नहीं कर रहा हूं। आज कोई सी.ई.ओ. नहीं है कोई दूरदर्शन महानिदेशक नहीं है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहां केवल श्री प्रमोद महाजन हैं। अतः मैं किसी से यह प्रश्न पूछ रहा था। दूरदर्शन में क्या हो रहा है? उसने कहा कि अब कोई दूरदर्शन नहीं है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों हैं। उसने कहा कि यह अब *सरकार दर्शन* हैं।

अब यह दूरदर्शन नहीं है लेकिन यह सरकार दर्शन दे रहा है ...(*व्यवधान*)

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह श्री महाजन का दर्शन है...(*व्यवधान*)

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मैं संसद के बारे में बात कर रहा हूं। श्री यशवंत सिन्हा आपको याद है कि जब आपने 1998-99 का बजट प्रस्तुत किया था तो संसद के इतिहास में पहली बार सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को "गिलोटिन" करना पड़ा था। केवल एक मंत्रालय कृषि मंत्रालय की मांगों पर 15 मिनट विचार-विमर्श हुआ था। श्री बलराम जाखड़ 15 मिनट तक बोले थे। यदि भारत की संसद इस देश के लोगों को बजट प्रस्तावों पर चर्चा से रोकती है और यदि हमें हर चीज को "गिलोटिन" करना पड़ता है तो क्या हम न्याय कर रहे हैं?

क्या सरकार कार्य कर रही है? क्या संसद कार्य कर रही है? मैं ये बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं।

जब से आपने कार्यभार संभाला है तब से आज तक इस सरकार ने 35 अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं...(*व्यवधान*) जीहां, 35 अध्यादेश। उनकी भारत की संसद ने पुष्टि नहीं की है। क्या यह केवल अध्यादेश सरकार है? भारत की संसद की प्रासंगिकता कहां है? मैं अपने संस्थानों को कमजोर बनाने के बारे में बात कर रहा हूं और संसद देश में अति प्रतिष्ठित संस्थान है। यदि इस देश के कानूनों को केवल लागू करना है और 13 महीने में आपने 35 अध्यादेश लागू किए हैं, जिन्हें भारत की संसद की पुष्टि नहीं मिली है, क्या हम संसदीय प्रजातंत्र के साथ न्याय कर रहे है। मैं यह बहुत सरल प्रश्न पूछ रहा हूं।

राज्यपाल कार्यालय के बारे में बात कीजिए। किसी और संस्थान की बात कीजिए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज कोई भी राज्यपाल बन सकता है। आपको केवल वफादार पार्टी कार्यकर्त्ता होना चाहिए यह ग्रहण करने के बाद आपको पार्टी कार्यकर्त्ता बने रहना होता है तथा अपने आपको पार्टी कार्यकर्त्ता होने की घोषणा करनी है। कार्यालय अथवा संस्थान की निष्पक्षता कहा हैं? क्या यह ठीक है। किसी की कोई विचारधारा हेनी चाहिए। मेरी एक विचारधारा है। कल मैं राज्यपाल बन सकता हूं। यदि मुझे अपने कार्य के साथ न्याय करना है तो जिस क्षण मैं राज्यपाल बनता हूं, मेरे विचार से मैं राज्यपाल ही हूं तथा इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए इस देश में आज कोई कुछ भी कुछ भी बन सकता है। मेरे विचार से हम संस्थानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। संस्थानों को नुकसान हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आपकी रोमेश भंडारी जी के बारे में क्या राय है? उनको आप ही ने भेजा था।...(*व्यवधान*) आपने यू.पी. में रोमेश भंडारी जी को राज्यपाल बना कर भेजा था। उनका कैसा व्यवहार था, उसके लिए आपने क्या किया?

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : आप नहीं जानते मैंने क्या किया है ...(*व्यवधान*)

मैंने रोमेश भंडारी के इश्यु पर इसी कुर्सी पर बैठ कर क्या किया, आप उसे देख लीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : वह स्पीकर ने किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया।...(*व्यवधान*) इस समय स्पीकर नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : नौकरशाही का मामला ही लें। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। प्रवर्तन निदेशक, श्री बेजबरूआ का क्या हुआ? सचिव, शहरी विकास मंत्रालय का क्या हुआ?

श्री मोहन सिंह : सतर्कता आयोग का क्या हुआ?

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : यह चाहे जो कुछ भी हो, श्री 'क' या श्री 'ख' को भारत सरकार का सचिव नियुक्त किया जाता है और मंत्री महोदय कहते हैं कि वह सचिव के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी और मैं उसे कोई काम नहीं दूँगा। ऐसा करना ठीक नहीं है। हम सुस्थापित व्यवस्थाओं और संस्थाओं की अवमानना कर रहे हैं। मैं ऐसी कई अन्य बातों के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि मुझे यह सब बताने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने अपनी पार्टी से वायदा किया है कि मैं केवल आधा घंटा ही समय लूँगा।

पिछली चर्चा में भी मैं एक छुपे हुए एजेंडा के बारे में बोला था जो कि शिक्षा व्यवस्था को केसरिया रंग देने के बारे में था। मेरा यह संदेह था कि आर.एस.एस. भारत के प्रत्येक विद्यालय में कैसे काम करेगा? डा॰ मुरली मनोहर जोशी तुरन्त खड़े हो गए और बोले, 'श्री संगमा, आपकी बात गलत हैं, हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं हैं। मैंने इस सदन को बताया कि मैं केवल अपनी संदेह व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने 'संदेह' शब्द का प्रयोग किया था क्या हमने इसे 13 महीने में नहीं देखा? क्या हमने इस अवधि में नहीं देखा कि मानव संसाधन मंत्रालय में क्या हो रहा है? क्या पूरा देश सकते में नहीं आ गया जब इस देश के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में डा॰ मुरली मनोहर जोशी ने आर.एस.एस. के एक आदमी को यह कहते हुए पेश किया था कि यही वह व्यक्ति हैं जो हमारी शिक्षा नीति बनाएँगे और यही हमारी भावी शिक्षा नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे यहां *सरस्वती वंदना* अनिवार्य होने जा रही है।

हमें केवल यही याद है। मुझे यह नहीं लगता कि कोई इसे भूल गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह विशेषज्ञ कौन था?

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : उस विशेषज्ञ का नाम श्री चीवलंजिया है। उस नाम का उच्चारण करना अत्यन्त कठिन है।

[श्री पूर्णो ए॰ संगमा]

महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि मानव संसाधन मंत्रालय की संस्थाओं में लोगों का चयन कैसे हो रहा है, लोगों की तैनाती कैसे हो रही है, पाठ्यक्रमों में कैसे परिवर्तन किया जा रहा है, इतिहास को किस प्रकार सुधारा जा रहा है इत्यादि। हम यह भी जानते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का किस प्रकार पुनर्गठन किया गया। वे इन सब बातों को अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मैं उसे गहराई से अनुभव करता हूँ कि हम ऐसी स्थिति की ओर जा रहे हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगी।

इसके बाद, एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी के मुद्दे को निपटाने का उदाहरण हैं। हम समाचारपत्रों में पढ़ते है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। दिनांक 30.12.1998 को जारी सरकारी वक्तव्य में कहा गया कि एडमिरल भागवत के आचरण से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था इसमें आगे यह कहा गया कि विष्णु भागवत ने ऐसे अनेक कार्य किए थे जो कि रक्षा सेनाओं के ऊपर मंत्रिमंडल के नियंत्रण की सुस्थापित व्यवस्था की अवज्ञा थी।

महोदय, मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि राष्ट्रपति की किस प्रकार उपेक्षा की गई। मैंने श्री ब्रजेश मिश्र के इस दावे के बारे में भी पढ़ा है कि विपक्ष के लोगों से परमर्श किया गया, श्री शरद पवार से परामर्श किया गया, श्री आई॰के॰ गुजराल से परामर्श किया गया इत्यादि। मैं जानता हूं कि श्री शरद पवार ने इसे पूर्णतया झूठ बताया है। प्रत्येक दिन, हम एडमिरल भागवत और श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा जारी किए जा रहे वक्तव्य और उन वक्तव्यों का खंडन पढ़ते हैं। कल मुझे एक बड़ी पुस्तिका प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया था कि उन्हें क्यों हटाया गया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जॉर्ज फर्नान्डीज जैसा साहसी और शुद्ध अन्तरात्मा वाला व्यक्ति जो कि मेरे बहुत नजदीकी हैं – मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ जब मैं श्रम मंत्री था तब उन्होंने मेरी बहुत सहायाता की थी और वे ट्रेड यूनियन नेता थे तब आज इतना भयभीत क्यों हैं। वे अपने बचाव के लिए प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में अपने वक्तव्य दे रहे हैं और अब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक पुस्तिका निकाली है। अगर रक्षा मंत्री इतने रक्षात्मक हो गए हैं, तब क्या होगा? देश की रक्षा करने के बजाए वे खुद की रक्षा कर रहे हैं। देश कैसे चलेगा?

महोदय, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि हमें आशा है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी और मैं उस चर्चा में भाग लूँगा। इसलिए मैं एडमिरल भागवत की बर्खास्तगी के पूरे मुद्दे पर चर्चा नहीं करूँगा लेकिन मैं केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब यह मामला सदन के सामने है, जब माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इस पर सदन में चर्चा होनी है, तब सरकार प्रचार माध्यमों के द्वारा प्रतिदिन ब्यान क्यों दे रही है। सरकार ने संसद के समक्ष इस मामले को पहले क्यों नहीं उठाया जो हुआ इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हमें सारी जानकारी प्रैस से मिली। संसद को इस संबंध में कुछ नहीं बताया मया है। सरकार अपनी कार्यवाही को संसद के बजाए प्रचार माध्यमों के द्वारा क्यों न्यायोचित ठहरा रही हैं मुझे इस पर सख्त एतराज है कि जब कोई मामला सदन के समक्ष प्रस्तुत है और माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तो मेरी समझ से सरकार को मीडिया के माध्यम से बयान नहीं देना चाहिए। सरकार को जो कुछ भी कहना है, वे उसे सदन में कहें। अन्यथा पूरा मामला पूर्वाग्रह युक्त हो जाएगा।

मैं कभी ऐसी बात नहीं करता कि मुझ में भविष्यवक्ता बनने के कुछ गुण है। लेकिन 28 मार्च, 1998 को मैंने इसके बारे में कुछ बातें कही थी। मैं अपना भाषण पढ़ रहा था। मैंने यह देखा कि उस दिन मैंने जो कुछ कहा वह हो रहा है। मैंने कुशासन के बारे में बहुत कुछ कहा।

उस दिन मैंने एक और बात कही थी जो काफी रोचक है। मैंने शासन के संबंध में ..ष्ट्रीय एजेंडा का उल्लेख किया था जिसमें पर इसमें राष्ट्रीय जल नीति का उल्लेख है। मेरा यह मानना था कि दक्षिण में किसी को खुश करने के लिए इसमें राष्ट्रीय जल नीति को शामिल किया गया है। मैंने प्रधानमंत्री को इसकी सफलता की शुभकामनाएँ दी थी। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ-

> "कावेरी जल के मामले में किसी व्यक्ति को खुश करने के प्रयास के लिए मैं अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ। मैं इस समस्या के समाधान में आपकी सफलता की कामना करता हूँ। लेकिन उस दक्षिण भारतीय नदी, बारे में जानने के कारण जो कि उतनी ही विशाल है पवित्र है, जितनी की *गंगा*, मुझे भय है कि कावेरी और नदीतटीय जल के मुद्दे कहीं आपकी सरकार को ही न बहा ले जाएँ।"

इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप आज यहां हैं। और यही उसका सही कारण है कि हम उस प्रस्ताव पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैं दूसरी बार आपको शुभकामना नहीं दे सकता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध करना है।

श्री आर॰ मुथैया (पेरियाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कल हमारे नेता द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद इस विश्वासमत को मांगने की बजाय त्यागपत्र दे दिया होता तो मैं उनकी प्रशंसा करता। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र मॉगने के कई कारण हैं। पूर्वाह्न में माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि जब मार्च, 1998 में यह सरकार बनी थी, तब राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को हमारी पार्टी द्वारा समर्थन का पत्र दिए जाने से पहले ही सरकार बनाने का आग्रह किया था। तथ्य यह नहीं है। हमारा पत्र प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रकार हम इस सरकार को बनाने के मुख्य कारण थे।...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : भाषण को सभा के पटल पर रखा जा सकता है।

श्री आर॰ मुथैया : मुझे तथ्यों को बताना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?...(*व्यवधान*)

श्री आर• मुथैया : श्री बालू की सदन में हमेशा व्यवधान उत्पन्न करने की आदत है। वे अब भी यही कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

न केवल सरकार बनाने के लिए, बल्कि पिछली लोकसभा के चुनाव के लिए बी.जे.पी. द्वारा किया गया गठजोड़ भी हमारे कारण हुआ और हमारी नेता पुरातजी थालाइवी प्रत्येक राज्य में किए गए चुनावी गठबंधन का कारण थीं। आडवाणी जी को याद होगा कि 1996 के आम चुनावों के बाद इस संसद में जब उनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब शिवसेना को छोड़कर किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया था। इसके विपरीत, 1998 के दौरान आपके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर क्या आपको इस सदन में इन अनेक पार्टियों का समर्थन माँगना पड़ा था? क्या हमारी नेता इन सभी बातों का मूल कारण नहीं हैं? आपने उन्हें इसका क्या पुरस्कार दिया?

अध्यक्ष महोदय : आप पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते। आप केवल कुछ पंक्तियां उद्धृत कर सकते हैं।

श्री आर• मुथैया : मैं इसे सम्पूर्ण रूप में नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है? क्या आपने हमें अपमानित नहीं किया है? पूरे विश्वास के साथ हमने अपना राष्ट्रीय एजेंडा बनाया और राष्ट्रीय एजेंडा में हमने तमिलनाडु से संबंधित अनेक बातें शामिल की हैं। क्या आपने तमिलनाडु की इन सभी आशाओं को पूरा किया है? अपने राष्ट्रीय एजेंडा में हमने 69 प्रतिशत आरक्षण, जो कि तमिलनाडु में लागू है, की संवैधानिक रक्षा के बारे में देश को आश्वस्त किया है। जिसमें हमने तमिल सहित देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को केन्द्र सरकार की राजभाषाओं के रूप में घोषणा करने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। हमने संसद में और राज्य के विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का आश्वासन दिया है। हमने कावेरी जल विवाद सहित नदी जल विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया है, जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती, लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष ने स्वयं ही इंगित किया। हमने तमिलनाडु की समुद्रम परियोजना को उचित ढंग से लागू करने का आश्वासन दिया है।

अब मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इस सभी परियोजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं जिनके बारे में अपने राष्ट्रीय एजेंडा में हमने राष्ट्र को आश्वासन दिया है। अब श्री वैको बोलने वाले हैं। हमने इस बजट में भी सेतु समुद्रम परियोजना को शामिल किया है। इसके बारे में थोड़ा सा ही यहाँ बताया गया है; लेकिन अपने बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसके लिए एक रुपया भी आबंटित नहीं किया गया है। अब हर कोई बी.जे.पी. की ओर से बोल रहा है। उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने समर्थन इसलिए वापस ले किया है क्योंकि उन्होंने डी.एम.के. सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। डी.एम.के सरकार की बर्खास्तगी हमारे छुपे हुए एजेंडा में नहीं है। हमने तमिलनाडु के लोगों को चुनाव के समय ही आश्वासन दिया था कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हमारे सहयोगी देश में सत्ता में आए, तब हम इस जन विरोधी डी.एम.के. सरकार को सत्ता से हटा देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे इसे कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ...(*व्यवधान*)

श्री आर• मुथैया : हमने लोगों को खुद माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष; खुद माननीय गृहमंत्री के समक्ष आश्वासन दिया है; हमारे नेता ने देश के लोगों को और राज्य के लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर हम सत्ता में आए तो डी.एम.के. के नेतृत्व वाली जन-विरोधी सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी...(*व्यवधान*)

श्री टी•आर• बालू : महोदय, वही छुपा हुआ एजेंडा है जिसे उन्होंने...(*व्यवधान*) वह उनका छुपा हुआ एजेंडा होगा...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, प्लीज

(व्यवधान)

श्री टी•आर• बालू : मैं श्री शरद पवार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह उनका छुपा हुआ एजेंडा है...(*व्यवधान*)

श्री आर• मुथैया : हमने तमिलनाडु सरकार को बरखास्त करने की माँग अपनी व्यक्तिगत बातचीत के दौरान नहीं की थी, लेकिन यह माँग इस सदन में ही की थी। हमने तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन दिया है कि हम तमिलनाडु की सरकार को बरखास्त करेंगे ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : वह कांग्रेस वाले करेंगे।

[अनुवाद]

श्री आर• मुथैया : चुनावों के समय हमारा उनसे गठबंधन नहीं था। चुनावों में हमारा गठबंधन बी.जे.पी. के साथ था। उनके नेता और सारी जनता के समक्ष हमने तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन दिया था कि हम तमिलनाडु में डी.एम.के. सरकार को बरखास्त कर देंगे। यह हमारे छुपे हुए एजेंडा में नहीं है। हमने लोगों को प्रकट रूप से कहा है...(*व्यवधान*)

श्री टी• आर• बालू : यह कांग्रेस का एजेंडा होगा...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया अध्यक्ष को संबोधित करें।

श्री आर• मुथैया : महोदय, अनेक अवसरों पर हमने उस सदन में ही खुले रूप में यह माँग रखी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि डी. एम.के. सरकार को बरखास्त नहीं किए जाने के कारण हमने समर्थन वापस ले लिया। महोदय यही एक मात्र कारण नहीं है।

श्री टी॰आर॰ बालू : यही एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन अन्य कारणों के साथ यह भी है..(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : हॉ, अब भी हम लोग यह कह रहे हैं कि डी.एम.के सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए। हम इस सरकार से यह मॉग कर रहे हैं। हमने यह मॉग तब भी की थी जब श्री इन्द्रजीत गुप्त माननीय गृह मंत्री थे। हमने राज्य सभा में उनसे यह मॉग की थी। यह मॉग केवल इस सरकार से नहीं की गई हैं...(*व्यवधान*)

श्री टी॰आर॰ बालू : अब, हम सब समझ सकते हैं...(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : हमने युनाइटेड फ्रंट सरकार से भी यही मॉग की थी। हमने इस सरकार से भी यह मॉग की है और भविष्य में आने वाली सरकार से भी हम यह मॉग करेंगे...(*व्यवधान*) हॉ, हम खुले रूप से यह मॉग करेंगे। यह हमारे छुपे हुए एजेंडा में नहीं है जैसा कि आपका एजेंडा है...(*व्यवधान*)

महोदय, जब हमने कावेरी जल विवाद में न्याय की मॉग की थी, तब हमें धोखा दिया गया। जब हमने ओबीसी के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक सुरक्षा करने पर जोर दिया था, तब हमें धोखा दिया गया। जब हम इस केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में तमिल को स्थान देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमें धोखा दिया गया। ये सब बातें केवल हमारे राज्य से संबंधित हैं। इसके अलावा अनेक अन्य बातें हैं।

जब हमारे नेता ने समन्वय समिति की बैठक में ही विष्णु भागवत के मुद्दे को उठाया था, तब इसकी अवहेलना की गई और इस अवहेलना ने अपने आप में ही देश की सुरक्षा को बनाए रखने में सरकार की विफलता को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है। वे यह कह रहे हैं कि इन बातों के बाद ही हमारे नेता ने भागवत मुद्दे पर जोर दिया था। लेकिन मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि बहुत पहले 2 जनवरी 1999 को ही हमारी नेता ने ऐसा वक्तव्य जारी किया था जिसमें इस संबंध में कार्रवाई करने और इस मामले में व्यापक जॉच-पड़ताल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था।

जब हमारी इन सभी मॉगों की अवहेलना की गई। तब हमने निर्णय लिया कि...(*व्यवधान*)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने रक्षा मंत्री के बारे में भी कुछ मॉग की थी...(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : हॉ। उन्होंने 2-1-1999 को यह वक्तव्य दिया था कि इसकी पूरी जांच करवाई जानी चाहिए। इसके बाद, इन सब बातों से हमें यह पता चला कि जब तक इस सरकार को सत्ता में रहने दिया जाता है, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा और इस सरकार की असफलताओं के कारण हमने मंत्रीमंडल से अपने मंत्रियों को वापस बुलाने और सरकार से बाहर रहने का निर्णय किया है। कल से हमने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है।

आज सुबह, श्री आडवाणी जी ने कई बातें कही हैं परन्तु उन्होंने अपने गृह मंत्रालय के बारे में कुछ भी नहीं कहा। गृह मंत्रालय जो कुछ लापरवाही बरत रहा है उसका एक उदाहरण मेरे पास है। श्री मदानी को कोयम्बटूर बम विस्फोट के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्रालय की लापरवाही के कारण कट्टर आतंकवादी, जिसने कोयम्बटूर विस्फोट में लिप्त आतंकवादी को हथियारों की आपूर्ति की थी, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया था। महोदय, अब हम क्या निष्कर्ष निकालें? आज, इन्होंने डी.एम.के. की उनके समर्थन के लिए प्रशंसा की है तो वे इस सरकार को मतदान के दौरान देने जा रहे हैं...(*व्यवधान*)

श्री टी॰आर॰ बालू : क्या आप हमारे प्रवक्ता हैं?...(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : हॉ। गृह मंत्री और आपकी पार्टी के बीच पिछले एक वर्ष से गुप्त एजेंडा क्या है? महोदय, उन्होंने इनको बहुत कुछ दिया है। किसके लिए? आपको हमें यह बताना चाहिए ...(*व्यवधान*)

श्री टी॰आर॰ बालू : आपको हमारा प्रवक्ता नहीं नियुक्त किया गया है...(*व्यवधान*)

श्री आर॰ मुथैया : पिछले एक वर्ष से उन्होंने श्री करूणानिधि को जैन आयोग द्वारा लगाए गए आरोपों से बचाने के लिए पूरा प्रयास किया है। इसलिए, डी.एम.के. इस सरकार को इनाम देने जा रही है। इस सरकार ने डी.एम.के की काफी मदद की थी। इसी कारण से, इन सब बातों के सामने आ जाने के कारण हमने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और इस प्रकार मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हम इस प्रस्ताव का पूरा-पूरा विरोध करते हैं और हमारी पार्टी के सभी 18 सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

कोई अफवाहें फैला रहा है इस सरकार के कुछ प्रबंधक जो इस सदन में नहीं आ सके हैं; बाहर अफवाह फैला रहे हैं कि ए.आई.डी.एम.के. का विभाजन होने जा रहा है। नहीं। सभी 18 सदस्य इस सदन में इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करने में हमारे नेता पुरात्ची थलैवी डा॰ जयललिता के पूरी तरह साथ हैं।...(*व्यवधान*)

डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी : हयात 'रिजेन्सी' होटल में वे यह कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वैको को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री वैको (शिवकासी) : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि यह सदन उनके नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है।

महोदय, मैं पूरी निष्ठा से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

महोदय, हमारे कुछ मित्र जनादेश के बारे में कहते आ रहे हैं। भारत की जनता ने अपने तरीके से सोचा और जनादेश दिया। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। 1996 में जनादेश दिया गया। उस समय भी कांग्रेस हारी थी।...(*व्यवधान*) हाँ, दोष उन्हीं का है। इसी कारण से मैं उनको निशाना बना रहा हूँ। पुनः 1998 में जनता ने कांग्रेस को सीधे नकार दिया। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई हमने जनता से जनादेश की मांग श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्थायित्व के नाम पर की थी। यह जनादेश मिला। इसमें नेता को ही महत्व दिया गया था। यह नेता देश को नेतृत्व देगा। परन्तु हमारे कैम्प में, वे पूरी तरह उहापोह की स्थिति में थे वे अपने बीच से कोई नेता नहीं दे सके। इसलिए, कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास है, जो इस देश में पिछले वर्षों में उनकी कार्यशैली रही है, कि इस सरकार को असंतुलित कर दिया जाए। यह जनता द्वारा दिए गए जनादेश को असंतुलित करने का प्रयास है। यह प्रजातंत्र को असंतुलित करने का प्रयास है।

जब श्री संगमा, संसदीय प्रजातंत्र के बारे में बोल रहे थे, मुझे उनके वे शब्द याद आ रहे हैं "दि डेविल कोट्स दि स्क्रिप्चर्स ऑफ दि बाइबल"। महोदय, मैं यहाँ गैर-कांग्रेस (आई) राजनैतिक पार्टीयों के अपने मित्रों की तरफ देख रहा हूँ। इस सदन में अथवा इस देश में एक भी गैर-कांग्रेस राजनैतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो अस्थिर करने की कांग्रेसी चाल के शिकार नहीं रहे हो। वर्ष 1996 के चुनावों के पश्चात इस सभा में, जब श्री देवेगौड़ा ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन की सरकार के गिरने के बाद, सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री नरसिम्हा राव ने यह आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी इस सरकार को पूरी पांच साल की अवधि के लिए अपना बिना शर्त समर्थन देगी। कुछ समय बाद, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सापेक्षता का एक विचित्र सिद्धान्त खोज लिया और पांच वर्ष की अवधि अचानक सिकुड़ कर मात्र 10 महीनों की हो गई। श्री गौड़ा को बाहर कर दिया गया। इसके बाद, मेरे अभिन्न मित्र, श्री इंद्र कुमार गुजराल ने सरकार की बागडोर संभाली। यह केवल छः महीने चली। और अब ये, कांग्रेस पार्टी, संसदीय प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के नियमों की बात करते हैं। यह देश भूला नहीं है और देश की जनता इन वर्षों में जो कुछ हुआ है उसके लिए उन्हें माफ नहीं करेगी।

कांग्रेस पार्टी किसी भी अन्य पार्टी, गैर-कांग्रेस पार्टी, को इस देश के किसी राज्य में, तथा केन्द्र में भी, शासन नहीं करने देती है। इसी वजह से आपको याद होगा कि केरल में 1959 में नम्बूदरीपाद सरकार के साथ क्या हुआ था? राज्यों सरकारों को 104 बार गिराया गया जिसमें केवल कांग्रेस पार्टी ने 95 बार ऐसा किया था।

प्रजातंत्र में जब सत्ताधारी पार्टी जनता के निर्णय द्वारा विरोधी पार्टी बन जाती है, यदि उस पार्टी के सदस्यों में प्रजातंत्र के प्रति कोई आदर भाव है, तो उन्हें अगले चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। परन्तु जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा, ने कहा है, वे सत्ता से बाहर रह ही नहीं सकते।...(*व्यवधान*)

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : प्रजातंत्र के दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो रहा है।...(*व्यवधान*)

श्री वैको : हाँ। मैं कह सकता हूँ मैं उनका समर्थन करता हूँ। आप कृपया सुनें।

श्री ए॰सी॰ जोस : मैं आपको सुन रहा हूँ।

श्री वैको : यह आपकी ही पार्टी है जिसने इस देश में प्रजातंत्र को नष्ट किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण जब आपकी सरकार को खतरा हुआ था तो यह आपकी पार्टी ही थी जिसने प्रजातंत्र, एक आदर्श प्रजातंत्र का गला घोंटा था। और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम अपने कुछ मित्रों के साथ जेल की काली कोठरियों में रहे।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : वह मान नहीं रहे हैं।

(*व्यवधान*)

श्री वैको : आपको प्रजातंत्र के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री ए॰सी॰ जोस : आप भी सुश्री जयललिता के समर्थन से ही निर्वाचित हुए हैं।...(*व्यवधान*)

श्री वैको : मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप कृपया बताएं कि आपने 1975 में प्रजातंत्र को नष्ट किया था या नहीं? 1975 में आपने ही प्रजातंत्र की हत्या की थी और आपको सत्ता से बाहर कर दिया गया। 1977 में भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पुनः पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था।

क्या हुआ। उन्होंने श्री मोरारजी देसाई की सरकार के साथ भी पुनः वही चाल चली। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भड़काया, झूठी आशाएं दी और पूरी तरह गुमराह करके सरकार गिरवा दी। इसके बाद क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह को भी संसद सत्रारंभ के पहले ही दिन वही कुछ सुनना पड़ा।

फिर, 1990 में जब श्री वी॰पी॰ सिंह की सरकार थी, तब क्या हुआ?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया सदन में व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री वैको : वे मेरे तर्कों से भयभीत हैं, इसलिए समस्या हो रही है। वे तर्कों का सामना नहीं कर सकते। वे भयभीत हैं।

जब श्री वी॰पी॰ सिंह की सरकार थी, उन्होंने पुनः क्या किया? उन्होंने फिर से उन्हें गुमराह किया, उन्होंने श्री चन्द्रशेखर को भड़काया, जैसा कि सिन्हा ने अपने उस भयानक अनुभव के बारे में बताया जिससे उन्हें गुजरना पड़ा। हरियाणा राज्य के दो पुलिस कर्मियों को देखते ही, उन्होंने तो-हल्ला मचा दिया और वह सरकार गिरा दी गई। उन्हें जाना ही पड़ा।

कांग्रेस के बारे में श्री लालू प्रसाद और श्री मोहन सिंह भी जानते हैं।...(*व्यवधान*) मैं आपका आदर करता हूँ, श्री लालू प्रसाद...

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : कितनों को प्रधान मंत्री बना दिया। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री वैको : श्री लालू प्रसाद, आप कांग्रेस के चक्कर में न पड़ें। कम से कम आप आक्टोपस के चुंगल में न फसें। आपका खात्मा हो जाएगा। यह पहले हो चुका है।

कांग्रेस पार्टी ने सरकार को अस्थिर करने का खेल अभी क्यों शुरू किया? इसका क्या कारण है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने पोखरण परीक्षणों के द्वारा विश्व के सामने देश का गौरव बढ़ाया। विश्व को यह दिखा दिया कि भारत एक परमाणु अस्त्र सम्पन्न देश है। हमने अपनी शक्ति दिखा दी है और विश्व की तथा-कथित शक्तियों के इस भ्रम को दूर कर दिया है कि वे ही परमाणु अस्त्र संपन्न देश हैं। अब यह भ्रम टूट चुका है। एक ओर उन्होंने हमारी क्षमता सिद्ध करते हुए इस देश को विश्व में एक परमाणु अस्त्र सम्पन्न देश के रूप में स्थापित किया है तथा साथ ही शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। विश्व ने इतिहास के कई निर्णयात्मक क्षण और अवसर देखे।

महोदय, जब कैंप डेविड में श्री अनवर सादात और मेनाचेम बेगिम ने हाथ मिलाया और समझौता किया तो विश्व में खुशी फैली; जब बर्लिन की दीवार गिराई गई, तब विश्व में खुशी मनाई गई; जब फिलीस्तीन और इजराइल ने व्हाइट हाऊस के लॉन में समझौता किया तो सारे विश्व ने उन्हें बधाई दी। इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री जुल्फीकार अली भुट्टों के साथ समझौता किया - शिमला समझौता - तो विश्व ने इसकी प्रशंसा की और बधाई दी। इसकी प्रकार जब बस सरहद के पार किया और पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया तो सारे विश्व ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई दी। यह एक शांति का संदेश है, यह एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश हैं।

ये लोग यह शोर मचा रहे हैं कि यह सरकार मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के विरूद्ध है, और जब यह तर्क असफल हो गया तो वे भयभीत हो गए। सरकार ने सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। इसलिए, वे सरकार गिराना चाहते थे। अब, मेरे मित्र उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। जनादेश श्री वाजपेयी को मिला था।

हमें विशेष रूप से कांग्रेस से एक विरासत मिली थी। परन्तु आर्थिक क्षेत्र की सभी खामियां इस सरकार को विरासत ही में मिली हैं। माननीय वित्त मंत्री ने यह विस्तार से बताया कि हमने विश्वव्यापी आर्थिक संकट और पूर्वी एशियाई आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न अपनी आर्थिक संकट पर कैसे काबू पाया है। इसलिए, प्रत्येक क्षेत्र में जब सरकार सफल हो रही है और सुदृढ़ हो रही है तब उन्होंने सरकार को गिराने का फैसला किया है। उनका प्रयास व्यर्थ साबित होगा और वे इसमें सफल नहीं होंगे। जब मतदान होगा तब बिहार के मामले में जो कुछ हुआ, वही इस सदन में होगा जिसे यह सदन और विश्व देखेगा।

पिछले पांच दशकों के दौरान जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, एक के बाद एक घोटाला हुआ। कांग्रेस सरकार का यह प्रयोग था। उदाहरणार्थ, मुद्रा भ्रष्टाचार कांड से लेकर, प्रतिभूति घोटाला, यूरिया घोटाला, शुगर घोटाला, बोफोर्स कांड और ऐसे कई और घोटाले हुए।

मैं बोफोर्स पर आ रहा हूँ। मैं अपने कामरेडों, अपने मार्क्सवादी मित्रों का आदर करता हूँ।

20 अप्रैल, 1987 को जब बोफोर्स पर वाद-विवाद हुआ तब उन्होंने क्या कहा था?

> "एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप लगाए गए हैं। यह सरकार उल्टी गंगा बहाने में लगी है। हम संसद को इस मामले में शामिल किए बिना तथ्यों को बता रहे हैं लेकिन वे सब कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।"

यह श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण था। जब कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह स्पष्टीकरण मांगा कि इस कांट्रैक्ट में कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त थी; श्री सोमनाथ चटर्जी ने पुनः बीच में ही कहा: "घूस का कितना प्रतिशत था?" एक बार फिर 1988 में जब 15 नवम्बर को बोफोर्स पर वाद-विवाद हुआ, श्री सोमनाथ चटर्जी ने कांग्रेसी मित्रों द्वारा श्री वी॰पी॰ सिंह के विरूद्ध आरोप और आलोचना किए जाने के बारे में उल्लेख करते हुए कहा : "ऐसा लगता है वह प्रतिपक्ष के साथ थे।" ये श्री सोमनार्थ चटर्जी के शब्द हैं। वह श्री वी॰पी॰ सिंह और प्रतिपक्ष के एक ही साथ होने के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा : "मुझे उम्मीद है वे कांग्रेस जनों के साथ नहीं होंगे। मैं दुबारा कहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि वे कांग्रेसियों के साथ नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें भयानक रोग हो जाएगा।" यह श्री सोमनाथ चटर्जी का वक्तव्य था। 1979 में भी, श्री ज्योतिर्मय बसु पोलैंड में वारसॉ में छुट्टी बिता रहे श्री ज्योति बसु से संपर्क करना चाहा, हमें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने सरकार का समर्थन नहीं किया और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अब कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से प्रजातंत्र को अस्थिर करने, प्रजातंत्र के नियमों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। यहाँ यही सब हो रहा है।

हमें एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले और घोटाले देखने को मिल रहे हैं। बोफोर्स कॉंट्रैक्ट के नाम पर लूटा गया पैसा बैंक ऑफ स्वीटजरलैण्ड के पांच खातों में जमा किया गया है।...(*व्यवधान*)

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा (कोलार) : श्रीलंका में आपकी भागीदारी क्या है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में व्यवधान मत डालिए। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वैको : मेरी भागीदारी को सारा विश्व जानता है। यह पारदर्शी है, यह गुप्त नही हैं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वैको : उन्होंने बोफोर्स कांट्रैक्ट में देश को लूटा है, उन्होंने प्रतिभूति घोटाले, चीनी घोटाले और यूरिया घोटाले में देश को लूटा हैं। आज सरकार ब्लैकमेलरों के चुंगल से मुक्त हो गई है। श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ब्लैकमेलरों और दबाव समूहों के चंगुल से मुक्त हो गई है। रक्षा के मामले में बड़ा हास्यास्पद वक्तव्य दिया गया था कि इस सरकार ने, खासकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अग्नि-2 का प्रक्षेपण नहीं होने दिया...(*व्यवधान*)। जब यह हास्यास्पद वक्तव्य अख़बारों में छपा, तब तक अग्नि-2 का प्रक्षेपण हो चुका था और यह पूर्वी तट को पार कर चुका था।

एक माननीय सदस्य : अब दिल्ली में अग्नि-3 का प्रक्षेपण होगा...(*व्यवधान*)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह किसने कहा?

श्री वैको : और किसी से बेहतर आप जानते हो। जो लोग ऐसा हास्यास्पद वक्तव्य दे सकते हैं, उन्होंने ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय, श्री शरद पवार, विपक्ष के नेता ने काफी लम्बा भाषण दिया। श्री संगमा भी बोले। इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : गुरूस्वामी का क्या कहना है?

श्री वैको : श्री मोहन गुरूस्वामी के मुद्दे पर, उस दिन उनका पूरा मामला ही खत्म हो गया था और उस दिन उनका बड़ा अपमान हुआ था।...(*व्यवधान*) कोई मामला ही नहीं था। उनके सभी तर्क पूरी तरह से काट दिए गए थे।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने बहस के लिए बहुत ही मजेदार सवाल किया था : 'वाजपेयी सरकार के बाद की स्थिति क्या होगी?' क्या इन लोगों में कोई मतैक्य है? रिवोलूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फारवर्ड ब्लाक ने साफ-साफ कह दिया है कि वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 18 से अधिक लोग हैं। बहस के लिए अगर मान भी लें कि यह सरकार गिरेगी, तो चुनाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

जनता का विचार क्या है? जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। 1998 में हुए चुनाव में जिन लोगों ने भा.ज.पा. और इसके सहयोगी दलों के पक्ष में वोट नहीं दिया था, जिन लोगों ने भा.ज.पा. के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, वे लोग भी चाहते हैं कि यह सरकार चलती रहे। यह ओपीनियन पोल का निर्णय है। सुबह हमारे गृह मंत्री महोदय ने *इंडिया टाइम्स* का ओपियन पोल पढ़ा था। एक सवाल यह था : 'क्या सोनिया वाजपेयी से बेहतर प्रधानमंत्री होंगी? 19 प्रतिशत ने 'हां' कहा था, 77 प्रतिशत लागों ने 'नहीं' कहा था और 4 प्रतिशत लोगों ने 'कह नहीं सकते' कहा था। यह पत्रिका हमेशा भा.जा.पा. सरकार की आलोचक रही है। यह ऐसी पत्रिका है जो (भा.ज.पा.) समर्थक नहीं है। इस पत्रिका में ओपिनियन पोल के बारे में रिपोर्ट है। यह 19 अप्रैल, 1999 का संस्करण है। सवाल था : 'वाजपेयी को पद पर बने रहना चाहिए अथवा त्यागपत्र दे देना चाहिए?' यह ओपीनियन पोल छह महानगरों में लिया गया था जिनमें चेन्नई भी शामिल है। महोदय, चेन्नई के मतदाताओं ने भा.ज.पा. गठबंधन के पक्ष में वोट नहीं दिये थे। चुनाव के समय हम तीनों लोक सभा चुनाव क्षेत्रों में हारे थे। फिर भी चेन्नई सहित छह महानगरों में किए गए ओपीनियन पोल का निष्कर्ष यही है कि वाजपेयी सरकारी चलती रहनी चाहिए। 63.9 प्रतिशत लोगों का विचार है कि उन्हें सरकार में बने रहना चाहिए। 26.2 प्रतिशत लोगों का विचार है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। यही जनता की इच्छा है।

महोदय, हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हमने भ्रष्टाचार के प्रश्न पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। भ्रष्टाचार तो सार्वजनिक जीवन में कैंसर की तरह है। भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी बुराई है और अब तक जितने साल तक...(*व्यवधान*) कांग्रेस सरकार की रही, वे एक के बाद दूसरे घोटाले में लिप्त रहे। किंतु 1998 का पूरा साल भारत के लिए घोटालों से मुक्त रहा। अतः जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से जनता के खजाने को लूटा है, यह उनका अपने निजी एजेंडा के लिए कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग करने का ढंग है। गुप्त एजेंडा क्या है? कोई गुप्त एजेंडा नहीं है।

'सरकार नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है।

अभी सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में उल्लेख किया गया था। मैं उस तरफ बैठे अपने मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतने साल से इस परियोजना को कार्यान्वित करने की पहल आपने क्यों नहीं की? आप 45 साल सरकार में रहे और कितने ही प्रधानमंत्री हुए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अन्ना की वर्षगांठ के अवसर पर एम डी एम के द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने के लिए 15 सितम्बर को मद्रास गए थे तब उन्होंने ही जनता का आश्वासन दिया था कि सरकार लम्बे अरसे से लंबित सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करेगी। इसलिए महोदय, इन बातों की आलोचना करने का अधिकार इन लोगों को कतई नहीं है।

ये लोग साम्प्रदायिकता की बात कर रहे थे। देश इन लोगों की भूमिका को भूला नहीं है। जब जम्मू-कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने ही साम्प्रदायिकता का कार्ड चला था। उन्होंने हिन्दू कार्ड चला था। हम धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध हैं। जब हमने समर्थन किया और जब हम गठबंधन में शामिल हुए तभी हमने साफ-साफ कह दिया था कि धर्मनिरेपक्षता और पूजा स्थलों पर चाहे वह चर्च हो या मस्जिद, मंदिर हो या गुरूद्वारा, सबका सम्मान होना चाहिए।...(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : इन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी है।

श्री वैको : मैं इस विषय पर भी बोलूँगा। हम किसी से पीछे नहीं हैं। जब कभी भी अल्पसंख्यकों पर हमला होता है, यह खेदजनक और निंदनीय है। ये शब्द श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। श्री वाजपेयी जब अविश्वास प्रस्ताव 1992 में लाए थे, उस समय के उनके भाषण को पढ़िए। उन्होंने दुःख और अप्रसन्नता व्यक्त की थी। लेकिन हुआ क्या?...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : किसकी मौजूदगी में इसे गिराया गया था?

श्री वैको : कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? येरूशलम की अल-अक्स मस्जिद की रखवाली आज भी की जा रही है। श्री आचार्य, कृपया आप सुनिए। येरूशलम में आज भी अल-अक्स मस्जिद की रखवाली की जा रही है। कांग्रेस सरकार 128 कम्पनियों का क्या कर रही थी। और सेना क्या कर रही थी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी?...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए किसे चार्जशीट किया गया है?

श्री वैको : यह होने किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने ही शिलान्यास होने दिया था। श्री राजीव गांधी ने शिलान्यास होने दिया था।

श्री शरद पवार : यह काम श्री कल्याण सिंह ने करवाया था।

श्री वैको : सरकार आपकी थी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी जिसने मंदिर निर्माण होने दिया। इसलिए ये सब बातें करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. की सरकार थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री वैको : लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं। आज भा.ज.पा. और इसके सहयोगी दलों में मतैक्य है, परस्पर एक जुटता है तथा आपस में मैत्रीपूर्ण समझ-बूझ बनी हुई है। हम सबकी एक ही इच्छा है, एक ही ध्येय है और हम देश में स्थिरता तथा सम्पन्नता चाहते हैं। श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार और इसकी सहयोगी पार्टियां इसके लिए वचनबद्ध हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? हर पार्टी का अलग-अलग एजेंडा है। कुछ भी हो, महोदय मैं पुनः यही कहूंगा कि तेरह महीने में और अभी तक ये लोग इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। यह सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी की पक्षधर है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने अपना समर्थन वापस क्यों लिया?...(*व्यवधान*) इसलिए कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, और यही वजह है कि...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वैको : यह एक-दो करोड़ रुपए का नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वैको : महोदय, मैंने किसी राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वैको : मैंने किसी राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है लेकिन जो दोषी हैं, वे तिलमिला रहे हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आप आधा घंटे से अधिक ले चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वैको : महोदय, संसद भवन के भीतर दीवारों पर कई पेंटिंग्स लटकी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री वैको : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं लेकिन ये लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं...(*व्यवधान*) मैंने किसी राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है। लेकिन जो लोग दोषी हैं, वे परेशान हो रहे हैं।...(*व्यवधान*) महोदय, आज कम से कम सरकार को सबसे बड़े ब्लैकमेलर से निजात मिल गई है।...(*व्यवधान*) मैंने ए आई ए डी एम के का नाम नही लिया है।...(*व्यवधान*) मैंने ए आई ए डी एम के की महासचिव का नाम नहीं लिया है।...(*व्यवधान*) ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? ये इतने आतंकित क्यों हो रहे हैं?...(*व्यवधान*) अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इतने आतंकित क्यों हो रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आपने लगभग चालीस मिनट ले लिए हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री वैको : महोदय, इन्हीं लोगों ने तमिलनाडु को लूटा है। इन्हीं लोगों ने राज्य में अपने शासन के दौरान करोड़ों बनाए हैं।

श्री आर. मुथैया : महोदय, आप इन्हें इस तरह की बातें क्यों कहने दे रहे हैं?

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वैको : मैंने एआईएडीएमके के भ्रष्टाचार को कभी भी किसी भी राजनीतिक प्लेटफार्म से उचित नहीं ठहराया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वैको : जब भी मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं ये लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। अभी कुछ लोग हवाई किले बना रहे हैं। जब वोटिंग होगा तो ये सब किले ध्वस्त हो जाएंगे।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसे सदन में सफलता और विजय मिलेगी।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

इस सदन में आने वाला यह दूसरा विश्वास प्रस्ताव है। पहले विश्वास प्रस्ताव पर सरकार बनने के बाद चर्चा हुई थी और 13 महीने के अंदर ही सदन में यह दूसरा विश्वास प्रस्ताव है।

अपराह्न 4.51 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

गृह मंत्री और जो लोग सरकार के समर्थन में बोले, उन्होंने विपक्ष पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। सबसे पहले, सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने का कारण क्या है? मैं इस बिन्दु पर चर्चा करना चाहूंगा। विपक्ष की गतिविधियां अथवा आरोप इसका कारण नहीं हैं। एआईएडीएमके के समर्थन के पत्र के कारण ही यह सरकार सत्ता में आई है। महामहिम राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एआईएडीएमके की प्रमुख द्वारा दिए गए समर्थन पत्र के अनुसार ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और कल ही उन्होंने समर्थन वापस लिया है।

इसलिए सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि इस सरकार को बने रहने का कोई भी नैतिक, कानूनी अथवा संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए बेहतर है कि यह सरकार सदन का विश्वास प्राप्त करने के बजाय त्यागपत्र दे दें। ऐसा सरकार के सहयोगियों में आंतरिक विरोधाभास होने के कारण हुआ है कि श्री बूटा सिंह, डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी और अब एआईएडीएमके और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने भी समर्थन वापस ले लिया तथा इन सभी पार्टियों ने जोर देकर साफ-साफ कहा है कि यह सरकार बहुमत में नहीं है। भा.ज.पा. विपक्ष पर यह आरोप कैसे लगा सकती है कि विपक्ष के कारण सदन में यह विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। हम किसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया है। महामहित राष्ट्रपति के निर्देश पर इस सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है।

भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार के घटकों ने विपक्ष के दोष अथवा गतिविधियों के कारण समर्थन वापस नहीं लिया है। अब भा. ज.पा. को अपने अगले कदम की चिंता है। इस सरकार के गिरने पर अगली कार्रवाई क्या होगी?

भा.ज.पा. सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बारहवीं लोक सभा के चुनावों में जनता ने विखंडित जनादेश दिया था इसीलिए ऐसा हुआ है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण कुछ सहयोगी पार्टियों के समर्थन से भा.ज.पा. सत्ता में आयी और एआईएडीएमके दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी थी जिसके 18 सांसद हैं और अब इस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। एआईएडीएमके की समर्थन वापसी के कारण देश की जनता को बताने होंगे। सरकार को भी इस देश की जनता को बताना होगा कि यह गठजोड़ क्यों टूटा।

मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार जो पिछले तेरह महीने से सत्ता में बनी हुई है, अल्पमत में है। यह तो समय की बात थी कि ये लोग सत्ता में आए। इनकी बेहतरी इसी में है कि ये विश्वास मत प्राप्त करने के बजाय त्यागपत्र दे दें। यह प्रधान मंत्री का और सरकार का भी नैतिक दायित्व है।

प्रथम विश्वास प्रस्ताव पर भी इस सदन में विस्तार से चर्चा हुई थी। पिछले चुनाव में भा.ज.पा. का मुख्य नारा क्या था? केवल चुनाव में ही नहीं बल्कि बाद में भी इन्होंने देश के शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा बनाया था। सभी 13 पार्टियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और पिछले चुनावों में उछाला गया प्रमुख नारा 'स्थायी सरकार' था। दूसरा वायदा योग्य प्रधान मंत्री देने का था और तीसरा वायदा देश को अच्छा शासन देना था। इन्होंने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा भी बनाया है। शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के पृष्ठ संख्या 3 पर निम्नवत उल्लिखित है, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :-

> "जनता के प्रति हमारी सबसे पहली यह वचनबद्धता है कि हम उन्हें एक स्थिर, ईमानदार, पादर्शी तथा दक्ष सरकार दें जो कि सर्वांगीण विकास करने में निपुण हो।"
>
> "इसके लिए, सरकार आवश्यक प्रशासनिक सुधारों के लिए जिसमें पुलिस तथा अन्य सिविल सेवाओं में सुधार लाना भी शामिल है, समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करें"

अतः इन लोगों की यह वचनबद्धता थी कि वे एक स्थिर, ईमानदार तथा पारदर्शी सरकार बनायें। जब हम लोग इस सरकार के विगत तेरह महीनों की स्थिरता के संबंध में विश्लेषण करें तो हम यह पायेंगे कि क्या सरकार को देश को शासित करने के लिए समय मिला? इन तेरह महीनों के दौरान सरकार के भीतर ही भागीदारों में

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन]

अर्न्तद्वंद शुरू हो गया था। सरकार का शासन प्रभावी दलों (प्रेशर ग्रुप) द्वारा किया जा रहा है।

ये प्रभावी दल कौन से हैं? एक तो कलकत्ता से अर्थात कुमारी ममता बनर्जी, दूसरा चेन्नई से ए.आई.ए.डी.एम.के., तीसरा पटना से समता पार्टी तथा चौथा चंडीगढ़ से शिरोमणी अकाली दल है। इस प्रकार देश का शासन इन प्रभावी दलों द्वारा चलाया जा रहा है तथा नियंत्रित किया जा रहा है। इन प्रभावी दलों को संतुष्ट करने के लिए माननीय विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन तथा रक्षा मंत्री, जैसा कि श्री पी॰ए॰ संगमा ने पहले ही कहा है, चेन्नई, कलकत्ता तथा पटना गए हैं? इन लोगों के पास देश को शासित करने के लिए समय नहीं हैं तथा हर समय सहयोगी दलों के मामलों तथा विवादों को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलायी जा रही इस मिली-जुली सरकार इन तेरह महीनों में देश को शासित करने के लिए कोई समय नहीं मिला। सरकार ने अधिकांश समय इन प्रभावी दलों को संतुष्ट करने में बिताया है।

हमने इस सदन में ही आरोप लगाया, जब सचिव (राजस्व) तथा वित्त सचिव को स्थानांतरित किया था तथा प्रवर्तन निदेशक को अपने पद से हटाया गया था। इसके क्या कारण थे? किन लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन्हें हटाया गया था? भा.ज.पा. सरकार को इसी सदन में कारणों को स्पष्ट करना चाहिये। इस सदन में यह भी बात उठाई गई थी कि कुछ मामले, जो कि विशेष न्यायालय में लंबित पड़े थे उन्हें स्थानांतरित किया गया है। यह स्थानान्तरण किन्हें संतुष्ट करने के लिए किये गये?

कुछ पैकेजों की घोषणा भी की गई है। तृणमूल कांग्रेस की कुमारी ममता बनर्जी को संतुष्ट करने के लिए बंगाल पैकेज की घोषणा की गई है। बिहार सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया था तथा इस बारे में सदन में विस्तार से चर्चा हुई थी। किन कारणों के लिए बिहार की राबड़ी सरकार को बर्खास्त किया गया था? ऐसा बिहार में समता पार्टी को संतुष्ट करने के लिये किया गया था। यही एक मात्र कारण था। जिसके लिए सरकार को बर्खास्त किया गया था। अब ए.आई.ए.डी. एम.के. पार्टी भी पूछ रही है कि आप डी.एम.के. सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप बिहार सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं तो फिर डी.एम.के. सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? यह प्रश्न ए.आई.ए.डी.एम.के. द्वारा पूछा जा रहा है और इसका उत्तर किसी दल को नहीं अपितु भा.ज.पा. को देना हैं।

सत्ता को हड़पने, सत्ता में रहने तथा देश को चलाने के लिए इन लोगों ने सभी राजनैतिक तथा नैतिक मूल्यों को त्याग दिया है। सभी कुछ त्याग दिया गया है तथा अब सरकार ही अपने सहयोगी दलों के आन्तरिक विरोध के कारण, न कि विपक्ष के दाब के कारण मुसीबत में है। विपक्ष ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की है। यह सरकार कैसे कह सकती है कि विपक्ष सरकार को अस्थिर कर रही है? मेरी तो यह राय है कि विपक्ष हर प्रकार का सहयोग दे रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों ने कतिपय विधेयकों के पक्ष में वोट किया ताकि इस सरकार को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान हो सकें। भा.ज.पा. तथा सरकार विपक्ष पर कैसे यह आरोप लगा रही कि वह देश को अस्थिर कर रही है? किस प्रकार श्री वैको यह कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं? ऐसा कहना पहले मामलों में उचित हो सकता है परन्तु वर्तमान मामले में ऐसा पूर्णतः सरकार की समझौता राजनीति तथा आत्मसमर्पण करने के कारण हुआ है। अब कोई राजनैतिक, नैतिक अथवा लोकतांत्रिक मूल्य नही रह गए हैं।

सत्ता में रहने के लिए उन्होंने 13 अथवा 14 दलों के बाहरी अथवा भीतरी समर्थन से एक अनैतिक गठबंधन बनाया है। जब कोई प्रभावी दल कोई मॉग करता है तो उसे मान लिया जाता है। पिछले तेरह महीनों से इस प्रकार हर एक की मॉग मानने के कारण सरकार की यह स्थिति हो गई है। अतः सरकार को चलाने में उनकी पूर्णतः अक्षमता के कारण ऐसा हुआ है। ये लोग गठबंधन सरकार को चलाने में पूर्णतः विफल हुए हैं। ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं और ऐसा विगत तेरह महीनों के कार्यकाल से सिद्ध हो गया है।

मैं, यह कहना चाहता हूँ कि इन प्रभावी दलों-समता पार्टी, ए. आई.ए.डी.एम.के. तथा तृणमूल कांग्रेस जो कि तीनों दिशाओं से अर्थात् पटना, चेन्नई, कलकत्ता से प्रभाव डाल रहे हैं, इनके अतिरिक्त एक और प्रभावी दल है जो कि नागपुर में है और यह दल है, संघ परिवार जिसमें आर.एस.एस., बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद हैं। ये दल सरकार को परोक्ष रूप से नियंत्रित कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

सभी महत्वपूर्ण निर्णय नागपुर मुख्यालय द्वारा लिये जाते हैं। जोकि एक बाहरी शक्ति है। इसे ही परोक्ष रूप से सरकार चलाना कहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। परन्तु उनके हाथ बंधे हुए हैं और वे पराधीन हैं। इन पर कौन निगरानी रखता है? विश्व हिन्दू परिषद इन पर निगरानी रख रही है। वे सरकार की नीतियॉं निर्धारित करते हैं कि सरकार क्या करे। यह सब नागपुर मुख्यालय अर्थात संघ परिवार के मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।

शिक्षा नीति का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नागपुर मुख्यालय से ही व्यक्ति को भेजा गया था। एक ऐसा व्यक्ति वहॉं उपस्थित था जिसे शिक्षा मंत्री तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों के अग्रणी सचिव भी नहीं जानते थे। ऐसा व्यक्ति जिसे श्रोतागण अथवा सरकारी नौकरशाह अथवा जन प्रतिनिधि नहीं जानते थे, मंत्रियों के सम्मेलन में बैठा हुआ था। किस प्रयोजनार्थ? ऐसा नागपुर मुख्यालय के निर्देशों पर किया गया था।

इस सरकार में निर्णय लेने की इच्छा शक्ति नहीं है। हॉलकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके हाथ बॅधे हुए हैं वे पराधीन है। उन पर कई लोगों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। अतः प्रधानमंत्री की कुशलता पर भी प्रश्न किए जा रहे

हैं? पिछले चुनावों के दौरान भा.ज.पा. का पहला नारा स्थिरता का था तथा दूसरा एक योग्य प्रधान मंत्री का था परन्तु स्थिरता खत्म हो गई। यह सरकार विगत तेरह महीनों के दौरान देश को एक स्थिर व्यवस्था प्रदान नहीं कर पायी तो फिर एक योग्य प्रधान मंत्री कैसे दे सकेगी? हम प्रधान मंत्री की योग्यता पर कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहें हैं परन्तु निर्णय किसी और व्यक्ति के द्वारा लिये जा रहे हैं। निर्णय का लेना अथवा नियंत्रण किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। इसी कारण सरकार की योग्यता पर भी प्रश्न किये जा रहे हैं। अतः सरकार योग्यता तथा स्थिरता के दोनों मुद्दों पर विफल हो गई है।

हमने आरंभ से ही इस सरकार का विरोध किया है। हम इस सरकार का राजनैतिक स्तर पर भी विरोध कर रहे हैं। इस सरकार का मुख्य एजेंडा क्या है? इस सरकार का मुख्य एजेंडा, लोगों की समस्याओं को सुलझाना नहीं है। शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा बनाया गया है। परन्तु इस एजेंडा में से इन लोगों के सभी कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं करूँगा। किसी भी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया गया। इन लोगों ने पोखरण में आणविक परीक्षण किया है तथा लाहौर बस यात्रा की है। इन दो कार्यों के अलावा भा.ज.पा. सरकार का क्या योगदान रहा है? आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

जहां तक साम्प्रदायिक सौहार्द की बात है यह सरकार दावा कर रही है कि देश में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। इससे ही पता चलता है कि इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कौन थे। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। इसके पीछे कौन थे? हॉलाकि कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन ऐसा भा.ज.पा. के नेतृत्व में किया गया। वर्तमान गृह मंत्री के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अब वही व्यक्ति सत्ता में हैं और ये कह रहे है कि देश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। क्या तेरह महीनों पुरानी सरकार की यही उपलब्धि है? महोदय क्या यही उपलब्धि है? विगत तेरह महीनों के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? ईसाइयों तथा मिशनरिज़ पर निदर्यता से हमला किया जा रहा है। कई धर्मार्थ संस्थाओं, गिरजाघरों तथा अन्य पूजा स्थलों को अपवित्र किया गया तथा अल्पसंख्यकों को निदर्यता से पीटा गया। क्या सरकार की यही नीति है? क्या यही सांप्रदायिक सौहार्द है? आस्ट्रेलिया के मिशनरी और उनके बच्चों को जला कर मार दिया गया। भारत को अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर गर्व है। परन्तु इन घटनाओं के बाद विश्व को क्या संदेश मिला है? इन तेरह महीनों के दौरान देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को क्षति पहुँची है।

इस सरकार का मुख्य कार्यक्रम क्या है? यही है हिन्दुत्व। लोग कहते हैं कि हम लोग हिन्दुत्व में विश्वास करते हैं। हिन्दुत्व क्या है? हम लोग नहीं समझ सकते। असली में हिन्दुत्व क्या है? क्या हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा है। किसी को भी भारत की सांस्कृतिक परम्परा अर्थात *सर्व धर्म सम्भाव* पर विवाद नहीं है। यही हिन्दुत्व की पहचान है। *वसुधैव कुटुम्बकम्* जिसका अभिप्राय है कि पूरा विश्व एक परिवार है और यही सार्वभौमिक भाईचारा है तथा भारत की सांस्कृतिक परम्परा है। क्या यह सरकार हिन्दुत्व के असली सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है? विगत तेरह महीनों में क्या हुआ है हम उसका जायजा लें। कई स्थानों जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को कुछ हद तक हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि साम्प्रदायिक आवेश के कारण कुछ घटनाएं हो रही हैं परन्तु इस संबंध में जिम्मेदार लोग क्या वक्तव्य दे रहे हैं? विशेषकर विश्व हिन्दू परिषद के अखिल भारतीय महासचिव तथा बजरंग दल के नेता धर्मांतरण के मामले पर अल्प संख्यकों के विरूद्ध खुलकर भडकाऊ वक्तव्य दे रहे हैं। अतः भा.ज.पा. के शासन में विगत तेरह महीनों के दौरान पूरे विश्व को जो संदेश गया है उससे हमारे देश के हित में प्रतिकूल असर पड़ा है। देश का धर्म निरपेक्ष स्वरूप नष्ट हो गया है। अतः इस सरकार को राजनैतिक सिद्धांतों तथा राजनैतिक विचारधारा पर जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार के मुद्दे का भी उल्लेख किया गया है। क्या यह सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है। इस सरकार के तेरह महीनों के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी श्री मोहन गुरूस्वामी ने वित्त मंत्री के विरूद्ध कई गंभीर आरोप लगाये हैं। वे, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। इस मामले पर भी इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार नौ सेना के चीफ को हटाया गया और संसद को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी के संबंध में भी अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई। इसके बारे में आज चर्चा होनी थी। इसके बारे में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया की। इस मामले में सरकार के एक सहयोगी दल, ए.आई.ए.डी एम.के. ने एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जॉच कराने की मॉग की। इस पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जॉच कराने पर क्या हानि है? बोफोर्स तोप सौदे के मामले में भा.ज.पा. की पहल पर ही संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जॉच कराने का आदेश दिया गया। यह सरकार इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जॉच कराने से क्यों डर रही हैं? सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण यह सरकार डर रही है मैं ऐसी कई बातें बता सकता हूँ।

इस सरकार ने कार्य करने का अपना नैतिक तथा वैधानिक अधिकार खो दिया है। इस सरकार ने इस देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का अनादर किया है। यह सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। यदि सरकार को लोकतांत्रिक मानदंडों तथा नैतिकता पर कोई विश्वास है तो इसे सदन में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही त्यागपत्र दे देना चाहिए।

दूसरे कार्यकाल के संबंध में मैं, यह कहना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 13 दिनों के भीतर ही त्यागपत्र देना पड़ा था उस समय किसी भी भावी कार्य योजना के बारे में नहीं बताया गया था। चूँकि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया इसलिए उसे त्याग पत्र देना पड़ा। राजनैतिक दल जनता और देश के प्रति उत्तरदायी है। हम लोग एक साथ बैठ कर कुछ एजेंडे अथवा कार्यक्रम के आधार पर भावी कार्य योजना के संबंध में चर्चा करें और मुझे विश्वास है कि हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे। हम सभी लोग जनता के प्रति जवाब देह हैं। हमारे भा.ज.पा. के सहयोगी अपने दूसरे कार्यकाल के बारे में चिंता न करें।

[श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन]

यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि सरकार अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकेगी। उसने सभी पक्षों से अपना विश्वास खो दिखा है। मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का कट्टरता से विरोध करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शनिवार अपराह्न 11.00 बजे यह सरकार दूसरी बार अपना विश्वास प्रस्ताव खो देगी और प्रधान मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ ही मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : सभापति जी, इस सदन में पिछले दस सालों में विश्वास मत प्राप्त करने के लिये यह नौवां प्रस्ताव आया है। यह प्रस्ताव ऐसी परिस्थिति में आया है जब एक सहयोगी दल ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की है।

आज देश के जो हालात हैं, उन को लेकर इस सदन में सुबह से चर्चा हो रही हैं। इसमें खासकर सबसे ज्यादा चर्चा स्टेबल मवर्नमेंट और एबल प्राइल मिनिस्टर की हुई है। लोगों ने स्टेबल गवर्नमेंट और ऐबल प्राइम मिनिस्टर के प्रति अपनी अलग-अलग चिन्तायें जतायी हैं लेकिन सब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की एबलिटी के बारे में को शक, शुबहा या संदेह नहीं है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर की एबिलिटी पर किसी तरह का कोई शक या शुबहा नहीं है, इसलिये सरकार को स्टेबिलिटी को किस तरह से डिस्टर्ब करें। वे प्राइम मिनिस्टर की एबिलिटी खत्म नहीं कर पाये। लेकिन सरकार किस तरह से अस्थिर हो, किस तरह से परेशान हो, किस तरह से देश की जनता के सामने यह संदेश दिया जा सके कि यह सरकार अस्थिर है, यह काम करने की असफल कोशिश जरूर की जा रही है। यह बात सही है कि विपक्ष में कांग्रेस के लोग या अन्य पार्टियों के जो लोग हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि दो दिनों की जो बहस होगी, उसका नतीजा उनके पक्ष में नहीं होने वाला है। वे यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दो दिनों की बहस के बाद उन्होंने जो विचार किया है, जो सोचा है, समझा है, जो साजिशें उन्होंने रची हैं, उसका जनता तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी ही, इस सदन में भी उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी।

आज 13 महीनों से यह सरकार चल रही है और जिस समय सरकार बनी थी उस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस के भाइयों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, आर.जे.डी. के लोगों को और उन लोगों को हुई थी जो कि पूरे देश के मुसलमानों को, पूरे देश के अल्पसंख्यकों को यह बता रहे थे कि यह सरकार बनने के बाद पूरे देश में खून-खराबा होगा, पूरे देश में लाशों के ढेर लगेंगे, पूरे देश में लोग परेशान होंगे और अल्पसंख्यक असुरक्षित होंगे। लेकिन उन्हें पिछले 12 महीनों के हमारी सरकार के काम को देखने के बाद पूरी तरह से निराशा हाथ लगी। उन्हें यह महसूस हुआ कि अल्पसंख्यकों में विश्वास बढ़ रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि देश के अन्य लोगों में कमजोर तबकों में विश्वास कायम हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि भारत एक ताकतवर और मज़बूत देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है और यह महसूस होने के बाद उनको परेशानी महसूस होना जायज़ था। इसके बाद जयललिता जी दिल्ली आईं और 40-50 सूटकेस लेकर आईं। एक दिन तक सुना कि कोई उनके पास नही गया। सारे लोग सूटकेस के अंदर क्या है उसका इंतज़ार करते रहे लेकिन उसके बाद दूसरे दिन काफी लंबी लाइनें लगी और वह लाइन लगने के बाद नतीजा आपके सामने है कि फिर तीन दिन पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं कि यह महसूस किया जा सके कि यह सरकार अब चल नहीं सकती।

सभापति जी, आज देश के हालात पिछले दस सालों के हालात से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। इस सदन में हम लोग नये हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं। उन्होंने इससे पहले कई सदन देखे होंगे। वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस देश में दंगों से लेकर, खून-खराबा से लेकर लोगों में जिस तरह से दहशत पैदा कर दी जाती थी, यह सदन हमेशा उस पर चिन्ता व्यक्त करता था। इस सदन में हमेशा इस बात को लेकर बहस हुआ करती थी कि अमुक स्थान पर सांप्रदायिक दंगों में इतने लोग मर गए, अमुक स्थान पर मुसलमानों के साथ ऐसा किया गया, दलित तबकों के साथ ऐसा किया गया। इस प्रकार का माहौल इस सदन में होता था। एक बार मात्र आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहस कराई वह भी उन्होंने क्रिश्चियन्स के मामले को लेकर, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सवाल को लेकर उन्होंने बहस कराने की शुरूआत की थी। इसके अलावा कभी भी सदन में किसी ने यह बात नहीं कही कि हिन्दुस्तान के मुसलमान आज असुरक्षित हैं, आज उनके अंदर विश्वास नहीं है, आज वह अपने आपको हिन्दुस्तान की मुख्यधारा से अलग महसूस कर रहे हैं। यह बात किसी ने न कही और न ही किसी ने इस बात को सदन में उठाया। यह खुशी की बात है कि पिछले 13 महीनों में इस सदन में कृत्रिम सवाल उठते रहे। कभी भागवत का सवाल, कभी कोई और सवाल, कभी ऐसे सवाल कि जिनमें कुछ दम नहीं था। उन सवालों के गुब्बारे ज़रूर पूरे देश में छोड़े जाते रहे जिनकी हवा थोड़ी देर में फुस्स हो जाती थी। लेकिन कोई ऐसा सवाल जिसकी प्रामाणिकता हो, जिससे लगे कि जो सवाल सही मायनों में उठाये जा रहे हैं, वे सही सवाल हैं, ऐसे सवाल इस सदन में आज तक नहीं उठाये गये। इसका अर्थ यह है कि जिन सवालात को लेकर हमने इस देश की सत्ता, इस देश की बागडोर को संभाला था, हमने उन सवालात को हल करने में कामयाबी हासिल की है। हमने लोगों में विश्वास कायम करने में कामयाबी हासिल की है। जिन सीमाओं पर गोलियां और बम चलते थे, जिन सीमाओं पर खून-खराबे होते थे, वहां आज बसें और ट्रेनें चल रही हैं, जिन सीमाओं पर लोगों को दहशत रहती थी, जिन सीमाओं पर लोग रह नहीं पाते थे, आज वहां प्यार और मौहब्बत के गीत गाये जा रहे हैं। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। यह उपलब्धि कांग्रेस से लेकर दूसरे सभी लोगों को घबराने और परेशान करने के लिए काफी है। कांग्रेस ने जैसा हमेशा किया है, कांग्रेस जिस रास्ते पर हमेशा चलती रही है, उसी तरह से उसने एक बार फिर से वही खेल खेलने की नाकाम कोशिश की है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद और विश्वास

है कि जिन लोगों ने इनकी इस चाल में आने की हिम्मत और हिमाकत की है, उन्हें बाद में निराशा ही हाथ लगेगी।

सभापति महोदय, मुल्क में हर स्तर पर, हर जगह लोगों में एक सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है। एक सवाल हर आदमी को परेशान किये हुए है। अभी एक साल पहले चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद हम सभी लोग सदन में चुनकर आये। लेकिन इस सदन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था। इससे पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं रहा है। सहयोगी दलों के साथ मिलकर इससे पहले भी सरकारें बनी हैं, इससे पहले भी विपक्षी दलों की और गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं और आज भी यहां एक गैर कांग्रेसी सरकार है। इससे पहले भी गैर कांग्रेसी सरकारों को कांग्रेस ने जिस तरह से गिराने की खतरनाक साजिश रची है, यह सारा सदन जानता है और आज भी वही कांग्रेस इस गैर कांग्रेसी सरकार को गिराने की किस तरह से साजिश रच रही है, यह स्पष्ट रूप से सारे लोगों को दिखायी दे रहा है और निश्चित तौर से यह एक ऐसा सवाल है जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। चाहे विश्वास मत हो या अविश्वास मत हो, आज यह प्रश्न नहीं रह गया है, आज यह भी प्रश्न नहीं रह गया है कि मुल्क की बागडोर किनके हाथों में है, आज यह सवाल रह गया है कि लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं, डेमाक्रेसी कायम रहेगी या नहीं। यदि डेमाक्रेसी कायम रहेगी तो किन लोगों के हाथों में कायम रहेगी। आज सेक्युलरिज़्म का नाम लेकर, धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर जिस तरह से पूरे मुल्क में एक गुमराही का माहौल पैदा किया गया और तमाम ऐसे कृत्रिम सवाल उठाये गये, जिससे आज पूरे मुल्क को दीख रहा है कि ये सवाल गलत थे, जात-पांत के नाम पर, धर्म के नाम पर इस मुल्क में कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी न तो सियासत कर सकी है और न सियासत करने में सफल हो सकती है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस देश में सेक्युलरिज्म कायम रहना चाहिए, इस देश में सेक्युलरिज्म को पूरी तरह से मजबूत रखना चाहिए । इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, मैं मुसलमान हूं, इस संसद का सदस्य हूं, मंत्री हूं, यहां तमाम तरह के लोग हैं जो अलग-अलग जाति, अलग-अलग . धर्मों और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो विदेश में रहने वाले हैं, लेकिन वे इस देश की बड़ी-बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसा इस देश में है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जो लोग विदेशी विचारधारा पर जी रहे हैं, वे आज स्वदेशी के बारे में चिंता और विचार व्यक्त कर रहे हैं। आज इन हालात में, इन परिस्थितियों में यह देश पूरी तरह से भारतीय सभ्यता, भारतीय मान्यता और भारतीय विचारों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जो लोग इसमें साज़िश कर रहे हैं, उन्हें इस बात को महसूस करना चाहिए कि पिछले दस वर्षों में जितने चुनाव हुए और एक चुनाव में एक व्यक्ति पर जो खर्च आता है, वह ऐसा खर्च है जो हर आदमी को परेशान करता है।

सभापति महोदय, आज अभी शरद पवार जी कह रहे थे कि इस बार फसल भी बहुत बेहतर हुई है। यह खुशी की बात है। इसका सदन के सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। फसल बेहतर हुई है, तो यहां पर दो महीने के बाद आवश्यक वस्तुओं के दाम भी जमीन पर आ जाएंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि पिछले 10 महीनों में जमीनों के दाम बड़े-बड़े नगरों में जमीन पर आए हैं। इसका कारण यह है कि हमने चोरबाजारी, कालाबाजारी और जखीरेबाजी एवं भ्रष्टाचार करने वालों के साथ सख्ती की है और ऐसे लोग जो उनके साथ मिलकर बेईमानी करते थे, उन पर अंकुश लगाया है। इस देश में ऐसे लोगों के साथ मिलकर पिछले 50 वर्षों में राज्य करने वाले ऐसे लोगों के ऊपर हमने अंकुश लगाने का काम किया है। निश्चित रूप से आज ऐसे लोगों को हमसे परेशानी हो रही है और उनके संरक्षकों को चिंता हो रही है।

महोदय, आज पूरे मुल्क में जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, वे सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अल्पसंख्यकों के वोटों को लेकर चौराहे पर खरीद-फरोख्त करते थे, उनके वोटों को नीलाम करते थे, आज उनको चिन्ता हो गई है, क्योंकि हमने अल्पसंख्यकों को उनकी वास्तविकता बता दी और यह दिखा दिया है कि किस प्रकार से वे अल्पसंख्यकों को धोखे में रखकर उनको उनके रीयल इश्यूज से हटाकर आर्टीफीशियल इश्यूज में फंसाकर लाभ उठाते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि अल्पसंख्यकों के असली इश्यूज रोजी-रोटी, शिक्षा है न कि मंदिर-मस्जिद का झगड़ा। आज 13 महीनों के पूरे काल में हमारी पार्टी के किसी मंत्री या किसी व्यक्ति पर कोई एक भी, किसी भी जगह, कहीं भी भ्रष्टाचार की एक छींट भी नहीं आई है जबकि इससे पहले वाली सरकारों पर हर एक-दो महीने बाद, एक के बाद एक आरोप लगते थे और घोटालों के केसेस खुलते थे। इस सरकार की खुली तस्वीर को पूरा देश जानता है वहीं इससे पहले वाली सरकारों के दिन प्रति दिन खुलने वाले घोटाले भी लोगों के सामने हैं।

महोदय, आज पूरी दुनिया देख रही है कि यह सरकार, स्वच्छ, ईमानदार और सत्ता के दलालों रिश्वतखोरी से दूर तथा जनता के लिए कुछ काम करने वाली सरकार है और देश के अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े लोगों एवं कमजोर तबकों को उनके अधिकार दिलाना चाहती है। ऐसी सरकार को गिराने की साजिश करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा न हो, मोहब्बत न बढ़े, तरक्की न हो, उनके ऐसे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जो लोग इस देश में लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं उनके मंसूबे किसी भी स्तर पर पूरे नहीं होंगे। ऐसे लोग जो अल्पसंख्यकों के सामने आर्टीफिशियल इश्यूज को खड़े करके उनको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी साजिश कभी पूरी नहीं होगी। आज तक उनको गलत इश्यूज बताकर 50 वर्ष तक इस देश में शासन किया गया और सैकुलर कहलाने वाले लोगों ने बताया कि इस देश में सैकुलरिज्म तभी रहेगा जब बाबरी मस्जिद रहेगी, जब सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम् का विरोध होगा तभी इस देश में सैकुलरिज्म रहेगा। इस प्रकार से अल्पसंख्यक लोगों को उनके ओरिजनल इश्यूज से दूर हटाने का काम इन लोगों ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि अल्पसंख्यकों के असली इश्यूज मंदिर मस्जिद, सरस्वती वंदना नही हैं, ये तो आर्टीफिशियल इश्यूज हैं और असली इश्यूज उनकी रोजी-रोटी कमाने तथा शिक्षा

[श्री मुख्तार नकवी]

ग्रहण करने के अधिकार हैं। अभी तक वे लोग गुमराह हो रहे थे और विगत वर्षों में इस देश में शासन करने वाले लोग उन्हें गुमराह करते रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि वे गुमराह न हों। इसलिए उनको परेशानी हो रही है कि अब आर्टीफीशियल इश्यूज से उनकी दाल गलने वाली नहीं है।

महोदय, जहां तक काश्मीर का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि काश्मीर में पिछले कई सालों से गोलाबारी हो रही थी, काश्मीर में बम फट रहे थे, इबादतगाह फूंकी जा रही थीं। चरारे-शरीफ में आग लगा दी गई, रोजाना हमारे नौजवान जलाए जा रहे थे, हमारे लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था, हमारी मां-बहनों को गोलियों से मारा जा रहा था, उनकी इज्जत लूटी जा रही थीं, उनको जिन्दा जलाया जा रहा था, जगह-जगह आगजनी हो रही थी।

पिछले एक साल में कश्मीर में शांति और सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। कश्मीर के चमन में फिर से फूल खिले हैं। कश्मीर के चमन में फिर से मोहब्बत का पैगाम लोगों के सामने आया है और कश्मीर में ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिससे फख्र के साथ कहा जा सकता है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है और कश्मीर के लोग भी हिन्दुस्तान के हैं। आज लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं। आज कश्मीर में लोग आम सवालों को लेकर, आम मुद्दों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वे अपनी रोजी-रोटी-शिक्षा के लिए जागरूक हो रहे हैं, न कि आतंकवाद के लिए। वहां पाकिस्तान का झंझा नहीं उठ रहा बल्कि वहां हिन्दुस्तान का झंडा लहरा रहा है। वहां हिन्दुस्तान के झंडे जलाए नहीं जा रहे हैं जबकि इससे पहले वहां हिन्दुस्तान के झंडे जलाए जा रहे थे और पाकिस्तान के झंडे लहराये जा रहे थे। हमने एक साल में हिन्दुस्तान के लोगों में, हिन्दुस्तान के हर हिस्से में, हर कोने के लोगों में यह विश्वास कायम करने में सफलता हासिल की है कि हम देश में हर वर्ग, हर कौम और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार, बराबरी का हक देना चाहते हैं और बराबरी का एक अहसास दिलाना चाहते हैं और सफल हुए हैं।

इसके साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर आज देश में अलग-अलग तरह की बातें की जा रही हैं, अलग-अलग तरह के माहौल तैयार किये जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुल्क के हालात किसी एक सियासी पार्टी के करने से बेहतर नही हो सकते। सियासी पार्टी या सरकार अपनी मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर सकती है, स्ट्रांग पोलिटिकल विल पावर का प्रदर्शन कर सकती है जिसे कि हमने हर मौके पर किया है लेकिन उस स्ट्रांग पोलिटिकल विल पावर को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ सारी की सारी राजनैतिक पार्टियों को राष्ट्र हित में आगे बढ़कर उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब पोखरण टैस्ट हुआ तो वह किसी एक राजनैतिक पार्टी का टैस्ट नहीं था। जब अग्नि-2 मिसाइल का टैस्ट हुआ तो वहां किसी एक राजनैतिक पार्टी का टैस्ट नहीं हुआ। इससे पहले हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर कभी दाऊद इब्राहिम, कभी हाजी मस्तान की बनाकर दिखाई गई। हमने हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर एक महीने में अब्दुल कलाम जैसे साईंटिस्ट के रूप में दिखाई जिसने पोखरण टैस्ट किया। हमने उन लोगों के अंदर यह महसूस कराने की कोशिश की कि इस देश का हिन्दू जितना राष्ट्रवादी है, उतना ही मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, उतना ही सिख भी राष्ट्रवादी है, उतना ही इसाई भी राष्ट्रवादी है। किसी की राष्ट्रवादिता पर कोई शक या शुब्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग अपने को सेक्युलर कहते हैं, उन्होंने बार-बार यह दिखाने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान के मुसलमान को अपनी राष्ट्रवादिता सिद्ध करनी होगी, हिन्दुस्तान के क्रिश्चियन्स को अपनी राष्ट्रवादिता सिद्ध करनी होगी, हिन्दुस्तान के सिखों को अपनी राष्ट्रवादिता सिद्ध करनी होगी - किस बात की राष्ट्रवादिता? क्यों आपने डराया, क्यों आपने धमकाया। सिर्फ इसलिए कि आप वोट के चौराहे पर खड़ा करके वोट की नीलामी और खरीद-फरोख्त कर सकें लेकिन आज न वोट की नीलामी हो पायेगी और न वोट की खरीद-फरोख्त हो पायेगी। को इस सदन में विश्वास दिलाता हूं कि अभी चार साल का कार्यकाल पड़ा है और किसी तरह की कोई चिन्ता नहीं है।

अभी लालू जी कह रहे थे कि यह बड़ा साईंटिफिक है। हमारी उससे ज्यादा साईंटिफिक व्यवस्था है। साईंटिफिक व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी या गलतफहमी की आवश्यकता नहीं है। हम चार वर्षों में इस देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा करेंगे, इस देश को पूरी दुनिया के सामने तरक्कीयाफ्ता देश ही नहीं बल्कि डैवलप्ड कंट्री के रूप में पेश करेंगे। इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिस माहौल के चलते पूरी दुनिया के लोग यह महसूस कर सकें कि भारत ऐसा शक्तिशाली देश है जिस के सामने अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ायेगा तो वह भी दोस्ती का हाथ बढ़ायेगा और अगर दुश्मनी का हाथ बढ़ायेगा तो उसका जवाब उसे मिल सकता है। एक ऐसे देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत की तस्वीर पेश करना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। किसी ने भी आज तक उनके नेतृत्व पर अंगुली नहीं उठाई। हमारे किसी भी सहयोगी दल ने, किसी ने भी यह नहीं कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का शक है। यहां तक कि जयललिता जी, जिन्होंने समर्थन तथाकथित वापस ले लिया, उन्होंने भी आज तक नहीं कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कोई शक है। आज आपका कोई नेतृत्व तैयार नहीं है। आपका कौन नेता है, कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है लेकिन सरकार बनाने के लिए तैयारी चल रही है। पूरी तरह से न विदेशी न स्वदेशी कोई नेता आज किसी को मानने के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से एक मत से, एक जुट होकर इस बात को मानते हैं कि पूरे देश के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, हमारे सहयोगी दलों और पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं इसमें कहीं पर किसी को कोई शक नहीं है। कहीं पर किसी को कोई शक नहीं है। आज जिस नेतृत्व में कोई उंगली न उठाई जा रही हो, जिस व्यक्ति पर कोई उंगली न उठाई जा रही हो, उस व्यक्ति को हटाने की साजिश लगातार करना देश के साथ, समाज के साथ, सदन के साथ धोखा और विश्वासघात है, इस देश की करोड़ों जनता के साथ विश्वासघात है और ऐसा विश्वासघात निश्चित तौर से अगर आगे भी किया गया तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता ऐसे लोगों के साथ ऐसा विश्वासघात

करेगी कि ये कभी इस सदन में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव लाने लायक नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और जिनके अंदर राष्ट्रवादी सोच है, जिनको देश के प्रति चिन्ता है, जो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश की अस्मिता, एकता, राष्ट्रवाद, अखंडता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, उन्हें इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : सभापति महोदय, बहुत बहस हो गई, अब वोटिंग करवा लीजिए।...(*व्यवधान*) सैकुलर, नान-सैकुलर, करप्शन, नान-करप्शन, इसके अलावा और कुछ क्या है।...(*व्यवधान*) इसके अलाव कोई मुद्दा ही नहीं है।

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : साढ़े पांच घंटे हो गए हैं। डायरैक्ट वोटिंग ले लें। अभी हाउस में अटैंडैंस है, वोटिंग करवा लें।. ..(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : इनकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपका सुझाव अमान्य किया जाता है, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस॰ सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी सरकार में विश्वास के लिए आज प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने इसी सदन में 13 महीने पूर्व भी विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस समय हमने विपक्ष की ओर से यह स्पष्ट किया था कि भा.ज.पा. सरकार शासन क्यों नहीं कर सकती तथा हमारे उनके बारे में क्या संदेह और भय हैं। दुर्भाग्यवश 13 महीनों के पश्चात् विपक्षी दलों की सभी आशंकाएं सही निकली हैं। आज भा.ज.पा. के 13 महीनों के कुशासन के पश्चात् इस देश की जनता का उनके प्रति मोह भंग हो गया है। 1998 में जनता के एक भाग को भा.ज.पा. सरकार अथवा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के देश के प्रधान मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व के बारे में भ्रम था। अब 13 महीनों के पश्चात् यह निःसन्देह स्थापित हो गया है कि भा.ज.पा. ने एक अस्थिर, अदक्ष सरकार दी है तथा एक कमजोर प्रधान मंत्री दिया है जो कि चुनाव के पूर्व अपने राष्ट्रीय एजेंडा में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाया। हम भा.ज.पा. सरकार पर अयोग्यता तथा कीमतों को नियंत्रित न करने के आरोप लगाते हैं। हम उन पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। हमारा यह विश्वास है कि इस सरकार को नैतिक एवं राजनैतिक तौर पर सत्ता में रहने का कोई हक नहीं हैं। इन लोगों ने लोक सभा में अपना बहुमत खो दिया है। वस्तुतः इस देश की जनता ने काफी पहले ही इस सरकार में विश्वास खो दिया था। अब इस सदन में आज हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करके राष्ट्र की जनता का भा.ज.पा. सरकार में विश्वास खो जाने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं।

भा.ज.पा. सरकार ने तेरह महीनों पहले कई वादे किये थे। पिछले महीने हमने सुना कि भा.ज.पा. सरकार ने अपना एक वर्ष पूरा करने के लिए सारे देश में अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने तीन मुख्य बातें कही : उन्होंने परमाणु बम बनाया; कावेरी विवाद को सुलझाया तथा भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध कायम करने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बस डिप्लोमेसी और अब अग्नि का प्रचार किया।

मैं, यह पूछना चाहता हूं कि क्या परमाणु बम से देश को अधिक सुरक्षा मिलती है अथवा वह खतरे में पड़ गया है। जब इस सदन में परमाणु बम के प्रश्न पर वाद-विवाद हुआ था तब इस सरकार ने हमें यह कहा था कि ऐसा सुरक्षा तथा इस देश की प्रति रक्षा एवं विदेशियों की घुसपैठ एवं आक्रमण के विरूद्ध आवश्यक था। परन्तु इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए उकसाया गया। इन्होंने उनको मिसाइल बनाने के लिए उकसाया। अब देश की सुरक्षा को पहले से अधिक खतरा हो गया है। आज इस देश को 1998 से पहले जो खतरा था उससे अधिक खतरा हो गया है। हमें बताया गया है कि परमाणु बम सबसे सस्ता शस्त्र है जिसे हम रख सकते हैं। यह सच हो सकता है परमाणु बम सस्ता बनता हो। परन्तु परमाणु बम और उसके परिणामों के कारण इस देश को पिछले वर्ष प्रतिरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े जबकि इस देश में 32 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। हजारों गॉवों में पीने के लिए पानी नहीं हैं। करोड़ों एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा नहीं है। लाखों लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही हैं। परन्तु इस सरकार की वरीयता परमाणु बम बना कर अपने अहं को संतुष्ट करना है।

हमारे माननीय मंत्री श्री एल॰के॰ आडवाणी आज सुबह यह कह रहे थे कि विश्व में सभी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोगों ने विश्व के सभी भागों से इस बारे में आरोप एवं निन्दा सुनी है कि भारत ने परमाणु बम क्यों बनाया। सभी यह महसूस कर रहे थे कि आज इस नाभिकीय ज्ञान के युग में हमें परमाणु बम बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस बारे में हमें पहले ही जानकारी थी। हमने अपना विकल्प खुला रखा था। परन्तु बम के निर्माण के द्वारा आज हम ने सुरक्षा की दृष्टि से देश को अधिक गंभीर खतरे में डाल दिया है। मूल्यों को नियंत्रित न कर पाने के लिए हम भा.ज.पा. सरकार दोषी मानते हैं। इस देश की जनता ने स्पष्टतः यह राय व्यक्त की कि उनके लिए परमाणु बम से अधिक प्याज महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान में चुनाव हुए थे। इन तीनों राज्यों में से दो राज्यों में भा.ज.पा. सत्ता में थी।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश के बाहर अथवा देश के अन्दर किसने इसकी सराहना की है। इससे केवल भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की संतुष्टि हुई है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस॰ सुधाकर रेड्डी]

भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आवश्यक वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है और इस देश के आम आदमी का जीवन दयनीय हो गया है और यह भारतीय जनता पार्टी की हार का ही परिणाम था जो हमने कुछ राज्यों में देखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम इस बात पर विश्वास कर लें कि इस एक वर्ष में मुद्रा स्फीति की दर में कमी आई है। परन्तु यह सच नहीं है। मुद्रा स्फीति में केवल वृद्धि ही नहीं हुई है बल्कि डालर और रुपए की विनिमय दर में भी गिरावट आई है। रुपए के वास्तविक मूल्य में गिरावट आई है। यही वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल रही है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति कैसी है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया अपने कारखाने बन्द कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश में, जहां से मैं आता हूँ, रामागुन्डम फर्टिलाइजर फैक्ट्री केवल इसलिए बन्द है क्योंकि सरकार उसे 30 करोड़ रुपए उपलब्ध नहीं करा पाई। उन्होंने कारखाने को अक्षुण्ण रखने के लिए 40 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये हैं। अब सरकार ने 600 करोड़ रुपए की लागत से एक अन्य कारखाना स्थापित करने का वायदा किया है। हैदराबाद स्थित इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बन्द हो गई है और बल्क ड्रग्स का आयात किया जा रहा है ताकि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का भविष्य एक बार फिर पूरी तरह समाप्त हो जाए।

सरकार इसी संसद में पेटेन्ट विधेयक लाई थी, वह बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक भी लाई थी। ये विधेयक किसके भले के लिए लाए गए हैं? ऐसा करके आप सबसे महत्वपूर्ण और विशाल वित्तीय क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंपने जा रहे हैं। ऐसा अमरीका के नेताओं, साम्राज्यवादियों और बहुद्देशीय निगमों को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के कारखाने और उद्योग एक के बाद एक समाप्त किये जा रहे हैं। निजीकरण के द्वारा आप लाखों लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। इस देश में कोई भी नया उद्योग नहीं लगाया जा रहा है।

जहाँ तक कृषि क्षेत्र का संबंध है आन्ध्र प्रदेश में दुर्भाग्यवश, पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 350 से अधिक किसानों ने, विशेष कपास का उत्पादन करने वाले किसानों ने आत्महत्या की थी। कोयम्बटूर और अहमदाबाद में मिलें बन्द पड़ी हैं। कपास की मांग कम हो गई और काफी मात्रा में कपास का आयात किया जा रहा है। किसानों को कपास का लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है। फसल बीमा के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किये गये बड़े-बड़े वायदों और प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त को लाल किले पर किये गए वायदों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में कृषि क्षेत्र नष्ट हो रहा है। लाखों किसान उजड़ रहे हैं। वे शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। वे छोटे से काम के लिए बाहर जा रहे हैं। वे अपनी जमीन छोड़ रहे हैं। इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस सरकार की प्राथमिकताएं हैं, बम, प्रक्षेपास्त्र और राकेट, न कि पेयजल, सिंचाई के लिए पानी, फसल बीमा इत्यादि। यह सरकार देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने में बुरी तरह असफल रही है। मेरा आरोप है कि यह सरकार देश में विशेषकर ईसाई अल्पसंख्यकों और मिशनरियों पर संघ परिवार द्वारा हमले करवाकर अल्पसंख्यकों के प्रति आतंक, मनौवैज्ञानिक आतंक, फैला रही है। हमने यह देखा है कि किस प्रकार संघ परिवार के एक वर्ग ने मध्य प्रदेश में ननों के साथ अत्यंत अमानवीय तरीके से हुए बलात्कार को धर्म परिवर्तन के विरूद्ध हिन्दुत्व का प्रतिरोध बताया है। क्या इसकी इससे भी अधिक शर्मनाक व्याख्या की जा सकती है? हमने देखा है किस प्रकार गुजरात और उड़ीसा में गिरजाघरों को जलाया गया और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले किये गए। एक ईसाई मिशनरी को उसके छह और आठ वर्ष की आयु के बच्चों के साथ जीवित जला दिया गया। ऐसा हिन्दुत्व की रक्षा करने के नाम पर किया गया है, क्या छह वर्ष की आयु का बच्चा हिन्दुत्व के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर सकता है? जहाँ एक ओर, इस अमानवीय घटना की देश के भीतर और देश के बाहर प्रत्येक व्यक्ति ने आलोचना की है तो वहीं दूसरी ओर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात और अन्यत्र गए और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निर्दोष ठहराया और यह कहा कि हमें इस पर राष्ट्रीय बहस करानी चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बहस किस पर हो? क्रूरता पर? अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंक फैलाने के मुद्दे पर? अथवा धर्म निरपेक्षता के मुद्दे पर? नहीं, प्रधानमंत्री जी धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस करना चाहते हैं। यह केवल राष्ट्र का ध्यान हटाने की कोशिश है जैसे कि धर्म परिवर्तन देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वे तथ्यों और आंकड़े देकर बतायें कि ये धर्म परिवर्तन, जोकि पिछले कई वर्षों से चली आ रही एक सतत् प्रक्रिया है, अचानक एक खतरा बन कैसे गया हैं। कारण यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कहीं पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति पर हमला कर दिया, बल्कि प्रश्न यह है कि संघ परिवार ने अन्य धर्मों के लोगों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ असहिष्णुता का जहर भर दिया है, यह उसी का परिणाम है और आज उनकी सरकार आ गई है और वे अल्पसंख्यकों तथा अन्य धर्मों के लोगों से प्रतिशोध ले सकते हैं। यह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि तेरह महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थायी सरकार एक योग्य प्रधानमंत्री और एक भिन्न तथा सरकार साफ-सुथरी देने के जो वायदे किये थे वह उन सबको पूरा करने में असफल हो गई है। वे बुरी तरह असफल हो गए हैं, आज मैं यह महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का बने रहना इस देश में लाखों लोगों के हितों के विरूद्ध होगा। इस सरकार को जाना ही चाहिए।

मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री चैको स्पष्टीकरण दे रहे थे कि वाजपेयी सरकार के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि मैं नहीं बल्कि एडमिरल विष्णु भागवत जो नौसेना के प्रमुख थे और इस देश के चीफस ऑफ स्टाफ की

संयुक्त परिषद के चेयरमैन भी थे, ने रक्षा मंत्री पर यह आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री के रूप में उनका बना रहना इस देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है।

यह बहुत गम्भीर आरोप है। यह सरकार उस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार क्यों नहीं है? वे कहते हैं कि रक्षा संबंधी मामले बहुत महत्वपूर्ण, गोपनीय और पावन होते हैं। हाँ हम भी उसे समझते हैं। हम भारतीय सेना की रणनीति पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय सेना की क्षमताओं पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम भारत के रक्षा मंत्री के खिलाफ घोटालों के आरोपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

विश्वयुद्ध के दौरान जब चर्चिल ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो वहाँ रक्षा संबंधी घोटाले के बारे में आरोप लगाया गया था और उस पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा की गई थी। चर्चिल ने चर्चा की अनुमति दी थी। वे चर्चा से भयभीत नहीं थे। तो फिर यहाँ ये लोग क्यों भयभीत हैं? मैं यह कह रहा हूँ कि रक्षा संबंधी सौदे और अन्य बातें गोपनीय नहीं हैं। इनको पारदर्शी होने चाहिए। घोटालों और रक्षा मंत्री, श्री जॉर्ज फर्नांडीज के खिलाफ लगाये गये आरोपों पर यहाँ सभा में चर्चा होनी चाहिए। उन्हें इसलिए मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे रक्षा मंत्री हैं। वे कानून और चर्चा से बढ़कर नहीं हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मोर्चों पर असफल हो गई है तो वे यह कैसे कह सकते हैं कि वे आज की बहस के बाद भी सत्ता में रहेंगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार-बार यह कह रही है कि यह विपक्ष का षडयंत्र है। हम पिछले तेरह महीनों से उन्हें यह बता रहे हैं कि यदि उनकी सरकार गिरती है तो वह केवल उनकी अपनी पार्टी के आन्तरिक मतभेदों के कारण ही गिरेगी। वे अपनी पार्टी में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में असमर्थ रहे हैं। वे अपने 19 सहयोगी राजनीतिक दलों को अपने साथ रखने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई व्यक्तियों और राजनीतिक दलों ने इनसे अलग होना आरम्भ कर दिया है। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया है।

इसलिए, आप विपक्षी दलों पर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं कि वे कोई षड़यंत्र रच रहे हैं। षड़यंत्र रचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज स्वयं गिरने जा रही है और वह संसद सदस्यों की संख्या की कमी की वजह से नहीं, अपितु इसलिए गिरेगी क्योंकि उन्होंने इस देश के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ शासन किया है। उन्होंने इस देश के लोगों का विश्वास खो दिया है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है।

मैं उन धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को अन्दर से समर्थन दिया हुआ है कि वे गठबंधन से स्वयं को अलग करके पाप से बचें। आज भी देर नहीं हुई है; उनको गठबंधन से बाहर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने से लोगों को अत्यंत खुशी होगी। इस सरकार के गिरने से देश की जनता को कोई दुःख नहीं होगा।

मैं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की ओर से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हम इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, आज सदन में प्रधान मंत्री जी द्वारा विश्वास मत हासिल करने हेतु प्रस्ताव मूव किया है, इससे देश की जनता के मन में बेचैनी फैली हुई है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर इन तेरह महीने की अवधि में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में जो केन्द्र में सरकार बनी है, उस सरकार ने ऐसा कौन सा कार्य किया है, जिसके चलते विपक्ष कोई-न-कोई बहाना बनाकर सरकार के ऊपर बार-बार हमला कर रहा है, ताकि इस सरकार को अपदस्थ किया जाए।... *(व्यवधान)* देश की जनता आज टी वी पर देश के सभी नेताओं के भाषणों को सुन रही है। हमने भी विपक्ष के नेता, श्री शरद पवार और लालू प्रसाद जी के भाषणों को सुना, लेकिन उन भाषणों में कहीं कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, जिससे लगे कि सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है। देश की जनता के मन में जो बेचैनी है, उसका सदन के माध्यम से समाधान नहीं किया जा रहा है।

महोदय, हम बताना चाहते हैं कि यह विश्वास मत हासिल करने की नौबत जयललिता जी के द्वारा समर्थन वापिस लेने की वजह से आई है। मैं बड़े नेताओं पर कोई कमैंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। नियमसम्मत नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैंने राष्ट्रपति जी पर कोई कमैंट नहीं किया है।

सभापति महोदय : इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सदन में वित्तीय बजट सामने हो और सरकार यह मानकर चलती हो कि हम बहुमत में हैं, तो बहुत से ऐसे मौके आते, जिसमें कि सरकार को अपना बहुमत साबित करने का अवसर भी मिलता, लेकिन इस प्रस्ताव में किसी दबाव में बहुमत साबित करने की बात है, मैं नहीं मानता हूं कि वह किसी ढंग से उचित है। आज विपक्ष के लोगों में बेचैनी है कि गठबन्धन दलों का केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय एजेंडा बना और उस राष्ट्रीय एजेंडे के माध्यम से सरकार ने एक नीति निर्धारण की। गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए नीति निर्धारण की। विदेश से मधुर संबंध बनाने के लिए नीति निर्धारण की और उस पर केन्द्र सरकार ने पहल करना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस के लोगों में सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ी। उसी बेचैनी का परिणाम हमारे गठबंधन की पूर्व की सहयोगी जयललिता जी का समर्थन वापसी भी है। समर्थन वापसी का जो कारण उनके दल के लीडर बोल रहे थे वह स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे थे लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार पर क्या आरोप है? यही आरोप है कि 13 महीनों के शासन में सबसे पहली और सबसे मजबूत उपलब्धि, जो

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

आजादी के बाद से कावेरी जल विवाद की समस्या इस देश में चल रही थी, कितने प्रधान मंत्री आए और गए लेकिन किसी ने इसके समाधान का रास्ता नहीं ढूंढा। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने भी समाधान का रास्ता नहीं निकाला। सर्वोच्च न्यायालय में भी वर्षों तक मामला लम्बित रहा लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर. मुथैया : हमने ऐसा देखा है परन्तु उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : परन्तु आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। यह एक उपलब्धि है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : यह एक उपलब्धि है।

श्री मोहन रावले : आपने उसकी सराहना की थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केन्द्र में जो सरकार बनी उन्होंने इतने दिनों के विवाद को, अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए समाधान करके देश की जनता को बता दिया कि हम में सरकार की चलाने की क्षमता है, विवाद को समाप्त करने की क्षमता है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यही आरोप इस सरकार पर है? पोकरण में जो बम विस्फोट हुआ, उस समय भी विपक्ष के लोग बहुत हाय-तोबा मचा रहे थे, इसका क्या कारण था? यह विस्फोट पहली बार नहीं हुआ, इंदिरा जी के जमाने में भी हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया और उन्होंने विश्व के बड़े-बड़े देशों को यह बताने का प्रयास किया कि हम किसी पर अंगुली नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे सीने पर हाथ लगाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या यही आरोप सरकार पर है, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बस पर चढ़ कर गए। उनके जाने से पहले लोगों के मन में तरह-तरह की शंका थी। लोग कह रहे थे कि यह केन्द्र सरकार का ड्रामा है लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी गए, जिस तरह पाकिस्तान में लोगों ने उनका स्वागत किया, जिस ढंग से आज हिन्दुस्तान के गांवों के गरीब मुसलमानों के मन में विश्वास पैदा करने का काम अटल जी ने दिल्ली से पाकिस्तान में जाकर किया है, यह आजादी के बाद का एक उदाहरण है। उन्होंने देश के मुसलमानों के प्रति एक आत्मविश्वास जगाया है, पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति एक विश्वास पैदा किया है।...*(व्यवधान)*

इस देश के मुसलमानों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी स्वागत किया है, लेकिन जो पाकिस्तान के आतंकवादी और उन लोगों के एजेंट हैं, उनको इस देश में अच्छा नहीं लगता है।

सभापति महोदय : अब आप कल बोलिए। अब सदन की कार्यवाही कल 16 अप्रैल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1999/ 26 चैत्र, 1921(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।